

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



दिसंबर 2021

खंड 75 अंक 12

अध्यक्ष
माइकल देबब्रत पात्र

संपादन समिति
अजित आर. जोशी
देबा प्रसाद रथ
राजीव रंजन
सितीकांत पट्टनाईक
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर
तुषार बर्मन दास
पुलस्त्या बंदोपाध्याय

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2021

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<https://bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य	
गवर्नर का वक्तव्य	1
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22	
मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प	7
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य	
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य	11
भाषण	
आर्थिक बहाली का स्वरूप	13
ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास	19
आलेख	
अर्थव्यवस्था की स्थिति	27
सरकारी वित्त 2021-22: एक अर्ध-वार्षिक समीक्षा	63
भारत के परिधान निर्यात में क्या-क्या कठिनाइयां हैं	85
कोयला आपूर्ति-मांग की स्थिति और प्रभाव	107
वर्तमान सांख्यिकी	115
हाल के प्रकाशन	162

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

यह वक्तव्य देते हुए, मैं एक वर्तमान-परिभाषित महामारी की दो लहरों से आघात पहुंचाने वाले अनुभव को देखता हूँ। वास्तव में मानव जीवन के लगभग हर पहलू में भारी बदलाव आया है। फिर भी इस मुश्किल सफर में जो हासिल हुआ है वो भी कम असाधारण नहीं है। हम अब अदृश्य दुश्मन, कोविड-19 से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं, जो समय-समय पर और यहां तक कि हाल ही में पूरी दुनिया को भयभीत करता रहता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने सचमुच 2020-21 की पहली तिमाही में सबसे गहरे संकुचनों में से एक से खुद को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, जिसमें हमारे अनुमान के अनुसार, 2021-22 की पहली छमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 13.7 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में, उत्पादन के पूर्व-महामारी के स्तर को पार कर लिया गया है। अल्पकालिक बढ़ोत्तरी को छोड़कर, मुद्रास्फीति मोटे तौर पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ संरेखित है। बाहरी वित्तपोषण आवश्यकताएं बहुत मामूली हैं और मजबूत बफर किसी भी वैश्विक स्पिलओवर का सामना कर सकती है। कर राजस्व में उछाल से सार्वजनिक वित्त को मजबूती मिली है। केंद्र और राज्य सरकारों और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने इस परिणाम को लाने के लिए अभूतपूर्व पैमाने और गुंजाइश पर नीतिगत कार्रवाइयां कीं। इसी तरह नगर निगम और स्थानीय निकायों, स्वास्थ्य देखभाल, पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों; परोपकारी संस्थाएं; और सिविल सोसाइटी के बीच हमारे गुमनाम योद्धाओं के निस्वार्थ और अथक प्रयास काबिले तारीफ है। वे हमें महात्मा गांधी के एक उद्धरण की याद दिलाते हैं: “खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दूसरों की सेवा में खुद को खो दें”¹। मुझे लगता है कि इस महामारी ने वास्तव में भारत को एक साथ ला दिया है और यह वैश्विक विकास चालक के रूप में भारत के आगमन का क्षण हो सकता है।

* गवर्नर का वक्तव्य - 8 दिसंबर 2021

¹ लीडर, आर (2015), द पॉवर ऑफ़ पर्सन : फाइंड मीनिंग , लीव लॉगर, बेटर, पृष्ठ .35

अब मैं 6, 7 और 8 दिसंबर, 2021 को हुई मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के बैठक के विचार-विमर्श की ओर मुड़ता हूँ। समष्टि आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के आकलन के आधार पर, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने और 5 से 1 के बहुमत से निभावकारी नीतिगत रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया। परिणामस्वरूप, नीतिगत रेपो दर 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रहा तथा यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखे गया एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखा गया। सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी रही। प्रतिवर्ती रेपो दर भी 3.35 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

अब मैं नीति दर तथा रुख पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए एमपीसी के औचित्य पर संक्षेप में बताना चाहूंगा। यह देखते हुए कि आर्थिक गतिविधि अक्टूबर में अपने आकलन के अनुरूप व्यापक रूप से विकसित हो रही है, एमपीसी का विचार था कि नए कोविड-19 संक्रमणों में तेज और निरंतर कमी और टीकाकरण कवरेज में वृद्धि, उपभोक्ता विश्वास और व्यापार आशावाद में योगदान दे रही है। आर्थिक गतिविधि की संभावनाओं में लगातार सुधार हो रहा है, जिसमें संपर्क-गहन सेवाएं भी शामिल हैं जो महामारी की चपेट में थीं। एमपीसी ने खाद्य कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए आपूर्ति पक्ष उपायों के साथ-साथ पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य वैट (मूल्य वर्धित कर) में अंशशोधित कटौती का उल्लेख किया। नवंबर के अंत से कच्चे तेल की कीमतों में भी नरमी आई है। ये कुछ हद तक घरेलू लागत-प्रेरित बिल्ड-अप को कम करेंगे।

सकल मांग में सुधार निजी निवेश पर टिकी है, जो अभी भी पिछड़ रही है। एमपीसी ने वैश्विक विकास से उत्पन्न होने वाली बाधाओं के आघात को घरेलू संभावनाओं के लिए मुख्य जोखिम के रूप में माना, जो अब कोविड-19 के ओमिक्रॉन उपभेद द्वारा कुछ हद तक धूमिल हो गया है। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में सुस्ती और गतिविधियों की निरंतर पकड़, विशेष रूप से निजी खपत, जो अभी भी अपने पूर्व-महामारी स्तरों से नीचे है, को

देखते हुए, एक टिकाऊ और वैविध्यपूर्ण सुधार के लिए निरंतर नीति समर्थन की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने मौजूदा रेपो दर को 4 प्रतिशत पर बनाए रखने और निभावकारी रुख को जारी रखने का निर्णय लिया।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

संवृद्धि

30 नवंबर 2021 को एनएसओ द्वारा जारी आंकड़े ने पुष्टि की कि पिछली तिमाही में 20.1 प्रतिशत के बाद 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए वर्ष-दर-वर्ष (वर्ष-दर-वर्ष) 8.4 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था की बहाली कर्षण प्राप्त कर रही है। जीडीपी के सभी घटकों ने वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, निर्यात और आयात ने अपने कोविड-पूर्व स्तरों को मजबूती से पार कर लिया।

आने वाली जानकारी से संकेत मिलता है कि दबी हुई मांग त्योहारी सीजन से पुनः वापस आने से खपत की मांग में सुधार हो रहा है। ग्रामीण मांग लचीलापन प्रदर्शित कर रही है और कृषि और संबद्ध गतिविधियों के मजबूत प्रदर्शन के साथ कृषि रोजगार बढ़ रहा है, जोकि रबी की बुवाई की मजबूत शुरुआत, पीएम-किसान योजना के तहत निरंतर सीधे अंतरण और मार्च 2022 तक प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने द्वारा समर्थित है। पिछले कुछ महीनों में यात्रा और पर्यटन पर खर्च बढ़ने के साथ शहरी मांग में भी मजबूती के संकेत मिले हैं। अन्य संकेतकों जैसे रेलवे माल यातायात, पोर्ट कार्गो, जीएसटी रसीदें, टोल संग्रह, पेट्रोलियम खपत और हवाई यात्री यातायात में भी अक्टूबर/नवंबर में तेजी आई है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और राज्य वैट में हालिया कटौती से क्रय शक्ति में वृद्धि करके खपत की मांग का समर्थन करेगा। अगस्त से सरकारी खपत भी बढ़ रही है, जिससे सकल मांग को समर्थन मिल रहा है।

निवेश गतिविधि के पुनरुद्धार के लिए सक्षम स्थितियाँ भी ठीक हो रही हैं। पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन सितंबर के दौरान लगातार तीसरे महीने महामारी पूर्व स्तर से ऊपर रहा, जबकि पूंजीगत वस्तुओं के आयात में अक्टूबर के दौरान लगातार आठवें महीने दोहरे अंकों की वृद्धि हुई। कुछ पूंजीगत व्यय से

संबंधित मील के पत्थर के अधीन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत के बराबर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अतिरिक्त बाजार उधार में छूट और कैपेक्स को फ्रंट-लोड करने के निर्णय से राज्यों के पूंजी परिव्यय में वृद्धि होने की संभावना है। कैपेक्स पर सरकार का ध्यान निजी निवेश में बढ़ जाना चाहिए, जो लंबे समय से मौन गतिविधि की स्थिति में है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपायों से उत्पन्न अनुकूल मौद्रिक और वित्तीय स्थितियों के बीच कॉर्पोरेट तुलन-पत्र में महत्वपूर्ण कमी आई है।

कुल मिलाकर, महामारी की दूसरी लहर से बाधित होने वाली बहाली फिर से कर्षण प्राप्त कर रही है, लेकिन यह अभी तक आत्मनिर्भर और टिकाऊ होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। यह निरंतर नीति समर्थन के महत्व को रेखांकित करता है।

कई देशों में ओमिक्रोन के उभरने और कोविड -19 संक्रमणों के नए सिरे से बढ़ने के साथ संभावनाओं के लिए नकारात्मक जोखिम बढ़ गए हैं। इसके अलावा, कुछ हालिया सुधारों के बावजूद, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा और पण्य की बढ़ी हुई कीमतों, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति के तेजी से सामान्य होने और लंबे समय तक वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाजारों में संभावित अस्थिरता से प्रतिकूल परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें 2021-22 की तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.0 प्रतिशत शामिल है। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 17.2 प्रतिशत और 2022-23 की दूसरी तिमाही के लिए 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति

जून और सितंबर के बीच तेजी से गिरने के बाद, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर में 4.3 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर में 4.5 प्रतिशत हो गई। यह तेजी मुख्य रूप से देश के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में तेजी को दर्शाती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कीमतों में सख्त होने से घरेलू एलपीजी और मिट्टी के तेल की कीमतें लगभग तीन तिमाहियों तक बढ़ी रही, जिससे अक्टूबर में ईंधन मुद्रास्फीति

बढ़कर 14.3 प्रतिशत हो गई। निविष्टि लागत दबावों, जो मांग के मजबूत होने पर तेजी से खुदरा मुद्रास्फीति में अंतरित हो सकता है, के मद्देनजर, जून 2020 के बाद से उच्च मुख्य मुद्रास्फीति (अर्थात्, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति) की निरंतरता नीतिगत चिंता का एक क्षेत्र है। इस संदर्भ में, पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और वैट में कमी से प्रत्यक्ष प्रभाव के साथ-साथ ईंधन और परिवहन लागत के माध्यम से संचालित होने वाले अप्रत्यक्ष प्रभावों के माध्यम से मुद्रास्फीति में स्थायी कमी आएगी।

अतः, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र हमारे पहले के अनुमानों के अनुरूप होने की संभावना है, और कीमतों का दबाव तत्काल अवधि में बना रह सकता है। रबी फसल की उज्ज्वल संभावनाओं को देखते हुए सर्दियों के आने पर सब्जियों की कीमतों में मौसमी सुधार देखने की उम्मीद है। सरकार द्वारा आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेपों ने घरेलू कीमतों पर उच्च अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों को जारी रखने के नतीजों को सीमित कर दिया है। यद्यपि कच्चे तेल की कीमतों में हाल की अवधि में कुछ सुधार देखा गया है, कीमतों के दबाव का एक टिकाऊ नियंत्रण, महामारी प्रतिबंधों में ढील आने पर मांग में वृद्धि से मेल खाने के लिए मजबूत वैश्विक आपूर्ति प्रतिक्रियाओं पर टिका होगा। मुख्य मुद्रास्फीति पर लागत-प्रेरित दबाव जारी है, यद्यपि अर्थव्यवस्था में सुस्ती के कारण उनका प्रभाव अंतरण मंद रह सकता है। शेष वर्ष के दौरान, मुद्रास्फीति प्रिंट कुछ अधिक होने की संभावना है क्योंकि आधार प्रभाव प्रतिकूल हो जाते हैं; हालांकि, यह उम्मीद की जाती है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2021-22 की चौथी तिमाही में चरम पर होगी और उसके बाद नरम हो जाएगी। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक रूप से संतुलित जोखिमों के साथ 2021-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत; 2021-22 की तीसरी तिमाही में 5.1 प्रतिशत; चौथी तिमाही में 5.7 प्रतिशत अनुमानित है। सीपीआई मुद्रास्फीति तब 2022-23 की पहली तिमाही में 5.0 प्रतिशत तक कम होने और 2022-23 की दूसरी तिमाही में 5.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

हमारी मौद्रिक नीति का रुख मुख्य रूप से उभरती घरेलू मुद्रास्फीति और संवृद्धि की गतिशीलता के अनुरूप है। फिर भी, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा मौद्रिक

नीति सेटिंग्स में आसन्न बदलाव स्पिलओवर के रूप में घरेलू समष्टि-वित्तीय स्थिरता के लिए नई चुनौतियां ला रहे हैं। ऐसे परिदृश्य में, घरेलू समष्टि-मूलभूत को उपयुक्त नीतिगत रुख तथा कार्यों और मजबूत बफर के साथ लचीला होने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे द्वारा प्रदान किए गए एक अच्छी तरह से स्थापित नाममात्र स्थिरक ने महामारी के दौरान विकास संबंधी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए मौद्रिक नीति को विश्वसनीयता और लचीलापन प्रदान किया है। मौजूदा स्थिति में, एक मजबूत संवृद्धि बहाली पर ध्यान केंद्रित करते हुए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के साथ संरेखित रखना महत्वपूर्ण है। साथ ही, रिजर्व बैंक यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता से अवगत रहता है कि वित्तीय स्थिरता जोखिमों के निर्माण को रोकते हुए वित्तीय स्थितियों को व्यवस्थित, कैलिब्रेटेड और अच्छे तरीके से पुनर्संतुलित किया जाता है। मूल्य स्थिरता मौद्रिक नीति के लिए मुख्य सिद्धांत बनी हुई है क्योंकि यह विकास और स्थिरता को बढ़ावा देती है। हमारा सिद्धांत एक सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करना है जो अच्छी तरह से समय पर हो।

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थिति

वैश्विक संदर्भ तेजी से विकसित हो रहा है। ओमिक्रॉन उपभेद के उद्गम ने स्थिति को और जटिल बना दिया है, यहां तक कि कई अर्थव्यवस्थाएं अभी भी वायरस से जूझ रही हैं, जबकि अन्य कोविड -19 के लंबे समय तक रहने वाले निशान से निपट रहे हैं। जैसे-जैसे अर्थव्यवस्थाएं फिर से खुली हैं, बंद आपूर्ति श्रृंखलाओं, प्रमुख निविष्टियों की कमी और सीमित श्रम बाजारों के साथ कैच-अप मांग में उछाल आया है। ऊर्जा और पण्य की उच्च कीमतों के साथ, इसने उत्पादन के पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस आने से पहले कई देशों में लंबे समय से निष्क्रिय मुद्रास्फीति को प्रज्वलित किया है। उन्नत और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं, दोनों में, कई केंद्रीय बैंकों ने संकट-समय की नीतियों से अपने स्वयं के संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता की आवश्यकता के अनुसार खोलना शुरू कर दिया है। अब, यात्रा और आवाजही पर फिर से प्रतिबंधों की आशंकाओं के साथ, इस समय काफी अनिश्चितता है कि तत्काल महीनों में संवृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता कैसे होगी। परिणामस्वरूप वित्तीय स्थितियां तेजी से अस्थिर होती जा रही हैं।

रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त अधिशेष तरलता बनाए रखी है ताकि उभरते विकास आवेगों को पोषित किया जा सके और एक टिकाऊ आर्थिक सुधार का समर्थन किया जा सके। इससे सरल और पूर्ण मौद्रिक नीति संचरण और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम के व्यवस्थित संचालन की सुविधा मिली है। रिज़र्व बैंक चलनिधि का प्रबंधन इस तरीके से करना जारी रखेगा जो बहाली को मजबूत करने और समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल हो।

फरवरी 2020 में तैयार किए गए संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे को बहाल करने के हमारे प्रयास में, रिज़र्व बैंक चलनिधि अधिशेष को स्थायी दर एक दिवसीय प्रतिवर्ती रेपो विंडो से दीर्घावधि परिपक्वता वाली परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) नीलामियों में अंतरित करके पुनर्संतुलित कर रहा है। इसका उद्देश्य मुख्य चलनिधि प्रबंधन परिचालन के रूप में 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी को फिर से स्थापित करना है। इस पुनर्संतुलन ने पूर्व-घोषित ग्लाइड पथ का अनुसरण किया जिसके द्वारा वीआरआरआर नीलामी राशि को उत्तरोत्तर बढ़ाकर 3 दिसंबर तक ₹6.0 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। इस वृद्धि के जवाब में, हाल के दिनों में एक दिवसीय संपार्श्विक मुद्रा बाजार दरों में मामूली मजबूती आई है। कुल मिलाकर, चलनिधि का पुनर्संतुलन, योजना के अनुसार समयबद्ध और गैर-विघटनकारी तरीके से आगे बढ़ा है। यह चलनिधि शेष पर रिज़र्व बैंक के नियंत्रण को मजबूत करने के अपने उद्देश्य को भी पूरा कर रहा है, जो बदले में, आवश्यकता पड़ने पर चलनिधि की स्थिति को सामान्य करने के लिए रिज़र्व बैंक की क्षमता को समर्थित करता है।

रिज़र्व बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त तरलता बनाए रखते हुए तरलता की स्थिति को गैर-विघटनकारी तरीके से पुनर्संतुलित करना जारी रखेगा। इस उद्देश्य के साथ, अब पाक्षिक आधार पर 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी राशि को निम्नलिखित तरीके से बढ़ाने का प्रस्ताव है: 17 दिसंबर को ₹6.5 लाख करोड़; और आगे 31 दिसंबर को ₹7.5 लाख करोड़। परिणामस्वरूप, जनवरी 2022 से, तरलता अवशोषण मुख्य रूप से नीलामी मार्ग के माध्यम से किया जाएगा।

जैसा कि पहले घोषित किया गया था, आरबीआई समय-समय पर अप्रत्याशित और एकमुश्त तरलता प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए अच्छा संचालन करता रहा है ताकि प्रणालीगत चलनिधि की स्थिति संतुलित और समान रूप से वितरित तरीके से विकसित हो। आरबीआई 28-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी भी आयोजित कर रहा है। आगे बढ़ते हुए, 14-दिवसीय वीआरआरआर का मुख्य संचालन लंबी अवधि के वीआरआरआर द्वारा पूरक होना जारी रहेगा, जिसका आकार और परिपक्वता, विकसित तरलता स्थितियों के निरंतर मूल्यांकन के आधार पर तय किया जाएगा। रिज़र्व बैंक आवश्यकता पड़ने पर अलग-अलग राशियों/परिपक्वताओं के फाइन-ट्यूनिंग संचालन करने के लिए लचीलापन भी बरकरार रखता है। जैसा कि मैंने अपने वक्तव्यों और भाषणों में बार-बार जोर दिया है, रिज़र्व बैंक का प्रयास एक प्रभावी चलनिधि प्रबंधन ढांचा तैयार करना है जो एक ऐसी अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो जो महामारी से उभर रही हो और एक नवीन लेकिन मजबूत बहाली कर रही हो। रिज़र्व बैंक उभरती समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थितियों के अनुरूप प्रभावी मौद्रिक संचरण और ब्याज दर की अपेक्षाओं को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक ऑपरेशन ट्विस्ट (ओटी) और नियमित खुले बाजार संचालन (ओएमओ) करने के लिए भी प्रतिबद्ध है।

चलनिधि अधिशेष को पुनर्संतुलित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 27 मार्च और 17 अप्रैल 2020 को घोषित लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालनों (टीएलटीआरओ 1.0 और 2.0) के तहत प्राप्त निधि की बकाया राशि का पूर्व भुगतान करने का एक और विकल्प प्रदान किया जाए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैंकों ने नवंबर 2020 में पहले ही ₹37,348 करोड़ का पूर्व भुगतान कर दिया है, जो इस योजना के तहत प्राप्त ₹1,12,900 करोड़ का लगभग एक तिहाई है।

कोविड से संबंधित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में सुधार के लिए ₹50,000 करोड़ की ऑन-टैप तरलता विंडो और कुछ संपर्क-गहन क्षेत्रों के लिए ₹15,000 करोड़ उनकी अंतिम तारीख अर्थात् 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।

इसके अलावा, यह देखते हुए कि अतिरिक्त चलनिधि स्थितियों के कारण एमएसएफ विंडो का उपयोग कम है, हम एमएसएफ के तहत सामान्य व्यवस्था पर लौटने का प्रस्ताव करते हैं। परिणामस्वरूप, बैंक 1 जनवरी 2022 से एमएसएफ के तहत एक दिवसीय उधारी के लिए 3 प्रतिशत के बजाय निवल मांग और मीयादी देयताएं (एनडीटीएल) के 2 प्रतिशत तक कम करने में सक्षम होंगे। महामारी की शुरुआत में प्रदान की गई इस छूट ने एक महत्वपूर्ण समय में बाजार के विश्वास को बढ़ाया था।

मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हम मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हुए विकास के आवेगों को व्यापक बनाने के लिए इस समय अपनी व्यापक प्राथमिकता के समर्थन में अपने रुख के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हम अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों में ऋण के पर्याप्त प्रवाह को प्रोत्साहित करना भी जारी रखेंगे।

अतिरिक्त उपाय

हमारे सतत आकलन के आधार पर आज कुछ अतिरिक्त उपायों की भी घोषणा की जा रही है। इन उपायों का विवरण मौद्रिक नीति वक्तव्य के विकासात्मक और विनियामक नीतियों (भाग-बी) पर वक्तव्य में प्रस्तुत किया गया है। अतिरिक्त उपाय इस प्रकार हैं:

विदेशी शाखाओं और बैंकों की सहायक कंपनियों में पूंजी का प्रवाह और इन संस्थाओं द्वारा प्रतिधारण/प्रत्यावर्तन/लाभ का हस्तांतरण

वर्तमान में, भारत में निगमित बैंक अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक कंपनियों में पूंजी लगा सकते हैं; इन केंद्रों में लाभ बनाए रख सकते हैं; और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से लाभ को प्रत्यावर्तित/हस्तांतरित कर सकते हैं। बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि यदि बैंक नियामक पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो उन्हें आरबीआई के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है।

बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा पर चर्चा पत्र

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड बड़े पैमाने

पर अक्टूबर 2000 में शुरू किए गए ढांचे पर आधारित हैं। तब से घरेलू वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण विकास और इस क्षेत्र में वैश्विक मानकों/सर्वोत्तम प्रथाओं को देखते हुए, परामर्श प्रक्रिया के बाद इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता महसूस की गई है। इस दिशा में, टिप्पणियों के लिए शीघ्र ही एक चर्चा पत्र भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

भुगतान प्रणाली में शुल्क पर चर्चा पत्र

सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से हाल के वर्षों में डिजिटल भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान उपकरणों (कार्ड और वॉलेट), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) और इसी तरह के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए ग्राहकों द्वारा किए गए विभिन्न शुल्कों की तर्कसंगतता पर कुछ चिंताएं हैं। भुगतान प्रणाली में विभिन्न शुल्कों पर एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव है ताकि इसमें शामिल मुद्दों और चिंताओं को कम करने के संभावित दृष्टिकोण के बारे में समग्र दृष्टिकोण ले सकें ताकि डिजिटल लेनदेन को और अधिक किफायती बनाया जा सके।

यूपीआई : सीमा का सरलीकरण, गहरा करना और बढ़ाना

लेन-देन की मात्रा के मामले में यूपीआई देश में सबसे बड़ी खुदरा भुगतान प्रणाली है, जो विशेष रूप से छोटे मूल्य के भुगतान के लिए इसकी व्यापक स्वीकृति को दर्शाता है। डिजिटल भुगतान को और गहरा करने और उन्हें अधिक समावेशी बनाने, उपभोक्ताओं के लिए लेनदेन को आसान बनाने, वित्तीय बाजारों के विभिन्न क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी की सुविधा प्रदान करने और सेवा प्रदाताओं की क्षमता बढ़ाने के लिए, यह प्रस्तावित है कि (i) फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए यूपीआई-आधारित भुगतान उत्पादों को लॉन्च करना, खुदरा भुगतान पर आरबीआई के नियामक सैंडबॉक्स से नवीन उत्पादों का लाभ उठाना; (ii) यूपीआई अनुप्रयोगों में 'ऑन-डिवाइस' वॉलेट के एक तंत्र के माध्यम से छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए प्रक्रिया प्रवाह को सरल बनाना; तथा (iii) सरकारी प्रतिभूतियों और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) अनुप्रयोगों में निवेश के लिए खुदरा प्रत्यक्ष योजना के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान के लिए लेनदेन की सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करना।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/व्यापार ऋण (टीसी) - लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में अंतरण

वर्तमान में, ईसीबी और व्यापार ऋण पर ब्याज दरें, लिबोर या उधार की मुद्रा पर लागू किसी अन्य अंतर बैंक दर के लिए बेंचमार्क की गई हैं। जैसे हम लिबोर से दूर हो रहे हैं, ऐसे लेनदेन के लिए किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर बैंक दर या वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) के उपयोग को सक्षम करने वाले दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

समापन टिप्पणी

वैश्विक स्तर पर, अर्थव्यवस्थाएं खुल रही हैं और गतिविधि स्तर पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच रहे हैं। साथ ही, दुनिया के कई हिस्सों में कोविड-19 तरंगों की पुनरावृत्ति, जिसमें ओमिक्रॉन संस्करण की उपस्थिति, जिद्दी मुद्रास्फीति और निरंतर आपूर्ति बाधाओं से हेडविंड शामिल हैं, ने संभावना पर एक छाया डाल रहा है। विभिन्न देशों में विकसित हो रही विकास-मुद्रास्फीति की गतिशीलता को देखते हुए, मौद्रिक नीति भी वित्तीय बाजारों को नुकीले रखते हुए एक परिवर्तन बिंदु पर पहुंच रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था बहाली के पथ पर अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में है, लेकिन यह वैश्विक स्पिलओवर या ओमिक्रॉन वेरिएंट सहित नए म्यूटेशन से संक्रमण के संभावित उछाल के प्रति प्रतिरक्षित नहीं हो सकती है। इसलिए, हमारे समष्टि आर्थिक

मूलभूत को मजबूत करना, हमारे वित्तीय बाजारों और संस्थानों को लचीला और मजबूत बनाना, और विश्वसनीय और सुसंगत नीतियों को लागू करना, इन अनिश्चित समय में सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

एक टिकाऊ, मजबूत और समावेशी बहाली का प्रबंधन करना हमारा मिशन है। हमें अपने प्रयासों में दृढ़, धैर्यवान और लगातार बने रहने की आवश्यकता है। हमें अपने सामने आने वाली नई वास्तविकताओं के प्रति भी जागरूक, सतर्क और चुस्त रहने की जरूरत है। पिछले एक साल और नौ महीनों के हमारे प्रयासों ने हमें आत्मविश्वास दिया है और आगे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नई शुरुआत की है। नेल्सन मंडेला का उद्धरण, “आशावादी होने का मतलब है अपने सर को सूर्य की ओर रखना, अपने पैरों को आगे बढ़ाना”² है। हमारी आगे की यात्रा अब और स्पष्ट हो गई है और हमारा मिशन तैयार हो गया है। आइए हम महात्मा गांधी के शब्दों: “मेरी सफलता मेरे निरंतर, विनम्र, सच्चे प्रयास में निहित है। मुझे रास्ता पता है। यह सीधा और संकरा है। यह तलवार के सीरे के समान है। मुझे उस पर चलने में खुशी होती है। ... जो प्रयत्न करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। मुझे उस वादे पर पूरा भरोसा है...”³ से प्रेरित एक मजबूत, स्थिर और जीवंत अर्थव्यवस्था की दिशा में मिलकर काम करें।

धन्यवाद। सुरक्षित रहें। स्वस्थ रहें। नमस्कार।

² मंडेला, एन. (1995) लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम: द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला।

³ द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (CWMG), वॉल्यूम 35, पी. 374-375।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22 मौद्रिक नीति समिति
(एमपीसी) का संकल्प

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2021-22

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी)

का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (8 दिसंबर 2021) को अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टि आर्थिक परिस्थिति का आकलन करने के आधार पर यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ़) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए।

एलएएफ़ के तहत रिवर्स रेपो दर बिना किसी परिवर्तन के 3.35 प्रतिशत पर और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ़) दर एवं बैंक दर 4.25 प्रतिशत पर बनी हुई हैं।

- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का भी निर्णय लिया।

ये निर्णय संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है।

इस निर्णय के पीछे के मुख्य विचार नीचे दिए गए विवरण में व्यक्त की गई हैं।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. 6-8 अक्टूबर 2021 के दौरान एमपीसी की बैठक के बाद से, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में संक्रमणों की वृद्धि, ओमिक्रोन उपभेद का उद्गमन, आपूर्ति श्रृंखला में रुकावटों की निरंतरता और ऊर्जा

और पण्य की कीमतों में वृद्धि का वैश्विक आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव जारी है। बंदरगाह सेवाओं में व्यवधान और टर्नअराउंड समय, माल ढुलाई की उच्च दरों और सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक कमी के कारण महामारी से तेज वापसी के बाद भी वैश्विक वस्तु व्यापार धीमा हो रहा है, जो भविष्य के विनिर्माण उत्पादन और व्यापार को कम कर सकता है। हालांकि, लगातार आठ महीने विनिर्माण की तुलना में सेवाओं के बेहतर प्रदर्शन के साथ कम्पोजिट वैश्विक क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) नवंबर में चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

3. अन्य के साथ-साथ नए कोविड-19 उपभेद से अनिश्चितताओं के बाद भी अक्टूबर के अंत में कुछ सौम्यता और नवंबर के अंत में और गिरावट के बावजूद वस्तुओं की कीमतें उच्च बनी रही। कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जिससे कई केंद्रीय बैंकों को सख्ती बरतने और अन्य को नीति सामान्यीकरण को आगे लाने के लिए प्रेरित किया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी मासिक संपत्ति खरीद में कमी और तेजी से कम होने की संभावना के साथ, अस्थिरता की नई पारी और बढ़ी हुई अनिश्चितताओं ने वैश्विक वित्तीय बाजारों को अस्थिर कर दिया है। मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों के कारण अधिकांश देशों में बढ़ी हुई बॉन्ड प्रतिफल नवंबर के अंतिम सप्ताह से कम हो गए। अमेरिकी डॉलर हाल के हफ्तों में ईई और ईएमई दोनों मुद्राओं के मुकाबले उच्च स्तर पर कारोबार कर रहा है।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. घरेलू मोर्चे पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 30 नवंबर 2021 को जारी किए गए आंकड़ों से पता चला है कि 2021-22 की पहली तिमाही के दौरान 20.1 प्रतिशत की वृद्धि के बाद 2021-22 की दूसरी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सुधार की गति के साथ, सकल मांग के सभी घटक निर्यात और आयात के साथ संवृद्धि क्षेत्र में प्रवेश कर गए, जो उनके कोविड-19 से पहले के स्तरों से स्पष्ट रूप से अधिक था। आपूर्ति पक्ष पर, 2021-22 की दूसरी तिमाही के

* 8 दिसंबर 2021 को जारी

दौरान वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 8.5 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष की वृद्धि हुई।

5. 2021-22 की तीसरी तिमाही के लिए उपलब्ध डाटा इंगित करता है कि आर्थिक गतिविधि की गति, अतिरिक्त कर्षण प्राप्त कर रही है जिसे टीकाकरण कवरेज के विस्तार, नए संक्रमणों में तेजी से कमी और रुकी हुई मांग के पुनः बढ़ने से समर्थन प्राप्त हुआ है। ग्रामीण मांग ने लचीलापन प्रदर्शित किया- 2019 के इसी महीने (पूर्व-महामारी स्तर) की तुलना में अक्टूबर में ट्रैक्टर की बिक्री में सुधार हुआ, जबकि मोटरसाइकिल की बिक्री धीरे-धीरे अपने पूर्व-महामारी के स्तर की ओर बढ़ रही है। पीएम किसान योजना के तहत निरंतर प्रत्यक्ष अंतरण ग्रामीण मांग का समर्थन कर रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम की मांग एक वर्ष पहले की तुलना में नवंबर में कम हुई, जो कृषि श्रमिकों की मांग में तेजी का संकेत देती है। अनुकूल मिट्टी की नमी और अच्छे जलाशय भंडारण स्तरों द्वारा समर्थित, रबी की बुवाई 3 दिसंबर 2021 को एक वर्ष पहले की तुलना में 6.1 प्रतिशत अधिक थी।

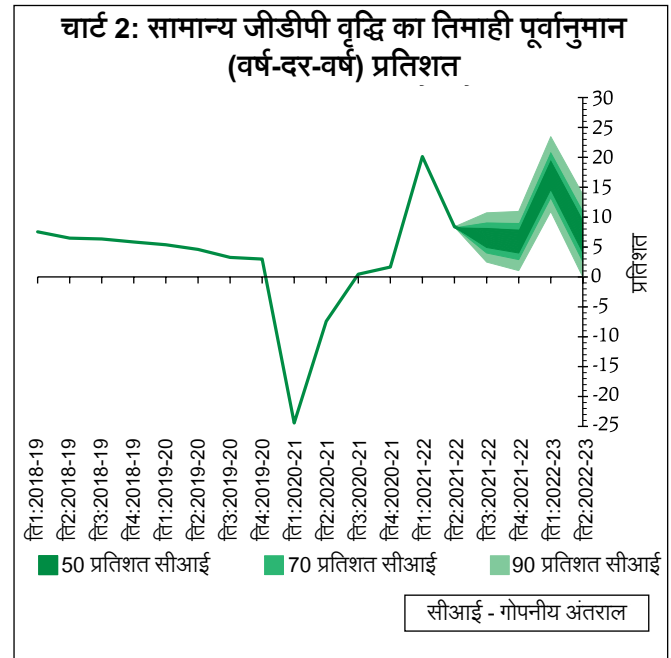
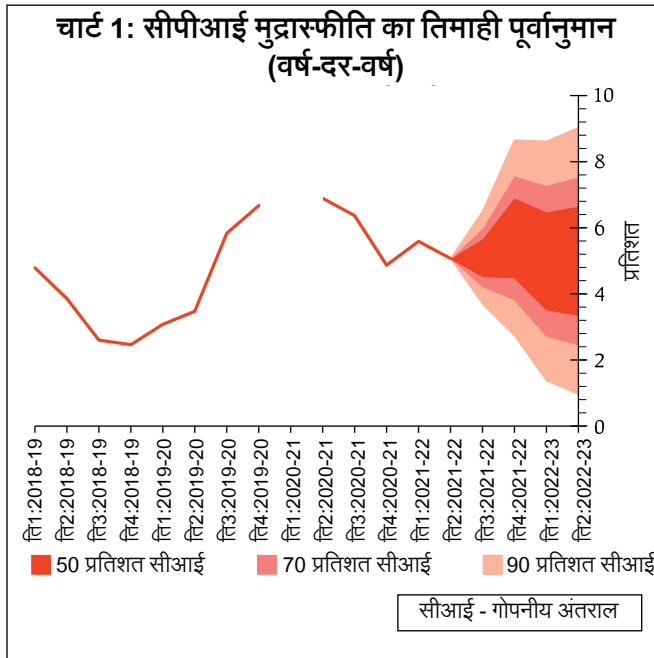
6. उपभोक्ता आशावाद में सुधार के बाद शहरी मांग और संपर्क-गहन सेवाओं की गतिविधियों में उछाल आ रहा है, जो त्योहार की मांग से समर्थित है। बिजली की मांग, रेलवे माल ढुलाई, पोर्ट कार्गो, टोल संग्रह और पेट्रोलियम खपत जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों ने 2019 के इसी महीनों की तुलना में अक्टूबर / नवंबर में मजबूत वृद्धि दर्ज की। आपूर्ति पक्ष की कमी के दूर होने के बाद अक्टूबर में उन्हें गति मिलने के बावजूद ऑटोमोबाइल बिक्री, स्टील की खपत और हवाई यात्री यातायात अभी भी 2019 के स्तर से नीचे रहा। निवेश गतिविधि में सुधार के मामूली संकेत दिखाई दे रहे हैं- पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन सितंबर के दौरान लगातार तीसरे महीने महामारी से पहले के स्तर से ऊपर रहा, जबकि अक्टूबर में पूंजीगत वस्तुओं का आयात दो साल पहले के स्तर से दो अंकों की गति से बढ़ा। नवंबर 2021 के लिए विनिर्माण और सेवाओं के पीएमआई के प्रिंट ने आर्थिक गतिविधियों में निरंतर सुधार का सुझाव दिया। नवंबर में लगातार नौवें महीने निर्यात में वृद्धि हुई, साथ ही घरेलू मांग को पुनर्जीवित करने के कारण गैर-तेल गैर-सोने के आयात में वृद्धि हुई।

7. हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति, जो जून 2021 से नीचे की ओर रही है, कई राज्यों में अक्टूबर में हुई भारी बारिश से फसल को हुए नुकसान और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस और मिट्टी के तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों से प्रेरित ईंधन मुद्रास्फीति के कारण अक्टूबर में बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गया, जो सितंबर में 4.3 प्रतिशत था। वास्तव में, अक्टूबर में ईंधन मुद्रास्फीति 14.3 प्रतिशत थी जो अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। कपड़ों और जूतों, स्वास्थ्य, और परिवहन और संचार उप-समूहों से उत्पन्न निरंतर बढ़ते दबाव के साथ सितंबर-अक्टूबर के दौरान खाद्य और ईंधन को छोड़कर कोर मुद्रास्फीति या सीपीआई मुद्रास्फीति 5.9 प्रतिशत पर बनी रही।

8. चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत स्थायी दर प्रतिवर्ती रेपो और परिवर्तनीय दर प्रतिवर्ती रेपो (वीआरआरआर) परिचालन के माध्यम से दैनिक अवशोषण के साथ, तरलता की स्थिति बड़े अधिशेष में बनी रही, जिसका औसत अक्टूबर-नवंबर में ₹8.6 लाख करोड़ रहा। आरक्षित धन (नकदी आरक्षित अनुपात में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव के लिए समायोजित) में 3 दिसंबर 2021 को 7.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। 19 नवंबर 2021 को मुद्रा आपूर्ति (एम3) और वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण में क्रमशः 9.5 प्रतिशत और 7.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2021-22 (3 दिसंबर 2021 तक) में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 58.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 635.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

संभावना

9. मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र, आगे जाकर, कई कारकों पर निर्भर होगा। अक्टूबर और नवंबर में भारी बारिश के कारण सब्जियों की कीमतों में आई तेजी में सर्दियों के आने के साथ पलटने की संभावना है। रबी की बुवाई अच्छी प्रगति कर रही है और पिछले साल की मात्रा से अधिक होने की संभावना है। सरकार द्वारा हाल ही में सक्रिय आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप ने घरेलू खुदरा मुद्रास्फीति के लिए अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि के पास-श्रू को रोकना जारी रखा है। हाल की अवधि में कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय सुधार देखा गया है। उच्च औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों, परिवहन लागत, और वैश्विक रसद और आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं से लागत-प्रेरित दबाव ने मुख्य मुद्रास्फीति पर प्रभाव



डालना जारी रखा है। अर्थव्यवस्था में सुस्ती बढ़ती इनपुट लागत और आउटपुट कीमतों के प्रभाव को कम कर रही है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, व्यापक तौर पर संतुलित जोखिम के साथ 2021-22 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.3 प्रतिशत; क्यू3 में 5.1 प्रतिशत; ति4: 2021-22 में 5.7 प्रतिशत अनुमानित है। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 5.0 प्रतिशत (चार्ट 1) अनुमानित है।

10. बढ़ते टीकाकरण कवरेज, नए कोविड-19 मामलों में मंदी और गतिशीलता के तेजी से सामान्य होने के साथ घरेलू आर्थिक गतिविधियों में सुधार तेजी से व्यापक-आधारित हो रहा है। ग्रामीण मांग में लचीलापन रहने की उम्मीद है। संपर्क-गहन गतिविधियों में तेजी और रुकी हुई मांग, शहरी मांग को बढ़ावा देना जारी रखेगी। सरकार का बुनियादी ढांचा, निष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का विस्तार, संरचनात्मक सुधार, क्षमता उपयोग की बहाली और सौम्य तरलता और वित्तीय स्थितियां, निजी निवेश की मांग के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करती हैं। रिज़र्व बैंक के सर्वेक्षणों ने व्यापार दृष्टिकोण और उपभोक्ता विश्वास में सुधार की ओर इशारा किया है। दूसरी ओर, पण्य की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक आपूर्ति में लगातार रुकावट, वायरस के नए म्यूटेशन और वित्तीय

बाजार में उतार-चढ़ाव ने दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा किया है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और भारत में कोविड-19 संक्रमणों में कोई पुनरुत्थान नहीं होने पर, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 2021-22 में 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है, जिसमें ति3 में 6.6 प्रतिशत; और ति4:2021-22 में 6.0 प्रतिशत शामिल है। 2022-23 की पहली तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 17.2 प्रतिशत और दूसरी तिमाही के लिए 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है (चार्ट 2)।

11. सब्जियों की कीमतों में हालिया वृद्धि का खाद्य मुद्रास्फीति प्रिंटों पर प्रभाव के समाप्त होने की उम्मीद है क्योंकि सर्दियों में कीमतों में सामान्य नरमी शुरू हो जाती है। नवंबर में पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क और राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) के आंशिक रोलबैक ने खुदरा बिक्री कीमतों में ढील प्रदान की है और समय के साथ दूसरे दौर के प्रभाव होंगे। कच्चे तेल में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन इसमें उतार-चढ़ाव बना हुआ है। मुख्य मुद्रास्फीति पर बारीकी से नजर रखने और नियंत्रण में रखने की आवश्यकता होगी। मुख्य मुद्रास्फीति को निरंतर कम करने के लिए, उत्पाद शुल्क और वैट के सामान्यीकरण को जारी रखने के साथ-साथ मांग में सुधार होने पर अन्य इनपुट लागत दबावों के

लिए उपाय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। घरेलू सुधार कर्षण प्राप्त कर रहा है, लेकिन गतिविधि केवल पूर्व-महामारी के स्तर पर आने की है और इसे अनुकूल नीतिगत सेटिंग्स द्वारा तब तक पोषित करना होगा जब तक कि यह अपनी जड़ न पकड़ लें और आत्मनिर्भर न हो जाए। विशेष रूप से, निजी निवेश को निर्यात द्वारा प्रदान किए जा रहे मजबूत प्रोत्साहन के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार का नेतृत्व करना होगा। ति2: 2021-22 में मजबूत सुधार के बावजूद, निजी खपत अपने पूर्व-महामारी स्तर से नीचे बनी हुई है और संपर्क-गहन सेवाओं की मांग संभावित रूप से हेडविंड का सामना कर सकती है यदि अधिकारी ओमीक्रोन के नतीजों को रोकने के लिए पूर्व-अधिकृत कदम उठाते हैं। अधोगामी जोखिम महत्वपूर्ण बने हुए हैं, जिससे दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित हो गया है, विशेष रूप से वैश्विक स्पिलओवर, नए म्यूटेशन्स के साथ कोविड-19 संक्रमणों में संभावित पुनरुत्थान, निरंतर कमी और अड़चनें के कारण और दुनिया भर में नीतिगत कार्यों और रुख में व्यापक भिन्नता के रूप में मुद्रास्फीति का दबाव बना रहता है। वैश्विक वित्तीय स्थितियों का कड़ा होना वैश्विक आर्थिक गतिविधियों और भारत की संभावनाओं के लिए भी जोखिम पैदा करता है। इस पृष्ठभूमि में, एमपीसी ने निर्णय लिया है कि चल रहे घरेलू सुधार को इसे और अधिक व्यापक बनाने के लिए निरंतर नीति समर्थन की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति की गतिशीलता पर सतर्क रहते हुए विकास संकेतों के ठोस रूप से मजबूत होने की प्रतीक्षा करना उचित मानते हुए, एमपीसी ने नीति रेपो दर को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने

और यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

12. एमपीसी के सभी सदस्य – डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, प्रो. जयंत आर. वर्मा, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीति रेपो दर को 4.0 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

13. प्रो. जयंत आर. वर्मा को छोड़कर एमपीसी के सभी सदस्यों अर्थात् डॉ. शंशाक भिडे, डॉ. आशिमा गोयल, डॉ. मृदुल के. सागर, डॉ. माइकल देवव्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने सर्वसम्मति से यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति भविष्य में लक्ष्य के भीतर बनी रहे, और टिकाऊ आधार पर संवृद्धि को बनाए रखने एवं अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए मतदान किया। प्रो. जयंत आर. वर्मा ने संकल्प के इस भाग पर संदेह व्यक्त किया।

14. एमपीसी की बैठक का कार्यवृत्त 22 दिसंबर 2021 को प्रकाशित किया जाएगा।

15. एमपीसी की अगली बैठक 7-9 फरवरी 2022 के दौरान निर्धारित है।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) विनियमन और पर्यवेक्षण; (ii) वित्तीय बाजार और; (iii) भुगतान और निपटान प्रणाली से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन और पर्यवेक्षण

1. बैंकों की विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं में पूंजी लगाना और इन संस्थाओं द्वारा लाभ का प्रतिधारण/प्रत्यावर्तन/अंतरण

भारत में निगमित बैंक, वर्तमान में अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं में पूंजी लगाने के साथ-साथ इन केंद्रों से लाभ के प्रतिधारण और प्रत्यावर्तन/अंतरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करते हैं। समीक्षा करने पर, और बैंकों को परिचालनात्मक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि विनियामक पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, कार्योत्तर रिपोर्टिंग के अधीन, अपने बोर्ड के अनुमोदन से, अपनी विदेशी शाखाओं और सहायक संस्थाओं में पूंजी डाल सकते हैं; इन केंद्रों में लाभ प्रतिधारित कर सकते हैं; और उससे होने वाले लाभों को प्रत्यावर्तित/अंतरित कर सकते हैं।

2. बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा पर चर्चा पत्र

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण और मूल्यांकन पर मौजूदा विनियामक निदेश अक्टूबर 2000 में शुरू किए गए ढांचे पर आधारित हैं, जो काफी हद तक तत्कालीन प्रचलित वैश्विक मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है। निवेश के वर्गीकरण, माप और मूल्यांकन पर वैश्विक मानकों में बाद के महत्वपूर्ण विकास के मद्देनजर, पूंजी पर्याप्तता ढांचे के साथ-साथ घरेलू वित्तीय बाजारों में प्रगति के साथ, इन मानदंडों की समीक्षा और अद्यतन करने की आवश्यकता है। इस दिशा में एक कदम के रूप में, सभी प्रासंगिक पहलुओं को शामिल करते हुए एक चर्चा पत्र शीघ्र ही भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर टिप्पणियों के लिए रखा जाएगा।

II. वित्तीय बाजार

3. बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/व्यापार ऋण (टीसी) - लिबोर से वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) में परिवर्तन

वर्तमान में, विदेशी मुद्रा (एफसीवाई) बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)/व्यापार ऋण (टीसी) के लिए बेंचमार्क दर 6-महीने लिबोर दर या उधार की मुद्रा पर लागू किसी अन्य 6-महीने की अंतर बैंक ब्याज दर के रूप में निर्दिष्ट है। लिबोर के निकटस्थ बंद होने के मद्देनजर, उधार की मुद्रा पर लागू किसी भी व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर-बैंक दर या वैकल्पिक संदर्भ दर (एआरआर) को, बंद होने के बाद, बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नई विदेशी मुद्रा ईसीबी और टीसी के लिए लिबोर और एआरआर के बीच क्रेडिट जोखिम और मियादी प्रीमियम में अंतर को ध्यान में रखते हुए, समग्र लागत सीमा को एआरआर पर क्रमशः 450 बीपीएस से 500 बीपीएस और 250 बीपीएस से 300 बीपीएस तक संशोधित करने का प्रस्ताव है। लिबोर से जुड़े मौजूदा ईसीबी और टीसी के परिवर्तन को सक्षम करने के लिए, समग्र लागत सीमा को एआरआर पर क्रमशः 450 बीपीएस से 550 बीपीएस और 250 बीपीएस से 350 बीपीएस तक संशोधित करने का प्रस्ताव है।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

4. भुगतान प्रणाली में प्रभारों पर चर्चा पत्र

हाल के वर्षों में सभी हितधारकों के ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल भुगतान के लिए स्वीकृति बुनियादी ढांचे में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई है। डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान करने में शामिल संस्थाएं लागत वहन करती हैं, जो आम तौर पर व्यापारी या ग्राहक से वसूल की जाती हैं या एक या अधिक प्रतिभागियों द्वारा वहन की जाती हैं। जबकि इन प्रभारों को वहन करने वाले ग्राहकों के फायदे और नुकसान दोनों हैं, उन्हें यथोचित होना चाहिए और डिजिटल भुगतान को अपनाने में बाधक नहीं बनना चाहिए। शामिल मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण लेने के लिए, एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव है जिसमें डिजिटल भुगतान के विभिन्न चैनलों जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रीपेड भुगतान लिखतों (कार्ड और वॉलेट), यूपीआई, आदि में शामिल प्रभारों से संबंधित सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा। यह चर्चा पत्र

सुविधा शुल्क, अधिभार, आदि से संबंधित मुद्दों और उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल लेनदेन को किफायती बनाने और प्रदाताओं के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी बनाने के लिए आवश्यक उपायों पर भी प्रतिक्रिया मांगेगा। चर्चा पत्र एक महीने के समय में जारी किया जाएगा।

5. फीचर फोन उपयोगकर्ता के लिए यूपीआई

भारत में लगभग 118 करोड़ मोबाइल उपयोगकर्ताओं (ट्राई, अक्टूबर 2021)¹ का एक बड़ा मोबाइल फोन उपभोक्ता आधार है, जिसमें से लगभग 74 करोड़ (स्टेटिस्टा, जुलाई 2021) के पास स्मार्ट फोन हैं, जो दर्शाता है कि देश में फीचर फोन उपयोगकर्ताओं की एक बड़ी संख्या है²। फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के पास अभिनव भुगतान उत्पादों तक सीमित पहुंच है। हालांकि फीचर फोन में *99# के लघु कोड का उपयोग करके मूल भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने के विकल्प के रूप में एनयूपी (नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म) है, लेकिन इसका उपयोग नहीं किया जाता है। वित्तीय पैठ को गहन बनाने के लिए, फीचर फोन उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की मुख्यधारा में लाना महत्वपूर्ण है। आरबीआई विनियामक सैंडबॉक्स के पहले कोहार्ट में, कुछ नवोन्मेषकों ने 'खुदरा भुगतान' की थीम के तहत फीचर फोन भुगतान के लिए अपने समाधानों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था। अन्य कॉम्प्लिमेंट्री सॉल्यूशंस के साथ ये उत्पाद व्यापक डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए फीचर फोन पर यूपीआई-आधारित डिजिटल भुगतान समाधान की सुविधा प्रदान करेंगे। फीचर फोन यूजर्स के लिए यूपीआई-आधारित भुगतान उत्पाद लॉन्च करने का प्रस्ताव है। आगे के विवरण की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी।

6. यूपीआई पर छोटे मूल्य के लेनदेन के लिए प्रक्रिया प्रवाह का सरलीकरण

लेन-देन की मात्रा (प्रति दिन 14 करोड़ लेनदेन, अक्टूबर 2021)³ के मामले में यूपीआई देश में सबसे बड़ी खुदरा भुगतान

प्रणाली है। यूपीआई के शुरुआती उद्देश्यों में से एक कम मूल्य के लेनदेन के लिए नकदी की जगह लेना था। लेन-देन डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि यूपीआई के माध्यम से किए गए 50 प्रतिशत लेनदेन ₹200 से कम वाले थे, जो इसकी सफलता को दर्शाता है। हालांकि, ये कम मूल्य के लेन-देन, महत्वपूर्ण प्रणाली क्षमता और संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे कई बार कनेक्टिविटी से संबंधित मुद्दों के कारण लेनदेन की विफलता के कारण ग्राहकों को असुविधा होती है। अतः, यूपीआई ऐप में "ऑन-डिवाइस" वॉलेट के माध्यम से छोटे मूल्य के लेनदेन को सक्षम करके एक सरल प्रक्रिया प्रवाह की पेशकश करने का प्रस्ताव है जो उपयोगकर्ता के लेनदेन अनुभव में किसी भी बदलाव के बिना बैंकों के सिस्टम संसाधनों का संरक्षण करेगा।

7. निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा में वृद्धि

रिजर्व बैंक वित्तीय बाजारों में खुदरा ग्राहकों की अधिक भागीदारी को सुगम बनाने के प्रयास कर रहा है, जैसे, खुदरा प्रत्यक्ष योजना के हालिया लॉन्च के माध्यम से जी-सेक खंड में निवेश, जहां यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग जैसे अन्य विकल्पों के अलावा, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में भाग लेने के लिए भुगतान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। समय के साथ, यूपीआई भी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (आईपीओ) के लिए 01 जनवरी 2019⁴ से इसकी उपलब्धता के बाद से एक लोकप्रिय भुगतान विकल्प बन गया है। यह रिपोर्ट किया गया है कि ₹2 से ₹5 लाख के आईपीओ आवेदन, सदस्यता आवेदनों का लगभग 10 प्रतिशत है। यूपीआई प्रणाली में लेनदेन की सीमा मार्च 2020 में ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹2 लाख कर दी गई थी। खुदरा निवेशकों द्वारा यूपीआई के उपयोग को और प्रोत्साहित करने के लिए, खुदरा प्रत्यक्ष योजना और आईपीओ आवेदनों के लिए यूपीआई के माध्यम से भुगतान हेतु लेनदेन की सीमा को ₹2 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख करने का प्रस्ताव है। एनपीसीआई को जल्द ही अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे।

¹ https://traai.gov.in/sites/default/files/PR_No.45of2021_0.pdf

² <https://www.statista.com/statistics/467163/forecast-of-smartphone-users-in-india/>

³ <https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/content/docs/PSDDP04062020.xlsx>

⁴ https://www.sebi.gov.in/sebi_data/commondocs/mar-2019/useofunifiedpaymentinterfacefaq_p.pdf

भाषण

आर्थिक बहाली का स्वरूप
शक्तिकांत दास

ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास
माइकल देब्रत पात्र

आर्थिक बहाली का स्वरूप*

शक्तिकांत दास

मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग एंड इकॉनामिक्स कॉन्क्लेव में एक बार फिर आकर खुशी हो रही है। इस गरिमापूर्ण सभा को संबोधित करने हेतु मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं एसबीआई के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ। इस वर्ष के कॉन्क्लेव का विषय 'कोविडोत्तर विश्व में आर्थिक बहाली का परिदृश्य' समसामयिक और प्रासंगिक-दोनों है। समसामयिक इसलिए कि इतनी जटिलता और परेशानियों का सामना करने के पश्चात, संभव है कि हम कोविडोत्तर विश्व के द्वार पर दस्तक दे रहे हों। प्रासंगिक इसलिए क्योंकि इतने व्यापक पैमाने का संकट न केवल अर्थव्यवस्था को बल्कि आर्थिक बहाली के स्वरूप को भी पुनः आकार प्रदान करेगा। उम्मीद है, हमारे जीवनकाल में और यहाँ तक कि भविष्य की पीढ़ियों में भी, हम कोविड-19 से ज्यादा बड़े संकट का सामना नहीं करेंगे। इसलिए, किसी संकट से कुछ सीखने का मौका नहीं गँवाने वाली भावना से, हमें महामारी के अनुभवों से सीखते हुए, ज्यादा सुदृढ़ और ज्यादा अघात-सह अर्थव्यवस्था बनानी है। आज मैं अपने संबोधन में कॉन्क्लेव के विषय पर चर्चा करूँगा।

वैश्विक अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा पिछले दो वर्षों से कोविड-19 का बंधक बना हुआ है। विषाणु की गिरफ्त से मानवता और इसके साथ-साथ अर्थव्यवस्थाओं को भी बचाने के लिए, वैक्सीन तक तीव्रतर और समानतापूर्ण पहुँच ही एकमात्र आशा रही है। इस मोर्चे पर भारत की उल्लेखनीय उपलब्धि हमारी वैज्ञानिक क्षमताओं और प्रौद्योगिकी से चालित सार्वजनिक सेवा का एक उज्ज्वल उदाहरण है। इतने बड़े पैमाने पर टीका उत्पादन करते हुए, जो पूरे विश्व में सबसे अधिक है, भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे है। यह उन सबों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का क्षण है, जिन्होंने इसे संभव कर दिखाया है। बेहतर टीकाकरण और घटते संक्रमण से अस्पतालों में भर्ती और मृत्यु जैसे स्वास्थ्य संबंधी चरम परिणामों में काफी कमी आई है। इससे उपभोक्ता आत्मविश्वास को बल मिला है। त्योहारी उमंग और दमित माँग से भी अतिरिक्त बल मिलने से, कई

* 16 नवंबर, 2021 को 8वें एसबीआई बैंकिंग एंड इकॉनामिक्स कॉन्क्लेव, मुंबई में दिया गया उद्घाटन भाषण

उच्च-बारंबारता संकेतक यह इंगित कर रहे हैं कि आर्थिक बहाली कायम हो रही है।

ए. सतत संवृद्धि की तलाश

यद्यपि यह देखना सुखद है कि विनाशकारी दूसरी लहर के बाद, अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर धीरे-धीरे दुबारा खड़ी हो रही है, तथापि आर्थिक बहाली असमान तरीके से आगे बढ़ी रही है। संपर्क-गहन सेवाएं, हालिया समय में तेज सुधार के बावजूद, अब भी अपनी खोई हुई क्षमता वापस हासिल नहीं कर पाई हैं। 2021-22 की पहली तिमाही की जीडीपी के आंकड़ों से पता चलता है कि 2019-20 के कोविड-पूर्व स्तरों की तुलना में, निजी उपभोग और निवेश, दोनों में अब भी उल्लेखनीय अंतर बना हुआ है। इसलिए, हालांकि अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ रही है, इसे व्यापक आधार वाली और गहरी होने से पहले, अभी बहुत अधिक जमीन नापनी है। यह निरंतर प्रोत्साहन की आवश्यकता की ओर इंगित करता है ताकि संवृद्धि महामारी-पूर्व रुझान तक लौट आए या इससे आगे बढ़ पाए।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि महामारी-पश्चात परिदृश्य में भारत के पास पर्याप्त ऊंची गति से संवृद्धि हासिल करने की क्षमता है। कई कारक भारत के पक्ष में खड़े हैं। पहला, उभरती बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत के पास सकारात्मक जनसांख्यिकी, बेहतर होते कौशल आधार और मजबूत घरेलू माँग के बूते बाकी दुनिया के समकक्ष खड़ा होने की उल्लेखनीय क्षमता है। दूसरा, सरकार उत्पादन बढ़ाने, आपूर्ति बाधाओं को दूर करने और कारोबारी माहौल को बेहतर बनाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए अन्य संस्थागत बदलावों के अलावा, खासकर पूँजीगत व्यय और अवसंरचना, विनिर्माण और दूरसंचार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के माध्यम से सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है। तीसरा, महामारी ने डिजिटल और हरित प्रौद्योगिकी में विकास के नए अवसर खोल दिये हैं। साथ ही, वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं के रिसेट होने से भी नए अवसर खुले हैं क्योंकि यह भारत के हक में लाभदायक हो सकता है। चौथा, हाल के महीनों में निर्यात एक चमकदार बिन्दु रहा है और वैश्विक आर्थिक बहाली से इसे और फायदा हो सकता है। ऐसी सक्षमकारी स्थितियों और समर्थक नीतियों की मौजूदगी से, मुझे कोई संदेह नहीं है कि महामारी से उबरते हुए, हमारे पास अपनी संवृद्धि को

तीव्र करने का विशिष्ट अवसर है। इन मुद्दों में से कुछेक मुद्दों पर में और विस्तार से बात करना चाहता हूँ।

निजी उपभोग – संवृद्धि की रीढ़

समग्र माँग के सबसे बड़े हिस्से (जीडीपी का लगभग 56 प्रतिशत) का योगदान करते हुए, निजी माँग हमारे देश की समावेशी, स्थायी और संतुलित संवृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। महामारी के दौरान समाज के निचले स्तरों पर रहने वाले दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों ने आय और रोजगार में बहुत अधिक नुकसान झेला है और इसकी भरपाई होने में समय लगेगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि 70 प्रतिशत से भी कम उभरती अर्थव्यवस्थाएँ 2022 के अंत तक भी 2019 के रोजगार-स्तरों को हासिल कर पाने में सक्षम हो पाएँगी। भारत में, मनरेगा¹ के अंतर्गत काम की माँग कोविड-पूर्व स्तर से करीब 10 मिलियन अधिक है, जो यह बताता है कि अनौपचारिक क्षेत्र में बहाली को अभी काफी दूरी तय करनी होगी। अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए, खासकर अवसंरचना क्षेत्र में ठेके का न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित करने और इनको परियोजनाओं की अवधि से जोड़ देने से संभवतः रोजगार निश्चितता और उपभोग बढ़ेगा। छोटे कारोबारों पर भी भारी चोट पड़ी है और इससे उबरने तथा रोजगार की पूरी क्षमता हासिल करने के लिए उन्हें सहायता की आवश्यकता होगी।

ऐसे संकेत हैं कि त्योहारी मौसम से उत्प्रेरित होकर उपभोग माँग जोरदार वापसी कर रही है। इससे फर्मों को अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों के बीच क्षमता में विस्तार करने और रोजगार तथा निवेश को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल के सीमा शुल्क में और कई राज्य सरकारों द्वारा मूल्य-वर्धित कर (वैट) में की गई हालिया कटौती से लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ेगी, जो फिर अतिरिक्त उपभोग के लिए गुंजाइश पैदा करेगी। क्या हम अनुक्रिया के एक सुचक्र के मुहाने पर खड़े हैं जहाँ मांगों के उच्चतर संवेग और अनुकूल आपूर्ति कार्रवाई एक साथ कदमताल करते हुए आगे बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था की सतत संवृद्धि को सुनिश्चित करेंगे? इस मोर्चे पर आशान्वित बने रहने के कारण हैं।

निवेश को पुनर्जीवित करना

भारत की संवृद्धि की संभावना को फलीभूत करने के लिए निजी निवेश को पुनर्जीवित करना आवश्यक है। निवेश को

बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय किए गए हैं। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती, कर-सुधार, 13 प्रमुख क्षेत्रों के लिए कार्यनिष्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना, सरकार द्वारा अवसंरचना विकास और आसित मौद्रिकरण पर बढ़ा हुआ फोकस, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा पहल और आरबीआई द्वारा अग्रसक्रिय चलनिधि उपाय शामिल हैं। उत्साहजनक यह है कि हालिया अवधि में निवेश गतिविधियों में प्रगति देखी गई है। पूँजीगत वस्तुओं के उत्पादन और आयात जैसे अग्रणी निवेश संकेतक सितंबर, 2021 में महामारी-पूर्व स्तर से ऊपर रहे हैं। 2021-22 की दूसरी तिमाही के लिए फर्मों के शुरुआती परिणाम, निविष्टि लागत दबावों के बावजूद मजबूत बिक्री और आघात-सह लाभप्रदता दर्शाते हैं। ऐसे रुझान आने वाली तिमाहियों में कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा क्षमता-विस्तार को बल प्रदान कर सकते हैं।

महामारी ने उत्पादन, प्रबंधन और अभिशासन की प्रणालियों में दूरगामी परिवर्तनों को उत्प्रेरित किया है। इस संकट ने रेखांकित किया है कि प्रौद्योगिकी काफी हद तक संसाधन के अंतर को पाट सकती है और यह समावेशी विकास का प्रमुख सक्षमकारक है। उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्वसंचालित वाहन, 3-डी प्रिंटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, ऊर्जा भंडारण और पदार्थ विज्ञान में विकास ने हमारे दैनिक जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है। भविष्य डेटा-संचालित स्मार्ट विनिर्माण का है और व्यवसायों को जल्द से जल्द सही निवेश करने के लिए कसरत की जरूरत है। ज्ञान और कौशल उन्नयन में निवेश विनिर्माण क्षेत्र की कायापलट करनेवाली कुंजी है। औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए उद्योग और शिक्षा प्रणाली के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता है। कुल मिलाकर भौतिक और मानव पूँजी में निवेश का सही मिश्रण सतत विकास के युग की शुरुआत कर सकता है।

अगली पीढ़ी के फर्मों, या स्टार्ट-अप्स के प्रवेश से निवेशगत संभावना को बल मिलता है। भारत स्टार्ट-अप परिदृश्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों में से एक देश के रूप में उभरा है जो नवोन्मेष और गतिशील उद्यमिता की अपार संभावना को प्रतिबिंबित करता

¹ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005

है। टेक स्टार्ट-अप में होने वाले निवेश का एक बड़ा हिस्सा महामारी के बाद खानपान की चीजों की डिलीवरी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों में इंटरनेट-आधारित सेवाओं की माँग में अचानक तेजी के कारण हुआ है। एंजल टैक्स में छूट देकर स्टार्ट-अप विकास पर नीतिगत जोर और बेहतर अभिशासन उपायों से भी इस क्षेत्र को समर्थन प्राप्त हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय अनुभव बताता है कि यदि दुर्लभ अर्थव्यवस्था के गतिशील क्षेत्रों के लिए संसाधनों का पुनः आबंटन किया जाए तो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में उल्लेखनीय सुधार हो सकता है। हालांकि, भारत में कुल रोजगार का लगभग 56 प्रतिशत हिस्सा कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है फिर भी सकल घरेलू उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी लगभग 25 प्रतिशत है। इस प्रकार कार्यबल का एक बड़ा तबका कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में फंस गया है जो हमारी विकास क्षमता को बाधित कर रहा है।

साथ ही, मजबूत बैलेंस शीट के साथ संगठित कॉर्पोरेट क्षेत्र उभरते क्षेत्रों में नया निवेश करने के लिए सुव्यवस्थित रूप से तैयार है। जैसे-जैसे माँग की बहाली होगी, मुझे आशा है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र निवेश चक्र को प्रारम्भ करने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा जो उत्पादक निवेश के लिए अधिशेष चलनिधि समावेश करने की सुविधा प्रदान करेगा।

इस पृष्ठभूमि में विकास के अवसरों का उपयोग करने के लिए उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने तथा संसाधनों के पुनर्वितरण करने की जिम्मेदारी एक प्रतिस्पर्धी एवं दक्ष वित्तीय प्रणाली की है।

सार्वजनिक व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका

कोविड -19 महामारी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, नवोन्मेष और डिजिटलीकरण सहित भौतिक और सामाजिक अवसंरचना पर खर्च करने की आवश्यकता को सुदृढ़ किया है जो न केवल कल्याण-संवर्धक है बल्कि विकास-उत्प्रेरक भी हैं। इसके अलावा, अच्छी गुणवत्ता वाले सार्वजनिक व्यय से निजी निवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है और आपूर्ति की कठिन समस्याओं का निदान होता है। यह मुद्रास्फीति दबाव को भी कम कर सकता है।

विकास और कल्याण संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हम सार्वजनिक खर्च को और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं? सर्वप्रथम, एक मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सार्वजनिक खर्च के विकास संवर्धक तत्वों को निश्चित रूप से संरक्षित और विकसित करना चाहिए। यदि हम सरकारी व्यय की गुणवत्ता के लिए कुछ मापनीय मानदंड विकसित करते हैं तो पूँजीगत व्यय पर नीतिगत जोर देते हुए निवेशोन्मुखी बहाली की दिशा में मौजूदा अभियान को और प्रोत्साहन मिल सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पथ के साथ गुणवत्ता लक्ष्यों को औपचारिक रूप से जोड़ने पर राजकोषीय नीति अधिक कुशल, प्रभावी और मानवोचित होगी। इस प्रकार के दृष्टिकोण से गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक वस्तुओं का स्थायी रूप से सुनिश्चित प्रावधान करने की एक चक्रीयतापक्षी प्रवृत्ति को समाहित किया जा सकता है। दूसरे, राज्यों में खर्च करने के व्यवहार में महत्वपूर्ण भिन्नता देखी गई है, जिसमें से कुछ राजकोषीय रूप से विवेकपूर्ण राज्य, अपने कम ऋण-जीएसडीपी अनुपातों के बावजूद और संरचनागत अंतर के बावजूद, अपनी पूरी संभावित क्षमता तक खर्च करने में संकोच करते देखे गए। राजकोषीय रूप से सुदृढ़ राज्य, वास्तव में सार्वजनिक आधारभूत ढांचे के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यय अभियान में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। यह न केवल उनकी अपनी संभाव्य विकास संभावनाओं को बढ़ावा देगा बल्कि अन्य राज्यों में सकारात्मक प्रसार के साथ अखिल भारतीय निवेश चक्र को भी आरंभ कर सकता है। तीसरा, मौजूदा योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करके और वास्तविक परिणामों के आधार पर उन योजनाओं को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करके या युक्तिसंगत बनाकर भी सीमित संसाधनों का अधिक कुशल आबंटन किया जा सकता है। आरंभ की गई किसी भी नई योजना की एक समापन तिथि निर्धारित होनी चाहिए, जो उसके परिणामों से सम्बद्ध हो।

निर्यात को बढ़ावा

इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पादों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, रसायन और कृषि उत्पादों जैसे भारतीय उत्पादों की मजबूत बाहरी माँग से प्रेरित होकर, भारत 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वार्षिक निर्यात का कीर्तिमान हासिल करने के लिए तैयार है। शीर्ष दस निर्यात भागीदार देशों में से पिछले

वर्ष की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-अगस्त 2021 के दौरान आठ देशों में भारत की हिस्सेदारी बढ़ी है। इसके बावजूद कई उभरते क्षेत्रों में निर्यात के महत्वपूर्ण अवसर बने हुए हैं। सबसे पहले, भारत को कृषि क्षेत्र का स्वाभाविक सहज लाभ प्राप्त है। पारंपरिक निर्यात वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी और कपास के अलावा, कृषि निर्यात को नए क्षेत्रों में वैविध्यपूर्ण बनाया जा सकता है ताकि उपभोक्ताओं को बदलती प्राथमिकताओं और पर्यावरण संबंधी चिंताओं से भी लाभ उठाया जा सके। दूसरा, जलवायु परिवर्तन की चिंताओं ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र को इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर केंद्रित कर दिया है। ईवी की बिक्री तेज गति से बढ़ रही है। इससे लिथियम और कोबाल्ट जैसी धातुओं की माँग बढ़ गई है जिनका उपयोग बैटरी में किया जाता है जो उनके भंडार से कहीं अधिक है। इसलिए, न केवल पर्याप्त घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बल्कि इस क्षेत्र में विशाल निर्यात क्षमता का लाभ उठाने के लिए, विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से नई सामग्रियों के साथ ईवी बैटरी के पुनर्चक्रण और उत्पादन हेतु एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र निर्मित करने का रणनीतिक महत्व है। तीसरा, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्रों में प्रक्षेपण वाहनों, उपग्रहों के लागत प्रभावी प्रक्षेपण, एयरोस्पेस और रक्षा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए महत्वपूर्ण निर्यात अवसर मौजूद हैं जहाँ सार्वजनिक-निजी भागीदारी से भरपूर लाभ मिल सकता है।

वित्तीय क्षेत्र की भूमिका

आधुनिक समाज में संवृद्धि और विकास की इमारत एक जीवंत, आघात-सहनीय और सुसंचालित वित्तीय क्षेत्र की नींव पर बनी है। चूंकि अब हम महामारी से उबर रहे हैं, मैं वित्तीय क्षेत्र के सामर्थ्य और चुनौतियों पर प्रकाश डालूंगा।

भविष्य के लिए प्रतिरोधकों (बफर्स) का निर्माण

बैंक कोविड-19 के आघातों से उम्मीद से बेहतर तरीके से उबरे हैं। शुरुआती रुझानों के अनुसार, एससीबी के जीएनपीए और पूँजी पर्याप्तता अनुपात में जून 2021 के मुकाबले सितंबर 2021 में और सुधार हुआ है। बैंक पूँजी जुटाने में भी विवेकपूर्ण रहे हैं। कई बैंकों के लाभप्रदता मैट्रिक्स भी कई सालों के उच्चतम स्तर पर हैं। आंकड़ों में यह सुधार आंशिक रूप से कोविड-19 के दौरान बैंकों को प्रदान की गई विनियामकीय राहत के साथ-साथ, सरकार द्वारा दी गई राजकोषीय गारंटी और वित्तीय सहायता को दर्शाते हैं। आने वाले समय में ऐसे जोखिम और चुनौतियाँ हैं जिन

पर बैंकिंग प्रणाली को गंभीर आत्मनिरीक्षण और कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

सर्वप्रथम, कोविड-19 प्रकरण ने आरबीआई द्वारा विनियमित वित्तीय संस्थाओं के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण और विनियामकीय मानदंडों के कुछ पहलुओं पर नए सिरे से विचार करने के लिए, एक असल ज़िंदगी का अनुभव प्रदान किया है। इस संकट से कुछ चिंताएँ फिर से उभरी हैं जिन पर हमें ध्यान देना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संकट के दौरान बैंकों की पूँजी और प्रावधानीकरण बफर, उनकी पर्याप्तता और परिणामी उपयोगिता का सवाल हमारे सामने है। इसलिए मैं बैंकों से आग्रह करता हूँ कि वे दूरदर्शी, वैज्ञानिक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के साथ अपनी पूँजी प्रबंधन प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करें तथा उन्हें और बेहतर बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण यह कि ऋण देने वाली संस्थाओं को चाहिए कि वे सतत जिम्मेदारी के रूप में हानि अवशोषण क्षमता की परिकल्पना करें। यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक विवेकपूर्ण जोखिम लेने वाले व्यवहार का प्रदर्शन करेंगे और अपनी पूँजी का कुशलतापूर्वक उपयोग करेंगे।

दूसरा, सुसंचालित, मजबूत और आघात-सहनीय वित्तीय संस्था के लिए सुशासन अत्यंत आवश्यक है। बैंकों को जनता से जमा राशि जुटाने का विशेषाधिकार प्राप्त है, जो उन पर अपने व्यवसाय को बहुत ही जिम्मेदार तरीके से संचालित करने का दायित्व भी डालता है। निदेशक मंडल उस विश्वास के संरक्षक होने की जिम्मेदारी निभाता है जो जमाकर्ताओं ने बैंक पर किया है। इसलिए, जमाकर्ताओं के प्रति बैंक की जिम्मेदारी को बैंक के शेयरधारकों के प्रति उसकी जिम्मेदारी से तौला जाना चाहिए। सुशासन सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक को बोर्ड की निगरानी भूमिका, इसकी संरचना, निदेशकों की कौशल प्रोफाइल, मजबूत जोखिम और अनुपालन संरचना और प्रक्रियाओं, अधिक पारदर्शिता और विभिन्न हितधारकों के हितों को संतुलित करने वाले एक मजबूत तंत्र से अत्यधिक उम्मीदें हैं। अतः व्यावसायिक प्राथमिकताओं के साथ-साथ, जिम्मेदार शासन और नैतिकता-युक्त कार्य की आवश्यकता है।

तीसरा, बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मात्र 'बाजार का अनुसरण' दृष्टिकोण द्वारा संचालित होने के बजाय, उनके व्यावसायिक मॉडल और व्यावसायिक रणनीतियाँ सचेत होकर बनाई गई हों जिस पर बोर्ड स्तर पर एक मजबूत रणनीतिक चर्चा

हुई हो। विकास के अपने प्रयास में, बैंकों को झुंड की मानसिकता से बचना चाहिए और अलग-अलग व्यावसायिक रणनीतियों की तलाश करनी चाहिए। आरबीआई में, हमने बैंकों के व्यावसायिक मॉडल और रणनीतियों पर करीब से नज़र डालना शुरू कर दिया है। कुछ बैंकों ने केवल अपने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए एक विषम प्राथमिकता के साथ उच्च जोखिम और उच्च रिटर्न व्यावसायिक रणनीति को अपनाया था। ऐसे में, विशेष रूप से प्रबंधन के प्रस्तावों को चुनौती देने में, बोर्ड की सक्रिय भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इससे निर्णय लेने में अधिक सावधानीपूर्ण और संतुलित दृष्टिकोण रखने की दिशा में सहायता मिलेगी।

चौथा, एक और बड़ी चुनौती कोविड-19 से प्रभावित दबावग्रस्त उधारकर्ताओं से निपटने की होगी। कोविड-19 की दो लहरों के दौरान, रिज़र्व बैंक ने उधारकर्ताओं और बैंकों को राहत प्रदान करने के लिए समाधान ढांचा 1.0 और 2.0 की घोषणा की। समाधान ढांचा 1.0 के तहत पुनर्संचित बड़े उधारकर्ता खातों के संबंध में समाधान 30 जून, 2021 तक लागू किया जाना था, तथापि उनके पास परिचालन मापदंडों को प्राप्त करने के लिए 30 सितंबर, 2022 तक का समय है। दूसरी ओर, व्यक्तियों, एमएसएमई और अन्य छोटे व्यवसायों के संबंध में 30 सितंबर, 2021 से पहले समाधान ढांचा 2.0 के तहत लागू किए गए प्रस्तावों को 31 दिसंबर, 2021 तक लागू किया जाना है। जैसे-जैसे प्रोत्साहनपरक उपायों को धीरे-धीरे कम किया जाता है, इनमें से पुनर्संचित कुछ खातों को आने वाली तिमाहियों में ऋण शोधन क्षमता से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विवेकसम्मत कार्रवाई में व्यावहारिक समाधान उपायों के लिए ऐसे गैर-अर्थक्षम फर्मों को तत्काल/ अग्रसक्रिय रूप से चिह्नित करना आवश्यक होगा।

पाँचवां, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वित्तीय सेवा उद्योग आज 'तकनीकी वर्चस्व' के बीच में है। वित्त के चल रहे डिजिटलीकरण ने कई मोर्चों पर सकारात्मक परिवर्तन पैदा किये हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि रिज़र्व बैंक फिनटेक के लिए विनियामकीय सैंडबॉक्स, सह-उधार मॉडल, एकाउंट एग्रीगेटर जैसे तंत्रों की परिकल्पना करके इस विविध विचार स्थल में नवाचार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही हम यह उम्मीद करेंगे कि उधार देने वाली संस्थाएं इन तंत्रों का लाभ उठाकर समग्र ग्राहक अनुभव, उत्पाद अनुकूलन, वैकल्पिक ऋण मूल्यांकन पद्धतियों का अंगीकरण, निगरानी उपायों इत्यादि को

उन्नत करेंगे। यहाँ सावधानी रखना उचित रहेगा: वैश्विक स्तर पर, 'फिजिटल' क्रांति ने बैंकों, एनबीएफसी और फिनटेक खिलाड़ियों जैसे इनक्यूबेशन, पूँजी निवेश, सह-निर्माण, वितरण और एकीकरण के बीच कई सहयोगी मॉडलों में भूमिका निभाई है। हालांकि उधारदाता इनमें से किसी भी मॉडल का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं, विनियामकीय अपेक्षा यह है कि अंतिम टाई-अप निर्णय, मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अधीन अपनी आंतरिक नीतियों के संदर्भ में अपने स्वयं की वाणिज्यिक बुद्धिमत्ता के अनुसार होना चाहिए। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आंकड़ों की सुरक्षा, आंकड़ों की गोपनीयता और शिकायतों के निवारण के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, आउटसोर्सिंग दिशानिर्देश, उचित व्यवहार संहिता आदि जैसे विनियमों के संदर्भ में अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। इसके अलावा, फिनटेक और बिगटेक संस्थाओं के साथ अनुबंधों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी सुनिश्चित किए जाने चाहिए। इसलिए, जैसा कि हम नवाचार की इस यात्रा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इस बात को मान लेना चाहिए कि जोखिम अंततः बैंकों और एनबीएफसी की बहियों में ही परिलक्षित होगा और इसलिए सहयोग की योजना उचित रणनीतिक योजना बना कर की जानी चाहिए।

छठा, उधारदाताओं को कभी भी अपने अस्तित्व के आधार यानी 'ग्राहक' से नज़र नहीं हटानी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत, और यहां तक कि पहले की लोकपाल योजनाओं के अंतर्गत, विनियमित संस्थाओं (बैंकों सहित) के पास 30 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को ही आरबीआई लोकपाल द्वारा निपटाया जाता है। ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए तीस दिन एक बहुत ही उचित अवधि है। मैं बैंकों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने शिकायत निवारण तंत्र को सुधारने/मजबूत करने के लिए विशेष ध्यान दें और आवश्यक उपाय करें तथा ग्राहकों के हित में यह देखें कि आरबीआई लोकपाल के पास शिकायतें कम से कम पहुंचें। बैंकों को ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार भी सुनिश्चित करना चाहिए तथा कर्मचारियों और प्रत्यक्ष बिक्री एजेंटों को उचित ढंग से संवेदनशील करते हुए, अनुचित बिक्री को टाला जाना चाहिए। ग्राहक को बेचा गया उत्पाद उसके लिए उपयुक्त और उसके जोखिम प्रोफ़ाइल के अनुकूल होना चाहिए।

निष्कर्ष

जैसा कि हम महामारी के बाद विकास पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था में सही स्थान एक मजबूत, स्थिर और लचीली वित्तीय प्रणाली पर निर्मित होगा। बैंक और एनबीएफसी हमारी अर्थव्यवस्था के पावर इंजन हैं, इस नाते परिवर्तनकारी यात्रा में तेजी लाने के लिए उन्हें निरंतर कार्यांतरण

से गुजरना होगा। मैं यहां उपस्थित वरिष्ठ बैंकरों को उनके संबंधित संस्थानों में इस पूरे परिवर्तन को उत्प्रेरित करने वाले परिवर्तन एजेंट के रूप में देखना चाहता हूँ।

आगामी फलदायी और सार्थक विचार-विमर्शों के लिए मेरी शुभकामनाएं!

धन्यवाद। स्वस्थ रहें। नमस्कार!

ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास*

माइकल देबब्रत पात्र

ब्रिक्स: ऐक्रनिम से लेकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति तक¹

प्रोफेसर पामी दुआ, निदेशक, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रो. योगेश सिंह, कुलपति, दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रो. संघमित्रा बंधोपाध्याय, निदेशक, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र, प्रो. चेतन घाटे, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, विशिष्ट आमंत्रित अतिथिगण और सम्मेलन प्रतिभागियों, मैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और भारतीय सांख्यिकी संस्थान, दिल्ली केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित 'ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास' विषय पर आयोजित इस सम्मेलन के उद्घाटन भाषण देने के लिए आमंत्रित किए जाने के लिए सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। भारत द्वारा वर्ष 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के मद्देनजर यह सम्मेलन सामयिक और प्रासंगिक है। सम्मेलन में चर्चा और प्रस्तुत किए जाने वाले हस्ताक्षरित पेपर निश्चित रूप से इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं ने महामारी के दौरान और महामारी के बाद के दिनों में अपनी प्रगति की रूपरेखा कैसे तैयार की है। मेरा संबोधन दो भागों में बंटा हुआ है, हालांकि मैं अंतर-संबंधों को बताने के लिए आगे-पीछे हो सकता हूँ। पहला भाग ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति और उनके समक्ष आने वाली तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के बारे में होगा। इसके बाद, ब्रिक्स की वर्तमान अध्यक्षता को देखते हुए भारत के सामने आने वाली चुनौतियों का अवलोकन किया जाएगा।

* दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), दिल्ली द्वारा 'ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में संवृद्धि और विकास' विषय पर आयोजित सम्मेलन में भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर माइकल देबब्रत पात्र द्वारा दिया गया मुख्य भाषण।

¹ दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (डीएसई) और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), दिल्ली ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी इनिशिएटिव के तत्वावधान में, 12 नवंबर 2021 को। महुआ रॉय, सितिकंठ पट्टनायक, स्मिता शर्मा, आशीष थॉमस जॉर्ज, हरेंद्र बेहरा, अजेश पी., सार्थक गुलाटी, कुणाल प्रियदर्शी और दुर्गेश पवार की बहुमूल्य टिप्पणियाँ, और विनीत कुमार श्रीवास्तव एवं समीर रंजन बेहरा के संपादकीय सहयोग के लिए आभारी हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स

संक्षिप्त नाम ब्रिक का पता 2001 में चला और व्यापक रूप से इसका श्रेय जिम ओ'नील को दिया गया, जो उस समय गोल्डमैन सैक्स एसेट मैनेजमेंट के अध्यक्ष थे, लेकिन जाहिर तौर पर इसकी उत्पत्ति के बारे में कुछ विवाद है। जो भी हो, ब्रिक यानी ब्राजील, रूस, भारत और चीन, की पहली औपचारिक बैठक, 2009 में येकातेरिनबर्ग, रूस में हुई थी जिसमें उनके नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया था। दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ और यह ब्रिक्स हो गया। एक साथ मिलकर, ब्रिक्स दुनिया की आबादी का 40 प्रतिशत से अधिक, वैश्विक जीडीपी का एक चौथाई, वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक चौथाई और विश्व व्यापार का पांचवां हिस्सा है। इसी संदर्भ में ब्रिक्स को एक उभरता हुआ वैश्विक महाशक्ति माना जा रहा है।

ब्रिक्स में व्यापक विविधता के साथ-साथ विशिष्ट समानताएं भी शामिल हैं। इनमें सबसे अधिक आबादी वाले देशों के साथ-साथ अपेक्षाकृत कम रहने वाले लोग शामिल हैं, विभिन्न जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ, विशेष रूप से जनसंख्या उम्र बढ़ने, जीवन प्रत्याशा और आश्रितों की हिस्सेदारी के मामले में। वे अपने वित्तीय विकास के मामले में भी काफी व्यापक रूप से भिन्न हैं, बैंक खातों के स्वामित्व वाले वयस्कों के अनुपात को वित्तीय समावेशन के उपाय के रूप में माना जाता है। ब्रिक्स में कई समान विशेषताएं भी हैं - विकास के मोटे तौर पर समान चरण; विकास रणनीति के रूप में स्थायी तरीके से संवृद्धि में तेजी लाना; समावेशिता और डिजिटलीकरण पर जोर; और जलवायु लचीलापन में निवेश करना। इन्हीं विशेषताओं के साथ ब्रिक्स पूरी दुनिया में मानव समाजों के विकास और समृद्धि में योगदान करने के लिए एक साथ आए हैं और इस तरह वैश्विक सामान्य भलाई के लिए काम करेंगे।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वैश्विक जीडीपी को वर्ष 2020 में 3.1 प्रतिशत की अभूतपूर्व गिरावट और वर्ष 2021 में 5.9 प्रतिशत तक विस्तार होने का पूर्वानुमान किया है। ब्रिक्स को वैश्विक सुधार का सबसे महत्वपूर्ण इंजन होने की उम्मीद है, जिसमें वर्ष 2021 में वैश्विक संवृद्धि का 42 प्रतिशत का योगदान है, जो अगले तीन संवृद्धि वाहकों (यूएस; यूरो क्षेत्र; यूके) की संयुक्त हिस्सेदारी से अधिक है। ब्रिक्स विश्व व्यापार में भी एक जबरदस्त

ताकत है, जिसकी मूल्य के आधार पर विश्व व्यापार और सेवाओं के व्यापार का लगभग 16 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इनमें कमोडिटी निर्यातक और आयातक दोनों शामिल हैं, जो विनिर्माण और सेवाओं की एक श्रृंखला में देश की विशेषज्ञता के साथ हैं। अंतर-ब्रिक्स व्यापार में मजबूती से विस्तार हो रहा है और इसने महामारी रोधी के एक स्तर का प्रदर्शन किया है - उदाहरण के लिए, ब्रिक्स भागीदारों के साथ भारत का व्यापार महामारी वित्तीय वर्ष 2020-21 (अप्रैल-मार्च) में बढ़कर 113.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो महामारी पूर्व वर्ष 2019-20 के 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। वर्ष 2021-22 में अब तक, सभी ब्रिक्स राष्ट्र मजबूत निर्यात प्रदर्शन कर रहे हैं।

ब्रिक्स राष्ट्र आर्थिक रूप से खुली अर्थव्यवस्थाएं हैं और पूंजी प्रवाह के लिए पसंदीदा जगह हैं। हाल के वर्षों में, उन्होंने अचानक बंद होने और पोर्टफोलियो प्रवाह के कारण उलटफेर का भी अनुभव किया है। इसके विपरीत, ये सभी अपेक्षाकृत स्थिर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के प्राप्तकर्ता भी हैं। वर्ष 2020 में, उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में पूंजी प्रवाह में कटौती हुई थी। ब्रिक्स में, केवल भारत और दक्षिण अफ्रीका निवल बहिर्वाह से बचे हुए थे। वर्ष 2021 में अब तक निवल पूंजी प्रवाह भारत और ब्राजील के पक्ष में बना रहा। वर्ष 2013 के टेंपर टैंट्रम के समय की स्थिति के विपरीत, ब्रिक्स बाहरी मोर्चे पर अच्छी तरह से मजबूत प्रतीत होता है। वर्तमान में, ब्रिक्स के पास वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार का 33 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें चीन, भारत और रूस दुनिया के शीर्ष दस आरक्षित निधि धारकों में शामिल हैं। संभावित आयात कवर द्वारा मापी गई आरक्षित पर्याप्तता 7 से 19 महीनों के बीच होती है। चीन और रूस आम तौर पर चालू खाता अधिशेष चलाते हैं, और इसलिए वित्तीय बाजारों का ध्यान आमतौर पर ब्रिक्स चालू खाता घाटे वाली अर्थव्यवस्थाओं - ब्राजील, भारत और दक्षिण अफ्रीका पर होता है। भारत अब तक वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में मामूली चालू खाता अधिशेष में चला गया है, लेकिन यह बढ़ती आयात मांग को देखते हुए नहीं रह सकता है।

बहुपक्षीय भूमिका में ब्रिक्स

ब्रिक्स बहुपक्षवाद के कट्टर समर्थक रहे हैं, आईएमएफ में कोटा और शासन सुधारों के लिए सर्वसम्मति से मतदान करते हैं

ताकि इसे वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं का अधिक प्रतिनिधि बनाया जा सके, विशेष रूप से ईएमई की बढ़ती प्रोफाइल जो देखते हुए। साथ में, उनके पास आईएमएफ के कोटा संसाधनों का 14.8 प्रतिशत है जो कुल एसडीआर 476.4 बिलियन और मतदान शक्ति का 14 प्रतिशत है। विश्व बैंक में, उन्होंने संस्था की पूंजी में अपना हिस्सा बढ़ाकर 14.1 प्रतिशत कर दिया है, जिसमें मतदान शक्ति में 13.4 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। एक प्रतिकूल और अस्थिर अंतरराष्ट्रीय वातावरण के बीच भविष्य के कोटा सुधार में गतिरोध का सामना करते हुए, ब्रिक्स ने अपने कोटा संसाधनों के पूरक के लिए आईएमएफ को लेनदार बना दिया है। आईएमएफ की उधार लेने की नई व्यवस्था (एनएबी) में ब्रिक्स का सामूहिक हिस्सा कुल एसडीआर 361 बिलियन का 16 प्रतिशत है। इसके अलावा, प्रत्येक ब्रिक्स राष्ट्र ने आईएमएफ के साथ द्विपक्षीय उधार व्यवस्था (बीबीए) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कुल एसडीआर 135 बिलियन के 17 प्रतिशत की हिस्सेदारी है। इसके अलावा, ब्रिक्स ने एक आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था या सीआरए के तहत 100 बिलियन अमरीकी डालर की स्वैप की व्यवस्था की है, जो आईएमएफ कोटा में उनके संयुक्त हिस्से से मेल खाता है और इसे ग्लोबल फाइनेंशियल सेफ्टी नेट (जीएफएसएन) के एक हिस्से के रूप में गिना जाता है।

ब्रिक्स महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ था, जिसमें संक्रमण की कई लहरें थीं, जो अब भी जान ले रही हैं। कुल संक्रमणों के मामले में, तीन ब्रिक्स, अर्थात्, भारत, ब्राजील और रूस दुनिया के शीर्ष पांच प्रभावित देशों में शामिल हैं। सात दिनों के रोलिंग औसत के संदर्भ में, रूस को छोड़कर सभी ब्रिक्स देशों में नए संक्रमणों में कमी आई है, जिसमें टीकाकरण अभियान के पैमाने और गति शामिल हैं। टीकाकरण के मामले में, हालांकि, चीन में तीन चौथाई आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया जा रहा है और दक्षिण अफ्रीका में केवल पांचवां हिस्सा है। पूर्ण टीकाकरण सभी ब्रिक्स देशों के लिए एक तात्कालिक चुनौती है। टीकों के प्रमुख निर्यातकों में चीन, रूस और भारत का प्रमुख स्थान है। भारत के मामले में, घरेलू संक्रमण बढ़ने पर टीके का निर्यात अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। जैसे ही संक्रमण कम हुआ, भारत ने अक्टूबर से टीकों का निर्यात फिर से शुरू कर दिया है, जिसमें क्वाड पहल भी शामिल है। वर्ष 2022 के अंत तक भारत-प्रशांत क्षेत्र के लिए टीकों की कम से कम 1 बिलियन खुराक का

उत्पादन करने की क्वाड पहल के तहत, भारत में अमेरिकी वित्तपोषण क्षमता विस्तार के साथ टीकों का उत्पादन किया जाएगा, जिसमें जापान भारत और ऑस्ट्रेलिया को रियायती ऋण प्रदान करेगा और अंतिम छोर तक डिलिवरी समर्थन देगा। क्वाड पहल के प्रति प्रतिबद्धता की दृढ़ता दर्शाते हुए, भारत ने अक्टूबर में 1 मिलियन खुराक की पहली खेप का 50 प्रतिशत वित्तपोषित किया।

समष्टि-आर्थिक विकास और नीतिगत प्रतिक्रियाएं

संक्रमण और टीकाकरण में अंतर के साथ-साथ मौद्रिक और राजकोषीय नीति समर्थन में अंतर के परिणामस्वरूप, ब्रिक्स को समष्टि-आर्थिक स्थितियों में भिन्नता का सामना करना पड़ रहा है। जहां चीन की रिकवरी तेज और मजबूत रही है, वहीं अन्य ब्रिक्स वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही के बाद से धनात्मक संवृद्धि क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। व्यापक अंतर मुद्रास्फीति के परिणामों की विशेषता बताता है। जहां ब्राजील और रूस - दोनों वस्तु निर्यातक - लक्ष्य और सहनशीलता के स्तर से बहुत अधिक मुद्रास्फीति दर का अनुभव कर रहे हैं, वहीं चीन ने उच्च उत्पादक मूल्य मुद्रास्फीति के बावजूद खुदरा मुद्रास्फीति को कम रखा है। दक्षिण अफ्रीका में मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा के भीतर है। भारत में, मुद्रास्फीति मई में ऊपरी सहनशीलता बैंड को पार कर गयी, लेकिन आयात और बफर स्टॉक के साथ-साथ उत्पादकता को प्रोत्साहित करने के उपायों के रूप में मजबूत आपूर्ति पक्ष उपायों के परिणाम मिले हैं, जिससे सितंबर और अक्टूबर 2021 में मुद्रास्फीति लक्ष्य के करीब आ गई है।

ब्रिक्स देशों में उनके मौद्रिक नीति ढांचे के संदर्भ में काफी समानता है। उनमें से चार ने मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण अपनाया है। संख्यात्मक लक्ष्य लगभग चार प्रतिशत हैं और उन सभी में रूस को छोड़कर सहिष्णुता बैंड हैं, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को चार प्रतिशत के करीब रखना है। दक्षिण अफ्रीका के पास एक बिंदु लक्ष्य नहीं है - यह 3 से 6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति लक्ष्य सीमा का अनुसरण करता है। चीन ने मुद्रास्फीति लक्ष्य को नहीं अपनाया है लेकिन मुद्रास्फीति को कम और स्थिर 3 प्रतिशत से नीचे रखता है। उन सभी ने बड़ी दर में कटौती और आरक्षित निधि आवश्यकता में कटौती के साथ महामारी से निपटा। अभी हाल ही में, ब्राजील और रूस ने नीतिगत समायोजन के सामान्यीकरण को पूरा कर

लिया है और ब्राजील रूढ़िवादी सख्ती में है। भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने उदार मौद्रिक नीति रुख बनाए रखा है।

ब्रिक्स के बीच एक और आम विशेषता बड़ी राजकोषीय प्रोत्साहन और अतिरिक्त खर्च और/या कर राजस्व को छोड़ देने के रूप में उनकी महामारी के संदर्भ में कार्रवाई रही है। परिणामस्वरूप, महामारी के कारण सकल राजकोषीय घाटा/जीडीपी अनुपात के संदर्भ में राजकोषीय स्थिति और खराब हो गई। महामारी से पहले रूस के पास राजकोषीय अधिशेष था और इसलिए उसके पास राजकोषीय गुंजाइश थी जिसका उपयोग महामारी के दौरान वित्तीय खातों पर कम से कम दबाव के साथ किया जा सकता था। तदनुसार, जीडीपी के 66 (चीन) - 99 (ब्राजील) प्रतिशत की सीमा में कर्ज-जीडीपी अनुपात के साथ राजकोषीय जोखिम तेजी से बढ़े हैं। जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, रूस एक अलग देश है, जिसका जीडीपी की तुलना में कर्ज अनुपात सकल घरेलू उत्पाद के 20 प्रतिशत से कम है।

ब्रिक्स के लिए मध्यम अवधि की चुनौतियां जलवायु जोखिमों और उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में उत्पन्न होती हैं, जो ऊर्जा की कमी, प्रौद्योगिकी अंतराल को जन्म दे सकती हैं और इस तरह, मध्यम अवधि की संवृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए जोखिम पैदा कर सकती हैं, खासकर बड़े कुल उत्सर्जन वाले देशों के लिए। भारत जैसे निवल आयातकों के लिए कमोडिटी की ऊंची कीमतों से एक और तत्काल चुनौती उत्पन्न होती है, हालांकि वे ब्राजील और रूस जैसे निवल निर्यातकों के लिए व्यापार की शर्तों (टीओटी) का लाभ प्रदान करते हैं। सभी ब्रिक्स देशों के लिए, प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के कारण मांग-आपूर्ति असंतुलन के कारण खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों में मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ गया है।

ब्रिक्स के भीतर, प्रति व्यक्ति आय का स्तर व्यापक रूप से भिन्न है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उत्कृष्टता केंद्र कैफरल (सीएफएआरएएल) में किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि प्रति व्यक्ति आय सभी तीन बाहरी रेटिंग एजेंसियों (एस एंड पी; मूडीज़; फिच) में क्रेडिट रेटिंग का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। सभी ब्रिक्स मध्यम-आय के फंदे की चपेट में हैं, जो एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें वे बढ़ती लागत और घटती प्रतिस्पर्धा के कारण उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था में संक्रमण करने में विफल

हो सकते हैं। मध्यम-आय वाली अर्थव्यवस्था को उच्च-आय वाली अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए निवेश और नवाचार दो प्रमुख तत्व हैं, और हमारी अर्थव्यवस्थाओं में उनमें से प्रत्येक को प्रभावित करने वाले समष्टि-आर्थिक कारकों को समझना आवश्यक है।

उपलब्धियां और सुपुर्दगी

वर्ष 2009-10 में ब्रिक्स के अस्तित्व में आने के बाद से, उनकी यात्रा महत्वपूर्ण पड़ावों से गुजरी है।

- **न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी)** ने वर्ष 2015 में काम करना शुरू किया और अपने सदस्य देशों में परिवहन, पानी और स्वच्छता, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामाजिक बुनियादी ढांचे और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में 30 बिलियन अमरीकी डालर के पोर्टफोलियो से जुड़ी लगभग 80 परियोजनाओं को मंजूरी दी। सितंबर 2021 से, एनडीबी नए सदस्यों (उरुग्वे; संयुक्त अरब अमीरात; बांग्लादेश) को मंजूरी दे रहा है। एनडीबी ने कोविड से संबंधित सहायता के लिए 10 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य रखा है, जिसमें से 7 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का संवितरण पहले ही किया जा चुका है।
- **आकस्मिक आरक्षित निधि व्यवस्था या सीआरए** भुगतान संतुलन संकट के दौरान अल्पकालिक स्वैप सहायता प्रदान करने के लिए कुल 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के साथ एक तंत्र है। स्वैप में 30 प्रतिशत का एक अलग हिस्सा होता है जिसे आपातकालीन चलनिधि सहायता और 70 प्रतिशत के एक जुड़े हिस्से के रूप में बढ़ाया जा सकता है, जो अनुरोध करने वाले वैसे देश पर आकस्मिक हैं जहां आईएमएफ कार्यक्रम चल रहा हो।
- **ब्रिक्स रणनीतिक आर्थिक साझेदारी वर्ष 2021-2025** व्यापार और निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था और संधारणीय विकास पर ध्यान देने के साथ सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक रोडमैप प्रदान करती है।
- **ब्रिक्स या ब्रिक्स सूचना सुरक्षा चैनल** वर्ष 2020 में रूस के राष्ट्रपति पद के दौरान शुरू की गई एक हालिया पहल है, जिसमें साइबर सुरक्षा और साइबर से संबंधित घटनाओं पर सूचना के आदान-प्रदान पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) और बुनियादी ढांचे संबंधी ब्रिक्स कार्यबल** बुनियादी ढांचे में सहयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक मंच स्थापित करने की एक और पहल है। वर्ष 2021 में, सामाजिक बुनियादी ढांचे (स्वास्थ्य, शिक्षा) पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **ब्रिक्स पेमेंट्स टास्क फोर्स (बीपीटीएफ)** सीमा पार से भुगतान के प्रस्ताव सहित भुगतान प्रणाली में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय बैंक की पहल है।
- **ब्रिक्स बिजनेस काउंसिल** को ब्रिक्स के व्यापारिक समुदायों के बीच व्यापार, व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए एक मंच के रूप में बनाया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि ब्रिक्स देशों की सरकारों और उनके बीच नियमित संवाद हो।
- **ब्रिक्स महिला व्यापार गठबंधन (डब्ल्यूबीए)** का उद्देश्य ब्रिक्स देशों में महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देना है।
- **ब्रिक्स अकादमिक फोरम (बीएएफ)** ब्रिक्स देशों के प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के बीच विचार-विमर्श और चर्चा के लिए एक मंच है, जो कई सामाजिक, पर्यावरणीय और शैक्षिक मुद्दों पर विचार और समाधान की कोशिश करता है।
- **ब्रिक्स थिंक टैंक काउंसिल (बीटीटीसी)** की शुरुआत वर्ष 2013 में ब्रिक्स देशों के अकादमिक समुदायों के बीच अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी।
- **ब्रिक्स ऊर्जा अनुसंधान सहयोग प्लेटफॉर्म** ऊर्जा आधारित संधारणीय विकास, उन्नत ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को साझा करने, शैक्षिक कार्यक्रमों पर

सहयोग के विस्तार, राष्ट्रीय ऊर्जा प्रणालियों के विकास संबंधी सांख्यिकीय डेटा और योजनाओं के आदान-प्रदान और ऊर्जा क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं और नियामक ढांचे की जानकारी को बढ़ावा देता है। मंच का उद्देश्य विभिन्न प्लेटफार्मों में ब्रिक्स ऊर्जा सहयोग में तालमेल बनाना भी है।

- **ब्रिक्स एनवायरनमेंटली साउंड टेक्नोलॉजी (बीईएसटी) प्लेटफॉर्म**, वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के संधारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम उपलब्ध प्रथाओं और पर्यावरण के अनुकूल ("हरित") प्रौद्योगिकियों से संबंधित अनुभव/सूचनाओं के संचय और आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है।
- **डिजिटल वित्तीय समावेशन संबंधी रिपोर्ट** डिजिटल प्रौद्योगिकी उपकरणों का लाभ उठाकर वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों में की गई पहलों, नवाचारों और सुधारों को एक साथ रखती है। रिपोर्ट में डिजिटल वित्तीय समावेशन पर जी-20 उच्च-स्तरीय नीति दिशानिर्देशों के मुकाबले इन प्रयासों का भी चित्रण किया गया है।

भारत की अध्यक्षता में, छह परियोजनाओं को पहले ही पूरा करने के लिए आगे बढ़ाया जा चुका है:

- **सूचना सुरक्षा विनियमनों पर ई-बुकलेट और सूचना सुरक्षा जोखिमों पर ब्रिक्स की सर्वोत्तम प्रथाओं का संग्रह** साइबर घटना प्रबंधन प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से ब्रिक्स अधिकार क्षेत्र में सूचना सुरक्षा नियमों और सर्वोत्तम प्रथाओं को कवर करता है।
- **सीआरए मूल्यांकन रिपोर्ट** में इस साल के सीआरए टेस्ट रन के साथ-साथ वर्ष 2018 के बाद से किए गए पिछले टेस्ट रन से उत्पन्न सभी मुद्दों और सिफारिशों को शामिल किया गया है।
- प्रथम **ब्रिक्स सहयोगात्मक अध्ययन 'कोविड-19: ब्रिक्स के भुगतान संतुलन के लिए प्रतिकूल और**

अनुकूल परिस्थितियां' में वैश्विक स्तर पर और ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में महामारी के कारण हुए गंभीर आर्थिक व्यवधानों पर प्रकाश डाला गया है, जिसके परिणामस्वरूप तेज चालू खाता समायोजन के साथ-साथ पूंजी प्रवाह में अस्थिरता हुई है।

- वर्ष 2021 के लिए **ब्रिक्स आर्थिक बुलेटिन** का विषय **'चल रही महामारी से निपटना: सुदृढ़ता और बहाली का ब्रिक्स अनुभव'** है। इसमें अलग-अलग आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति जोखिम, राजकोषीय दबाव, बाह्य क्षेत्र का प्रदर्शन और वित्तीय क्षेत्र की कमजोरियां शामिल हैं।
- वर्ष 2021 में, सीआरए के आईएमएफ से जुड़े हिस्से का परीक्षण पहली बार किया गया था। आईएमएफ के साथ सहयोग के तौर-तरीकों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- शेष वर्ष में डिलिवरेबल्स में, **ब्रिक्स बॉन्ड फंड (बीबीएफ)**, जो सदस्य देशों में स्थानीय बॉन्ड बाजारों को विकसित करने की दृष्टि से ब्रिक्स केंद्रीय बैंकों की एक संयुक्त पहल है, अब पूरा होने के करीब है।
- ब्रिक्स के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों (एफएमसीबीजी) ने अगस्त 2021 में **'वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण और कोविड-19 संकट पर प्रतिक्रिया संबंधी एक ब्रिक्स वक्तव्य'** अपनाया। वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रयास जारी रखने पर सहमति व्यक्त की। महामारी के बाद की दुनिया में संधारणीय, संतुलित और समावेशी आर्थिक विकास और महामारी के लिए घरेलू आर्थिक प्रतिक्रियाओं पर ब्रिक्स देशों द्वारा नीतिगत अनुभवों को साझा करने का स्वागत किया।
- **एमएसएमई गोलमेज 2021** ने एमएसएमई के विकास की दृष्टि से ब्रिक्स सहयोग को बढ़ाने में मदद की है, जिससे उन्हें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया जा सके।

- वर्ष 2021 में, सीमा शुल्क मामलों में सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर ब्रिक्स समझौते को अंतिम रूप दिया गया था।

अध्यक्ष के समक्ष चुनौतियां

अब मैं ब्रिक्स की अध्यक्षता के वर्ष में भारत के सामने आने वाली चुनौतियों की ओर आता हूँ।

जीडीपी वृद्धि व्यापक रूप से किसी देश की आर्थिक प्रगति के संकेतक के रूप में उपयोग की जाती है। यदि कोई पिछले 75 वर्षों में पीछे मुड़कर देखता है, तो बाई-पेरॉन संरचनात्मक विराम बिंदु परीक्षण से पता चलता है कि भारत की वृद्धि प्रक्षेपवक्र तीन चरणों से गुजरी है। 1970 के दशक के अंत तक, भारत ने 3.5 प्रतिशत की जीडीपी वृद्धि की औसत प्रवृत्ति - तथाकथित हिंदू वृद्धि दर - जो उस अवधि में अपनाई गई आवक-दिखने वाली नीतियों से जुड़ी रही है। उदारीकरण और खुलेपन के रूप में वर्ष 1980-2002 के दौरान रुझान वृद्धि 5.5 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसके बाद, वर्ष 2003-20 की अवधि में महामारी के आने तक जीडीपी की वृद्धि औसतन 7 प्रतिशत के करीब पहुंच गई। वर्ष 2020-21 में, जीडीपी में 7.3 प्रतिशत की गिरावट आई, जो उस वर्ष दुनिया भर में सबसे गहरे संकुचनों में से एक था।

भारत में संवृद्धि के वाहक क्या हैं? यह पता चला है कि भारत की वृद्धि हाउसहोल्ड्स - निजी उपभोग व्यय के कारण हुई है - हालांकि जीडीपी में इसकी हीसेदारी 1960 के दशक में 75 प्रतिशत से कम होकर हाल के वर्षों में लगभग 55 प्रतिशत हो गयी है। निर्यात-आधारित और निवेश-आधारित संवृद्धि के चरण ऐसे रहे हैं, जिन्हें कायम नहीं रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने वृद्धि पथ में महत्वपूर्ण मोड़ प्रदान किए।

भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा इतनी मेहनत से बनाए गए क्लेम्स² (केएलईएमएस) डेटाबेस से पता चलता है कि भारत की संवृद्धि में पूंजी संचय सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, जो लगभग 60 प्रतिशत है। इसलिए, निवेश दर (कुल निवेश/जीडीपी) को भारत में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण उत्तोलक माना जाता है। एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि हमारी

वृद्धि धरेलू है - निवेश को मुख्य रूप से धरेलू बचत द्वारा वित्तपोषित किया जाता है, जिसमें विदेशों से पूंजी प्रवाह केवल एक पूरक भूमिका निभाता है। एक और उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद बचत दर धीमी होने लगी है। आखिरकार, इसने वर्ष 2012-13 से निवेश दर को नीचे ला दिया। उच्च वृद्धि हासिल करने के लिए इस प्रवृत्ति को उलटना महत्वपूर्ण है।

बीओपी (एक्स-एम) में चालू खाता घाटा (सीएडी) यह निर्धारित करता है कि देश में कितने निवल पूंजी प्रवाह को अवशोषित किया जा सकता है या संवृद्धि के लिए उपयोग किया जा सकता है। हमारा अनुभव रहा है कि भारत बाह्य क्षेत्र के संकट में पड़े बिना 2.5-3.0 प्रतिशत के चालू खाते के घाटे को बनाए रख सकता है। वास्तव में, इस तथ्य की एक याद दिलाने में, सोने के आयात में रिकॉर्ड वृद्धि ने वर्ष 2011-13 के दौरान इस प्लिमसोल लाइन से ऊपर चालू खाता घाटा ऐतिहासिक रूप से उच्च स्तर पर चला गया। भारत को टेपर टैट्रम का सामना करना पड़ा और उसे नाजुक पांच³ में से एक के रूप में लेबल किया गया।

2000 के दशक में लगभग 20 प्रतिशत की प्रभावशाली औसत निर्यात वृद्धि के बाद, जो व्यापार और वित्त के लिए अर्थव्यवस्था के खुलेपन में वृद्धि और जीडीपी की रुझान वृद्धि में उछल के साथ मेल खाता था, निर्यात वृद्धि वर्ष 2015 के बाद से गिर गई। बढ़ते व्यापार संरक्षणवाद ने अपना असर डाला, और यह अवधि जीडीपी वृद्धि दर में गिरावट के साथ भी जुड़ी हुई है। वर्ष 2021 में विश्व व्यापार में अब तक की मजबूत रिकवरी ने अपने साथ निर्यात के बारे में एक नए सिरे से आशावाद की भावना को फिर से संवृद्धि के इंजन के रूप में काम किया है। भारत का निर्यात वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित 400 बिलियन अमरीकी डॉलर के वार्षिक लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में, वास्तविक निर्यात स्तर पहले से ही लक्ष्य का आधा था। उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना जैसे उपायों से निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।⁴ व्यापार के खुलेपन के

³ ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की।

⁴ धरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और आयात बिलों में कटौती करने के लिए, केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में एक पीएलआई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य धरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों से वृद्धिशील बिक्री पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।

² केएलईएमएस से आशय पूंजी, श्रम, ऊर्जा, सामग्री और सेवाओं से है। यह ग्रोथ अकाउंटिंग फ्रेमवर्क पर आधारित है।

अनुरूप वित्तीय खुलेपन में भी सुधार हो रहा है - भारत ने वैश्विक प्रवृत्ति को पीछे छोड़ दिया और वर्ष 2020-21 में 82 बिलियन अमरीकी डॉलर के उच्चतम आवक एफडीआई दर्ज किया।

भारत में बैंक के नेतृत्व वाली वित्तपोषण प्रणाली है और इसलिए, बैंक ऋण वृद्धि संवृद्धि के लिए वित्तपोषण चुनौतियों का एक बेहतर संकेतक है। हाल के वर्षों में - 2017 के बाद से - बैंक ऋण में मंदी आई है, विशेष रूप से उद्योग के लिए। यह काफी हद तक अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के एक बड़े ओवरहैंग के कारण बैंकों के तुलन-पत्र में तनाव के कारण है, जो 2000 के दशक के मध्य में ऋण उछल के कारण हुआ था। वैश्विक अति-क्षमता और अर्थव्यवस्था की मंदी के कारण निवेश चक्र में बदलाव आया, परियोजना में देरी हुई और लागत में वृद्धि हुई। बैंक चूक में वृद्धि हुई, और दबावग्रस्त बैंक नए ऋण जोखिम लेने के लिए अनिच्छुक हो गए। इसके अलावा, जीएफसी के बाद में, बैंकों को आस्तियों के पुनर्गठन और उन्हें 'मानक' अग्रिम के रूप में मानने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अतिरिक्त प्रावधानों के साथ। अप्रैल 2015 से अग्रिमों की पुनर्चना पर विनियामकीय सहनशीलता को वापस लेने और बाद में आर्स्टि गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) के कारण सकल एनपीए (जीएनपीए) की अधिक यथार्थवादी पहचान हुई। मार्च 2018 में 11.5 प्रतिशत के शिखर पर पहुंचने के बाद जीएनपीए अनुपात में गिरावट आई है, जिसका मुख्य कारण दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया के तहत दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान और दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए रिजर्व बैंक के संशोधित ढांचा है। कोविड-19 की शुरुआत से पहले, भारत में जीएनपीए अनुपात मार्च 2020 के अंत में 8.3 प्रतिशत था। यह मार्च 2021 के अंत तक 7.5 प्रतिशत तक गिर गया, जो यह दर्शाता है कि बैंकों ने महामारी की अवधि का उपयोग वसूली में सुधार के लिए किया था और अपनी तुलन-पत्र में उच्च प्रावधान करते हुए अचूक ऋणों को बट्टे खाते में डाला। बैंकों के जोखिम से बचने की स्थिति में, गैर-बैंकिंग स्रोत (घरेलू और विदेशी दोनों) हाल के वर्षों में भारत के वाणिज्यिक क्षेत्र में संसाधनों के प्रवाह में उतना ही या उससे भी अधिक योगदान दे रहे हैं।

आपूर्ति में व्यवधान, स्वास्थ्य संकट, अद्वितीय सामूहिक प्रवास और प्रतिकूल वैश्विक वातावरण के कारण उत्पादन का काफी नुकसान हुआ है - जो एक सामान्य वर्ष के वार्षिक जीडीपी के दसवें हिस्से से अधिक है। वर्ष 2021-22 में (भारतीय रिजर्व

बैंक के अनुमानों के अनुसार) 9.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, भारत की जीडीपी वर्ष 2019-20 में अपने स्तर से ऊपर होगी। इस खोए हुए उत्पादन को पुनर्प्राप्त करने में कई साल लग सकते हैं - इसे मैं दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चुनौती मानूंगा। इससे पहले मैंने ब्रिक्स के संदर्भ में कहा था कि पूरी आबादी का त्वरित टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है।

श्रम ब्यूरो के अप्रैल 2021 के तिमाही रोजगार सर्वेक्षण (क्यूईएस) में 9 क्षेत्रों और 85 प्रतिशत संगठित क्षेत्र के रोजगार को शामिल किया गया है, जो यह दर्शाता है कि 21 मार्च 2020 और 1 जुलाई 2020 के बीच, यानी लॉकडाउन अवधि में, सभी क्षेत्रों में कर्मचारियों की संख्या में गिरावट का सामना करना पड़ा। स्वास्थ्य और वित्तीय क्षेत्रों को छोड़कर, केवल 34 प्रतिशत इकाइयाँ 25 मार्च 2020 से 30 जून 2020 के दौरान कार्य कर सकीं। वेतन हानि के संबंध में, संगठित क्षेत्र पर प्रभाव नरम था क्योंकि 80.7 प्रतिशत कर्मचारियों को पूर्ण वेतन मिला और केवल 2.7 प्रतिशत बिना वेतन के चले गए। लोगों को काम पर वापस लाना, बदलते परिवेश का सामना करने के लिए उन्हें फिर से कुशल बनाना और उनकी उत्पादकता को बढ़ाना तीसरी चुनौती है। 132 देशों में से भारत श्रम उत्पादकता के मामले में 100वें स्थान पर है।

भारत की 1.38 अरब की आबादी 28.4 वर्ष में दुनिया की सबसे युवा आबादी है, लेकिन उम्र बढ़ने से 2045 तक जनसांख्यिकीय लाभांश खत्म हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या संभावनाओं के अनुसार, वर्ष 2027 तक, भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश (1.47 बिलियन) होगा। जनसंख्या की इस संरचना को आयु निर्भरता अनुपात द्वारा बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है - कुल कामकाजी-आयु की आबादी के अनुपात में आश्रित जनसंख्या (0-14 वर्ष और 65+ वर्ष) का अनुपात: अनुपात के कम मान का अर्थ अधिक उत्पादक आबादी से है। भारत का आयु निर्भरता अनुपात घट रहा है और वर्ष 2025 तक इसमें और गिरावट आने की संभावना है जिसके बाद यह वर्ष 2040 तक स्थिर रह सकता है और उसके बाद बढ़ सकता है। कुल जनसंख्या या डबल्यूएपी अनुपात के अनुपात के रूप में भारत की कामकाजी उम्र की आबादी की तुलना से पता चलता है कि भारत एक लाभप्रद स्थिति में है - भारत का डबल्यूएपी अनुपात

वर्ष 2045 तक बढ़ जाएगा, भले ही यह दुनिया में कहीं और घट रहा हो। इस जनसांख्यिकीय लाभांश का अधिकतम लाभ उठाना भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने चौथी बड़ी चुनौती है।

वर्ष 2013 में भारत नाजुक पांच देशों में से एक था क्योंकि बाह्य क्षेत्र की व्यवहार्यता टेपर टैंट्रम के दौरान बिगड़ गई थी। वर्ष 2013 में समष्टि-आर्थिक विन्यास के सापेक्ष, भारत वर्तमान में बेहतर स्थिति में है क्योंकि इसके समष्टि-आर्थिक के मूल तत्वों में काफी सुधार हुआ है और बाह्य क्षेत्र के संकेतक बाहरी झटकों को प्रबंधित करने के लिए पर्याप्त कुशन की उपलब्धता की ओर इशारा करते हैं। मैं इस ताकत को एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता हूँ क्योंकि भू-राजनीतिक तनावों, कोविड के लंबे समय तक रहने वाले असर और जलवायु परिवर्तन की अनिवार्यता के साथ अंतरराष्ट्रीय वातावरण प्रतिकूल हो रहा है। इसके अलावा, दुनिया

भर के देश अपने नीतिगत रुख को एक महामारी मोड से दूर एक सामान्य स्थिति में ले जाने पर विचार कर रहे हैं। इसमें वैश्विक प्रभाव विसरण शामिल होंगे जिससे भारत अछूता नहीं कर सकता है। इसलिए बाह्य क्षेत्र की व्यवहार्यता महत्वपूर्ण है।

भारत वर्तमान में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) की दृष्टि से भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अनुमानों से पता चलता है कि वर्ष 2040 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। मेरे विचार से यह अंतिम चुनौती है - ब्रिक्स के साथ मिलकर वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनने की तैयारी करना।

धन्यवाद।

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

सरकारी वित्त 2021-22: एक अर्ध-वार्षिक समीक्षा
भारत के परिधान निर्यात में क्या-क्या कठिनाइयां हैं
कोयला आपूर्ति-मांग की स्थिति और प्रभाव

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

ओमीक्रॉन की रोकथाम हेतु किए जाने वाले नए उपायों के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी अनिश्चितता की गिरफ्त में है। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जोरदार वापसी की है जिसके कारण जीडीपी महामारी पूर्व के आँकड़े को पार कर गया है और मुद्रास्फीति मोटे तौर पर लक्ष्य के अनुरूप है। सभी प्रमुख संकेतकों के संदेश आशाजनक हैं और उपभोक्ता का विश्वास धीरे-धीरे लौट रहा है। सकल मांग की स्थिति निरंतर सुधार की ओर है यद्यपि क्रमिक धीमेपन के कुछ संकेत भी हैं। आपूर्ति के मोर्चे पर कृषि क्षेत्र की स्थिति रबी बुवाई की मजबूती के साथ सुदृढ़ है, जबकि, मांग की स्थिति मजबूत होने और नए व्यापार में उछाल के कारण विनिर्माण और सेवाओं में मजबूत सुधार दर्ज किया गया है।

परिचय

वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी अनिश्चितता की गिरफ्त में है। संक्रमण में उछाल के कारण, आपूर्ति शृंखला में रुकावट आ रही है, आवागमन संबंधी व्यवधान हो रहा है और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कई वर्षों के उच्च स्तर पर चली गयी है। ओमीक्रॉन के नए स्ट्रेन B.1.1.1.529 -के परिणामस्वरूप, रोकथाम के नए उपाए किए जा रहे हैं और यात्रा पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इन घटनाक्रमों ने वैश्विक विकास की गति और व्यापार को बाधित किया है। यद्यपि, बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण कई देशों में नीति सामान्यीकरण समयसीमा अपनायी जा रही है।

इन वैश्विक प्रतिकूलताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2021-22 की दूसरी तिमाही में जोरदार वापसी की। जीडीपी महामारी पूर्व के अपने स्तर से अधिक था और मुद्रास्फीति, कुछ अल्पकालिक बढ़त को छोड़कर लक्ष्य के अनुरूप थी। यह भांपकर कि वृद्धि को सतत आधार पर बनाए रखना जरूरी है, मौद्रिक

* यह आलेख कुणाल प्रियदर्शी, मधुरेश कुमार, शशिधर एम. लोकरे, सार्थक गुलाटी, राजीव जैन, विनीत कुमार श्रीवास्तव, बरखा गुप्ता, प्रियंका सचदेवा, अभिनंदन बोराड, जॉन वी. गुरिया, मनु शर्मा, प्रशांत कुमार, रिग्जेन यंगडॉल, सक्षम सूद, अवनीश कुमार, साक्षी अवस्थी, आशीष थॉमस जॉर्ज, ऋषभ कुमार, देबा प्रसाद रथ और समीर रंजन बेहरा द्वारा तैयार किया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

नीति समिति (एमपीसी) ने थोड़ा रुककर नरम रुख कायम रखने का निर्णय लिया।

सभी प्रमुख संकेतकों के संदेश आशाजनक हैं। संक्रमण के कम होने के साथ, सक्रिय मामलों की संख्या 14 दिसंबर को 90,000 से नीचे गिर गई और मई 2020 के अंत के बाद यह निम्नतम थी। टीकाकरण की दर बढ़ी है, दिसंबर में प्रतिदिन औसतन 75 लाख से अधिक टीकाकरण किया गया है जो एक महीने पहले 55 लाख की औसत से अधिक था। 4 दिसंबर तक हमने प्रतिदिन एक करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को छह बार प्राप्त कर लिया था। उल्लेखनीय है कि भारत ने नवंबर के दौरान हर चौथे और पाँचवें व्यक्ति को कोवैक्सिन की सुविधा अपलब्ध कराने के साथ-साथ 20 लाख के करीब कोविड-19 टीकों का निर्यात, कम और मध्यम आय वाले देशों में किया।

रिजर्व बैंक के नवंबर 2021 के उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) में पाया गया कि उपभोक्ताओं का विश्वास धीरे-धीरे लौट रहा है। सामान्य आर्थिक स्थिति, रोजगार के परिदृश्य और परिवारों की आय पर समग्र दृष्टिकोण आशावादी बना हुआ है। आने वाले वर्ष के लिए, आय और रोजगार को लेकर उपभोक्ता उत्साहित हैं। गतिशीलता के संकेतक बढ़ गए हैं। जॉब मार्केट में, हायरिंग गतिविधि बढ़ी है, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से दूरसंचार और इंटरनेट सेवाएं कर रहे हैं। निर्माण क्षेत्र की गतिविधि बढ़ी है। सीमेंट उत्पादन में भी तेजी आई है और आवासीय इकाइयों की मांग गति पकड़ रही है।

नवंबर में माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व उगाही दूसरी बार सर्वाधिक थी। हालांकि ई-वे बिल कम जारी हुए जिससे पता चलता है कि आगे के महीनों में जीएसटी की उगाही साधारण रहेगी। तेज वृद्धि दर्ज करते हुए (महीने-दर-महीने) दिसंबर (12 दिसंबर तक) में ई-वे बिल जनरेशन में फिर से तेजी आई है। वहीं, टोल उगाही नवंबर में अच्छी रही। गतिविधियाँ बढ़ने के साथ दूसरे महीने से लगातार भारत की बिजली की खपत में सुधार जारी है। बिजली प्लांट में कोयला भंडार नौ दिनों तक के लिए उपलब्ध हैं जिससे आपूर्ति की कमी की चिंता कम हुई। रबी की चल रही बुवाई में अच्छी प्रगति बनी हुई है। बुवाई वार्षिक औसत रकबे का लगभग आधा हो चुकी है। मांग की स्थिति को मजबूत होने और विवेकपूर्ण विपणन रणनीतियों के कारण

हेडलाइन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई) ने पिछले दस महीनों में सबसे मजबूत सुधार दर्ज किया गया। हेडलाइन सर्विसेज पीएमआई ने नये कार्य व्यापार के साथ अच्छी गति पकड़ी है। मजबूत समष्टि आर्थिक आधार के सहयोग से भारत सतत विकास की राह पर है।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, शेष लेख चार खंडों में विभक्त है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से विकसित हो रहे विकासों को दर्शाया गया है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में प्रस्तुत किया गया है। खंड IV में भारत की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा की गई है, जबकि अंतिम खंड में लेख का समापन किया गया है।

II. वैश्विक परिदृश्य

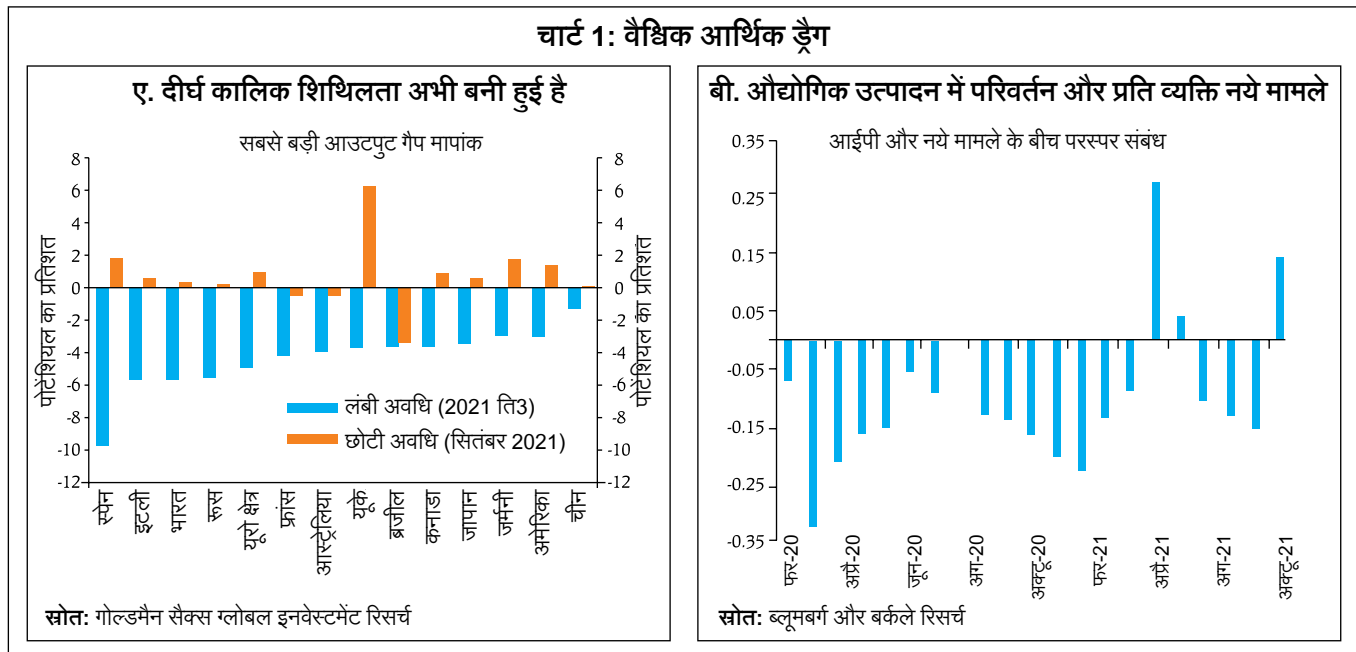
ओमिक्रॉन वेरिएंट के तीव्र फैलाव के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था बड़ी हुई अनिश्चितता से घिरी है। बाधित आपूर्ति शृंखला और यातायात में व्यवधान के कारण विनिर्माण लाइनों और व्यापार में मुश्किलों के साथ-साथ मुद्रास्फीति का जोखिम बढ़ रहा है। महामारी के नुकसान की भरपाई हो रही है, आउटपुट अंतराल में लगभग हर जगह शिथिलता दिख रही है (चार्ट 1)।

कई केंद्रीय बैंक सामान्य मौद्रिक नीति शीघ्र अपनाने पर विचार कर रहे हैं जिसके कारण वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़

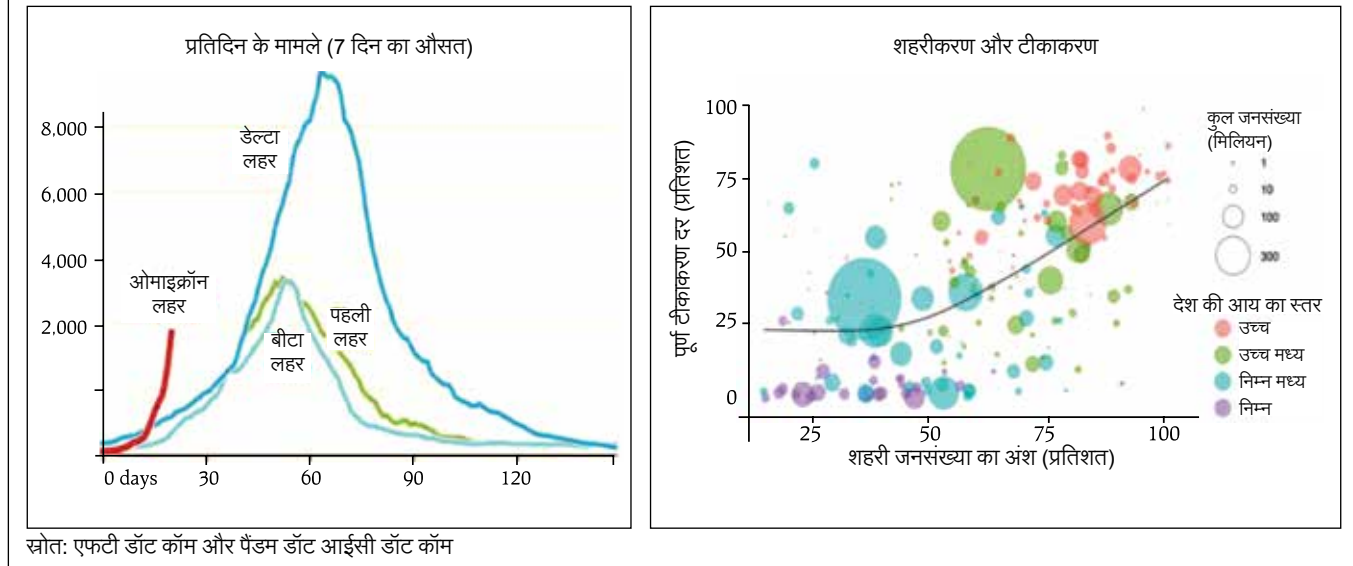
गई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ जो धीमी और असमान टिकाकरण गति (चर्ट 2) की मार झेल रही हैं, के लिए वैश्विक सुधार के विरुद्ध जोखिम कम हुए हैं। अफ्रीकी देशों में टीकाकरण की दर काफी कम है, उनकी आबादी के केवल 10 प्रतिशत (वैश्विक आबादी का 16.7 प्रतिशत) को कम से कम एक खुराक प्राप्त हुआ है।

अपने 1 दिसंबर, 2021 के आर्थिक दृष्टिकोण में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी ने 2021 के लिए वैश्विक वृद्धि पूर्वानुमान को सितंबर में किए गए अपने पहले के अनुमान (सारणी 1) से 0.1 प्रतिशत अंक घटाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए विकास अनुमानों को संशोधित कर घटा दिया गया है, जो, लगातार आपूर्ति शृंखला व्यवधान के कारण धीमी गति, बढ़ती इनपुट लागत और रोजगार के बावजूद श्रमिकों की कमी और काम के घंटे में महामारी पूर्व के स्तर की तुलना में कमी को दर्शाता है। जैसा कि ओईसीडी द्वारा चिह्नित किया गया है, अधिकांश उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ (एई) 2023 तक अपनी महामारी पूर्व स्थिति में लौटने के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल कुछ मुट्टी भर उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएँ (ईएमई) उस अवधि तक पूर्णतः दुरुस्त हो पाएँगी। कम आय वाले देशों के उत्पादन में अपने पूर्व-महामारी की अपेक्षा कमी होने की संभावना है। भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान, 2021 के लिए

चार्ट 1: वैश्विक आर्थिक ड्रैग



चार्ट 2: “ओमिक्रॉन की लहर” और असमान टीकाकरण के कारण बढ़ते कोविड मामले



सारणी 1 जीडीपी वृद्धि अनुमान चुनिंदा ए ई और ईएमई

(प्रतिशत)

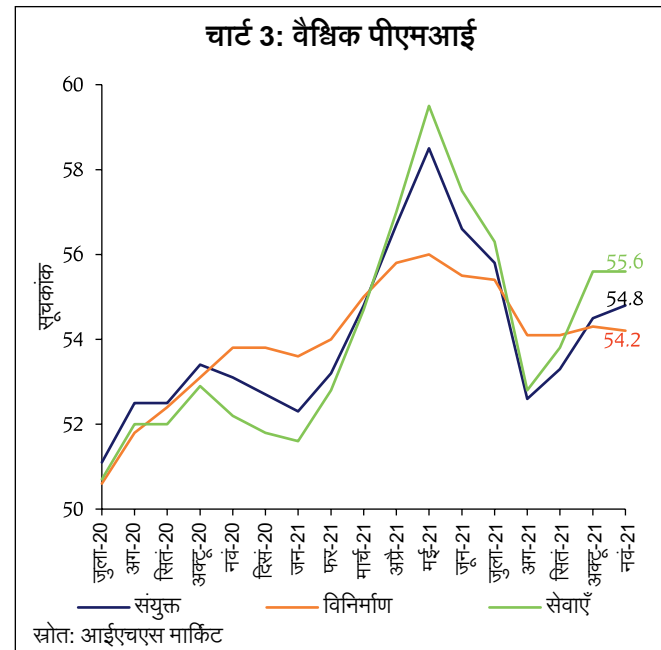
देश	2021		2022	
	सितं-2021	दिसं-2021	सितं-2021	दिसं-2021
विश्व	5.7	5.6	4.5	4.5
उन्नत अर्थव्यवस्थाएँ				
यूएस	6.0	5.6	3.9	3.7
यूके	6.7	6.9	5.2	4.7
यूरो क्षेत्र	5.3	5.2	4.6	4.3
जापान	2.5	1.8	2.1	3.4
उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाएँ				
ब्राजील	5.2	5.0	2.3	1.4
रूस	2.7	4.3	3.4	2.7
भारत	9.7	9.4	7.9	8.1
चीन	8.5	8.1	5.8	5.1
दक्षिण अफ्रीका	4.6	5.2	2.5	1.9

स्रोत: ओईसीडी

0.3 प्रतिशत अंक घटाकर 9.4 प्रतिशत किया गया है, जबकि 2022 के अनुमान को 0.2 प्रतिशत अंक घटाकर 8.1 प्रतिशत तक संशोधित किया गया है।

हाल के उच्च आवृत्ति संकेतकों का अनुसरण करते हुए, वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) नवंबर में चार महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। इसके साथ-साथ सेवा क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हुई, जिसने विनिर्माण क्षेत्र की अल्पवृद्धि (चार्ट 3) को

चार्ट 3: वैश्विक पीएमआई



पीछे छोड़ दिया। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई, हालांकि 17 महीने से विस्तार वाले क्षेत्र में था लेकिन आपूर्ति शृंखला में लगातार व्यवधान के कारण इसमें कमी आई है। दूसरी ओर, उपभोक्ता सेवाओं में कमजोरी के मुकाबले वित्तीय और व्यावसायिक सेवाओं में मजबूत वृद्धि के साथ, सेवा क्षेत्र का पीएमआई अक्टूबर में अपने तीन महीने के उच्च स्तर पर स्थिर रहा।

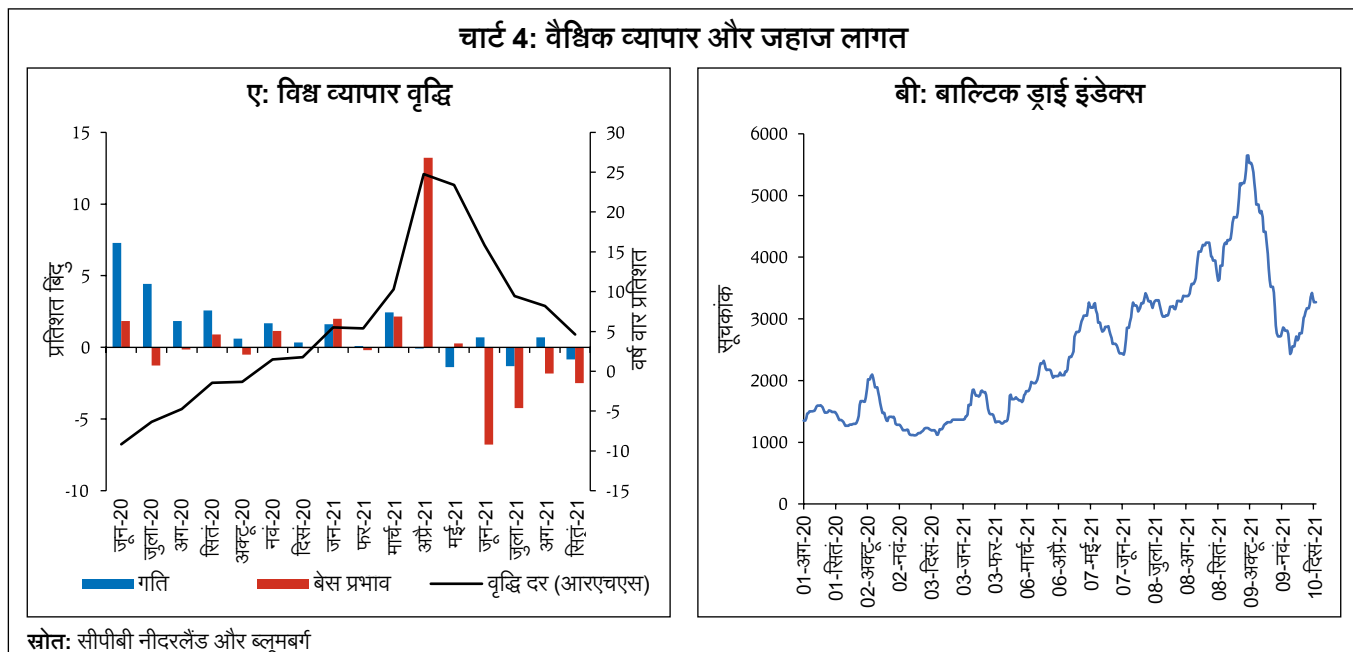
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा 15 नवंबर को जारी गुड्स ट्रेड बैरोमीटर की नवीनतम रीडिंग 99.5 थी जो धीमी व्यापार वृद्धि की ओर इशारा करती है। महत्वपूर्ण क्षेत्रों में व्यवधान के कारण वैश्विक माल व्यापार की वृद्धि में व्यापक हानि हुई, जिसके कारण बैरोमीटर के सभी घटक सूचकांक कमजोर हुए। प्रतिकूल आधार प्रभाव (चार्ट 4ए) के कारण सितंबर में लगातार पांचवें महीने पण्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि वर्ष-दर-वर्ष घटी। तदनुसार, विश्व वस्तु व्यापार की मात्रा वृद्धि में तीसरी तिमाही (तिमाही-दर-तिमाही) में 1.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जो मुख्य रूप से चीन के व्यापार में मंदी को दर्शाता है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (अंकटाड) के नवंबर ग्लोबल ट्रेड अपडेट के अनुसार, वैश्विक वस्तुओं के व्यापार के मूल्य में तिमाही वृद्धि, सकारात्मक होने के बावजूद, तीसरी तिमाही :2021 में 0.7 प्रतिशत तक धीमी हो गई, जबकि सेवा व्यापार में 2.5 प्रतिशत का विस्तार हुआ। चौथी तिमाही में, माल व्यापार वृद्धि (तिमाही - दर

- तिमाही) नगण्य होने का अनुमान है, जबकि सेवा व्यापार के धीरे-धीरे ठीक होने की उम्मीद है, लेकिन महामारी पूर्व के स्तर से नीचे रहने की संभावना है। हाल की मंदी के बावजूद, अंकटाड ने 2021 में वस्तुओं और सेवाओं के वैश्विक व्यापार के मूल्य में 23 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो 28 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच जाएगा।

कोयले की आपूर्ति (चार्ट 4बी) में उछाल के बाद सभी पोट खंडों में कीमतें बढ़ने के कारण, शुष्क थोक वस्तुओं के लिए शिपिंग शुल्क का एक मानक - बाल्टिक ड्राई इंडेक्स में, अक्टूबर के शुरुआती शिखर से 50 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद, नवंबर के मध्य से कुछ सुधार देखा गया। आपूर्ति शृंखला की बाधाएँ पिछले कुछ हफ्तों से दूर हुई हैं जिसके कारण अमेरिकी बंदरगाहों में कंटेनर जहाजों के गतिरोध में कमी आई है। बहरहाल, अपतटीय लंगर डाले और बंदरगाहों पर उतारने की प्रतीक्षा में जहाजों की संख्या अभी भी रिकॉर्ड स्तर के आसपास है।

ब्लूमबर्ग क्मोडिटी प्राइस इंडेक्स, जो सात साल के उच्च स्तर पर चल रहा था, नवंबर के आखिरी सप्ताह में गिर गया, उसके बाद दिसंबर में अब तक कुछ सुधार हुआ (चार्ट 5 ए)। 26 नवंबर, 2021 को कच्चे तेल की कीमतों में 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट आई जो अप्रैल 2020 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी की गिरावट थी और नवंबर में कुल गिरावट लगभग 17

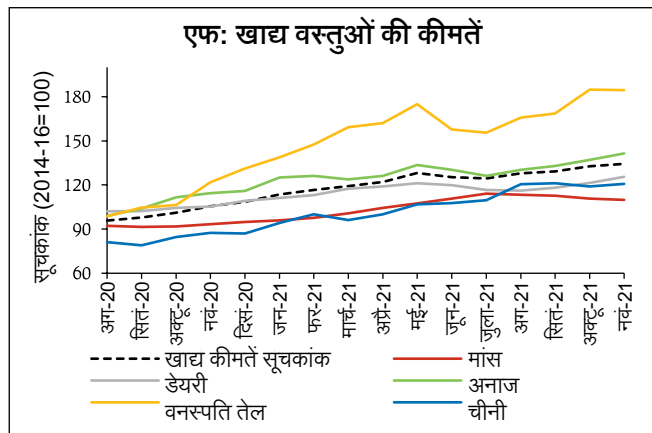
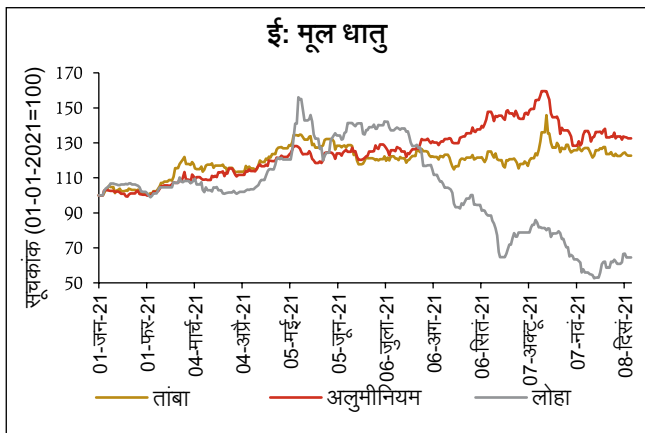
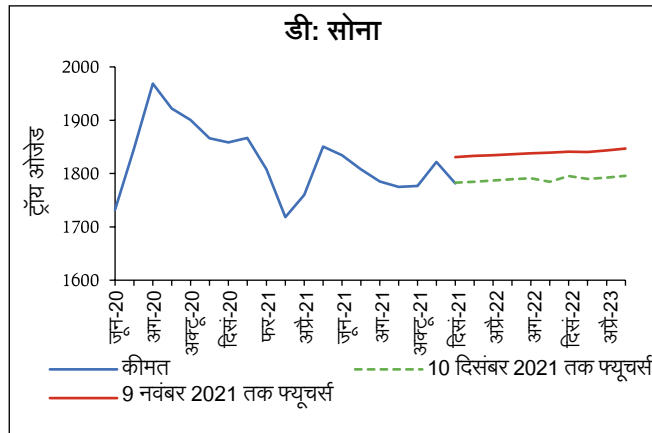
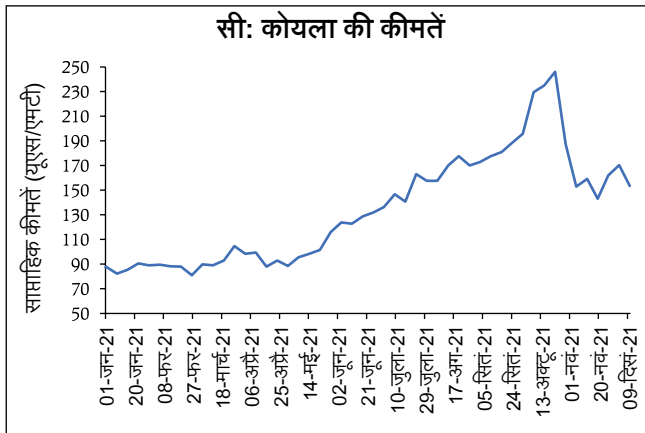
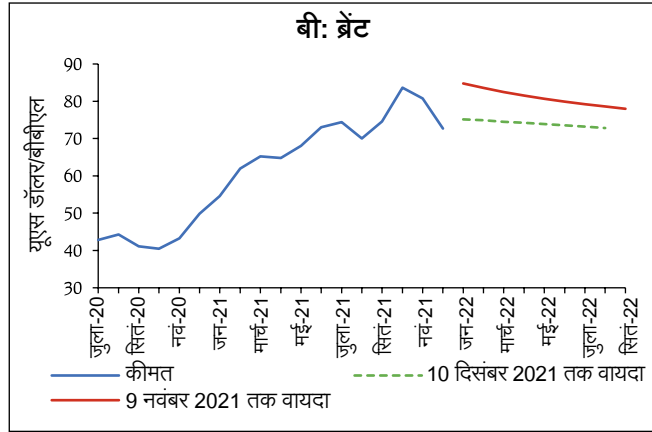
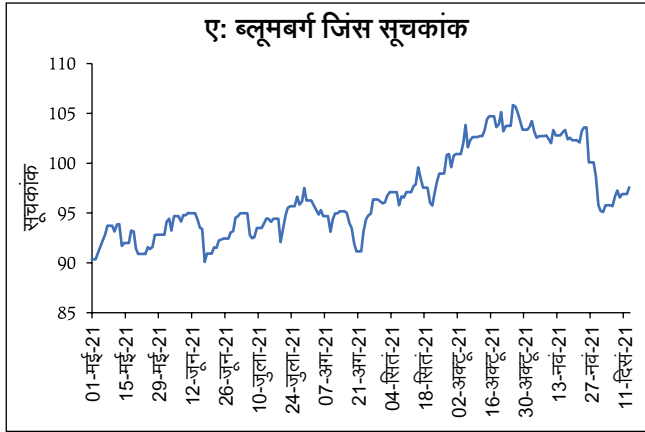
चार्ट 4: वैश्विक व्यापार और जहाज लागत



प्रतिशत के साथ समाप्त हुआ। ओपेक प्लस की 02 दिसंबर, 2021 की बैठक में प्रति दिन 4,00,000 बैरल जारी करने की अपनी योजना पर कायम रहने के बाद, कच्चे तेल की कीमतों में दिसंबर की शुरुआत में गिरावट देखी गई जिसके बाद कुछ बढ़ोतरी हुई (चार्ट 5 बी)। अन्य ईंधनों में, कोयले और प्राकृतिक गैस की

कीमतें भी हाल के उच्च स्तर से नीचे आई हैं क्योंकि आपूर्ति में सुधार हुआ है और मौसमी मांग में कुछ कमी आई है (चार्ट 5 सी)। सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का देखा गया, जिसमें नवंबर की शुरुआत में मजबूती आई, जो मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीदों के कारण महीने के उत्तरार्ध में, नरम

चार्ट 5: जिंस और खाद्य वस्तुओं की कीमतें

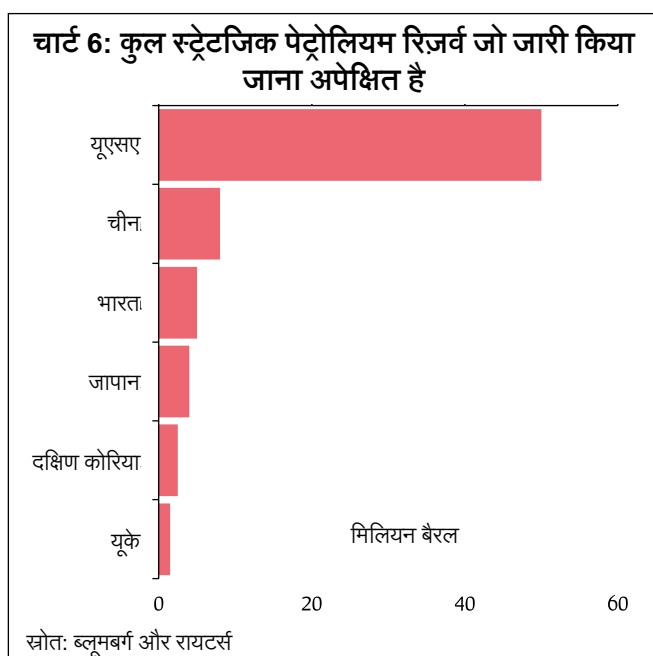


स्रोत: ब्लूमबर्ग : विश्व बैंक पिक शीट और एफएओ

पड़ गई (चार्ट 5डी)। चीन की मंदी के साथ-साथ मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण मूल धातु की कीमतें कम कारोबार कर रही हैं। हाल के सप्ताहों में नए वेरियंट के बारे में चिंताएं और भी कम हो गई हैं (चार्ट 5ई)। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा जारी खाद्य मूल्य सूचकांक ने मांग-आपूर्ति असंतुलन पर नवंबर में अपने उर्ध्वगामी रुख को बनाए रखा, जो लगातार चौथे महीने जून 2011 के बाद के उच्चतम स्तर पर चढ़ गया। अनाज की बढ़ती कीमतों में, मुख्य रूप से एक दशक की गेहूं की उच्च कीमतें, डेयरी और चीनी की कीमतों का अहम योगदान रहा (चार्ट 5एफ)।

नवंबर के दौरान, अमेरिका, भारत और यूके ने अन्य देशों के बीच स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम भंडार जारी करने की घोषणा की, जो लगभग 70 मिलियन बैरल¹ (चार्ट 6) हो सकता है।

जैसा कि मीडिया में छाया है- अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ रहे हैं और एक दशक से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गए हैं। ओईसीडी के नवीनतम अनुमानों के अनुसार, ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के लिए वार्षिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति 2021 तक लगभग 5 प्रतिशत तक रहने की संभावना है, इसके बाद 2022 में 3.5 प्रतिशत की गिरावट हो सकती है। ऊर्जा की बढ़ी हुई लागत और आपूर्ति संबंधी दबावों के बीच यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति नवंबर में

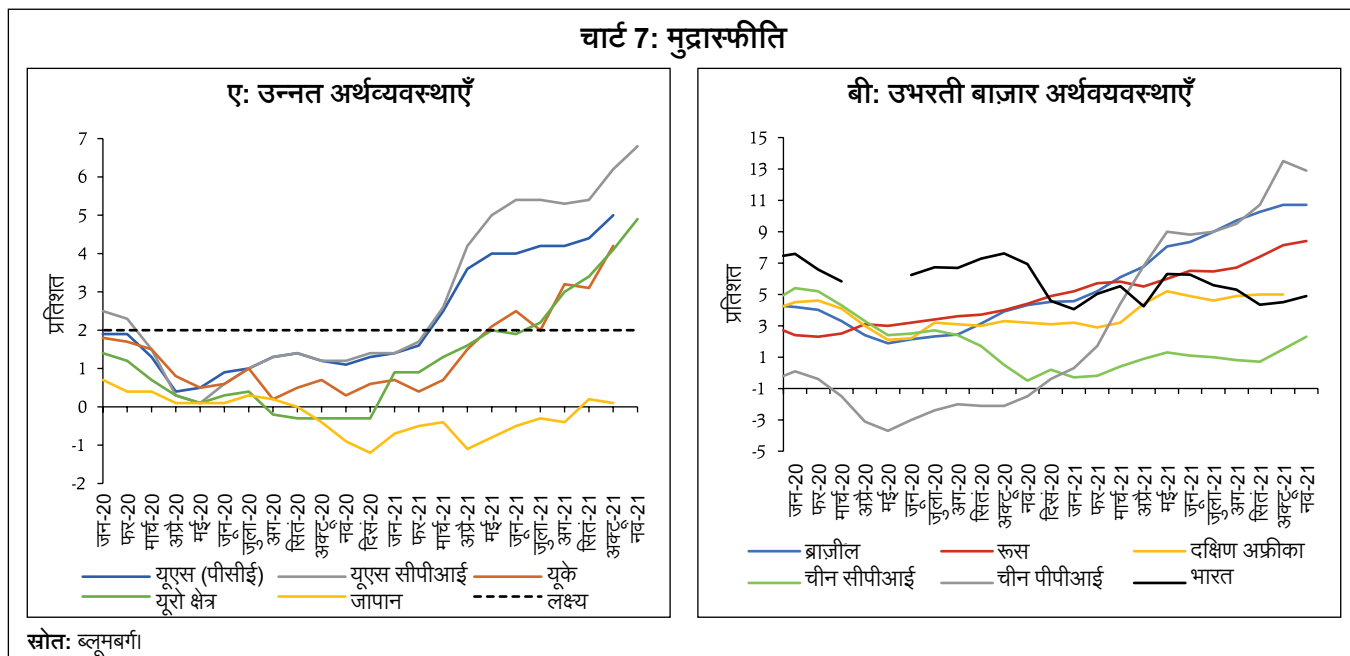


¹ यह ब्लूमबर्ग के अनुमान के अनुसार है।

30 साल के उच्च स्तर- 4.9 प्रतिशत पर पहुंच गई है (चार्ट 7ए)। उच्च उपभोक्ता मांग और आपूर्ति व्यवधानों के परिणामस्वरूप उच्च ऊर्जा और खाद्य कीमतों के कारण अमेरिका में, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 6.8 प्रतिशत हो गई जो जून 1982 के बाद से उच्चतम स्तर पर थी। मुख्य रूप से आवास और उपयोगी सेवाओं की लागत में वृद्धि के बाद परिवहन लागत में वृद्धि के कारण यूके में मुद्रास्फीति अक्टूबर में बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गई जो सितंबर में नरमी के बाद, दिसंबर 2011 के बाद से सबसे अधिक थी। प्रमुख ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, रूस में मुद्रास्फीति, नवंबर में बढ़कर 8.4 प्रतिशत हो गई, जबकि ब्राजील में, यह उसी महीने के 18 साल के उच्च स्तर- 10.74 प्रतिशत पर पहुंच गई। चीन में, अगस्त 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर मुद्रास्फीति की दर में बढ़ोतरी के साथ उपभोक्ता कीमतें नवंबर में लगातार दूसरे महीने बढ़नी शुरू हो गई हैं। मौसमी मांग और लगातार आपूर्ति में बाधा के कारण खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण यह उछाल आया (चार्ट 7 बी)।

नए वायरस स्ट्रेन और फेड की पाईवोट² से तीव्र टेपरिंग के कारण वित्तीय बाजारों में उच्च अनिश्चितता के साथ परिवर्तन जारी है। एई में इक्विटी बाजार नवंबर में लाल निशान में बंद हुए क्योंकि बाज़ार से जुड़ी भावनाओं में तेजी से उतार-चढ़ाव के कारण तेज बिकवाली हुई; हालांकि, दिसंबर में अब तक कुछ सुधार देखा गया है और अधिकांश सूचकांक नवंबर के नुकसान से उबर रहे हैं (चार्ट 8 ए)। नवंबर की शुरुआत में नई ऊँचाई के बाद, यूएस एस एंड पी इंडेक्स दिसंबर में फिर से ठीक होने से पहले अंतिम सप्ताह में गिर गया। अपने एई समकक्षों के साथ आगे बढ़ते हुए, ईएमई में शेयर बाजारों ने लाभ कम किया। इसके साथ ही, एमएससीआई के उभरते बाजार सूचकांक ने नवंबर में नकारात्मक रिटर्न दर्शाया। नवंबर में बाजार के रिस्क-ऑफ मोड में आने के साथ, यूएस का 10-वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल कम हो गया, जबकि मुद्रास्फीति की चिंताओं पर अल्पकालिक प्रतिफल कम हो गया, जिससे प्रतिफल वक्र और अधिक समतल हो गया (चार्ट 8 बी) था। मजबूत आर्थिक आंकड़ों के बीच अमेरिकी डॉलर में तेजी

² फेडरल रिज़र्व के जेरोम पॉवेल ने 30 नवंबर, 2021 को अपनी कांग्रेस की गवाही में आरिस्ट खरीद कार्यक्रम को तेजी से वापस लेने का संकेत कड़े शब्दों में दिया क्योंकि मुद्रास्फीति के जोखिम बहुत अधिक हैं और मुद्रास्फीति का वर्णन करते समय यह भी सुझाव दिया है कि यह संभवतः 'क्षणिक' शब्द को सेवानिवृत्त करने का समय है।

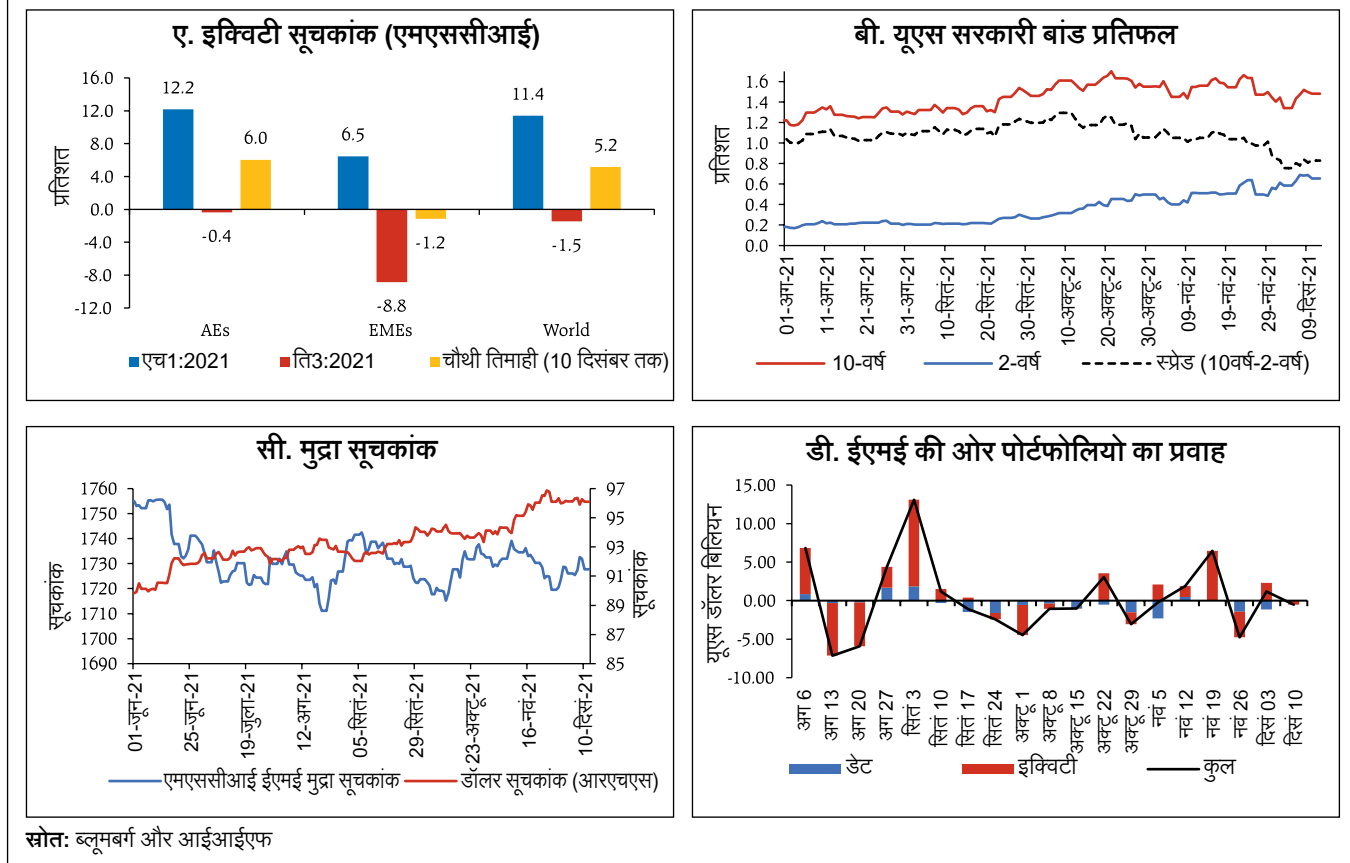


आई, जबकि फेड के रुख में बदलाव ने बढ़त को और मजबूत किया (चार्ट 8 सी)। इसके साथ ही, अधिकांश ईएमई मुद्राओं का नवंबर में मूल्यहास हुआ, जिसमें निवल पोर्टफोलियो आउट फ्लो ने डाउनट्रेंड को बढ़ा दिया। हालांकि, दिसंबर में अब तक आउट फ्लो में कटौती के कारण कुछ सुधार हुआ (चार्ट 8 डी)।

कई अर्थव्यवस्थाओं ने नीति सामान्यीकरण की दिशा में अपने कदम तेज करने के साथ मौद्रिक नीति कार्रवाइयों को बदल दिया है। हालांकि, कुछ अन्य लोगों ने बढ़ती अनिश्चितता के बीच इंतजार करना और देखना जारी रखा। फेड ने मौद्रिक प्रोत्साहन को जल्दी वापस लेने की संभावना का संकेत दिया था। अपनी नवंबर की बैठक में, सीवरजिस रिस्कबैंक ने अपनी नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा लेकिन 31 दिसंबर, 2021 तक अपनी शुद्ध संपत्ति खरीद कार्यक्रम को समाप्त करने की घोषणा की। सेंट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड ने नवंबर में अपनी दर को 50 आधार अंक (bps) बढ़ा दिया जो 2021 की इसकी चौथी दर - वृद्धि थी, जबकि न्यूजीलैंड के रिज़र्व बैंक ने 25 बीपीएस (चार्ट 9) की अपनी लगातार दूसरी दर वृद्धि को लागू किया। अक्टूबर की अपनी बैठक में एक विराम के बाद, बैंक ऑफ कोरिया ने अपनी नीतिगत दर में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की क्योंकि मुद्रास्फीति लक्ष्य से आगे निकल गई थी, जबकि नोर्गेस बैंक, सितंबर में अपनी

पहली दर वृद्धि के बाद नवंबर में कोई कार्रवाई नहीं की। दूसरी ओर, यूरोपीय सेंट्रल बैंक ने यथास्थिति बनाए रखी। अधिकांश ईएमई केंद्रीय बैंकों ने चौथी तिमाही में नीति को टाईटनिंग रखा है। दक्षिण अफ्रीका भी इस समूह में शामिल गया है क्योंकि इसने नवंबर में अपनी दर 25 बीपीएस बढ़ा दी है जो पिछले तीन वर्षों में पहली वृद्धि है। ब्राजील ने दिसंबर में वर्ष के लिए अपनी सातवीं दर में 150 बीपीएस की वृद्धि की जो इस स्केल की लगातार दूसरी वृद्धि थी और 2021 में सकल वृद्धि 725 बीपीएस हो गई। अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं में, मेक्सिको और पेरू ने क्रमशः 25 बीपीएस और 50 बीपीएस के परिमाण से अपनी चौथी और पांचवीं दर वृद्धि को प्रभावित किया। इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित कुछ अन्य प्रमुख ईएमई ने यथास्थिति बनाए रखी। दूसरी ओर, तुर्की ने अक्टूबर में 200 बीपीएस और सितंबर में 100 बीपीएस की कमी के बाद नवंबर में अपनी दर में 100 बीपीएस की और कमी की, जिससे 2021 के लिए कुल संचयी परिवर्तन (-)200 बीपीएस हो गया। दिसंबर की अपनी बैठक में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने अर्थव्यवस्था को समर्थन देने के लिए लंबी अवधि की चलनिधि के 1.2 ट्रिलियन युआन (लगभग यूएस \$ 188 बिलियन) को जारी करते हुए, 15 दिसंबर से प्रभावी, प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरक्षी जरूरत को 50 बीपीएस तक कम कर दिया।

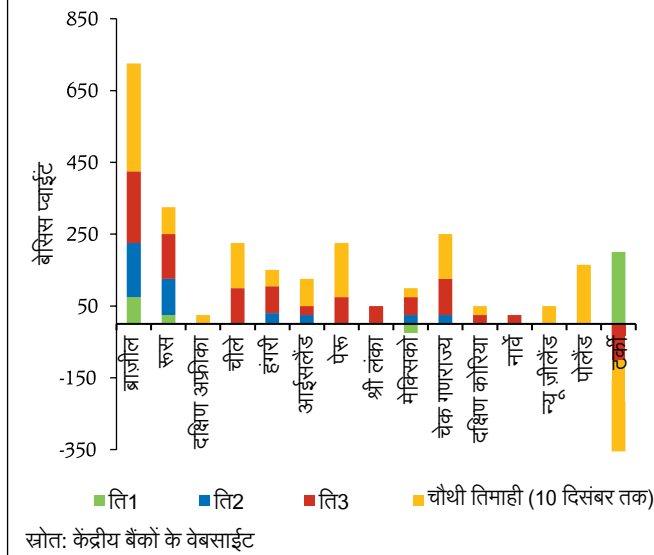
चार्ट 8: वित्तीय बाजार



वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कुछ हद तक कम आशावादी बना हुआ है, जिससे सुधार के जोखिम कम हुए हैं। अधिकांश

अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति बहु-वर्ष के उच्चतम स्तर पर होने के कारण, नीतिगत परिवर्तन की गुंजाईश कम होती जा रही है। समय वित्तीय स्थिरता के लिए संकेत प्रतिकूल रहने की संभावना है।

चार्ट 9: 2021 में चुनिंदा देशों के केंद्रीय बैंकों की दरों में परिवर्तन

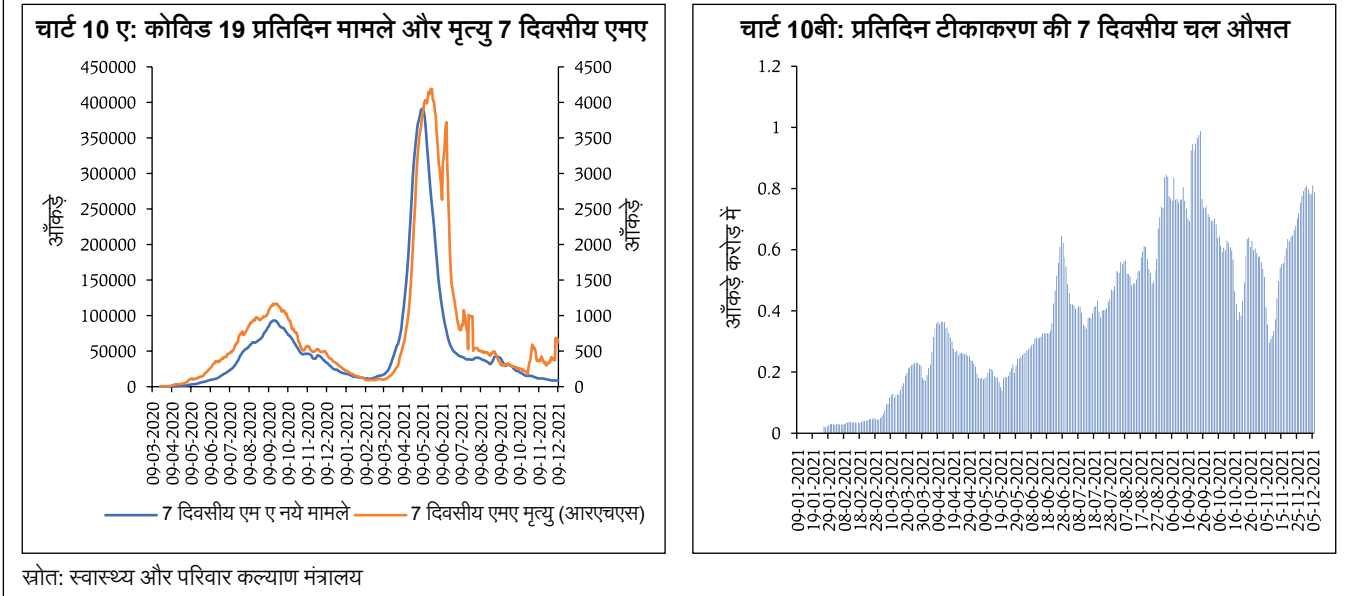


III. घरेलू घटनाक्रम

विशेषकर, निजी क्षेत्र के निवेश, बैंक ऋण में बढ़ोतरी और केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा उच्च पूंजीगत व्यय के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है। साथ ही रोजगार की स्थिति में भी सुधार हुआ है। दृष्टिकोण उत्साहजनक है, हालांकि नए ओमिक्रॉन वेरियंट के प्रसार की चिंता सामने आ रही है।

नवंबर के अंत तक दैनिक कोविड -19 मामलों की 7-दिवसीय चल औसत 9000 से नीचे आ गई। नवंबर के शुरुआती हिस्से में त्योहारी मौसम के दौरान एक ब्लिप के बाद, टीकाकरण ने गति पकड़ ली है। नवंबर के अंत तक टीकाकरण की 7-दिवसीय चल

चार्ट 10: कोविड-19 मामले और टीकाकरण

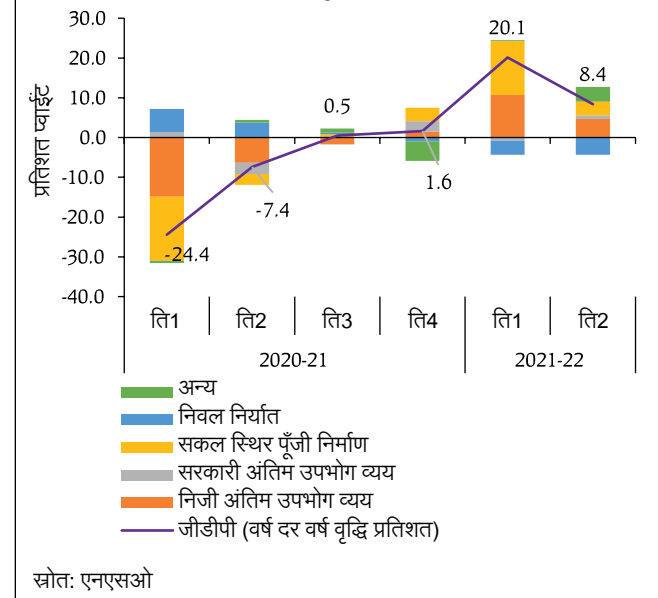


औसत 80 लाख प्रति दिन और 4 दिसंबर 2021 में छठी बार 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। (चार्ट 10ए और 10बी)।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के 30 नवंबर, 2021 की विज्ञप्ति के अनुसार, 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी में जोरदार उछाल आया, जो अनुकूल आधार से उपर 8.4 प्रतिशत की वृद्धि थी और रिज़र्व बैंक के 7.9 प्रतिशत के अनुमान से अधिक था। जीडीपी का स्तर 2019-20 की दूसरी तिमाही के आँकड़े से 0.3 प्रतिशत से अधिक हो गया। कुल मांग में सुधार मामूली था जबकि सरकार के अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई), सकल अचल पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) और निर्यात (चार्ट 11) में यह खास देखा गया। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) ने संपर्क-गहन सेवाओं की तेजी से बहाली और उपभोक्ता विश्वास की बहाली के कारण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर वृद्धि दर्ज की, लेकिन अभी भी यह 2019-20 के स्तर से नीचे बनी हुई है। भारत के निर्यात ने प्रभावशाली सुधार दिखाना जारी रखा, जो उच्च विकास के एक प्रमुख घटक के रूप में उभरा।

गूगल और एप्पल के मोबिलिटी सूचकांकों ने एक साल पहले दर्ज किए गए स्तरों को पार करते हुए, त्योहारी सीजन में तेजी को बनाए रखते हुए गतिशीलता में वृद्धि जारी रखी। पार्कों, किराना और फार्मसी, ट्रांजिट स्टेशनों और कार्यस्थलों के आसपास

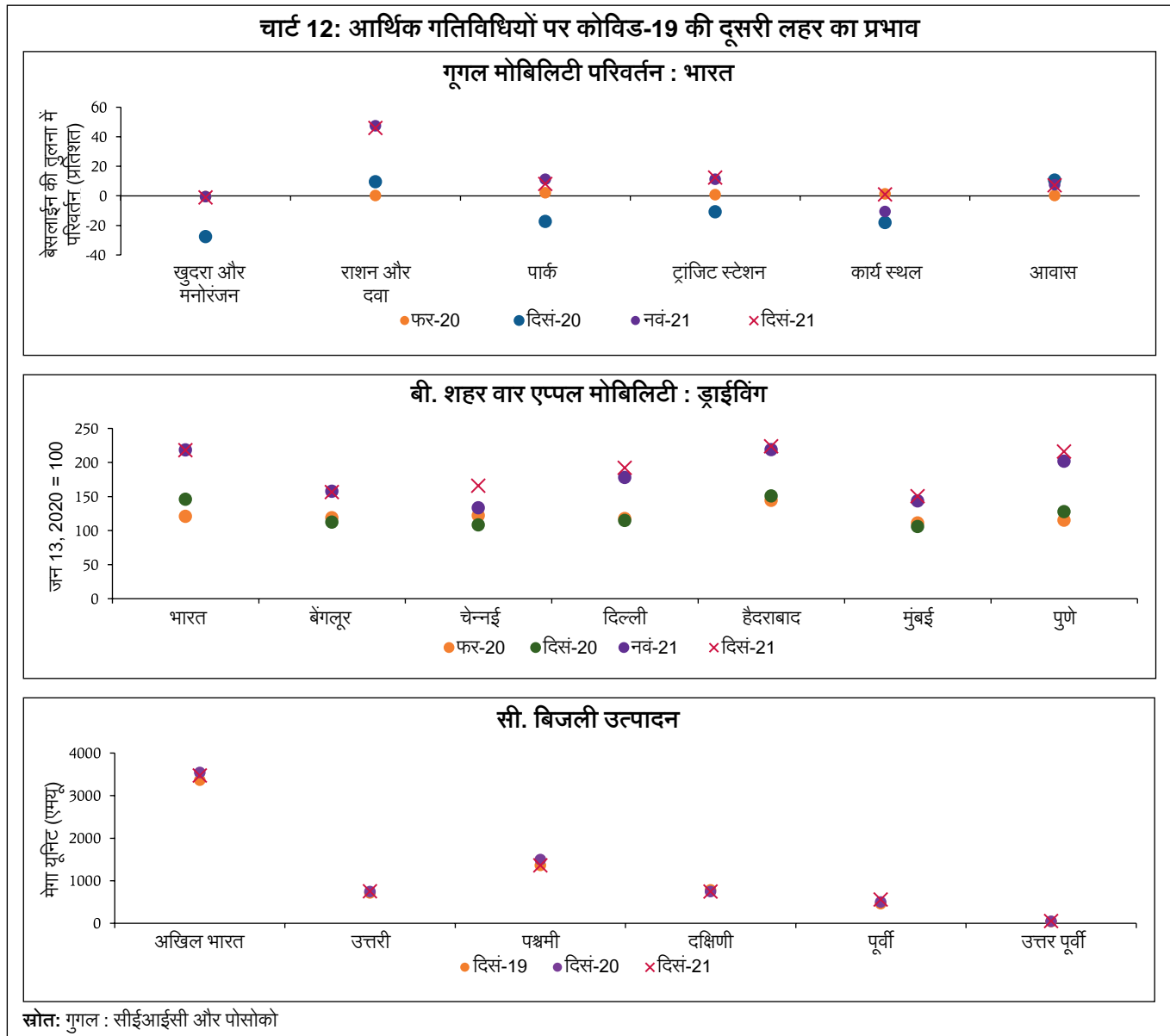
चार्ट 11: जीडीपी वृद्धि में भारत योगदान



गतिशीलता के लिए गूगल गतिशीलता सूचकांक महामारी पूर्व के स्तर पर पहुंच गया, जबकि एप्पल गतिशीलता सूचकांक सभी प्रमुख शहरों (चार्ट 12ए और 12बी) में ऊंचा बना रहा। साप्ताहिक नोमुरा इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स एनआईबीआरआई³ ने 12 दिसंबर, 2021 को समाप्त सप्ताह के दौरान महामारी से पहले

के स्तर से 15.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। महामारी से पहले के स्तर (चार्ट 12सी) को पार करते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में बिजली उत्पादन में तेजी आई।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 2019-21 एनएफएचएस⁴ और शिक्षा की वार्षिक स्थिति⁵ एएसईआर [ग्रामीण] 2021 को



³ एनआईबीआरआई में गूगल मोबिलिटी इंडेक्स, एप्पल से ड्राइविंग मोबिलिटी, बिजली की मांग और श्रम बल की भागीदारी दर शामिल हैं।

⁴ हाउसहोल्ड, महिला, पुरुष और बायोमार्कर के लिए चार सर्वेक्षण अनुसूचियों का उपयोग करके एनएफएचएस -5 का संचालन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई नोडल एजेंसी थी, जिसे कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीपीआई) का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में प्रचारित किया गया था।

⁵ एएसईआर एक नागरिक के नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है, जिसे प्रथम, एक गैर-सरकारी संगठन द्वारा बनाया गया है और प्रत्येक वर्ष कॉलेज, विश्वविद्यालयों, गैर-लाभकारी संगठनों और शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे सहयोगी संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा किया जाता है।

नवंबर 2021 में जारी किया गया था। एनएफएचएस इसकी स्थापना के बाद पहली बार, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में कुल जनसंख्या के लिंगानुपात में 1 से अधिक (अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं) वृद्धि दर्शाता है। कुल फर्टिलिटी दर टीएफआर रिप्लेसमेंट लेवल (2.1) से नीचे 2.0 पर आ गया है। इसके अलावा, सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में जनसांख्यिकीय बदलाव की पुष्टि करते हुए, युवा आबादी (अंडर -15) 2019-21 के दौरान घटकर 26.5 प्रतिशत हो गई है, जो 2015-16 में 28.6 प्रतिशत थी। दूसरी ओर, एएसईआर 2021 में ग्रामीण भारत में निजी स्कूल से हटकर सरकारी स्कूल में नामांकन बदलाव दिखाई दिया। महामारी में वर्चुअल शिक्षा में वृद्धि दर्शाते हुए, नामांकित बच्चों के घरों में मोबाइल फोन की पहुंच 2018 में 36.5 प्रतिशत से बढ़कर 2020 और 2021 में क्रमशः 61.8 प्रतिशत और 67.6 प्रतिशत हो गई।

कुल मांग

कुल मांग के संकेतकों के अनुसार क्रमिक धीमेपन साथ सभी क्षेत्रों में निरंतर सुधार की उम्मीद है। भले ही ई-वे बिल जनरेशन महामारी पूर्व स्तरों (चार्ट 13 ए) से उपर रहा, नवंबर के पूर्वार्द्ध में त्योहारी मौसम की शिथिलता के कारण कुछ क्रमिक गिरावट आई। ई-वे बिल जनरेशन ने दिसंबर (12 दिसंबर तक) में तेज

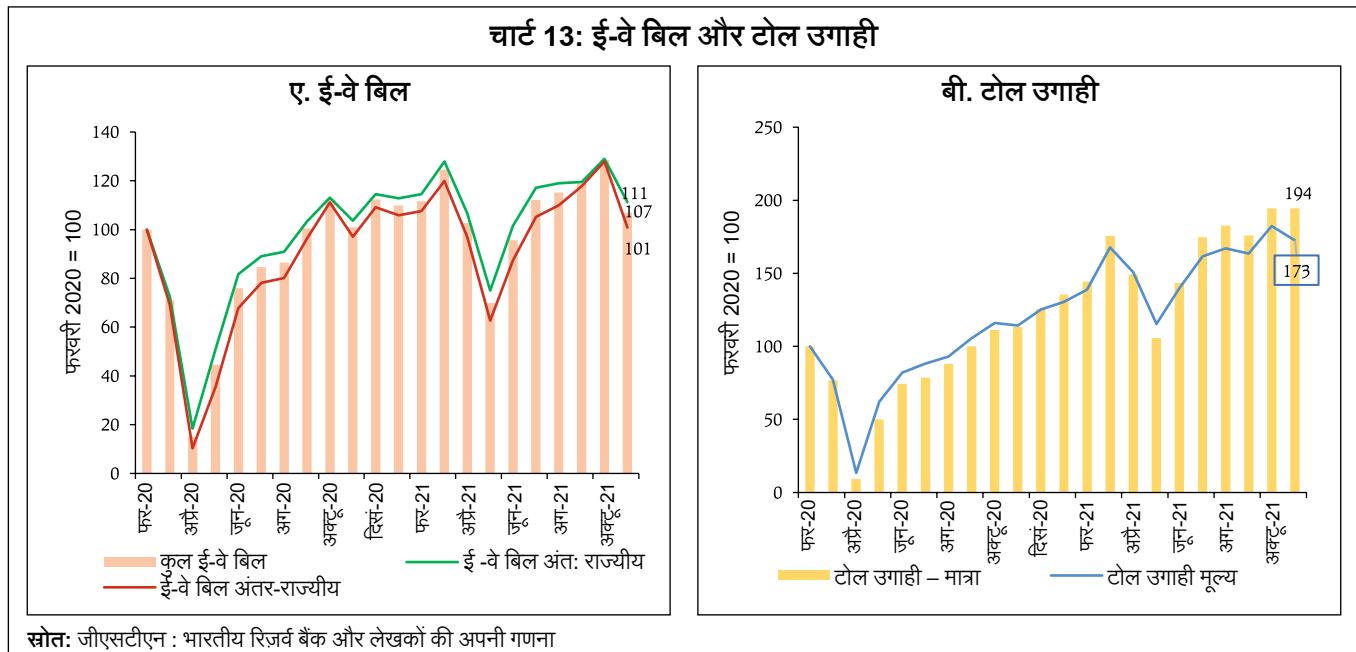
माहवार वृद्धि दर्ज की है। दूसरी ओर, टोल संग्रह नवंबर 2021 (चार्ट 13बी) में 71.5 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के साथ सुदृढ़ रहा।

त्योहारी मौसम के अंत में पेट्रोलियम खपत-वृद्धि में नरमी आई जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की खपत में महामारी पूर्व के स्तर में कमी आई। विमानन टरबाइन ईंधन खपत में नवंबर 2021 (चार्ट 14 ए) में स्थिर वृद्धि दर्ज की गई।

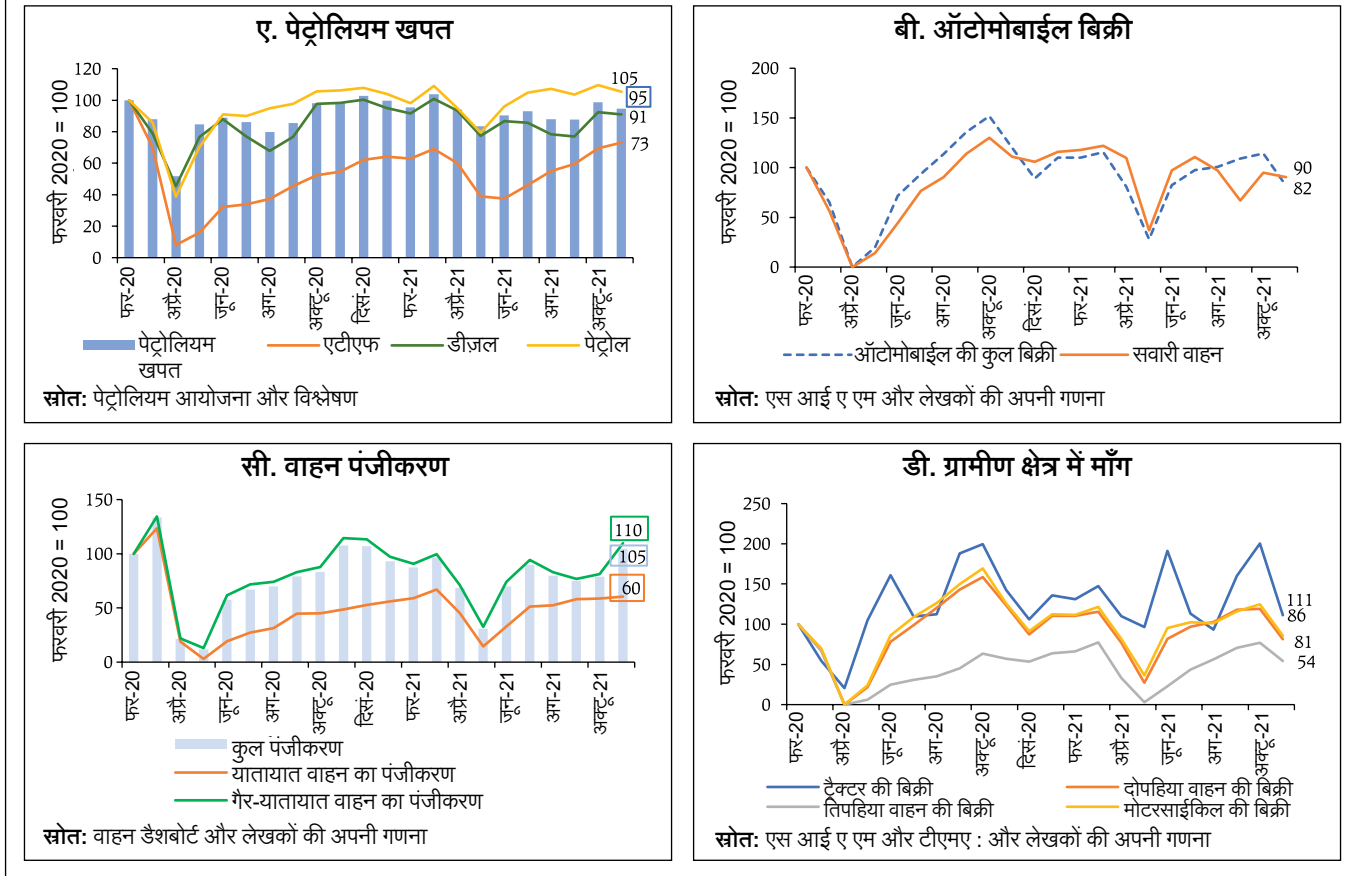
वैश्विक आपूर्ति शृंखला और आवागमन व्यवधानों का घरेलू ऑटोमोबाइल क्षेत्र पर भारी दबाव बना रहा। आपूर्ति की बाधाओं के कारण त्योहारी मौसम में मोटर वाहनों की बिक्री में कमी आई।

तथापि, गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण में वृद्धि के साथ वाहन पंजीकरण में वृद्धि देखी गई (चार्ट 14ग)। नवंबर में ट्रैक्टरों की घरेलू बिक्री में 22.5 प्रतिशत की वार्षिक गिरावट के साथ ग्रामीण मांग में कमी देखी गई। उद्योग जगत के नेताओं के अनुसार, मांग में गिरावट के लिए उच्च आधार प्रभाव और देर से मानसून के कारण खरीफ फसलों की कटाई में देरी को जिम्मेदार ठहराया गया था। ग्रामीण मांग में कमी के कारण दुपहिया, तिपहिया और मोटरसाइकिलों की बिक्री में साल-दर-साल गिरावट आई है (चार्ट 14डी)। दो पहिया वाहनों के भीतर, इलेक्ट्रिक सेगमेंट ने एक मजबूत प्रदर्शन दर्ज करना जारी रखा- नवंबर 2021 में 233.3

चार्ट 13: ई-वे बिल और टोल उगाही



चार्ट 14: यातायात क्षेत्र के संकेतक



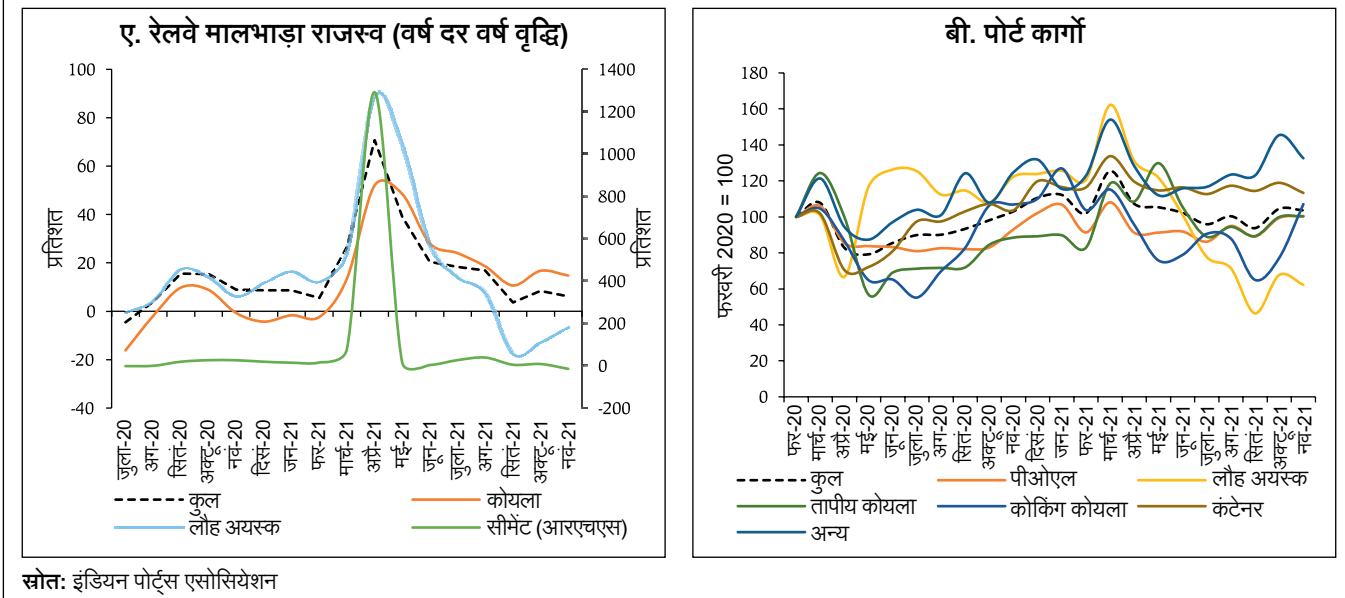
प्रतिशत वर्षवार वृद्धि हुई क्योंकि ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं ने लॉजिस्टिक संचालन और अंतिम लक्ष्य डिलीवरी के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की ओर रुख किया।

रेलवे माल ढुलाई में, एक साल पहले 9.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (चार्ट 15 ए)। चूँकि, दुनिया भर में जहाजों के आवागमन में बाधाएँ बढ़ीं और कंटेनर की अधिक कमी हो गई इसलिए नवंबर में पत्तन-यातायात की वृद्धि में कमी आई (चार्ट 15 बी)। कोकिंग कोल शिपमेंट में वृद्धि के बावजूद लौह-अयस्क के शिपमेंट में गिरावट के कारण यह कमी देखी गई। पीएम गति शक्ति योजना के तहत पहचानी गई 101 परियोजनाओं के साथ, 2024-25 तक भारतीय बंदरगाहों पर कार्गो क्षमता को 37.2 प्रतिशत बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पत्तनों के बीच जुड़ाव बढ़ने की उम्मीद है।

निर्माण क्षेत्र की गतिविधि मजबूत हुई, क्योंकि सीमेंट उत्पादन ने अक्टूबर में लगातार चौथे महीने दो अंकों की वर्षवार वृद्धि दर्ज की। मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल क्षेत्र से कम मांग के कारण इस्पात की खपत में नरमी आई। सीमेंट उत्पादन और इस्पात खपत दोनों ने महामारी पूर्व स्तरों (चार्ट 16) से अधिक वृद्धि दर्ज की। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर सरकार के जोर के कारण आने वाली तिमाहियों में सीमेंट की मांग मजबूत रहने की संभावना है। हालांकि सीमेंट उद्योग मानवजनित CO₂ उत्सर्जन का कारण बनता है। विशेष रूप से रिवर्स कैल्सीनेशन से संबंधित, हाल की हरित प्रौद्योगिकियों में विकास के लिए भारत में अच्छी संभावनाएँ हैं (बॉक्स)।

विमानन क्षेत्र में, यात्री और कार्गो यातायात अगस्त 2021 से बढ़त की ओर है, नवंबर 2021 में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू माल

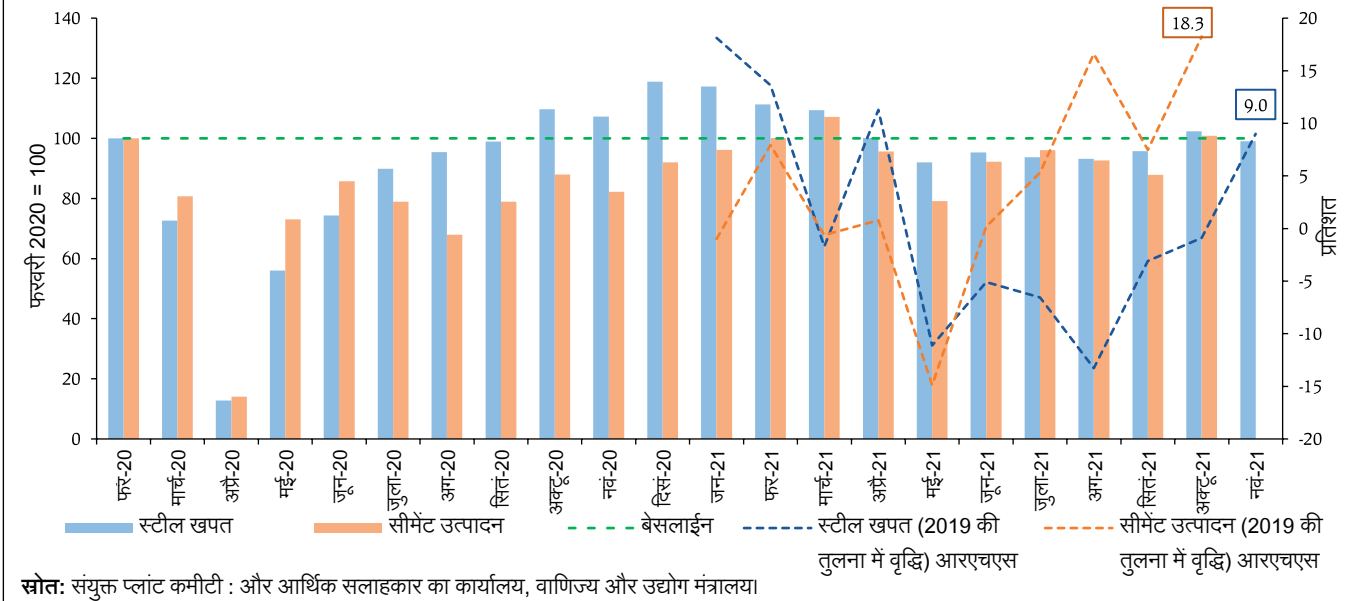
चार्ट 15: रेलवे और पोर्ट ट्रैफिक



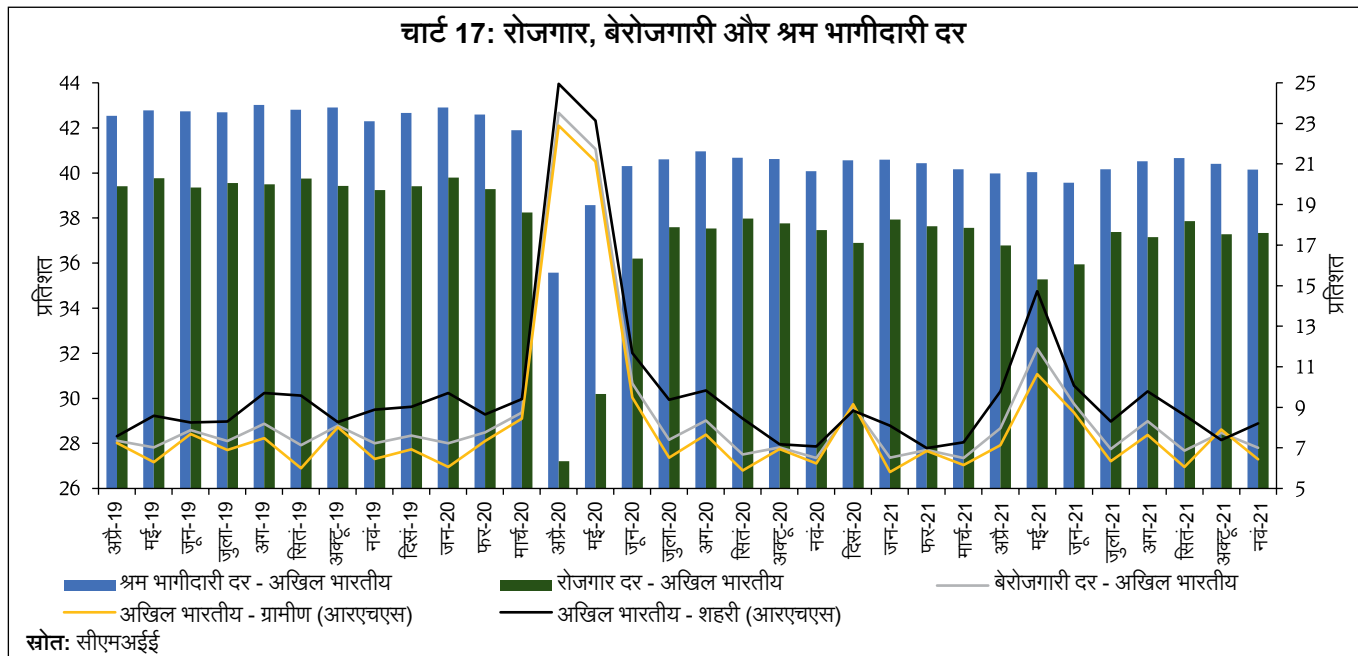
भाड़ा दोनों सामान्य हो गए हैं। त्योहारी मौसम के साथ यात्री-यातायात बढ़ने की संभावना है। हालाँकि, ओमिक्रॉन के मद्देनजर आने वाले नए यात्रा दिशानिर्देश नये सुधार को बाधित कर सकते हैं। दिसंबर के पहले दस दिनों में, घरेलू हवाईअड्डों पर दैनिक

उड़ान-आगमन⁶ संख्या औसतन 7.1 लाख प्रति दिन थी जो नवंबर में इसी अवधि की तुलना में 12.1 प्रतिशत अधिक थी। अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों की उड़ान-आगमन संख्या में भी क्रमिक रूप से 24.7 प्रतिशत का सुधार हुआ, जबकि कार्गो खंड में घरेलू

चार्ट 16: निर्माण क्षेत्र के संकेतक



⁶ इसमें प्रस्थान करने वाले और आने वाले दोनों यात्री शामिल हैं।



और अंतरराष्ट्रीय कार्गो के लिए क्रमशः 23.3 और 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

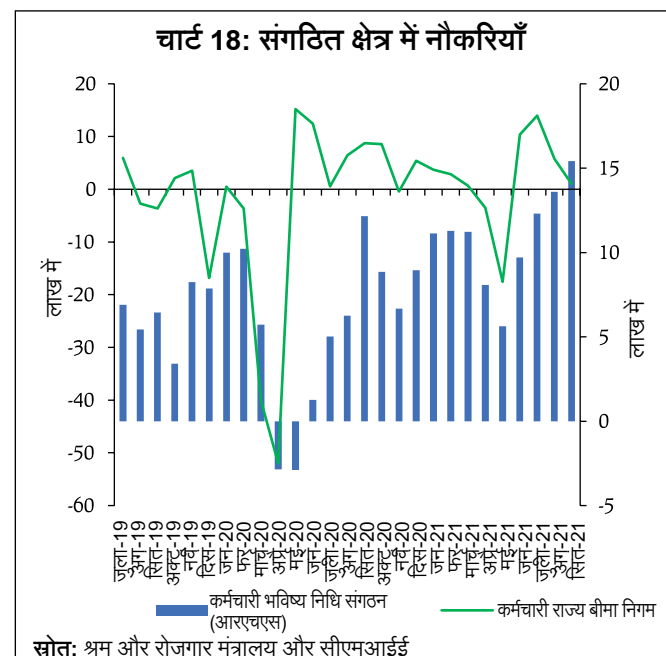
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार, श्रम भागीदारी दर सितंबर में 12 महीने के उच्च स्तर- 40.66 को छूने के बाद, अक्टूबर 2021 की 40.4 से घटकर नवंबर में 40.2 हो गई। नवंबर में बेरोजगारी दर 80 आधार अंक गिरकर 7 प्रतिशत पर आ गई। बेरोजगारी दर में गिरावट ग्रामीण बेरोजगारी में 1.5 प्रतिशत अंक की गिरावट के कारण आई (चार्ट 17)।

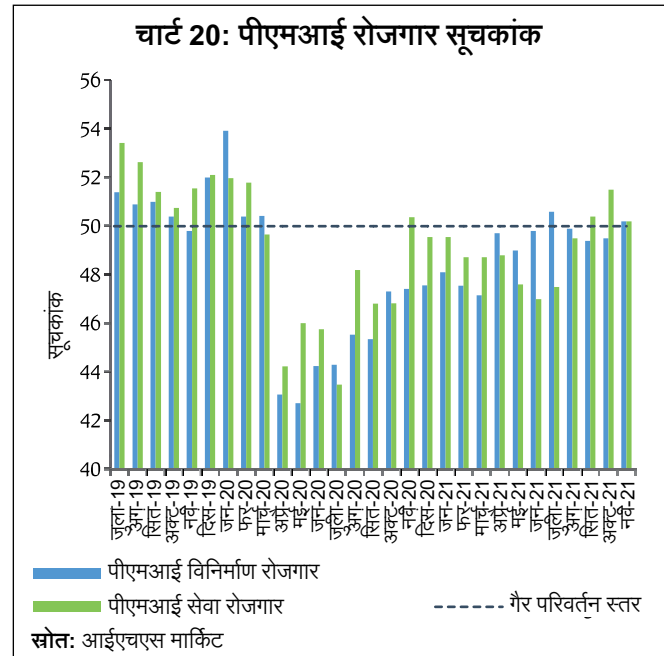
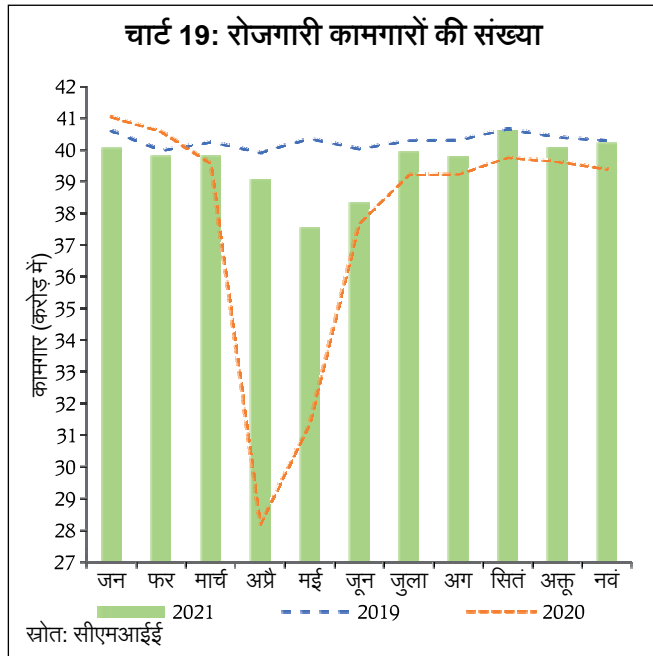
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कैप्चर किए गए संगठित क्षेत्र के श्रम बाजार के आंकड़े, मिश्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ईपीएफओ के तहत अभिदाताओं की निवल संख्या में निरंतर वृद्धि के मुकाबले ईएसआईसी के अभिदाता निवल संख्या की वृद्धि में कमी देखी गई। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अपनी वर्तमान नौकरियों से बाहर निकलने वाले अभिदाताओं की संख्या अगस्त 2021 में 6.43 लाख से गिरकर सितंबर 2021 में 3.31 लाख हो गई। ऐसा जनवरी-मार्च 2021 में भी देखा गया था जब अर्थव्यवस्था मजबूत सुधार दिखा रही थी (चार्ट 18)।

सीएमआईई के रोजगार आंकड़ों के अनुसार, श्रम बाजार महामारी पूर्व स्तर के करीब पहुंच गया है, अक्टूबर-नवंबर में

कार्यरत श्रमिकों की संख्या 2019 (चार्ट 19) में देखे गए स्तरों के करीब पहुंच गई है।

पीएमआई का रोजगार खंड, नवंबर 2021 में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की नौकरियों में मामूली विस्तार दिखा रहा है। जबकि, विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार में तीन महीने के बाद विस्तार हुआ और



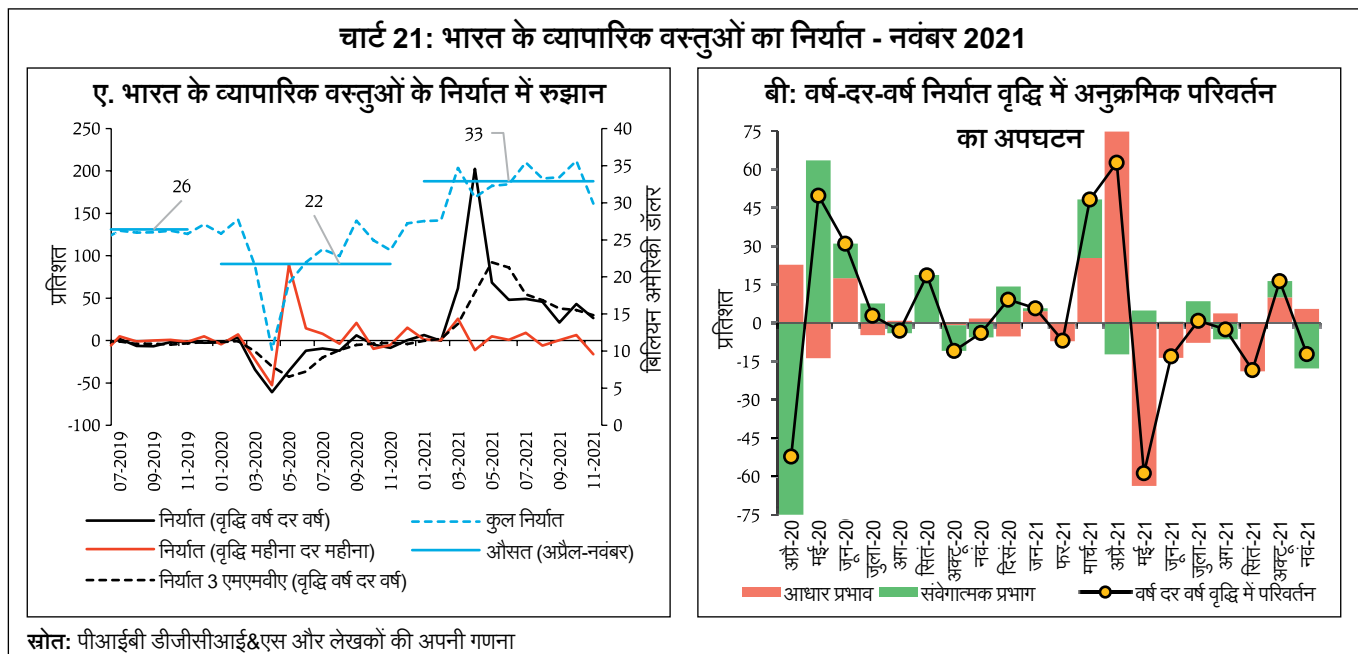


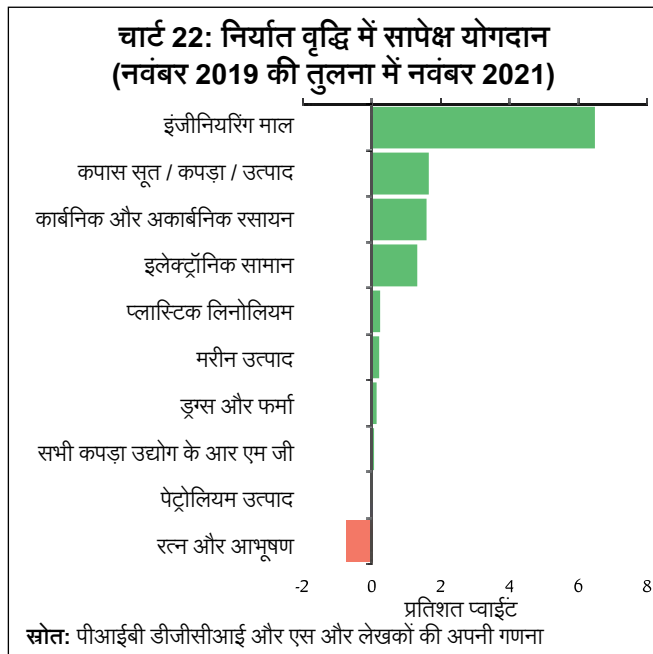
सेवा क्षेत्र का रोजगार विस्तार पिछले महीने (चार्ट 20) से कम हो गया।

भारत के माल व्यापार के लिए बाहरी मांग मजबूत रही, निर्यात में नवंबर 2021 में पूर्व-महामारी के स्तर की तुलना में 16.6 प्रतिशत (30.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर) की वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, लगातार वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बाधाओं, उच्च

शिपिंग दरों और वैश्विक शिपिंग कंटेनर की कमी (चार्ट 21ए और 21बी) के कारण क्रमिक मंदी थी।

इंजीनियरिंग सामान, सूती धागे, कपड़े, हथकरघा उत्पाद, रसायन और इलेक्ट्रॉनिक्स (चार्ट 22) के उच्च निर्यात से व्यापारिक माल निर्यात में वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बिजली परियोजनाओं में महत्वपूर्ण निवेश से मजबूत,





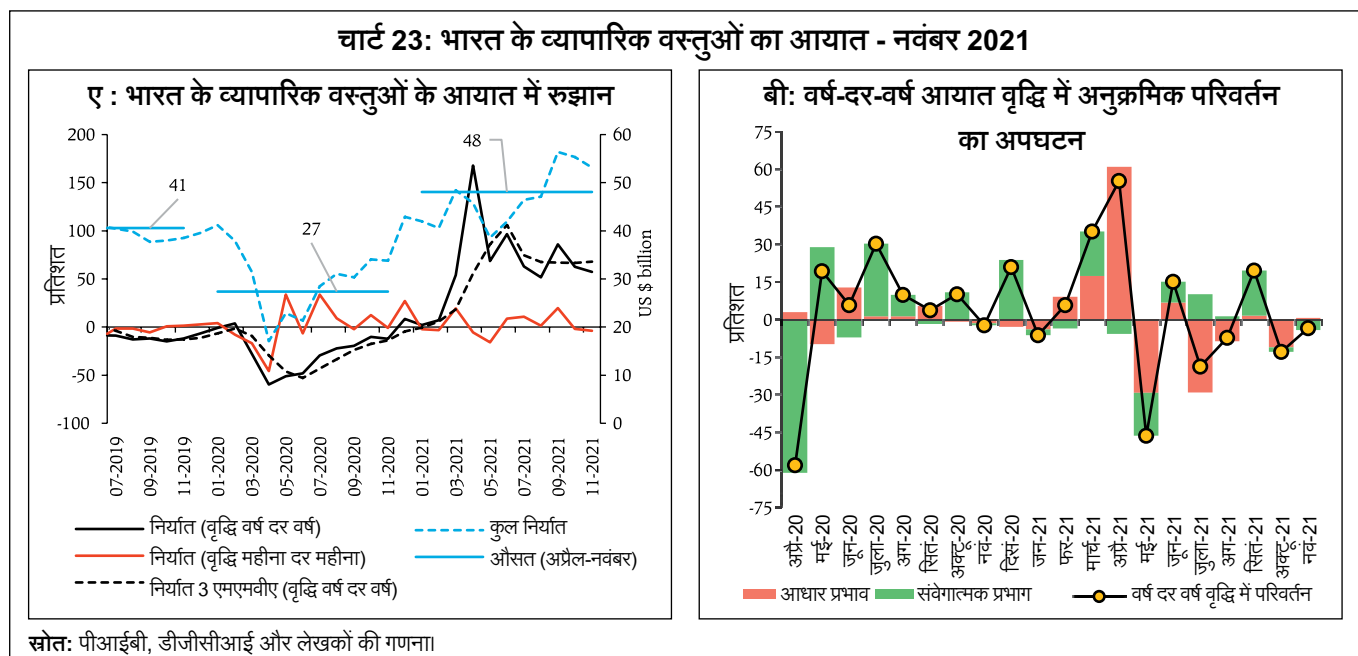
इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात नवंबर 2021 में लगातार नौवें महीने, 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर रहा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईईपीसी) को उम्मीद है कि कम लॉजिस्टिक लागत और बेहतर कारोबारी माहौल के माध्यम से लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि से इन निर्यातों को और बढ़ावा मिल सकता है।

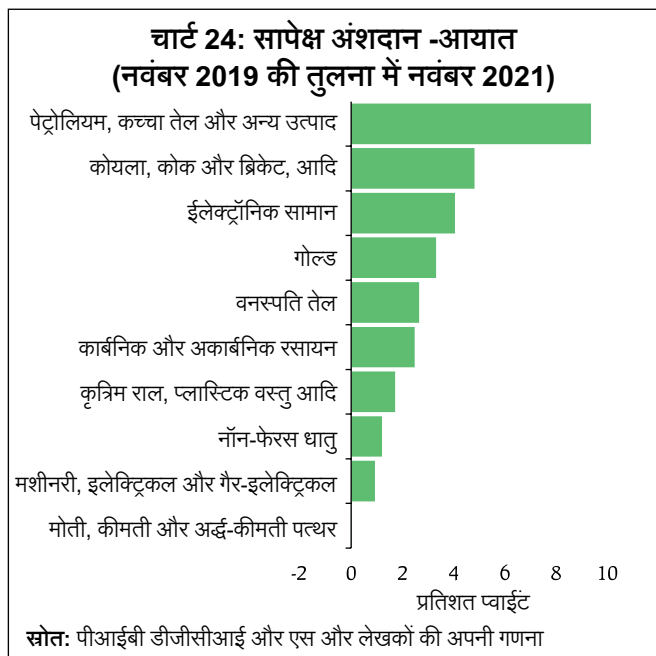
दुनिया भर में भारत, सस्ता और लाभकारी उपग्रह-प्रक्षेपण के लिए अंतरिक्ष केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्थापित बुनियादी ढांचे का लाभ उठाकर, निजी क्षेत्र की संस्थाएं प्रक्षेपक-वाहनों का उत्पादन कर सकती हैं और वाणिज्यिक प्रक्षेपण कार्यक्रमों को बढ़ावा दे सकती हैं ताकि भविष्य में अंतरिक्ष क्षेत्र में वृद्धि की संभावनाएँ प्रबल हों। सक्रिय, सार्वजनिक और निजी भागीदारी से अंतरिक्ष उद्योग के लिए प्रक्षेपक-वाहनों जैसे हार्डवेयर क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है।

घरेलू आर्थिक गतिविधि (चार्ट 23ए और 23बी) में मजबूत अंतर्निहित गति को दर्शाते हुए, भारत का माल आयात लगातार तीसरे महीने 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर से उपर रहा।

पेट्रोलियम उत्पादों, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और सोने की उच्च मांग से आयात मजबूत था (चार्ट 24)। इसके अलावा, 70 प्रतिशत से अधिक आयात वाले दस प्रमुख कमोडिटी समूहों में से नौ में वृहत्-मांग में वृद्धि के कारण महामारी पूर्व के स्तर की तुलना में विस्तार देखा गया।

कोयले, कोक और ब्रिकेट्स का आयात महामारी पूर्व के स्तर से दोगुने से अधिक हो गया और नवंबर के दौरान मजबूत गति प्राप्त हुई, जिससे थर्मल पावर प्लांटों के स्टॉक की स्थिति में



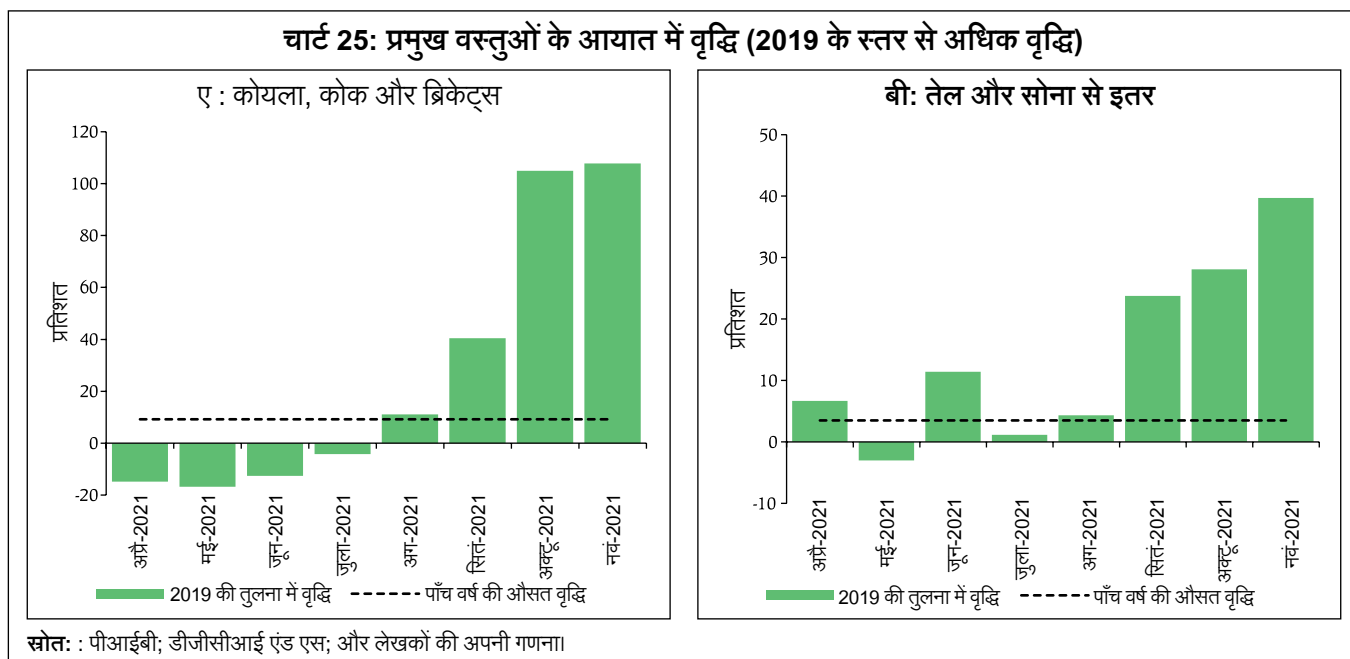


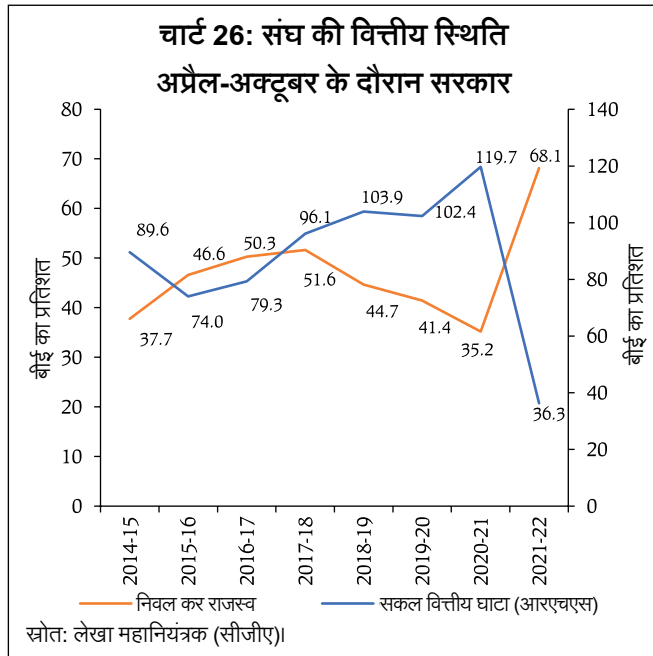
सुधार हुआ (चार्ट 25ए)। कुल मिलाकर, तेल और सोने से इतर आयात ने नवंबर में लगातार छठे महीने महामारी-पूर्व के स्तर (चार्ट 25 बी) की तुलना में मजबूत वृद्धि दिखाई। कोयले जैसे जीवाश्म स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए, फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एफएएमई जैसी योजनाओं के माध्यम से इलेक्ट्रिक

वाहनों के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दुर्लभ भू-तत्वों आरईई की मांग को बढ़ाएगा। निर्यात की तुलना में आयात में तेज विस्तार के कारण नवंबर 2021 के दौरान व्यापार घाटा 22.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा।

केंद्र सरकार की राजकोषीय स्थिति में सुधार जारी रहा, क्योंकि निवल कर राजस्व, बजट अनुमानों (बीई) के 68.1 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर के पास था और सकल राजकोषीय घाटा, अप्रैल -अक्टूबर (चार्ट 26) के दौरान बीई के अब तक के सबसे निचले स्तर 36.3 प्रतिशत दर्ज किया गया। व्यय के मोर्चे पर, पूंजीगत व्यय में 28.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि राजस्व व्यय में 2020-21 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय में सर्वाधिक वृद्धि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने की, जिन्होंने अपने बजटीय पूंजीगत व्यय का 68.2 प्रतिशत उपयोग किया। बीई के प्रतिशत के अनुसार, हालांकि, अप्रैल-अक्टूबर 2021 के दौरान राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों पूर्ववर्ती वर्षों के स्तर से नीचे रहे।

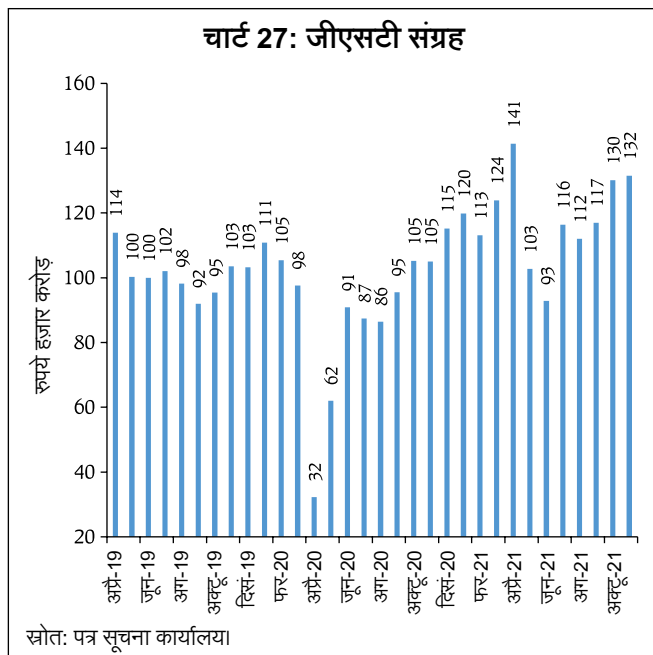
नवंबर में कुल जीएसटी उगाही में सालाना आधार पर 25.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो लगातार दूसरे महीने ₹1.3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर गया (चार्ट 27)। नवंबर में जीएसटी राजस्व





उगाही, जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरी सबसे बड़ी राजस्व उगाही थी।

3 दिसंबर, 2021 को, केंद्र सरकार ने संसद में अनुदान के लिए दूसरी पूरक मांग एसडीजी-2 का प्रस्ताव रखा, जिसमें ₹ 2.99 लाख करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल है। इसमें से ₹2.33 लाख करोड़, राजस्व व्यय के लिए है और ₹0.66 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए है (सारणी 2)⁷। पहले और दूसरे



**सारणी 2: एसडीजी द्वारा प्रस्तावित नकद व्यय
(03 दिसंबर, 2021)**

(राशि करोड़ में)

मंत्रालय/ विभाग	प्रयोजन	राजस्व	पूंजी	कुल
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	उर्वरक सब्सिडी	58,430		58,430
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	खाद्य सब्सिडी	49,805		49,805
नागरिक विमानन मंत्रालय	एयर इंडिया आदि में इक्विटी में लगाना	2,135	64,685	66,820
वित्त मंत्रालय	निर्यात प्रोत्साहन/छूट	53,123		53,123
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी	14,102		14,102
ग्रामीण विकास मंत्रालय	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	22,039		22,039
अन्य		33,774	1,150	34,924
कुल नकद व्यय		2,33,408	65,835	2,99,243

एसडीजी द्वारा प्रस्तावित कुल व्यय में वृद्धि ₹3.23 लाख करोड़ है, जो आंशिक रूप से बजटीय कर और गैर-कर राजस्व से अधिक होगी।

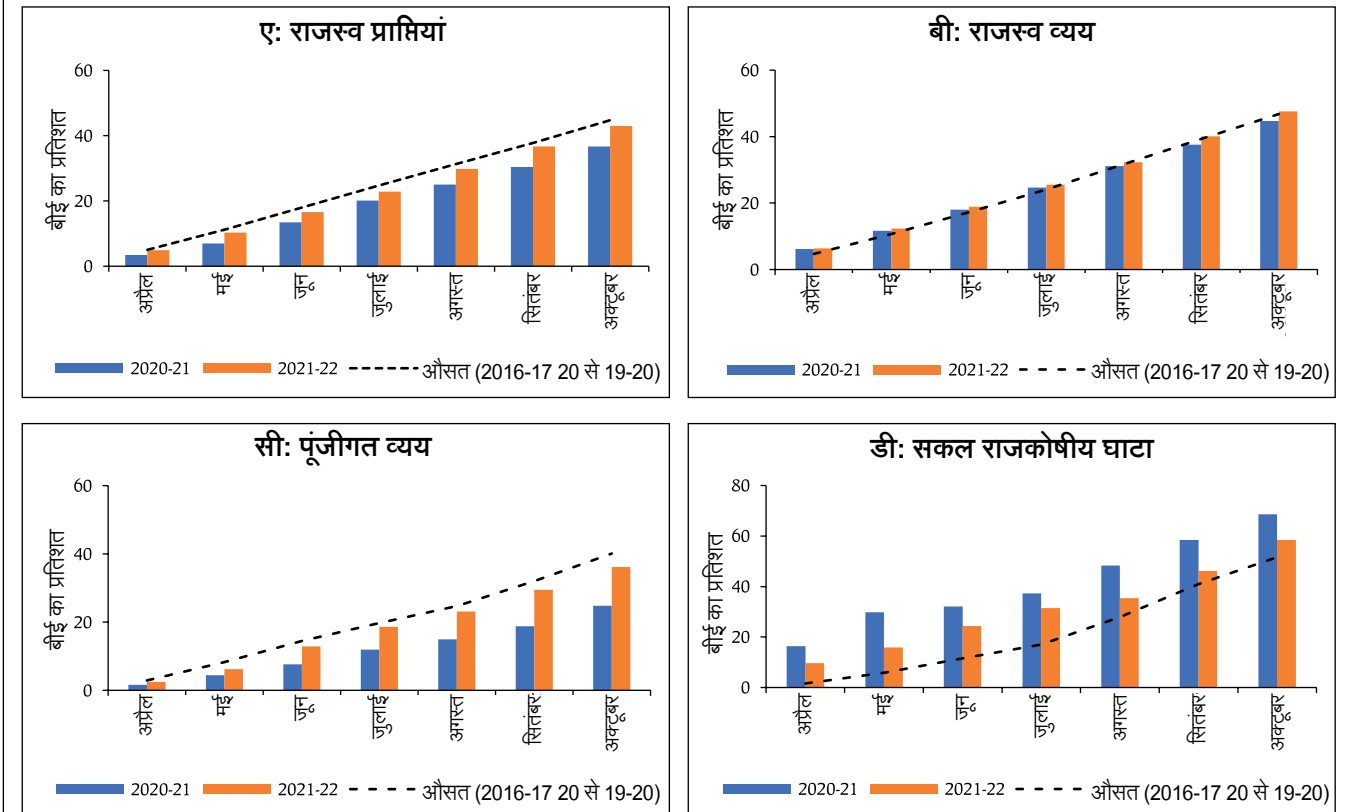
अप्रैल-अक्टूबर 2021 में, राज्यों के लिए बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में 2021-22 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय दोनों बड़े पैमाने पर पूर्व-महामारी के स्तर पर वापस आ गए हैं। नतीजतन, राजकोषीय दबाव कुछ हद तक कम हो गया है, जो शेष वर्ष की व्यय योजनाओं के लिए बिना अनुचित वित्तीय कमी या दबाव के कारण अच्छा है। इसके अलावा, नवंबर 2021 में राज्यों के संसाधनों को निवेश, इन्फ्रास्ट्रक्चर और वृद्धि को बढ़ाने के लिए कर हस्तांतरण की दो किस्तों⁸ को जारी करने के माध्यम से ₹47,541 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मिली।

आगे बढ़ते हुए, सामान्य सरकार (केंद्र के साथ 18 राज्यों) का राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और सब्सिडी से कम) नवंबर

⁷ यह अनुदान की अनुपूरक मांग (जुलाई 2021) के पहले बैच के अतिरिक्त है, जिसमें ₹23,675 करोड़ का निवल नकद व्यय शामिल था।

⁸ <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1774224>

चार्ट 28: राज्यों की राजकोषीय स्थिति



टिप्पणी: डेटा 18 राज्यों से संबंधित है, जो 2021-22बीई में सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का 68.5 प्रतिशत है।
स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी)

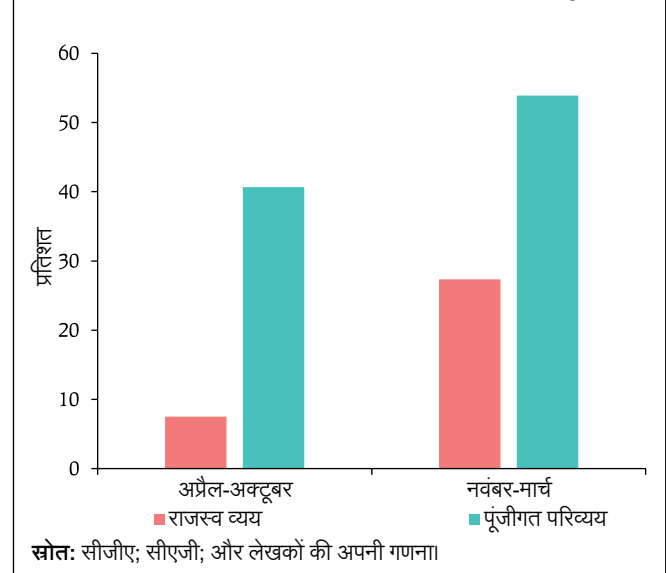
2021-22 के दौरान एसडीजी -2 में निहित व्यय प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए और राज्य अपने बजटीय लक्ष्यों को पूरा करेंगे ऐसा मानते हुए 27 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। इसी तरह, नवंबर-मार्च के दौरान पूंजीगत व्यय में 54 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है (चार्ट 29)। उच्च राजस्व व्यय वृद्धि, सरकार के अंतिम उपभोग व्यय का एक प्रतिनिधि, को आर्थिक सुधार का समर्थन करने की उम्मीद है, जबकि मजबूत पूंजीगत व्यय निजी निवेश बढ़ा सकता है और मध्यम अवधि की वृद्धि की संभावनाओं में सुधार कर सकता है।

कुल आपूर्ति

कृषि क्षेत्र की स्थिति मजबूत बनी हुई है और जलाशयों की ठीक ठाक स्थिति से पर्याप्त रूप से समर्थित है (चार्ट 30ए)। नवंबर में प्रमुख उर्वरकों की उपलब्धता आवश्यकता से अधिक थी (चार्ट 30बी)। रबी की बुवाई की प्रगति अच्छी तरह से चल रही है: 513.3 लाख हेक्टेयर में अब तक बोया गया रकबा एक साल

पहले की इसी अवधि की तुलना में 1.9 प्रतिशत अधिक है (चार्ट 30सी)। विशेष रूप से रेपसीड और सरसों की बुवाई, प्रमुख

चार्ट 29: 2021-22 में सामान्य सरकारी व्यय वृद्धि



रबी तिलहन, ने किसानों की बेहतर कीमत की उम्मीदों को दर्शाते हुए पूरे मौसम के सामान्य का 114.3 प्रतिशत कवरेज दर्ज किया है। इसके अलावा, देश के कई हिस्सों में अत्यधिक बेमौसम बारिश के कारण लगी हुई खरीफ फसलों की कटाई में देरी के कारण भी खाद्यान्न की कम बुवाई हो सकती है। मोटे अनाज को छोड़कर सभी प्रमुख फसल समूहों की बुवाई में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है।

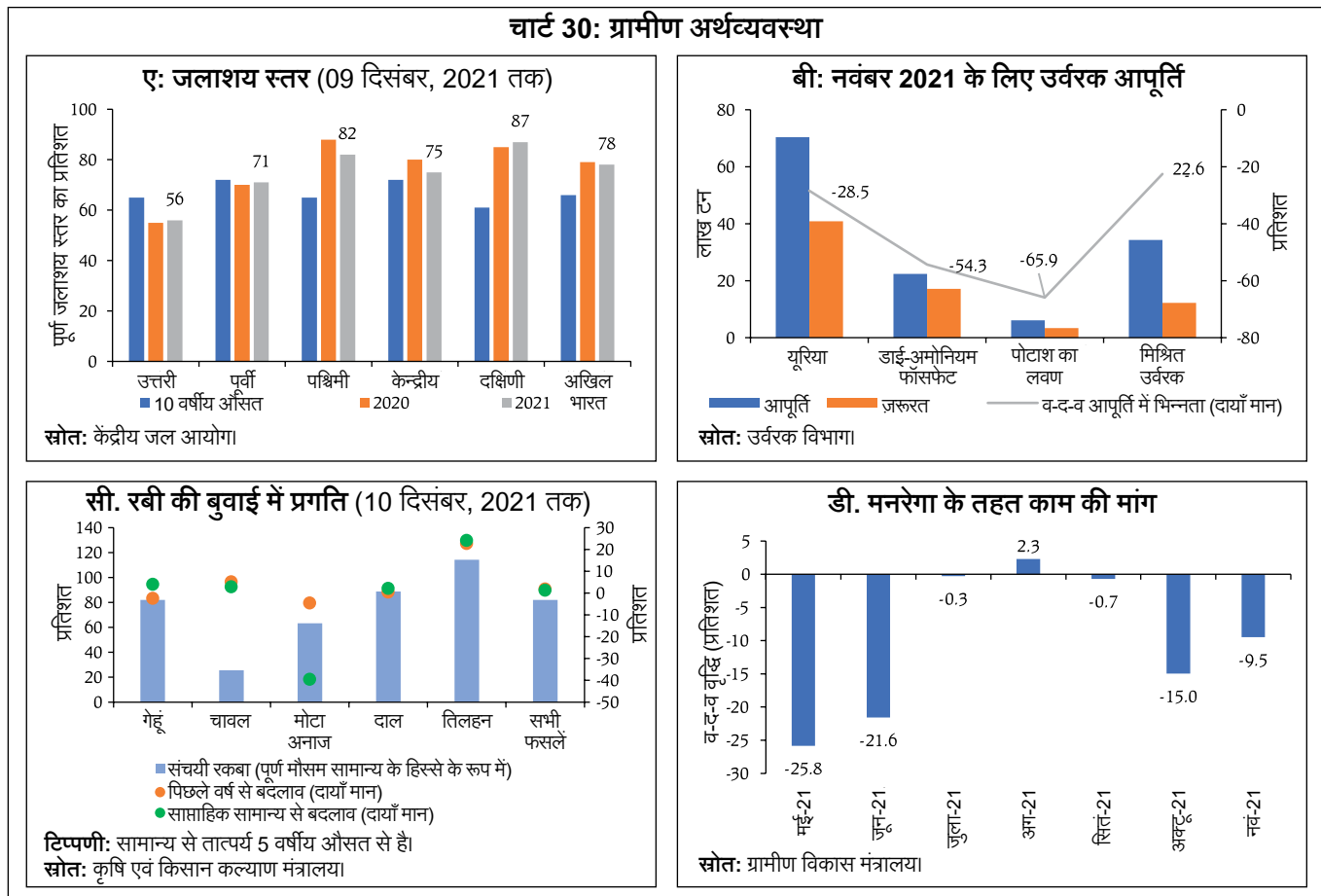
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत काम की मांग में कमी के लिए अधिक बुवाई गतिविधि का योगदान हो सकता है [चार्ट 30डी]।

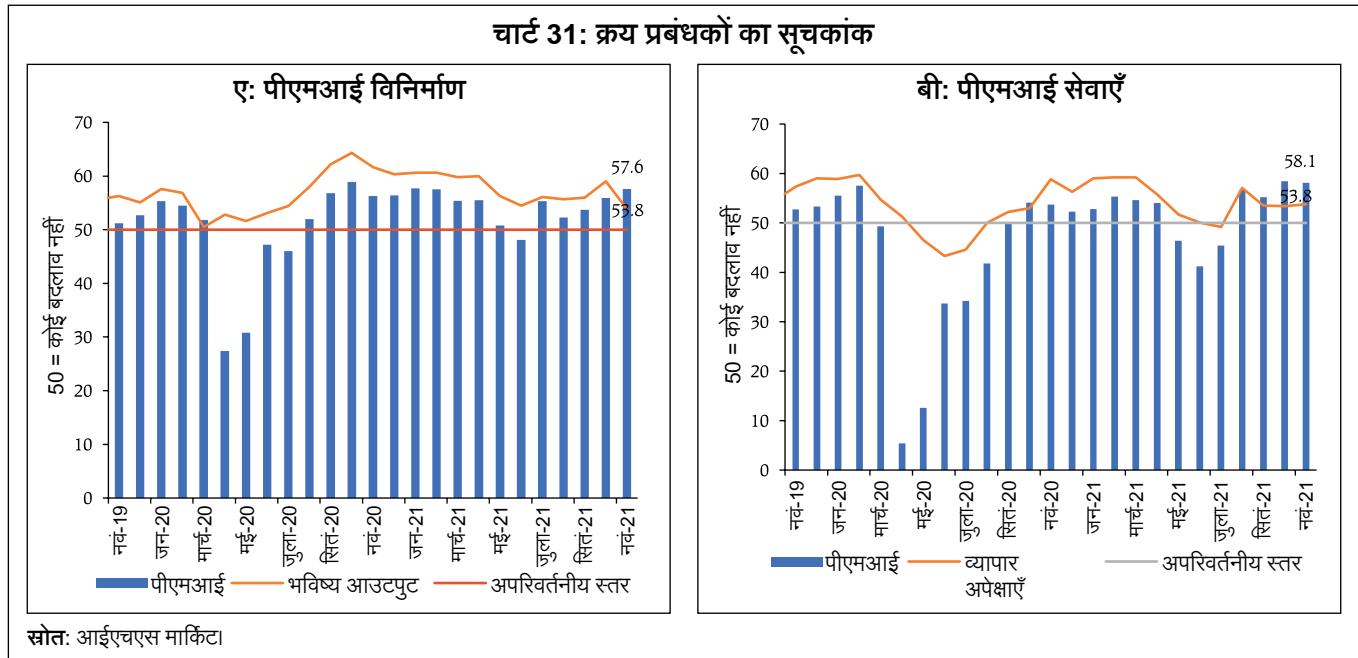
वर्तमान खरीफ विपणन सत्र (केएमएस) [01 अक्टूबर, 2021 से शुरू] के लिए धान की खरीद सुचारु रूप से आगे बढ़ी

है, 12 दिसंबर, 2021 तक 34.6 मिलियन टन से अधिक की खरीद हुई है, जबकि एक साल पहले यह 37.3 मिलियन टन थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) योजना के तहत चल रहे 67,825 करोड़ रुपये के केएमएस खरीद कार्यों से लगभग 2.9 मिलियन किसान लाभान्वित हुए हैं। नवंबर के अंत तक चावल और गेहूं का बफर स्टॉक तिमाही मानदंडों (क्रमशः 4.4 और 1.8 गुना) से काफी ऊपर था।

औद्योगिक क्षेत्र में, हेडलाइन विनिर्माण पीएमआई एक महीने पहले 55.9 से नवंबर में 57.6 हो गया, जो फरवरी 2021 के बाद से समग्र परिचालन स्थितियों में सबसे मजबूत पुनरुद्धार की ओर इशारा करता है। आउटपुट में सुधार और नए ऑर्डर ने फर्मों को उत्पादन बढ़ाने और अधिक इनपुट देने के लिए प्रेरित किया। नए ऑर्डर में वृद्धि के कारण पीएमआई सेवाओं का विस्तार 58.1 पर

चार्ट 30: ग्रामीण अर्थव्यवस्था





रहा। सेवाओं के लिए व्यापार अपेक्षा सूचकांक (बीईआई) में नवंबर में लगातार चौथे महीने विस्तार जारी रहा (चार्ट 31)।

व्यापार, होटल, परिवहन संचार और जीएसटी ई-वे बिल में सुधार के रूप में सेवा क्षेत्र ने मजबूत वृद्धि प्रदर्शित किया (सारणी 3)।

सारणी 3: उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाएं

उच्च आवृत्ति संकेतक- सेवाओं में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)		2019 में विकास									
		जुला-21	अग-21	सितं-21	अक्टू-21	नवं-21	जुला 21/ जुला 19	अग 21/ अग 19	सितं 21/ सितं 19	अक्टू 21/ अक्टू 20	नवं 21/नवं 19
शहरी मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	44.7	7.6	-41.2	-27.1	-18.6	39.1	22.8	-25.6	-16.7	-14.8
ग्रामीण मांग	दुपहिया वाहनों की बिक्री	-2.1	-14.6	-17.4	-24.9	-34.4	-17.1	-12.1	-7.7	-12.3	-25.5
	दुपहिया वाहनों की बिक्री ट्रैक्टर बिक्री	40.5 3.3	59.7 -17.0	53.8 -14.8	19.1 0.4	-6.6 -22.5	-67.9 43.1	-60.5 45.0	-56.0 9.3	-52.6 8.2	-59.7 17.2
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	24.5					0.6				
	रेलवे माल यातायात	18.4	16.9	3.6	8.4	6.1	13.0	21.5	19.7	25.1	15.6
	पोर्ट कार्गो यातायात	6.7	11.5	0.5	6.3	-0.2	-7.2	-0.1	-1.4	5.3	2.7
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	41.3	35.7	10.1	6.7		-17.2	-13.1	-11.8	-10.0	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	31.5	25.8	18.1	23.8		-8.0	-5.5	2.0	8.4	
	अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	140.7	132.6	76.5	68.7		-58.1	-43.8	-38.4	-27.0	
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	45.9	119.2	155.9	162.9		-86.1	-77.5	-68.9	-61.0	
	जीएसटी ई-वे बिल (आंतर-राज्यीय)	32.7	33.3	18.3	14.5	5.9	23.0	28.6	29.6	39.0	14.5
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर राज्यीय)	31.6	30.8	15.6	14.1	7.3	26.5	32.7	33.0	40.7	17.6
पर्यटकों का आगमन	34.4	37.2	22.3	15.1	3.9	17.9	22.9	25.0	36.7	10.1	
निर्माण	इस्पात खपत	4.2	-2.2	-3.2	-6.8	-8.0	-6.6	-13.3	-3.1	-0.9	9.0
	सीमेंट उत्पादन	21.7	36.4	11.3	14.6		5.3	16.6	7.5	18.3	
पीएमआई सूचकांक	विनिर्माण	55.3	52.3	53.7	55.9	57.6					
	सेवाएं	45.4	56.7	55.2	58.4	58.1					

स्रोत: सीएमआईई; सीईआईसी डेटा; आईएचएस मार्किट; सियाम; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और संयुक्त संयंत्र समिति।

मुद्रास्फीति

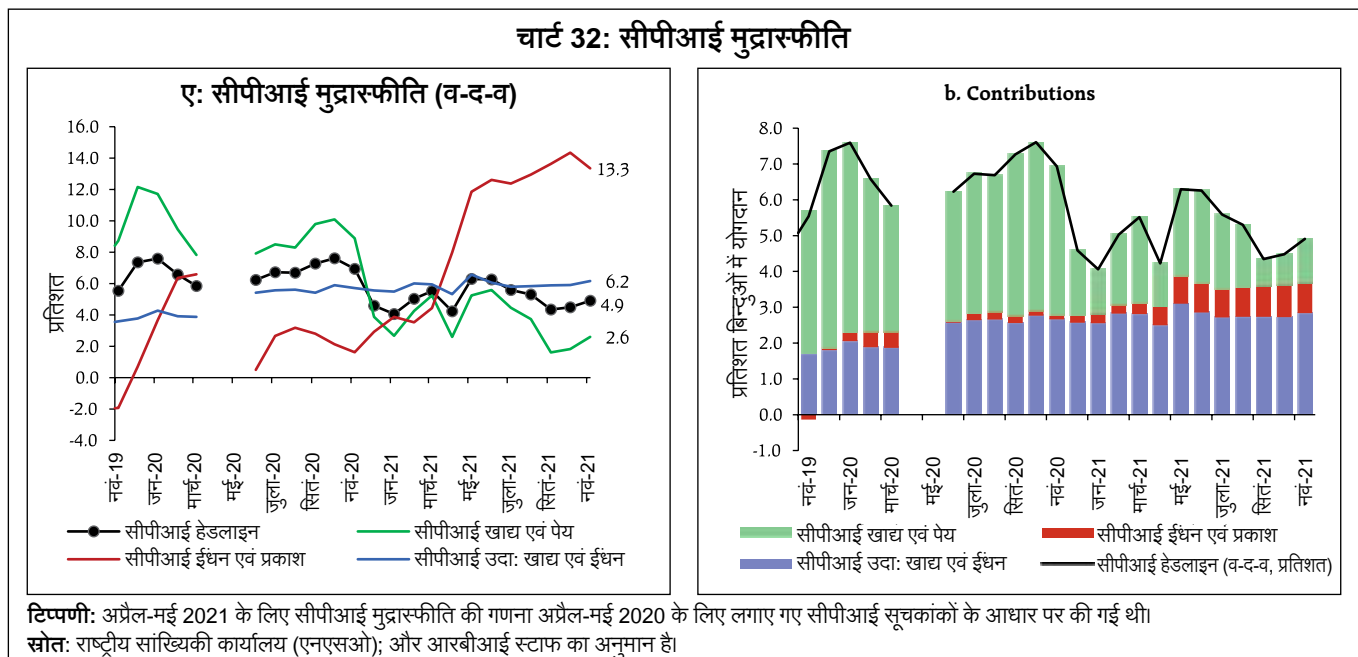
एनएसओ द्वारा 13 दिसंबर, 2021 को जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2021 के महीने के लिए हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति 4.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) थी, जो अक्टूबर के महीने में 4.5 प्रतिशत से 43 बीपीएस की वृद्धि दर्ज कर रही थी (चार्ट 32 ए)। लगभग 70 बीपीएस की मूल्य गति (चालू महीने में कीमतों में मासिक परिवर्तन) लगभग 30 बीपीएस के अनुकूल आधार प्रभावों से आंशिक रूप से प्रति संतुलित थी।

घटकों में, खाद्य और पेय पदार्थ मुद्रास्फीति नवंबर में बढ़कर 2.6 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर में 1.8 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से सब्जियों की कीमतों में निरंतर वृद्धि से प्रेरित थी। अनाज, दूध, फल और चीनी और कन्फेक्शनरी ने भी खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान दिया। दूसरी ओर, खाद्य-तेल, मांस और मछली, दालें, गैर-मादक पेय, तैयार भोजन और मसालों के संबंध में मुद्रास्फीति में नरमी दर्ज की गई। सीपीआई खाद्य (सीपीआई बास्केट में 45.86 प्रतिशत के भार के साथ) ने नवंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 25 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 32 बी)।

ईंधन मुद्रास्फीति अक्टूबर में 14.3 प्रतिशत (2012=100 आधार वर्ष श्रृंखला में) के सर्वकालिक उच्च स्तर से कम होकर नवंबर में 13.3 प्रतिशत हो गई (चार्ट 32ए), मुख्य रूप से बिजली की कीमतें एलपीजी और मिट्टी के तेल के रूप में भी अपस्फीति में होने के कारण कीमतें अत्यधिक ऊंचे स्तर पर बनी रहीं। सीपीआई ईंधन (सीपीआई बास्केट में 6.84 प्रतिशत का भार) ने नवंबर में हेडलाइन मुद्रास्फीति में 17 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट 32बी)।

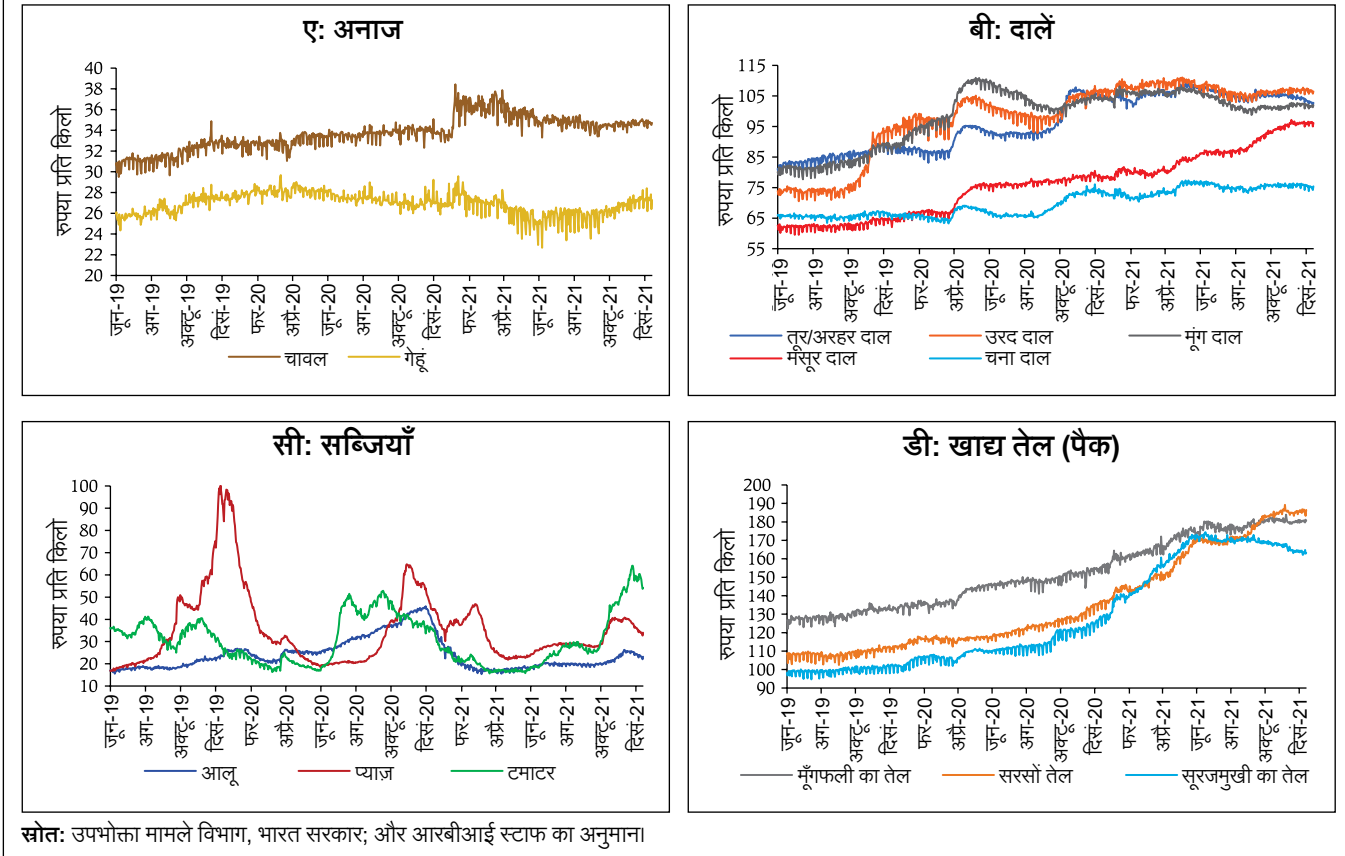
कपड़ों और जूतों, घरेलू सामानों और सेवाओं, खेलकूद और मनोरंजन, , आवास, और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव उप-समूह में मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण खाद्य और ईंधन⁹ या कोर मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति अक्टूबर में 5.9 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर में 6.2 प्रतिशत हो गई (चार्ट 32ए)। परिवहन और संचार और स्वास्थ्य उप-समूहों में मुद्रास्फीति ऊंची बनी रही।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) से अब तक (दिसंबर 1-13, 2021) के लिए उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य डेटा कीमतों के दबाव में कुछ



⁹ हेडलाइन सीपीआई से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाने से खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना की जाती है।

चार्ट 33: डीसीए आवश्यक वस्तु मूल्य



नरमी की ओर इशारा करते हैं। अनाज की कीमतों की गति धीमी होती दिख रही है। दालों की कीमतों में भी कुछ नरमी दर्ज की गई है। खाद्य तेलों के तहत मूँगफली तेल और सरसों तेल की कीमतें स्थिर रहीं और सूरजमुखी तेल की कीमतों में और गिरावट आई। प्रमुख सब्जियों में, दिसंबर में अब तक टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में नवंबर के अंत के स्तर से गिरावट दर्ज की गई है (चार्ट 33)।

मूल्य वर्धित कर (वैट) दर में कटौती के कारण 2 दिसंबर, 2021 को नई दिल्ली में पेट्रोल पंप की कीमतों में ₹8.56 प्रति लीटर की कमी को छोड़कर, दिसंबर के पहले अर्धांश में चार प्रमुख महानगरों में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतें काफी सीमा तक अपरिवर्तित रहीं। एलपीजी की कीमतें अक्टूबर 2021 से स्थिर बनी हुई हैं जबकि मिट्टी के तेल की कीमतों में दिसंबर के पहले अर्धांश में गिरावट दर्ज की गई (सारणी 4)।

इनपुट लागत दबाव, जैसा कि पीएमआई में परिलक्षित होता है, नवंबर में सभी विनिर्माण और सेवाओं में बना रहा। बिक्री लागत

वृद्धि विनिर्माण क्षेत्र में मौन रही, जबकि सेवा क्षेत्र में पंजीकृत कीमत दीर्घावधि औसत से अधिक बढ़ गयी।

सारणी 4: पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतें

मद	Unit	घरेलू कीमतें			माह-दर- माह (प्रतिशत)	
		दिसं-20	नव-21	दिसं-21 [^]	नव-21	दिसं-21
पेट्रोल	₹/लीटर	86.27	105.57	103.03	-0.7	-2.4
डीजल	₹/लीटर	77.59	91.69	90.51	-6.4	-1.3
केरोसिन (सब्सिडि सहित)	₹/लीटर	23.21	39.51	38.68	14.3	-2.1
एलपीजी (गैर सब्सिडि)	₹/सिलेंडर	704.63*	910.13	910.13	0.0	0.0

*: 15 दिसंबर, 2020 तक। [^]: 1-13 दिसंबर, 2021 की अवधि के लिए।

टिप्पणी: मिट्टी के तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) के इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिट्टी के तेल के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में रियायती मूल्य के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

IV. वित्तीय स्थितियां

रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर, 2021 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में विभिन्न चलनिधि संबंधी उपायों की घोषणा की। 14-दिवसीय परिवर्तनीय दर रिवर्स रिपो (वीआरआरआर) नीलामियों के तहत अवशोषित राशि 17 दिसंबर को बढ़कर 6.5 लाख करोड़ रुपये हो गई; और 31 दिसंबर को ₹7.5 लाख करोड़ तक चली गई। जनवरी 2022 से, चलनिधि अवशोषण मुख्य रूप से नीलामी मार्ग के माध्यम से किया जाएगा। चलनिधि अधिशेष के इस पुनर्संतुलन को निर्धारित दर ओवरनाइट रिवर्स रिपो विंडो से वीआरआरआर नीलामियों में पुनर्संतुलित करने के साथ, 14-दिवसीय वीआरआरआर नीलामी को मुख्य चलनिधि प्रबंधन साधन के रूप में फिर से स्थापित करने की मांग की गई है। चलनिधि अधिशेष को पुनर्संतुलित करने की दिशा में एक कदम के रूप में, अब यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को 27 मार्च और 17 अप्रैल, 2020 को घोषित लक्षित दीर्घकालिक रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ 1.0 और 2.0) के तहत प्राप्त बकाया राशि का पूर्व भुगतान करने का एक और विकल्प प्रदान किया जाए।

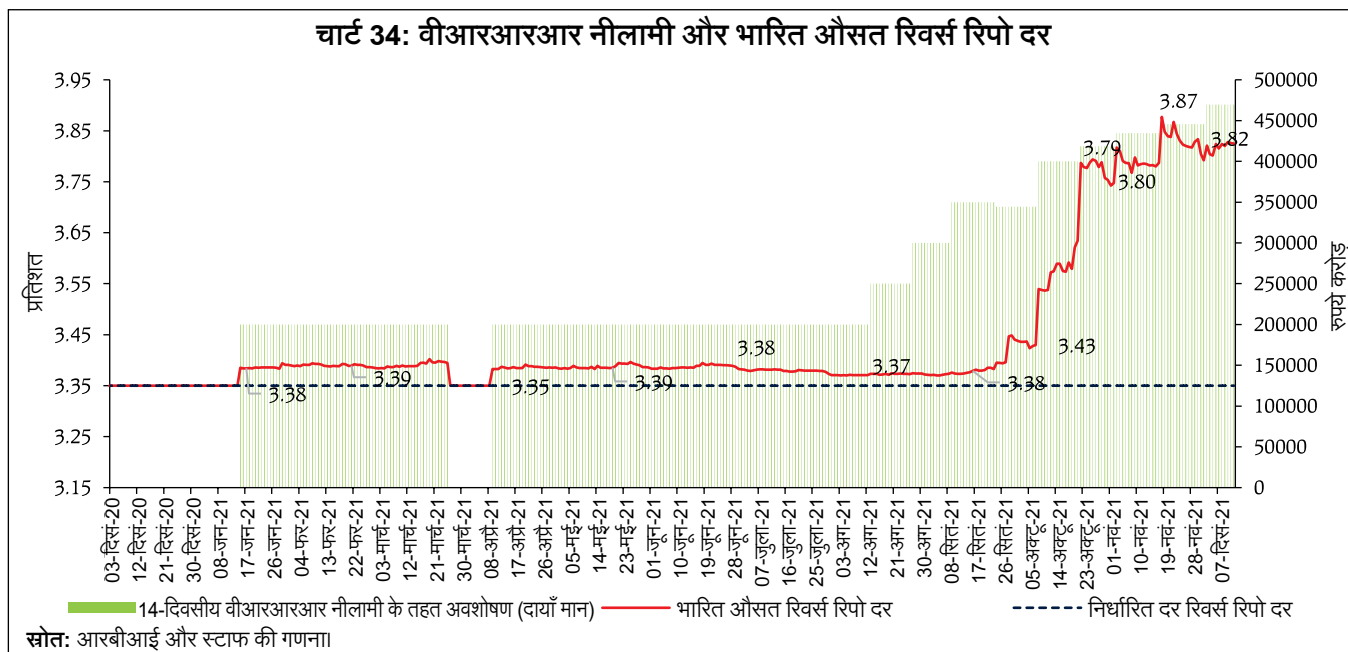
इसके अलावा, यह देखते हुए कि बैंकों ने अधिशेष चलनिधि की स्थिति के कारण महामारी के बाद की अवधि में सीमांत स्थायी

सुविधा (एमएसएफ) विंडो का सीमित सहारा लिया, बैंकों को उनकी निवल मांग और मियादी देयताओं के 2 प्रतिशत तक गिरने की अनुमति देने की सामान्य व्यवस्था (एनडीटीएल) को 1 जनवरी, 2022 से एमएसएफ के तहत रातोंरात उधार लेने के लिए (3 प्रतिशत के बजाय) बहाल कर दिया गया है।

कुल मिलाकर वित्तीय स्थितियां अच्छी बनी रहीं क्योंकि प्रणाली में चलनिधि की बाढ़ आ गई थी। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक अवशोषण नवंबर की दूसरी छमाही में ₹8.5 लाख करोड़ से बढ़कर दिसंबर 2021 के दौरान अब तक (13 दिसंबर तक) ₹9.5 लाख करोड़ हो गया। इसमें से निर्धारित दर रिवर्स रिपो के तहत अवशोषित राशि में औसतन 2.0 लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। नीलामियों के तहत कट ऑफ दरें 3.99 प्रतिशत तक पहुंच गई हैं, जिससे एलएएफ के तहत कुल अवशोषण की भारत औसत दर 3.82 प्रतिशत हो गई है (चार्ट 34)।

ओवरनाइट मुद्रा बाजार वाले भाग में दरें - भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर), त्रिपक्षीय रिपो दर और बाजार रिपो दर - संक्षिप्त अवधि के लिए सख्त होने के बाद, कॉरिडोर की निम्नतम सीमा की ओर बढ़ी। त्रिपक्षीय रिपो ओवरनाइट गतिविधि

चार्ट 34: वीआरआरआर नीलामी और भारत औसत रिवर्स रिपो दर



वाले भाग में हावी रहा, जो नवंबर में कुल मुद्रा बाजार की मात्रा का लगभग 75 प्रतिशत था।

हॉकिश फेड नीति कार्यवृत्त द्वारा प्रबलित अक्टूबर नीति के समय से ही, अवधि वाले भाग में जैसे, 3-महीने का टी-बिल, जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र - एनबीएफसी (सीपी-एनबीएफसी) में दरें अधिक रहीं और थोड़े से वक्र में पुनर्मूल्यांकित मौद्रिक नीति अपेक्षाओं को दर्शाती हैं। नवंबर के उत्तरार्ध और दिसंबर की शुरुआत तक रिवर्स रिपो दर पर उनके संबंधित स्प्रेड क्रमशः 16 बीपीएस, 19 बीपीएस और 69 बीपीएस थे (चार्ट 35)।

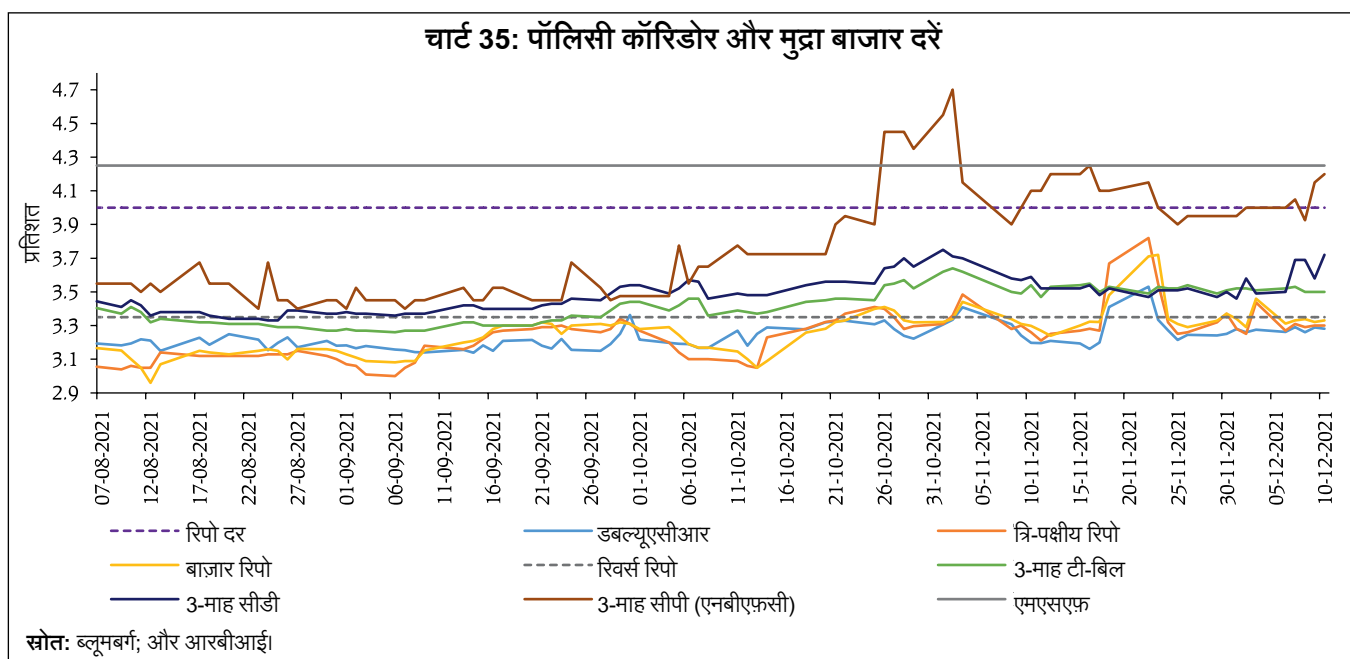
सीपी बाजार में प्राथमिक निर्गम नवंबर में 2.9 लाख करोड़ रुपये पर रहा, जबकि अक्टूबर 2021 में यह 1.1 लाख करोड़ रुपये था।

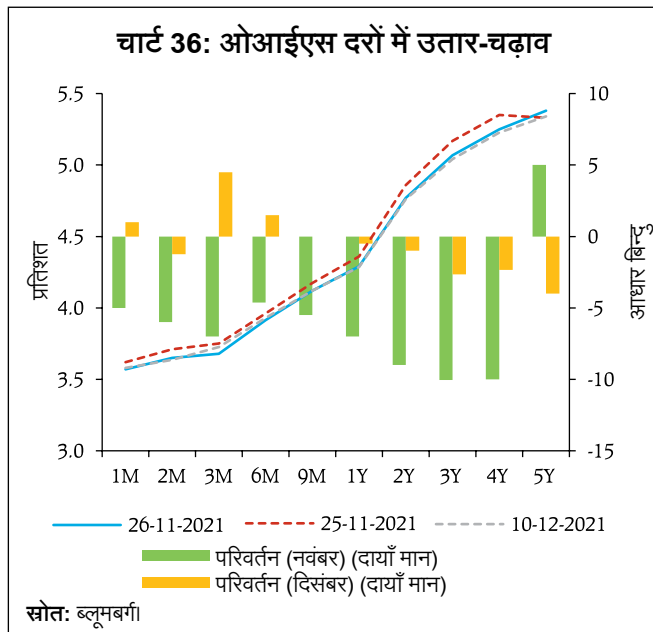
ओवरनाइट सूचकांकित स्वैप (ओआईएस) दरों ने 26 नवंबर को पूरे वक्र में बहुत बड़े पैमाने पर गिरावट दर्ज की, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट के उभरने की रिपोर्ट की वजह से जोखिम की भावना ने बाजारों को जकड़ लिया। गिरावट 5-वर्षीय ओआईएस दर के कारण हुई, जो 5.38 प्रतिशत पर बंद हुई, जबकि 1 वर्षीय ओआईएस दर 26 नवंबर, 2021 को 4.29 प्रतिशत पर बंद हुई।

इसके बाद आम तौर पर 3 महीने और 6 महीने की दरें मामूली सख्त होने के साथ गिरावट जारी रही (चार्ट 36)।

वक्र के छोटे छोर पर, जी-सेक प्रतिफल ने एक सख्त पूर्वाग्रह प्रदर्शित किया, जबकि लंबी परिपक्वता के प्रतिफल में आम तौर पर गिरावट आई (चार्ट 37 ए), जिससे प्रतिफल वक्र समतल हो गया। 10-साल वाले सरकारी प्रतिभूति के प्रतिफल 7 दिसंबर को सख्त होकर 6.39 फीसदी पर बंद हुए, जो पहले 6.37 फीसदी थे। जी-सेक प्रतिफल को प्रतिबिंबित करते हुए, कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिफल छोटी अवधि के लिए बहुत सख्त हो गए - नवंबर 2021 की दूसरी छमाही और दिसंबर की शुरुआत के दौरान एए रेटेड 1 साल और 3 साल के बॉन्ड पर क्रमशः 15 बीपीएस और 26 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट 37 बी)।

समग्र मौद्रिक और ऋण स्थितियां सामान्य हो रही समष्टि आर्थिक स्थितियों के अनुरूप बनी रहीं। 3 दिसंबर, 2021 (एक साल पहले 19.3 प्रतिशत) के अनुसार नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) बहाली के पहले दौर के प्रभाव को छोड़कर आरक्षित धन (आरएम) में 7.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) का विस्तार हुआ, जिसमें मुद्रा प्रचलन में इसका सबसे बड़ा घटक थी जो समान गति

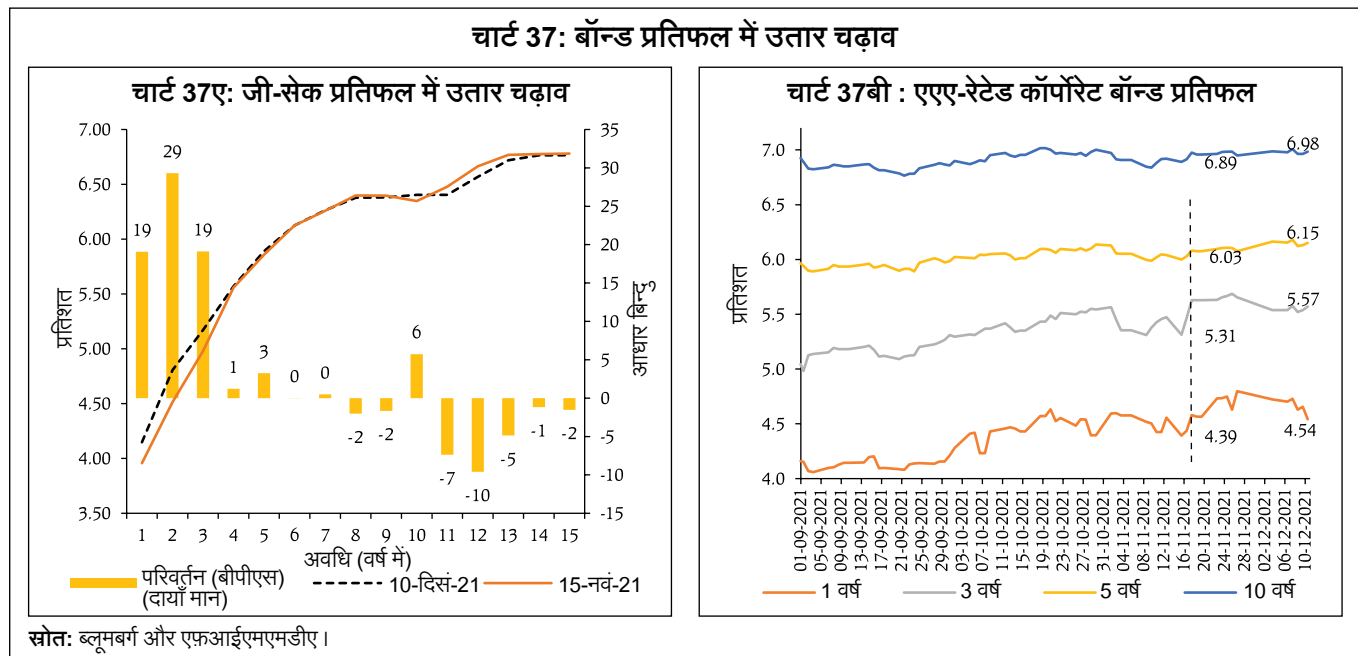


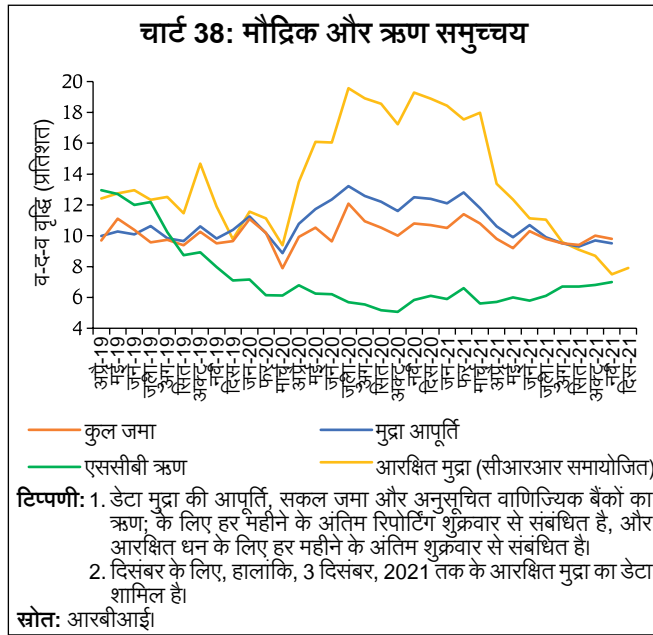


मजबूत जमा वृद्धि के कारण थी। 19 नवंबर, 2021 तक वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के ऋण में वृद्धि 7.0 प्रतिशत (एक साल पहले 5.8 प्रतिशत) तक बढ़ गई।

बड़ी अधिशेष चलनिधि ऋण बाजार में मौद्रिक संचरण के लिए अभी भी जिम्मेदार है। मार्च 2020 से नवंबर 2021 तक एससीबी की फंड-आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की एक वर्षीय औसत सीमांत लागत में संचयी रूप से 105 बीपीएस की कमी आई। बैंक समूहों में, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों ने 1 साल के एमसीएलआर के संबंध में समान प्रभाव अंतरण का प्रदर्शन किया। इसी अवधि के दौरान ताजा जमाराशियों पर औसत सावधि जमा दर में 154 बीपीएस की गिरावट आई है। निधियों की समग्र लागत में कमी ने एससीबी को बकाया रुपया उधारों पर अपनी भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) को कम करने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा, कुल बकाया अस्थायी दर ऋणों में बाह्य मानदंड आधारित ऋणों की हिस्सेदारी मार्च 2020 में 9.4 प्रतिशत से बढ़कर जून 2021 में 32 प्रतिशत हो गई, जिसने बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर के मामले में तेजी से

से बढ़ रही है (एक साल पहले 21.9 प्रतिशत) और नकदी रखने की प्रवृत्ति में पर्याप्त गिरावट आई (चार्ट 38)। दूसरी ओर, मुद्रा आपूर्ति (एम3) 19 नवंबर, 2021 (एक साल पहले 12.5 प्रतिशत) की स्थिति में 9.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो 9.8 प्रतिशत की



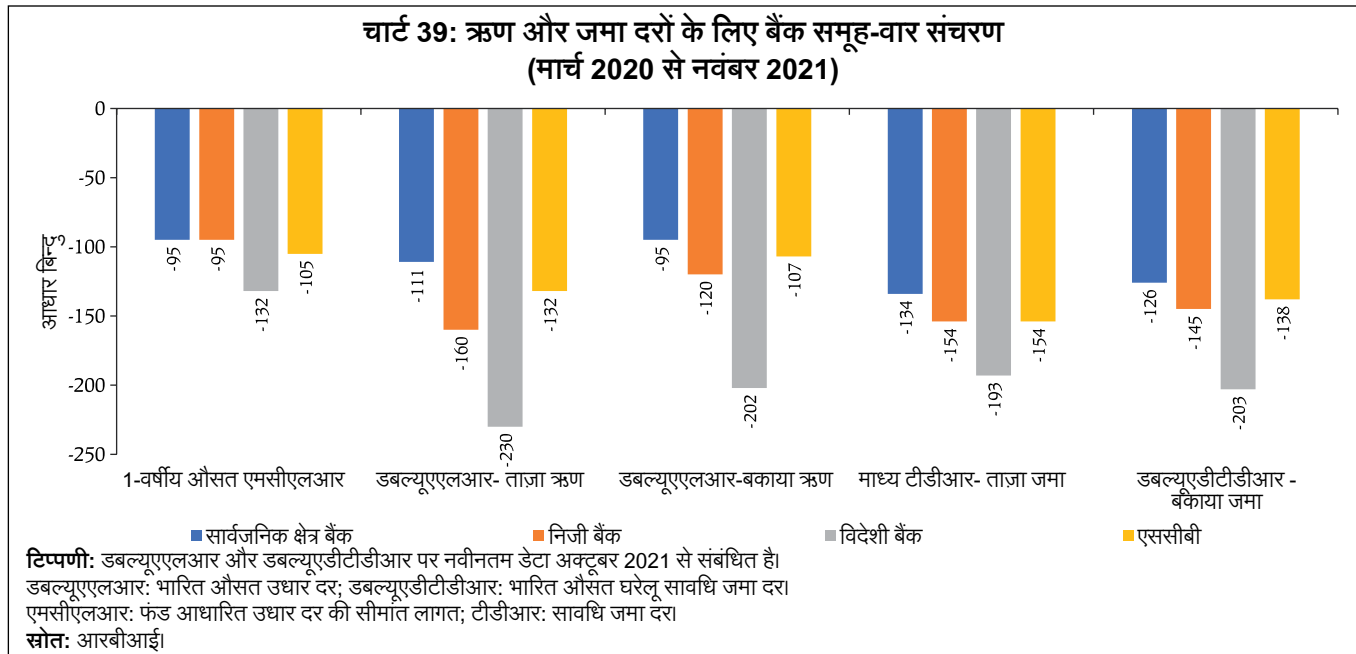


सभी अवधियों के लिए मियादी जमा दरों में कमी रही है, जिसमें अधिकतम प्रभाव अंतरण 1 वर्ष की परिपक्वता (181 बीपीएस) तक की छोटी अवधि की जमाराशियों के लिए दिखाई दे रहा है और सबसे कम 3 वर्ष (107 बीपीएस) से अधिक की परिपक्वता की लंबी अवधि की जमाराशियों के लिए दिखाई दे रहा है। घरेलू बैंकों में, निजी बैंक अपने सार्वजनिक क्षेत्र के समकक्षों की तुलना में मजबूत जमा जुटाने के कारण सावधि जमा दरों के लिए अधिक प्रभाव अंतरण प्रदर्शित करते हैं (चार्ट 40)।

31 दिसंबर, 2021 को लघु बचत लिखतों (एसएसआई) पर ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी जो अपेक्षित फॉर्मूला-आधारित दरों से अधिक हैं। 2021-22 की चौथी तिमाही में एसएसआई के लिए मौजूदा ब्याज दरें फॉर्मूला-आधारित दरों की तुलना में 42-168 बीपीएस अधिक थीं।¹¹

संचरण में योगदान दिया¹⁰। मार्च 2020 से, एससीबी के लिए बकाया ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में 107 बीपीएस की गिरावट आई है (चार्ट 39)।

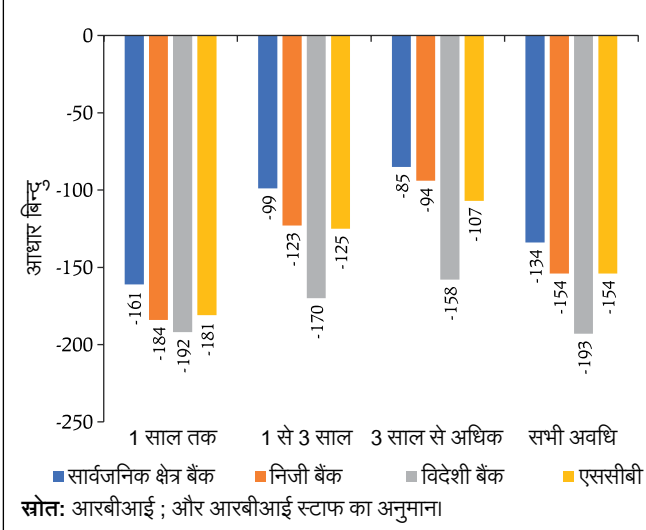
सकारात्मक समष्टिआर्थिक डेटा जारी होने के बाद, इक्विटी बाजारों ने सकारात्मक नोट पर नवंबर 2021 की शुरुआत की (चार्ट 41)। ओमिक्रॉन की वजह से महीने के अंत में गिरावट में



¹⁰ मौद्रिक नीति रिपोर्ट, आरबीआई, अक्टूबर 2021।

¹¹ लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें भारत सरकार द्वारा प्रशासित और निर्धारित की जाती हैं। ये प्रशासित ब्याज दरें एक अंतराल के साथ सरकारी प्रतिभूतियों पर बाजार प्रतिफल से जुड़ी होती हैं और तुलनीय परिपक्वता वाले जी-सेक प्रतिफल के ऊपर 0-100 बीपीएस के स्प्रेड पर तिमाही आधार पर तय की जाती हैं।

चार्ट 40: माध्य सावधि जमा दर में परिपक्वता-वार संचरण
(मार्च 2020 से नवंबर 2021)



तीव्रता आयी। नवंबर 2021 के दौरान कुल मिलाकर बीएसई सेंसेक्स में 3.8 फीसदी की गिरावट आई।

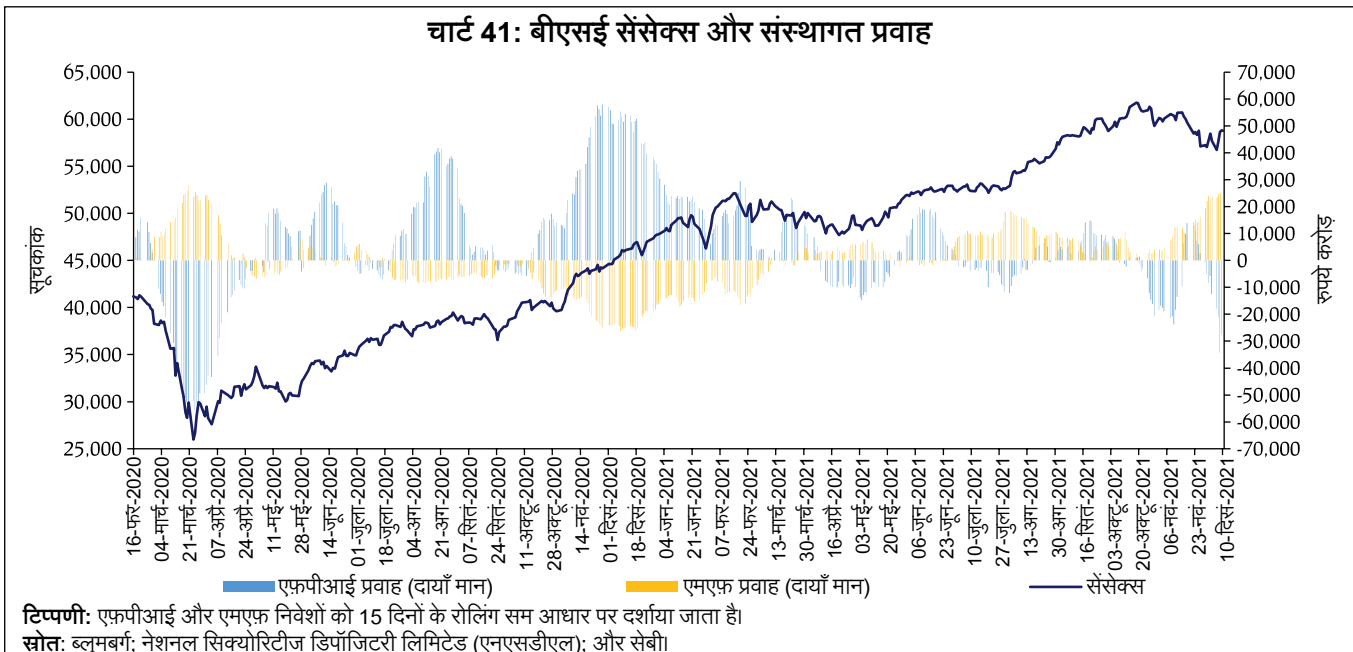
दिसंबर 2021 के महीने में (10 दिसंबर तक), बीएसई सेंसेक्स 3 प्रतिशत उछला क्योंकि निवेशकों ने 2021-22 की

दूसरी तिमाही के मजबूत जीडीपी डेटा, मजबूत जीएसटी संग्रह और नवंबर 2021 के लिए विनिर्माण विस्तार और सेवाओं पीएमआई से संकेत लिया। रिजर्व बैंक की नीति रिपो दर को अपरिवर्तित रखने और 2021-22 के लिए अपने पांचवें द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य में समायोजनात्मक रुख के साथ जारी रखने की घोषणा के साथ युग्मित वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेतों से बाजार की धारणा भी उत्साहित थी।

इस बार फेड द्वारा की गई घोषणा की तुलना 2013 में इस तरह के पिछले प्रकरण के साथ करने से पता चलता है कि ईएमई में इक्विटी, बॉन्ड और मुद्रा बाजारों ने 2013 की तुलना में अब तक अधिक आघातसहनीयता प्रदर्शित किया है (चार्ट 42ए, 42बी और 42सी)।

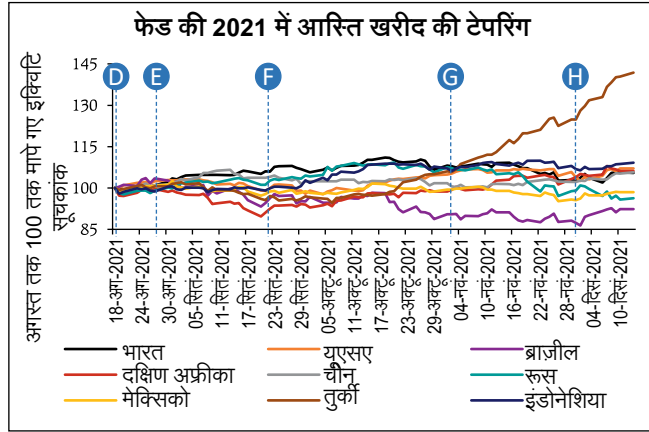
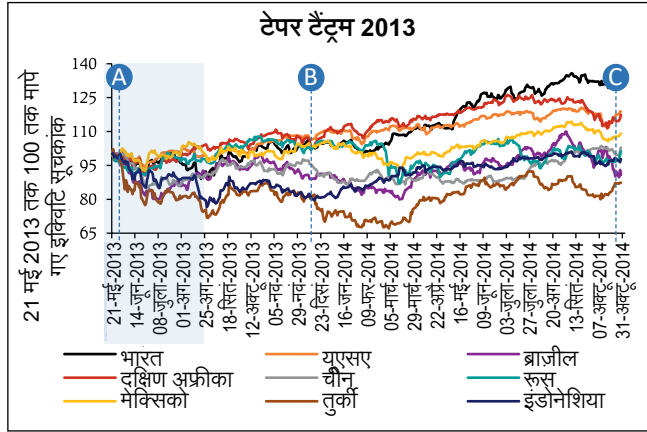
इसके अलावा, 2013 में टेंपर टेंट्रम के तत्काल बाद में, भारत ने 23 मई-अगस्त 30, 2013 के दौरान पूंजी बाजारों से कुल मिलाकर ₹79,375 करोड़ का पोर्टफोलियो बहिर्वाह का अनुभव किया, जिसमें इक्विटी बाजारों से ₹19,165 करोड़ और ऋण बाजारों से ₹60,210 करोड़ शामिल हैं (चार्ट 43)। फेड द्वारा 3 नवंबर, 2021 को आरिस्टि खरीद में कमी की नवीनतम घोषणा

चार्ट 41: बीएसई सेंसेक्स और संस्थागत प्रवाह

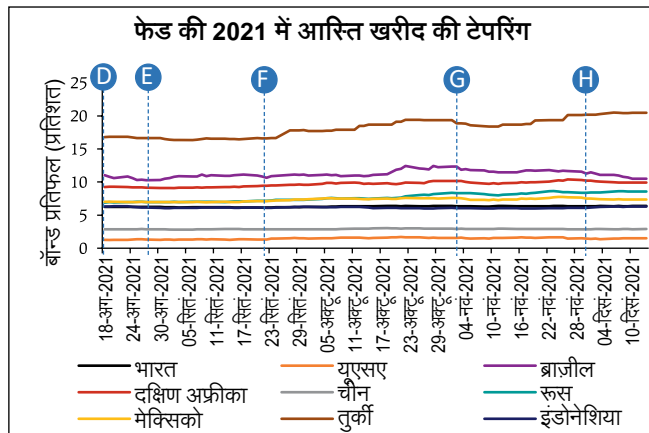
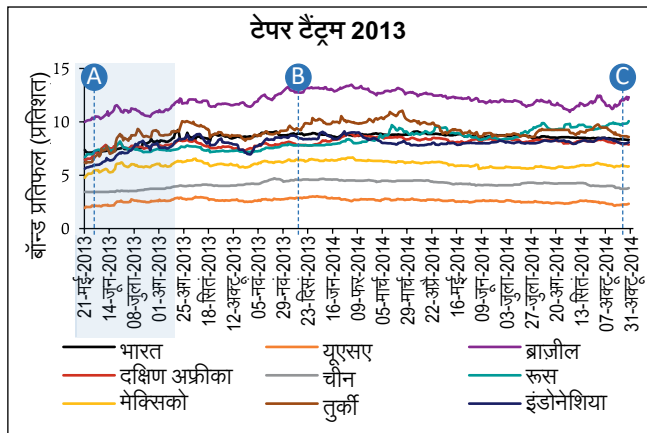


चार्ट 42: वित्तीय बाजारों पर टेपरिंग का प्रभाव

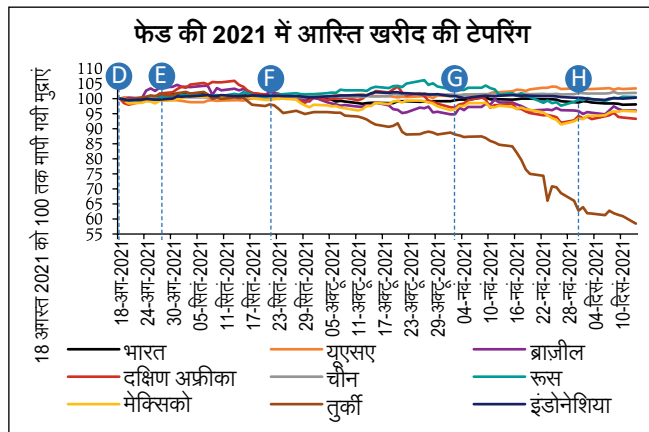
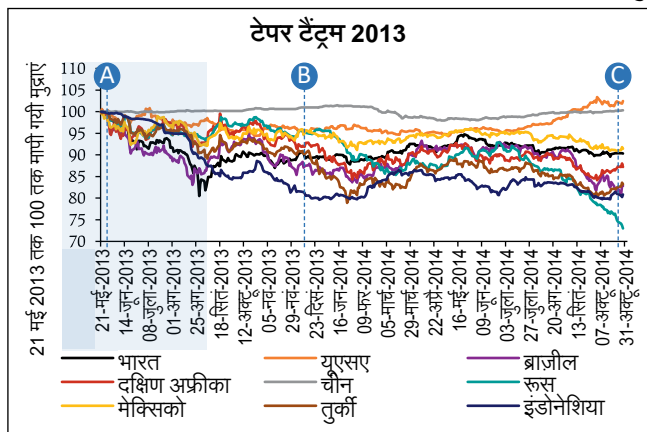
ए. इक्विटी बाजार



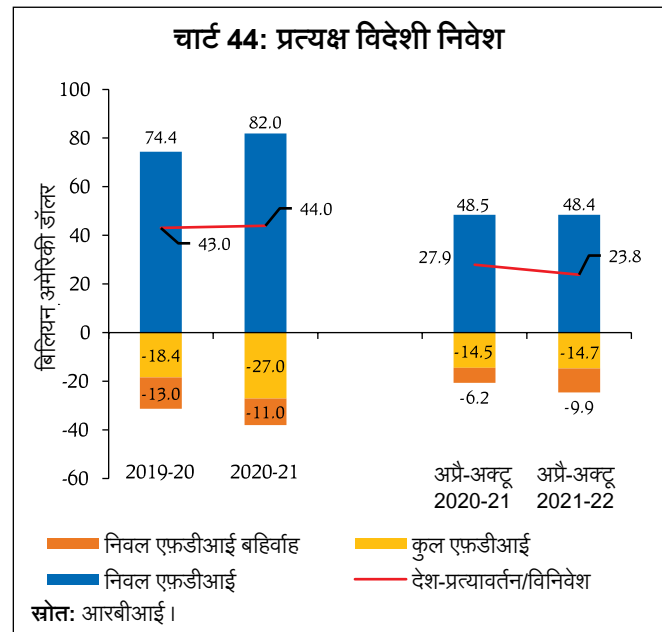
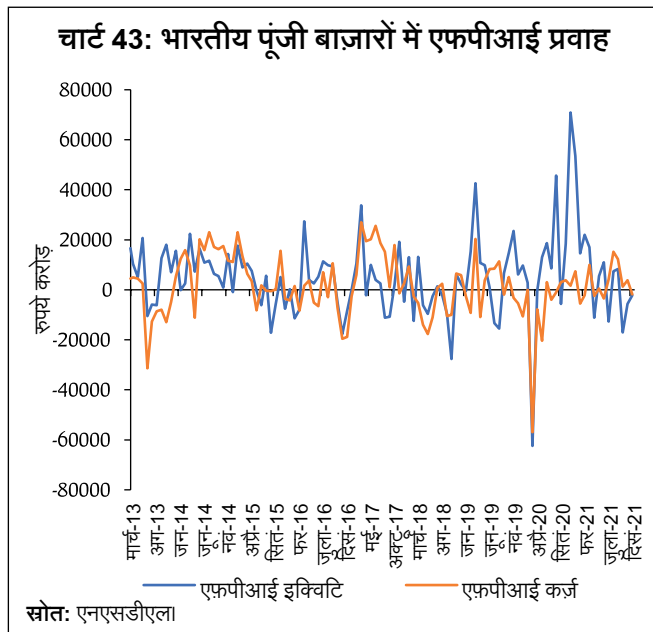
बी. बॉन्ड बाजार



सी. मुद्रा बाजार



ए: फेड चेंबर आरिस्त खरीद को कम करने के बारे में चर्चा करता है (22 मई, 2013)।
 बी: फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) ने जनवरी 2014 (से शुरू होने वाली मासिक आरिस्त खरीद में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कमी करके 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की घोषणा की। इसके बाद अक्टूबर 2014 तक आरिस्त खरीद में क्रमिक कमी आई (18 दिसंबर, 2013)।
 सी: एफओएमसी ने अपने आरिस्त खरीद कार्यक्रम के समापन की घोषणा की (29 अक्टूबर, 2014)।
 डी: एफओएमसी कार्यवृत्त ने दिखाया कि फेड 2021 में आरिस्त खरीद को कम कर सकता है (18 अगस्त, 2021)।
 ई: फेड चेंबर ने 2021 (27 अगस्त, 2021) में आरिस्त खरीद की गति को कम करने का संकेत दिया।
 एफ: एफओएमसी ने कमी आने का संकेत दिया (22 सितंबर, 2021)।
 जी: एफओएमसी ने नवंबर 2021 में मासिक निवल आरिस्त खरीद को 120 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटाकर 105 बिलियन अमेरिकी डॉलर और दिसंबर 2021 में 90 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने की घोषणा की (3 नवंबर, 2021)।
 एच: फेड चेंबर ने टेपरिंग की त्वरित गति के बारे में सुझाव दिया (30 नवंबर, 2021)।
 स्रोत: ब्लूमबर्ग

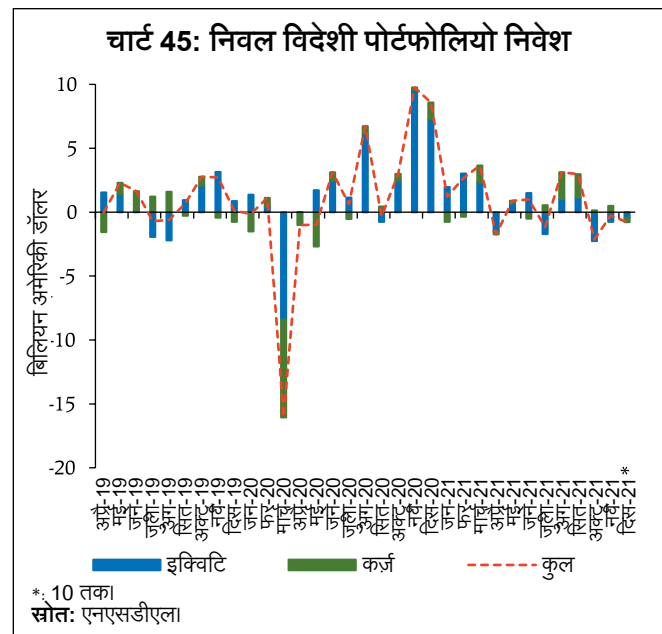


का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि पोर्टफोलियो प्रवाह अपेक्षाकृत स्थिर रहा। नवंबर-दिसंबर 10, 2021 की अवधि के दौरान इक्विटी खंड ने ₹8,854 करोड़ का निवल बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि कर्ज खंड ने ₹1,147 करोड़ का निवल अंतर्वाह दर्ज किया।

अप्रैल-अक्टूबर 2021 के दौरान 48.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सकल आवक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एक साल पहले के अपने स्तर के बराबर था (चार्ट 44)। एक साल पहले के 27.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में निवल एफडीआई 23.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भारत से बढ़ते हुए एफडीआई को दर्शाता है। प्रमुख एफडीआई इक्विटी प्राप्तकर्ता क्षेत्रों में विनिर्माण, कंप्यूटर सेवाएं, संचार सेवाएं, वित्तीय सेवाएं और खुदरा और थोक व्यापार शामिल हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नवंबर 2021 में घरेलू इक्विटी बाजार में निवल विक्रेता थे, जो अमेरिका में नए कोविड वैरिएंट और नीति सामान्यीकरण पर चिंताओं के बीच था (चार्ट 45)। अन्य प्रमुख ईएमई ने भी माह के दौरान बहिर्वाह दर्ज किया। हालांकि, कर्ज बाजार में एफपीआई द्वारा 0.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवल खरीद एक महीने पहले की तुलना में कुछ अधिक थी। कर्ज खंड में प्रवाह काफी हद तक अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल की दिशा द्वारा निर्देशित किया गया है।

एक साल पहले के 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल बहिर्वाह की तुलना में अंतर-कंपनी उधार सहित भारत को बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ईसीबी) का निवल संवितरण अप्रैल-अक्टूबर 2021 के दौरान 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि निवल संवितरण अंतर-कंपनी उधार और चुकौती को छोड़कर एक साल पहले 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल पुनर्भुगतान के मुकाबले 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के थे।

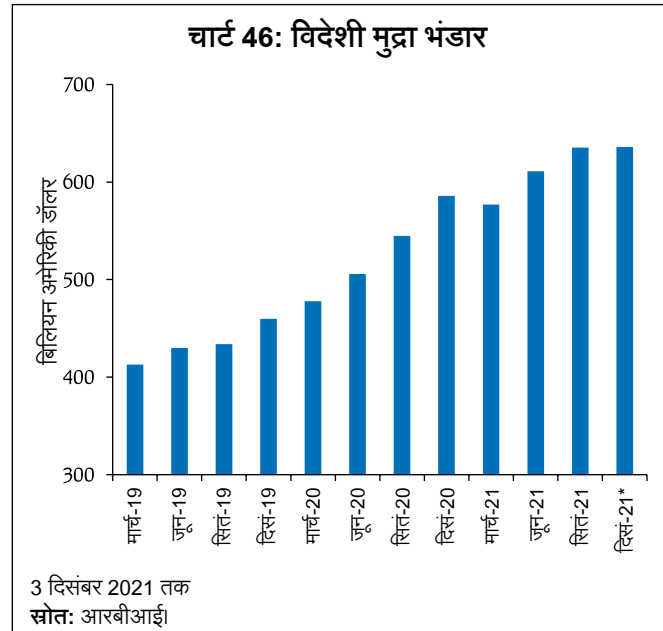


3 दिसंबर, 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार 635.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट 46), जो 2021-22 के लिए अनुमानित 14 महीनों के आयात के बराबर था।

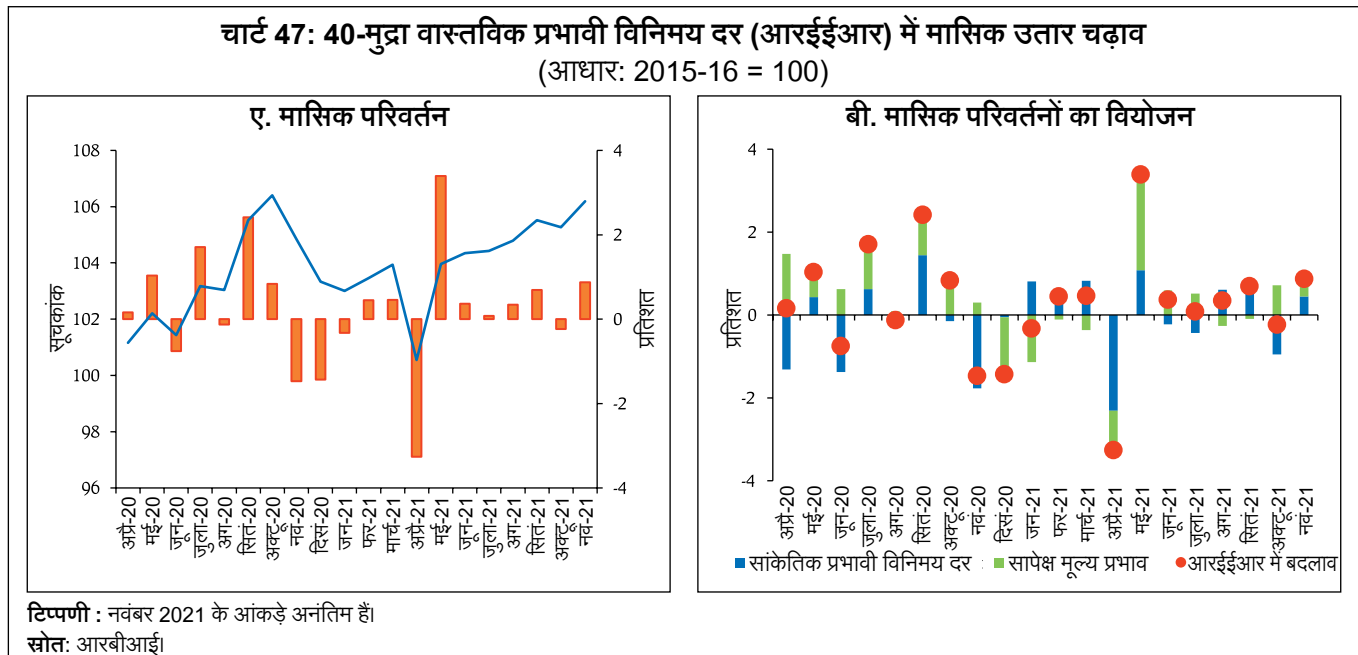
विदेशी मुद्रा बाजार में, भारतीय रुपये (आईएनआर) की कीमत नवंबर 2021 में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 0.6 प्रतिशत (म-द-म) बढ़ गयी। यह 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक के संदर्भ में आईएनआर की गति में परिलक्षित होता था, जो एक महीने पहले अपने स्तर से 0.9 प्रतिशत तक बढ़ गया (चार्ट 47 ए और 47 बी)।

भुगतान प्रणाली

त्योहारी मांग के कारण अक्टूबर में एक मजबूत प्रदर्शन के बाद, थोक और खुदरा चैनलों में डिजिटल लेनदेन ने नवंबर और दिसंबर (8 दिसंबर तक) में अपनी वृद्धि की गति (वर्ष-दर-वर्ष) को बनाए रखा। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से बड़े मूल्य के हस्तांतरण में पिछले महीने की वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष) की तुलना में 18 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, जो दोहरे अंकों की मात्रा में वृद्धि द्वारा समर्थित है। खुदरा भुगतान मोड ने भी और अधिक कर्षण प्राप्त किया (सारणी 5)। एकीकृत भुगतान इंटरफेस



(यूपीआई) चैनल के तहत लेनदेन पिछले महीने प्राप्त रिकॉर्ड 400 करोड़ अंक से काफी ऊपर रहा। हाल ही में, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) ने यूपीआई और रुपये कार्ड की वैश्विक स्वीकृति का विस्तार करने के लिए वैश्विक भुगतान प्रदाता पीपीआरओ के साथ भागीदारी की है। त्योहारी सीजन के



¹² <https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/npci-takes-upi-global-ties-up-with-leading-payments-provider-ppro/articleshow/87759248.cms>

सारणी 5: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि दर

भुगतान प्रणाली	लेन-देन की मात्रा में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)				लेन-देन मूल्य वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)			
	अक्टू-2020	अक्टू-2021	नव-2020	नव-2021	अक्टू-2020	अक्टू-2021	नव-2020	नव-2021
आरटीजीएस	7.2	33.2	2.9	24.9	-18.4	19.3	-8.0	37.5
एनईएफटी	13.9	29.4	24.6	24.1	20.1	10.8	27.9	4.3
यूपीआई	80.4	103.6	81.3	89.4	101.8	99.8	106.6	96.5
आईएमपीएस	34.6	35.0	48.7	21.5	29.1	35.0	36.3	31.9
एनएसीएच	-21.6	31.6	2.5	15.7	-12.2	22.0	5.7	7.1
एनईटीसी	289.0	75.1	257.6	71.5	204.1	57.1	171.6	51.1
बीबीपीएस	88.3	155.6	78.7	148.6	75.9	165.8	78.1	175.3

स्रोत: आरबीआई

दौरान खपत में वृद्धि से उत्साहित, क्रेडिट कार्ड खर्च 56 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) उछलकर अक्टूबर 2021 में अब तक के उच्चतम स्तर 1 लाख करोड़ को पार कर गया। 7 महीनों की अवधि में, यानी अप्रैल से अक्टूबर के बीच 2021 में, भुगतान मोड ने 2020-21 में दर्ज किए गए कुल डिजिटल भुगतानों के 84 प्रतिशत को छू लिया है, जो देश में तेजी से डिजिटल अपनाने का संकेत देता है।

1 जनवरी, 2021 से भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निधि (पीआईडीएफ) योजना¹³ के संचालन के साथ, तैनात किए गए स्वीकृति उपकरणों की कुल संख्या 57.82 लाख तक पहुंच गई है, और आधारभूत निधि ₹614 करोड़ (सितंबर 2021 के अंत) पर पहुंच गयी है। तैनात किए गए उपकरणों में से आधे से अधिक टियर 5 और टियर 6 केंद्रों में हैं, इसके बाद टियर 3 और टियर 4 केंद्र, उत्तर-पूर्वी राज्य और टियर 1 और टियर 2 केंद्र हैं जो पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मा निर्भर निधि (पीएम) के अंतर्गत आते हैं। स्वानिधि) योजना¹⁴। बढ़ती मर्चेट स्वीकृति के प्रमाण के रूप में, भुगतान टचप्वाइंट की पहुंच कुशल डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान कर सकती है और वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकती है।

महामारी के दौरान प्रदर्शित तेजी से डिजिटलीकरण ने भारतीय फिनटेक क्षेत्र को गति दी है, जैसा कि मजबूत फंडिंग गति और फिनटेक यूनिकॉर्न की संख्या में वृद्धि द्वारा पुष्टि की गई है। 2021 के नौ महीनों में, फिनटेक क्षेत्र को 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ, जो 2020 में प्राप्त कुल निवेश (1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर)¹⁶ का लगभग तीन गुना है। 2021 में अब तक 8 फिनटेक ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया है (2020 में 3 के मुकाबले)¹⁷। डिजिटल परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए फिनटेक की क्षमता का लाभ उठाने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, रिजर्व बैंक ने स्मार्ट डिजिटल भुगतान¹⁸ की थीम के साथ पहली बार वैश्विक हैकथॉन कार्यक्रम 'हारबिगर 2021 - परिवर्तन के लिए नवाचार' शुरू किया है।

18 नवंबर, 2021 को, रिजर्व बैंक ने ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और एक सुरक्षित और नैतिक डिजिटल उधार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर कार्य समूह की रिपोर्ट जारी की।¹⁹ रिपोर्ट में प्रणाली में प्रतिभागियों को शामिल करते हुए एक नोडल एजेंसी और एक स्व-नियामक

¹³ पीआईडीएफ योजना देश के टियर -3 से टियर -6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) इन्फ्रास्ट्रक्चर (भौतिक और डिजिटल मोड) की तैनाती को सब्सिडी देती है। 26 अगस्त, 2021 से टियर-1 और टियर-2 केंद्रों में पीएम स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) के लाभार्थी भी शामिल हैं।

¹⁴ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52571

¹⁵ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियां।

¹⁶ <https://www.pwc.in/assets/pdfs/services/startups/start-up-perspectives-october-2021.pdf>

¹⁷ वेंचर इंटेलिजेंस डेटा, 30 नवंबर, 2021 को एक्सेस किया गया।

¹⁸ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52533

¹⁹ https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=52589

संगठन (एसआरओ) द्वारा डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स के लिए सत्यापन प्रक्रिया की सिफारिश की गई है।²⁰

अपनी विकासात्मक और नियामक नीतियों (8 दिसंबर, 2021) में, बैंक ने भुगतान शुल्क पर एक चर्चा पत्र जारी करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें किफायती डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक मुद्दों और उपायों की पहचान की गई है। इसके अलावा, लेन-देन में आसानी बढ़ाने और व्यापक डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए, बैंक ने फीचर फोन के लिए एक यूपीआई-आधारित भुगतान समाधान विकसित करने का; "ऑनडिवाइस" वॉलेट के माध्यम से छोटे मूल्य के यूपीआई लेनदेन के लिए प्रक्रिया प्रवाह को सरल बनाने का; और खुदरा प्रत्यक्ष योजना और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) आवेदनों के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा `2 लाख से `5 लाख तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

V. निष्कर्ष

महामारी की बेड़ियों से बाहर निकलते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार आगे बढ़ रही है। चल रहे पुनरुद्धार कारकों

के संगम से प्रेरित है, जैसे, रुकी हुई मांग को जारी करना, पूंजीगत व्यय के लिए सरकार का जोर, मजबूत बाहरी मांग और सामान्य मानसून। संपर्क-गहन सेवाओं की तेजी से बहाली और उपभोक्ता विश्वास की त्वरित बहाली निकट अवधि की संभावनाओं को उज्ज्वल करती है।

आगे बढ़ते हुए, ओमिक्रॉन स्ट्रेन के उद्भव ने वैश्विक समष्टिआर्थिक वातावरण में अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर यात्रा प्रतिबंधों / संगरोध नियमों को फिर से शुरू करने के साथ वैश्विक व्यापार के लिए जोखिम को तेज कर दिया है। आपूर्ति पक्ष की मौजूदा बाधाओं से इनपुट कीमतों और माल दुलाई दरों को ऊंचे स्तर पर रखने की संभावना है और यह समग्र निर्यात पर एक दबाव के रूप में कार्य कर सकता है। जबकि कम घरेलू संक्रमण संख्या और टीकाकरण की स्वस्थ गति अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा संकेत है, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को अधिक सावधानी और तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता देखने की आवश्यकता है।

²⁰ कुछ अन्य सिफारिशों में अवैध डिजिटल उधार गतिविधियों को रोकने के लिए एक अलग कानून का अधिनियमन शामिल है; कुछ आधारभूत प्रौद्योगिकी मानकों का विकास और बाद में डिजिटल ऋण समाधान प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में अनुपालन; सत्यापन योग्य ऑडिट ट्रेल्स के साथ सहमति-आधारित डेटा संग्रह; और भारत में स्थित सर्वरों में डेटा का भंडारण।

बॉक्स : भारत के निवल शून्य उत्सर्जन (एनजेडई) लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रौद्योगिकी कैसे मदद कर सकती है- भारतीय सीमेंट उद्योग पर एक अध्ययन

भारत ने 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसका लक्ष्य नवीकरणीय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के आधे हिस्से तक पहुंचना और 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करना है। इसके लिए सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से जहां कार्बन उत्सर्जन उच्च है, नीतिगत पुनर्विचार की आवश्यकता है। सीमेंट उद्योग उनमें से एक है।

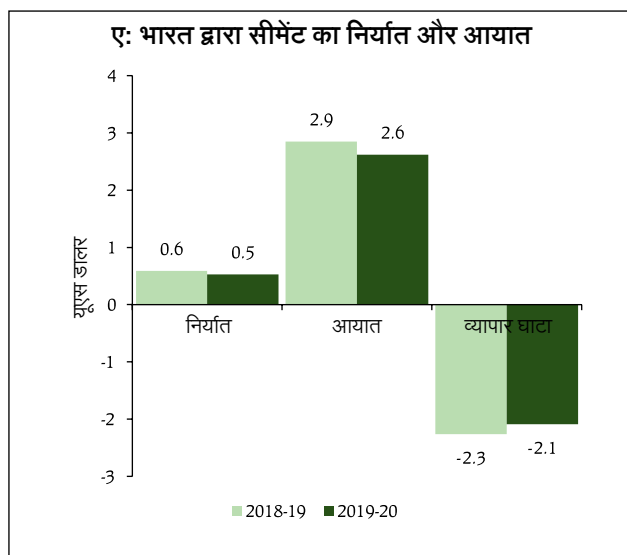
विश्व स्तर पर, मानवजनित CO₂ उत्सर्जन में, सीमेंट उत्पादन का योगदान दुनिया का लगभग 8 प्रतिशत है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक और उपभोक्ता है। वित्तीय वर्ष 20 में इसका हिस्सा वैश्विक स्थापित क्षमता का 8 प्रतिशत से अधिक है। भारत का सीमेंट उत्पादन 2021-22 तक 381 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है; जबकि खपत लगभग 379 मिलियन टन हो सकती है। पिछले पांच वर्षों में, 2018-19 को छोड़कर, भारत के सीमेंट उत्पादन की मात्रा इसकी सीमेंट खपत से अधिक हो गई है। सीमेंट क्षेत्र में 2.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का व्यापार घाटा है (चार्ट 1ए)। भारत का सीमेंट क्षेत्र एक बड़ी क्षेत्रीय उपस्थिति के साथ अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है। सीमेंट क्षेत्र को भारत (डीपीआईआईटी21) को प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का लगभग 1 प्रतिशत (5.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) प्राप्त हुआ।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एक लाख करोड़ से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ), कम लागत वाले आवास (प्रधान मंत्री आवास योजना) जैसी बड़ी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं पर नए सिरे से ध्यान देने

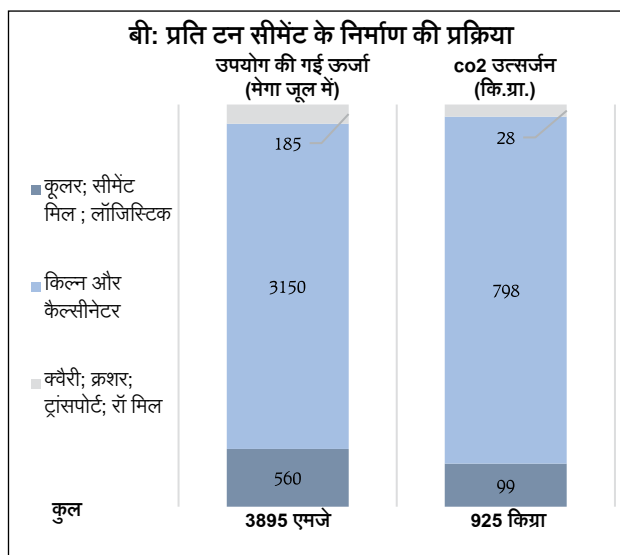
और स्मार्ट (एसएमएआरटी) शहरों के मिशन पर सरकार द्वारा बल दिए जाने के कारण सीमेंट की मांग बढ़ने की संभावना है। भविष्य में उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी अवसंरचना के निर्माण के प्रति यह प्रतिबद्धता एनजेडई (एनजेडई) मानदंडों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के लिए एक जोखिम भी है। इस प्रकार, भारत को, उभरते हरित तकनीकी समाधानों को अपनाकर अपने आर्थिक लक्ष्य और अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है।

सीमेंट बनाने में, कैल्सीनेशन के कारण CO₂ की अच्छी-खासी मात्रा उत्सर्जित होती है, जबकि शेष मात्रा कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन (चार्ट 1 बी) को जलाने से उत्सर्जित होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि CO₂ उत्सर्जन को वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले कैप्चर करना और रिवर्स कैल्सीनेशन के माध्यम से इसे दूर स्टोर करना सीमेंट उद्योग को डीकार्बोनाइज करने का सबसे प्रभावी तरीका है, (फेनेल और अन्य, 2021)। मैकिन्से (2020) का अनुमान है कि रिवर्स कैल्सीनेशन वर्तमान में सीमेंट के उत्सर्जन को 5 प्रतिशत तक कम कर सकता है, जिसे प्रौद्योगिकी में सुधार के साथ 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है। कैल्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए जीवाश्म ईंधन के बजाय हरित ऊर्जा को नियोजित कर और बढ़ाया जा सकता है। बायोमास जैसे नगरपालिका और औद्योगिक अपशिष्ट का उपयोग जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। भारत, सीमेंट के विकल्प के रूप में प्लाई ऐश, ग्राफीन, प्राकृतिक और सिंथेटिक फाइबर को भी आजमा सकता है।

चार्ट 1: सीमेंट उद्योग में व्यापार और विनिर्माण प्रक्रिया



स्रोत: इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन; मैकिन्से और द इकॉनॉमिस्ट।



(जारी....)

²¹ https://dpiit.gov.in/sites/default/files/FDI_Factsheet_June2021.pdf

भारत के घरेलू सीमेंट उद्योग ने 1996 और 2017 के बीच उत्पादित सीमेंट के 1.12t/t से 0.719t/t तक CO₂ उत्सर्जन के स्तर को लगभग 36 प्रतिशत कम करने की उल्लेखनीय प्रगति की है। 2050 तक 0.35t CO₂/t सीमेंट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीमेंट उद्योग को 29 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की आवश्यकता है।

नीतिगत संस्तुतियाँ

- रियायती ब्याज ऋणों के माध्यम से हरित सतत समाधान के लिए वित्तपोषण बढ़ाएँ।
- सीमेंट उद्योग में हरित तकनीक से संबंधित नवाचार से जुड़े अग्रणी अनुसंधान संस्थानों/देशों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें।

- रिवर्स कैल्सीनेशन और शुद्ध कार्बन कैप्चर की प्रक्रिया को निष्पादित करने के लिए बायोमास ईंधन के रूप में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उत्तरी राज्यों से पराली खरीदने के लिए सीमेंट उद्योग को प्रोत्साहित करना।

संदर्भ:

1. Czigler T., Reiter S., Schulze P., Somers K., 2020. Laying the Foundation for Zero-Carbon Cement. McKinsey & Company Insights.
2. Fennell PS, Davis SJ, Mohammed A, 2021, Decarbonizing cement production, Vol: 5, Pages: 1305-1311, ISSN: 2542-4351.
3. "How cement may yet help slow global warming", 2021, The Economist, November 6th, 2021 Edition.

सरकारी वित्त 2021-22: एक अर्ध-वार्षिक समीक्षा*

सरकारी वित्त ने दूसरी लहर के लिए उल्लेखनीय आघात सहनीयता प्रदर्शित किया, जिसमें यह कर संग्रह अपेक्षाओं को पार कर गया, और सरकारी व्यय मोटे तौर पर उच्च महामारी संबंधी खर्च के बावजूद बजट अनुमानों के अनुरूप बना रहा। केंद्र और राज्यों दोनों के लिए व्यय की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो एक टिकाऊ विकास सुधार के लिए अच्छा है। आगे बढ़ते हुए, सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा, जो 2021-22 की पहली छमाही में कम रहा, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में विकास में सुधार को समर्थन और बनाए रखने के लिए व्यय में तेजी लाने की अनुमति देता है।

I. परिचय

वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय बजट एक ऐसे मोड़ पर पेश किया गया था जब अर्थव्यवस्था महामारी की पहली लहर के बाद आई भीषण मंदी से एक मजबूत प्रोत्साहन-नेतृत्व वाला सुधार देख रही थी, लेकिन दूसरी लहर की संभावना के बारे में अनिश्चितता के बीच। तदनुसार, बजट में एक नाजुक संतुलन का अनुसरण किया गया, एक चुनौतीपूर्ण व्यापक आर्थिक वातावरण में राजकोषीय समेकन की व्यवहार्य डिग्री का लक्ष्य रखते हुए एक व्यापक-आधार वाले और टिकाऊ आर्थिक सुधार के लिए समर्थन बनाए रखा। बजट में सकल राजकोषीय घाटे (जीएफडी) को 2020-21 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद के 9.5 प्रतिशत से 2021-22 (बीई) में 6.8 प्रतिशत करने की परिकल्पना की गई है।¹ राज्यों ने अपने जीएफडी में 2020-21 (आरई) में सकल घरेलू

* यह लेख आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग के रचित सोलंकी, सक्षम सूद, इप्सिता पाद्री, डॉ. सोमनाथ शर्मा, डॉ. समीर रंजन बेहरा और डॉ. अत्री मुखर्जी द्वारा तैयार किया गया है। टीम, डॉ. देब प्रसाद रथ को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देती है। लेखक श्री सितिकंठ पटनायक और श्री बिचित्रानंद सेठ की टिप्पणियों और बहुमूल्य सुझावों के लिए भी उनके प्रति आभारी हैं। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और जरूरी नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों को व्यक्त करें।

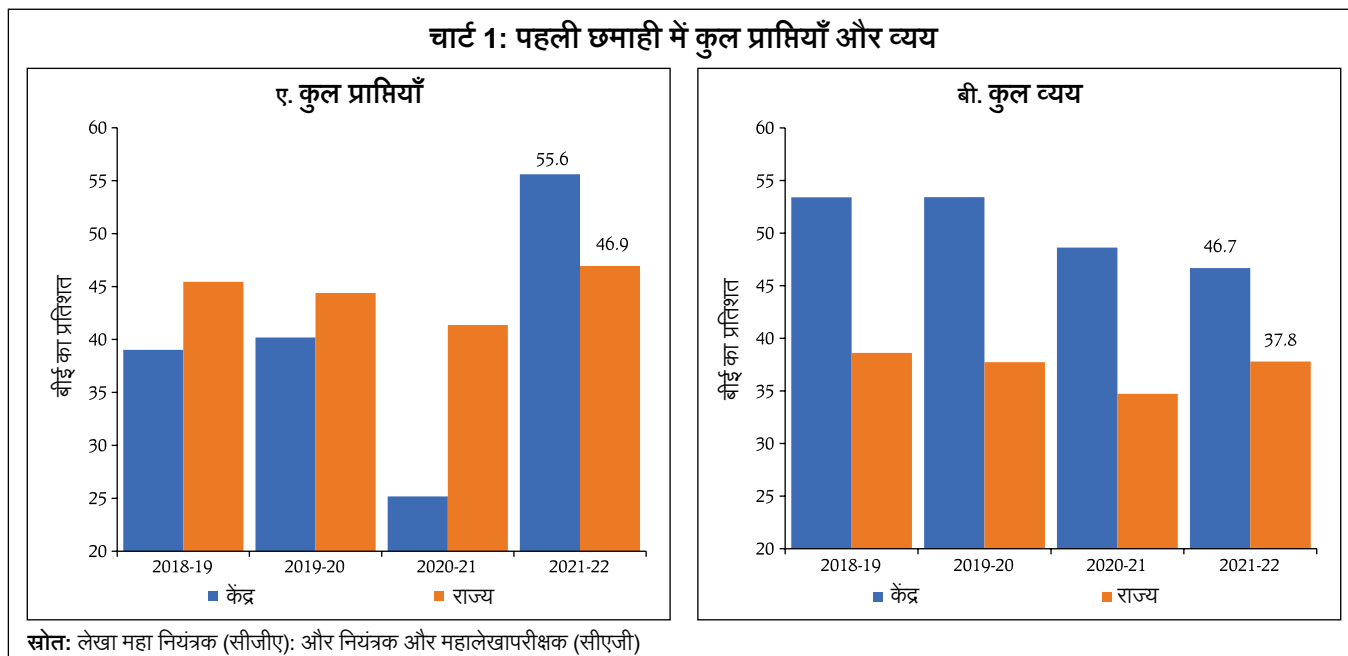
¹ ये अनुमान 14.4 प्रतिशत की मामूली जीडीपी वृद्धि और 1.2 की कर उछाल और राजस्व व्यय में मामूली संकुचन की सामान्य धारणाओं पर आधारित थे।

उत्पाद के 4.7 प्रतिशत से 2021-22 (बीई) में 3.7 प्रतिशत तक समेकन का बजट रखा। दूसरी लहर, बाद में अप्रैल-मई 2021 के दौरान मानव जीवन के नुकसान के मामले में अधिक गंभीर हो गई, लेकिन आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव स्थानीय प्रतिबंधों और वायरस के साथ रहने के लिए बेहतर अनुकूलन के माध्यम से निहित था। सरकारी वित्त ने उल्लेखनीय लचीलापन और उछाल दिखाया, और इसके परिणामस्वरूप, दूसरी लहर द्वारा लगाए गए अतिरिक्त व्यय बोझ के बावजूद, सरकारी खर्च मोटे तौर पर बजट अनुमानों के अनुरूप रहा है। पूंजीगत व्यय पर सरकार के जोर के परिणामस्वरूप व्यय की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ - मध्यम अवधि में विकास समर्थक राजकोषीय समेकन के लिए एक आवश्यक शर्त। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में सभी प्रमुख कर शीर्षों में मजबूत वृद्धि दर्ज करने के साथ, केंद्र का कर संग्रह, प्राप्तियों के संबंध में अपेक्षाओं को पार कर गया। राज्यों के कर संग्रह ने भी मजबूत वृद्धि का प्रदर्शन किया, हालांकि केंद्र के समान गति से नहीं, और वह 2021-22 की पहली छमाही में अपने पूर्व-महामारी के स्तर पर पहुंच गए हैं।

शेष लेख को इस प्रकार संरचित किया गया है: खंड II 2021-22 की पहली छमाही के लिए केंद्र और राज्यों (तिमाही आवृत्ति पर) के लिए प्राप्ति और व्यय परिणामों का विश्लेषण करता है। खंड III प्रमुख घाटे के संकेतकों और उनके वित्तपोषण के संदर्भ में परिणामों से संबंधित है। खंड IV 2021-22 की दूसरी छमाही के अनुमानों के साथ ति.1 और ति.2: 2021-22 के लिए सामान्य सरकारी वित्त पर अनुमान प्रस्तुत करता है। खंड V समापन टिप्पणियों और निकट अवधि के वित्तीय दृष्टिकोण को निर्धारित करता है।

II. वर्ष 2021-22 ति. 1 और ति. 2 में राजकोषीय परिणाम:

केंद्र सरकार की कुल प्राप्तियों ने अपने प्रवृत्ति स्तर पर एक उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया और कुल व्यय 2021-22 की पहली छमाही में निहित रहा, दूसरी लहर द्वारा आवश्यक अतिरिक्त व्यय के बावजूद, क्योंकि सरकार ने परिहार्य व्यय को कम करने के लिए एहतियाती उपाय किए। राज्य का वित्त भी 2021-22 की पहली छमाही में अपने पूर्व-महामारी स्तर पर वापस आ गया।



राज्यों ने अपनी बजटीय प्राप्तियों का 46.9 प्रतिशत संग्रह किया जो पिछले तीन वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों से अधिक है। व्यय पक्ष पर, 2021-22 की पहली छमाही में व्यय बजट लक्ष्य का 37.8 प्रतिशत था, जो व्यापक रूप से पूर्व-महामारी के वर्षों (चार्ट 1) के दौरान औसत के अनुरूप था।

ए. प्राप्तियाँ

केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियों ने ति.1: 2021-22³ में एक मजबूत वृद्धि दर्ज की, क्योंकि दूसरी लहर के बावजूद कर राजस्व में उच्च उछाल दर्ज किया गया और गैर-कर राजस्व को रिजर्व बैंक से बजटीय लाभांश हस्तांतरण से अधिक से बढ़ावा मिला। दूसरी तिमाही में राजस्व प्राप्तियों में 35.0 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, इसने एच1 में समग्र रूप से बीई का 60.4 प्रतिशत का उच्च स्तर देखा। गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ⁴ में भी एच1:2021-22 की

तुलना में एच1:2020-21 में सुधार हुआ, लेकिन 2019-20 के स्तर से कम हो गया (चार्ट 2 ए और बी)।

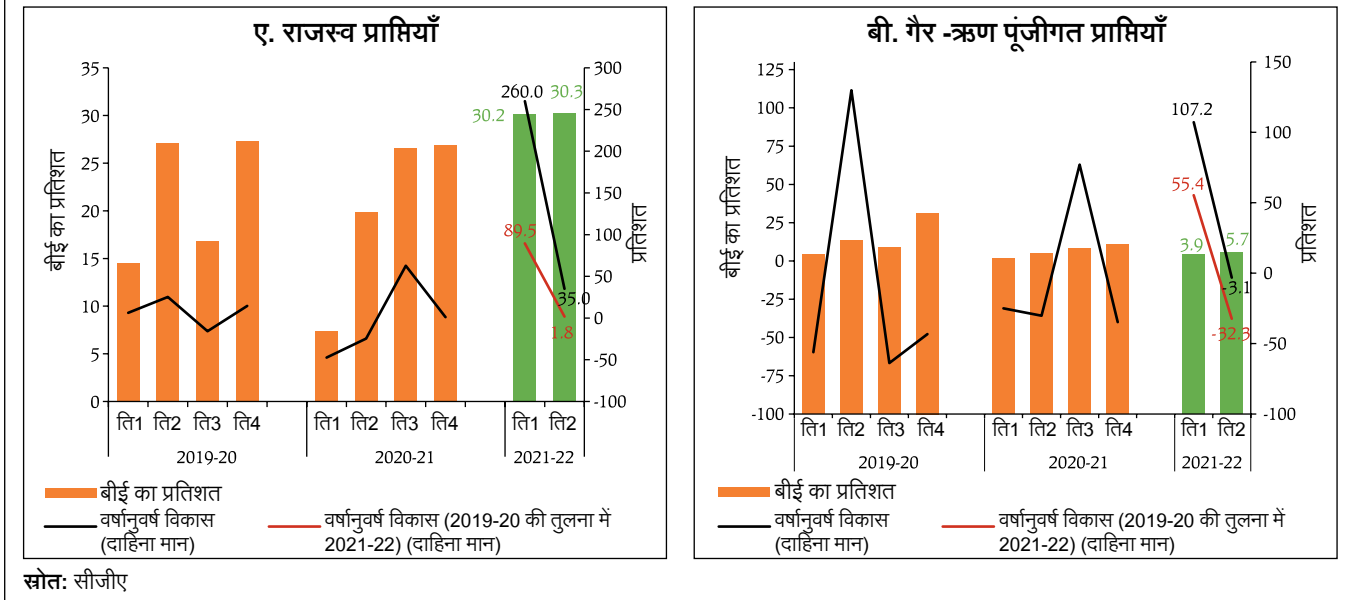
राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ भी महामारी की दूसरी लहर के लिए लचीला बनी हुई हैं, कुल राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ति.1: 2021-22 में 33.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि और 2019-20 की इसी तिमाही में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में भी इसी तरह का प्रदर्शन कायम रहा, जिसमें साल-दर-साल राजस्व में 21.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, 2021-22 की पहली छमाही में राज्यों की राजस्व प्राप्तियाँ 2020-21 की पहली छमाही में (2019-20 की पहली छमाही में से 8.2 प्रतिशत) की तुलना में 26.7 प्रतिशत अधिक थीं। राज्यों की गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों ने भी 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही दोनों में उच्च वृद्धि दर्ज की, हालांकि काफी उतार-चढ़ाव के साथ (चार्ट 3)।

² 26 राज्यों के लिए समग्र आंकड़ों के आधार पर, जिसके लिए 2021-22 की दूसरी तिमाही तक का पूरा ऐतिहासिक और अद्यतन डेटा उपलब्ध है।

³ 2020-21 की तुलना में 260.0 प्रतिशत और 2019-20 की तुलना में 89.5 प्रतिशत की वृद्धि।

⁴ गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियों में ऋण और अग्रिम की वसूली और विविध पूंजी प्राप्तियों (विनिवेश और अन्य प्राप्तियाँ) शामिल हैं।

चार्ट 2: केंद्र की प्राप्ति का तिमाहीवार विवरण

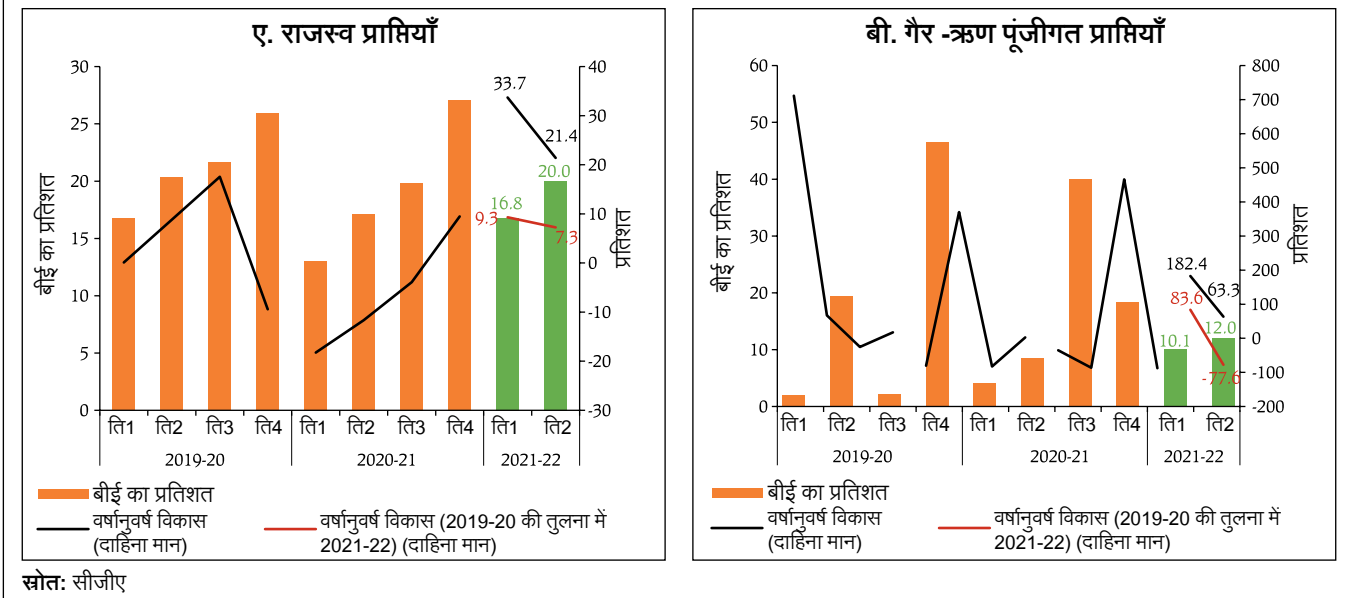


केंद्र के प्रत्यक्ष कर संग्रह ने 2021-22 की पहली छमाही में 83.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जिसका नेतृत्व आयकर और निगम कर में क्रमशः ⁵ 64.7 प्रतिशत और 105.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया गया, जो मजबूत कॉर्पोरेट प्रदर्शन के आधार पर था। राज्यों के लिए, स्टॉप शुल्क जो स्वयं के प्रत्यक्ष कर

राजस्व का 85 प्रतिशत से अधिक है, ति.1: 2021-22 में दोगुने से अधिक हो गया है; ति.2 में 53.4 प्रतिशत (चार्ट 4) की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई।

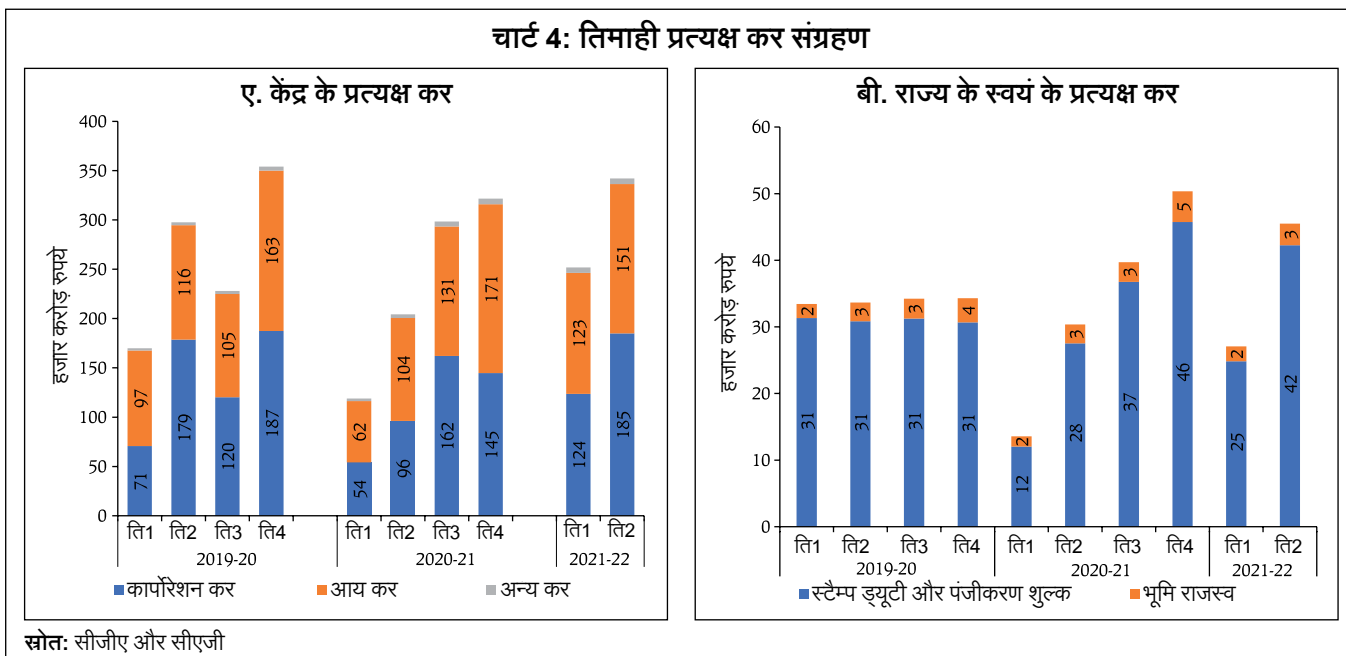
व्यापार गतिविधि में सुधार और उच्च आयात मांग के कारण सीमा शुल्क संग्रह में 100 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के कारण

चार्ट 3: केंद्र की प्राप्ति का तिमाहीवार विवरण



⁵ 2019-20 में, आय और निगम करों में क्रमशः 28.7 प्रतिशत और 23.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई

चार्ट 4: तिमाही प्रत्यक्ष कर संग्रहण



पहली छमाही के दौरान केंद्र के अप्रत्यक्ष कर संग्रह में भी वृद्धि हुई। महामारी प्रेरित आपातकाल उपाय के रूप में अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए पिछले साल (मार्च और मई 2020) में लगाए गए उच्च शुल्क के कारण इस अवधि के दौरान केंद्रीय उत्पाद शुल्क संग्रह में 2020-21 (2019-20 की तुलना में 79.0 प्रतिशत) की तुलना में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

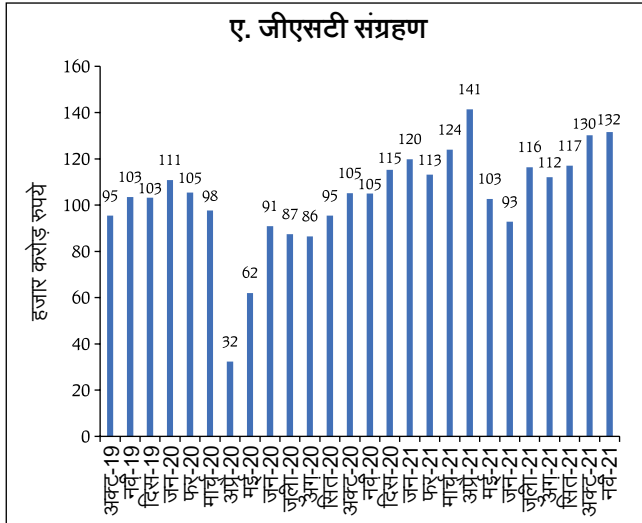
जीएसटी संग्रह (केंद्र के साथ राज्य) पहली छमाही में क्रमशः 2020-21 और 2019-20 के स्तर पर 50.1 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महामारी से संबंधित प्रतिबंधों के कारण मई-जून में जीएसटी राजस्व में गिरावट आई थी, लेकिन इसके बाद आर्थिक सुधार के अनुरूप और कर प्रशासन द्वारा कर चोरी को रोकने और अनुपालन बोझ को कम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण जल्दी से ठीक हो गया। नवंबर 2021 में, जीएसटी संग्रह ने 25.3 प्रतिशत⁶ की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज करके ₹1.32 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो जीएसटी की शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक है। अप्रैल-अक्टूबर के दौरान 1 लाख करोड़ रुपये के बजटीय जीएसटी मुआवजा उपकरण संग्रह का लगभग पाँच में से तीसरा हिस्सा वसूल किया

गया। केंद्र सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकरण के बदले बैक-टू-बैक ऋण सुविधा के तहत 2021-22 में राज्यों को जारी की जाने वाली ₹1.59 लाख करोड़ की पूरी राशि भी हस्तांतरित कर दी है। राज्यों को अपने खर्च की प्रभावी ढंग से योजना बनाने में सक्षम बनाने के लिए फ्रंट-लोडिंग की गई है। राज्यों के जीएसटी संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष पहली तिमाही में 71.6 प्रतिशत और वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में 27.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे कई राज्यों ने वर्ष 2020-21 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2021-22 की पहली छमाही 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की (चार्ट 5)। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर मोर्चे पर बेहतर राजस्व स्थिति को देखते हुए, केंद्र ने नवंबर में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि जो महामारी की पहली लहर के दौरान पेश की गई थी, को आंशिक रूप से वापस ले लिया। राज्यों ने भी इसका अनुसरण करते हुए ईंधन पर अपनी वैट दरों को कम किया (बॉक्स 1)।

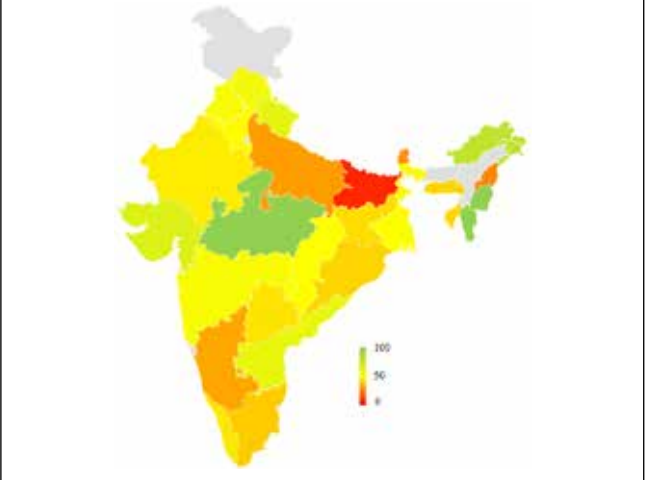
केंद्र के गैर-कर राजस्व में भी 2021-22 की पहली छमाही के दौरान रिजर्व बैंक से बजटीय अधिशेष हस्तांतरण से अधिक

⁶ 2019-20 की तुलना में 27.1 प्रतिशत की वृद्धि

चार्ट 5: जीएसटी निष्पादन



बी. वर्ष 2021-22 की पहली छमाही राज्य-वार व-द-व विकास दर



नोट: राज्य-वार जीएसटी के आंकड़े का संबंध राज्यों द्वारा रिपोर्ट किए जाने वाले आंकड़ों से है
स्रोत: सीजीए; ई -राज्य संबंधी आंकड़े ; और सीबीआईसी

होने के कारण वृद्धि हुई (चार्ट 6)। विनिवेश के मोर्चे पर, 1.75 लाख करोड़ रुपये के बजटीय विनिवेश लक्ष्य का केवल 5.2

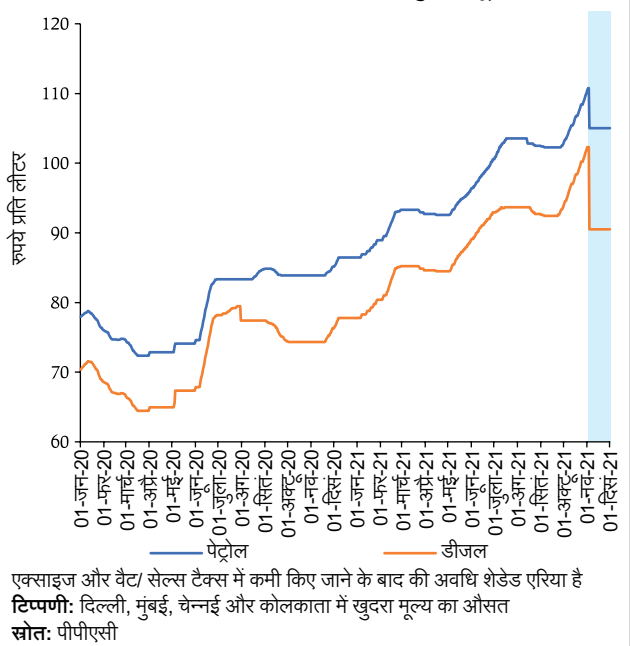
प्रतिशत ही पहली छमाही में जुटाया गया है। हालांकि, एयर इंडिया की प्रस्तावित बिक्री की प्रगति ने सरकार के विनिवेश कार्यक्रम को

बॉक्स 1: ईंधन करों में कमी का राजस्व प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों (चार्ट 1.1) के महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने के परिणामस्वरूप पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से वृद्धि से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए, केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क को 4 नवंबर, 2021 से क्रमशः ₹5 और ₹10 प्रति लीटर कम करने का फैसला किया। केंद्र के बाद, कई राज्यों ने भी अपने मूल्य वर्धित कर (वैट) को पेट्रोल में ₹0.8 से ₹10.0 प्रति लीटर और डीजल में ₹1.4 से ₹7.0 प्रति लीटर की सीमा में घटा दिया।

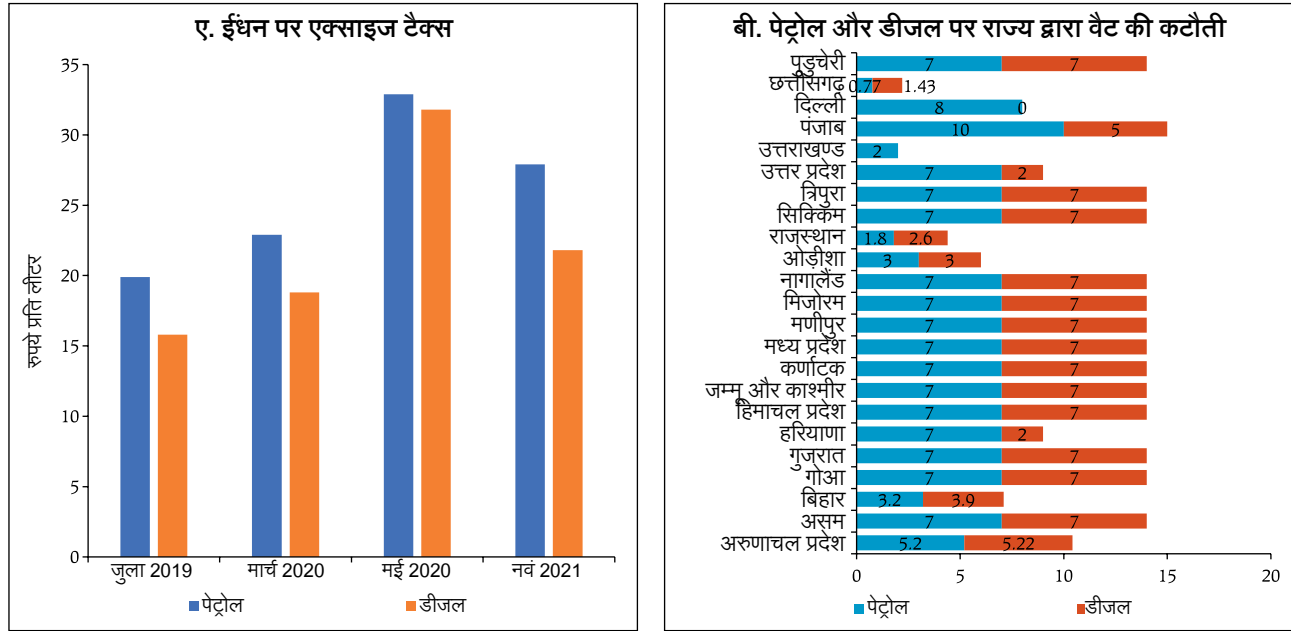
पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क और मूल्य वर्धित कर (वैट) / बिक्री कर में कमी से प्रत्यक्ष अल्पकालिक राजस्व हानि होती है, लेकिन बाद में खपत और निवेश की मांग की अपेक्षित वृद्धि के कारण आय प्रभाव के माध्यम से राजस्व में कुछ वृद्धि की गुंजाइश होती है। मध्यम अवधि में, ईंधन की कीमतों में कमी से लागत के दबाव को कम करने में मदद मिल सकती है और इससे व्यापार और उपभोक्ता भावना में सुधार हो सकता है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में हालिया कटौती के संभावित वित्तीय प्रभाव (चार्ट 1.2 ए) और बाद में 23 राज्यों द्वारा वैट / बिक्री कर में कमी (चार्ट 1.2 बी) का विश्लेषण यहां किया गया है।

चार्ट 1.1: पेट्रोल और डीजल खुदरा मूल्य



(Contd...)

चार्ट 1.2: ईंधन पर एक्साइज और वैट में कमी



स्रोत: सीजीए; ई-राज्य के आंकड़े; और सीबीआईसी

केंद्र को राजस्व हानि का अनुमान नवंबर-मार्च के दौरान पेट्रोल और डीजल की अखिल भारतीय अनुमानित खपत को उत्पाद शुल्क में इसी कटौती के साथ गुणा करके लगाया जाता है। पेट्रोल और डीजल की राज्य-वार खपत का अनुमान (नवंबर-मार्च 2021-22)⁷ पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल (पीपीएसी) से पेट्रोल और डीजल के राज्य-वार बिक्री डेटा का उपयोग कर रहा है। राज्य-वार राजस्व हानियों की गणना कीमत में

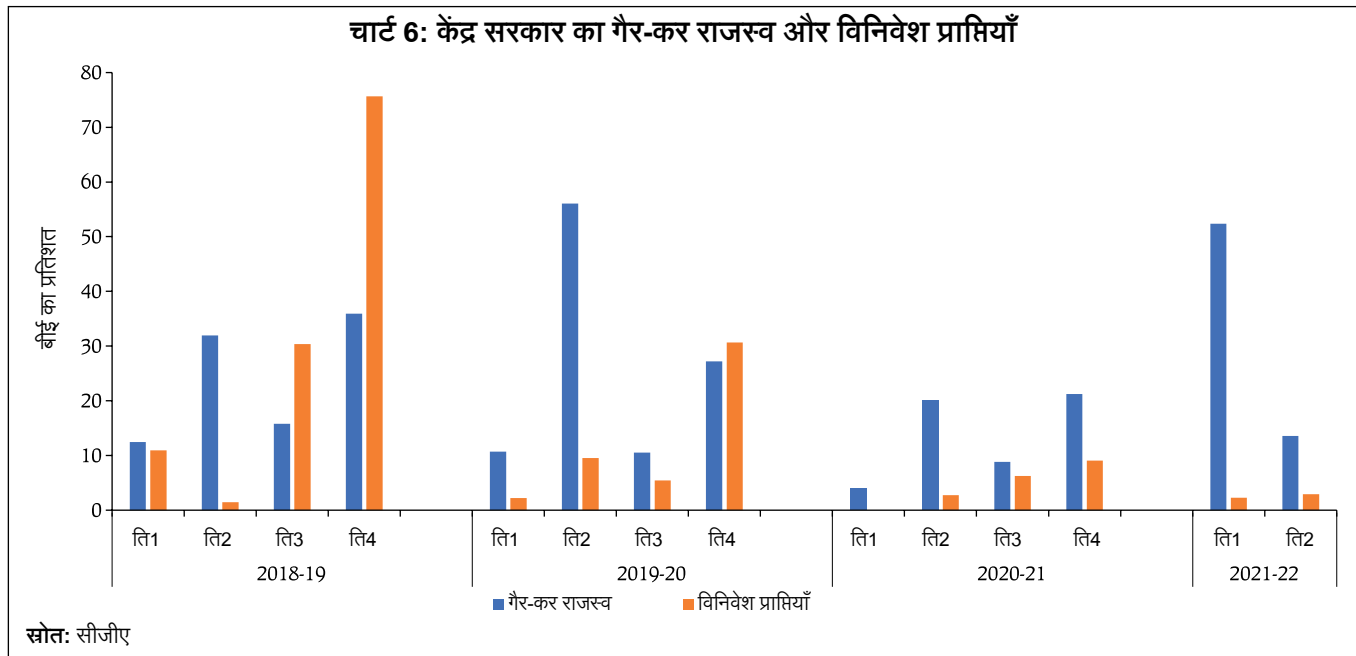
राज्य-विशिष्ट कमी (वैट/बिक्री कर में कमी के कारण) के साथ इन मात्राओं को गुणा करके की जाती है।

2021-22 में केंद्र को राजस्व हानि सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत होने का अनुमान है जबकि वैट / बिक्री कर में कटौती के कारण राज्यों को राजस्व हानि सकल घरेलू उत्पाद का 0.1 प्रतिशत होने का अनुमान है।

गति प्रदान की है। केंद्र का लक्ष्य परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से संसाधन जुटाना भी है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत, 2021-22 से 2024-25 तक, चार साल की अवधि में, ₹ 6.0 लाख करोड़ की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान है, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित ₹0.88 लाख करोड़ के सांकेतिक मूल्य के साथ। हालांकि, वास्तविक प्राप्ति समय, लेनदेन संरचना

और निवेशक की रुचि पर निर्भर करेगी। राज्यों के लिए, गैर-कर राजस्व में क्रमशः 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही में 40.2 प्रतिशत और 53.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (वर्ष 2019-20 की पहली और दूसरी तिमाही की तुलना में क्रमशः 15.9 प्रतिशत और 20.6 प्रतिशत क्रमशः)।

⁷ फुटनोट: दिल्ली और छत्तीसगढ़ के लिए, यह दिसंबर से मार्च 2021-22 तक है।

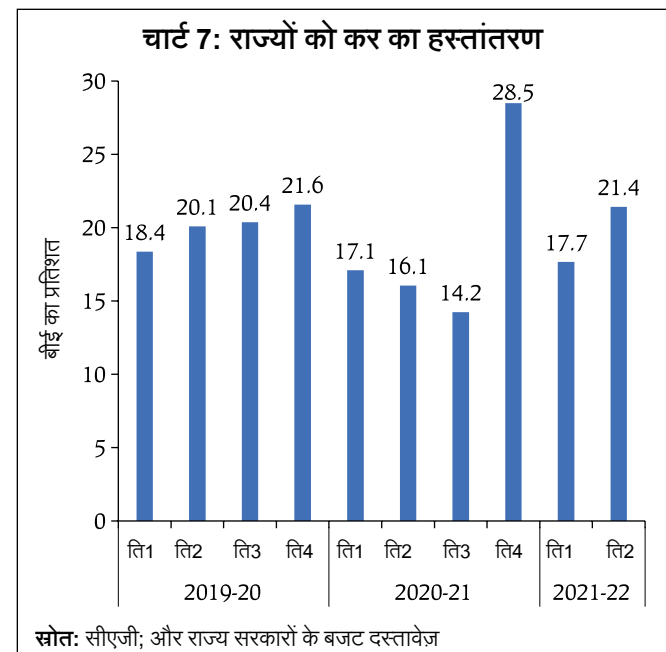


राज्यों को कर अंतरण में 2021-22 की पहली तिमाही के लिए लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। हालांकि, राज्यों के बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में, हस्तांतरण मोटे तौर पर 2020-21 और 2019-20 में उन लोगों के अनुरूप थे। वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए, स्थानांतरण पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.3 प्रतिशत अधिक थे और राज्यों के बजट अनुमानों के प्रतिशत के रूप में वे पिछले दो वर्षों (चार्ट 7) की ति2 की तुलना में भी अधिक थे।

बी. व्यय

केंद्र ने दूसरी लहर के जवाब में जून 2021 में 6.3 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय पैकेज की घोषणा की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत खाद्यान्नों के मुफ्त प्रावधानों को नवंबर तक बढ़ाना, उर्वरकों के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव के कारण आवश्यक बढ़ी हुई उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक स्वास्थ्य को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। और कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजनाएं। जबकि इनमें से कुछ उपायों ने बजट राशि के अलावा और उससे अधिक अतिरिक्त व्यय का नेतृत्व किया, एक बड़ा हिस्सा चलनिधि समर्थन के रूप

में था और इसमें कोई अतिरिक्त राजकोषीय बोझ नहीं था। इसके बाद, जुलाई 2021 में शुरू की गई अनुदान की पहली अनुपूरक मांग में अतिरिक्त व्यय उपायों का प्रस्ताव किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 23,675 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद व्यय हुआ। सरकार ने ति2: 2021-22 में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों पर व्यय प्रतिबंधों के माध्यम से खर्च को सीमित करने के

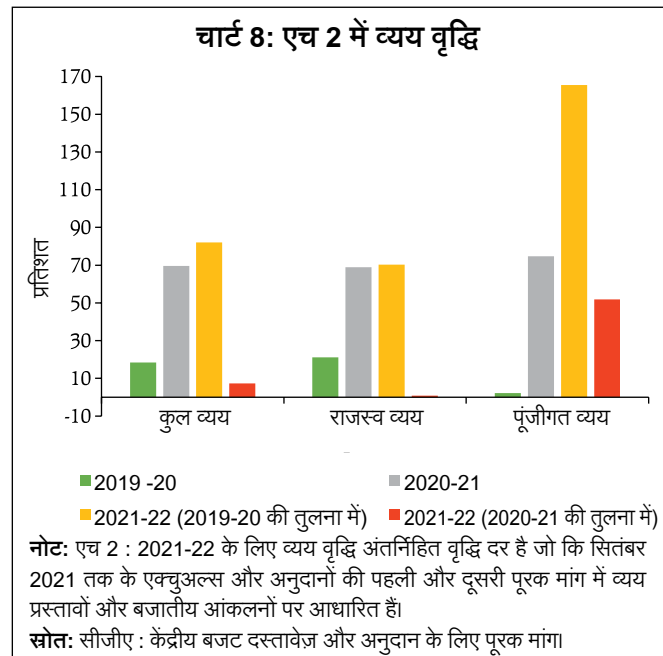


⁸ इसे मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है (परिशिष्ट तालिका 5)।

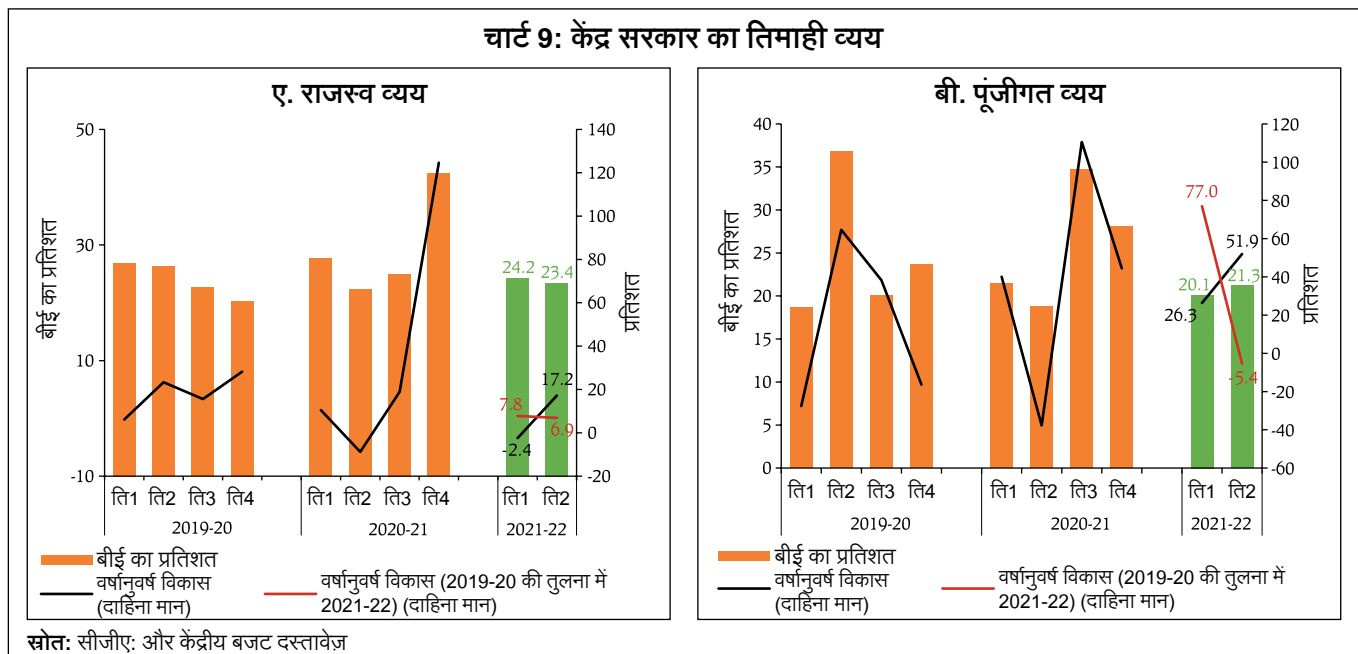
लिए एहतियाती कदम उठाए (इन व्यय सीमाओं को 24 सितंबर, 2021 से शिथिल कर दिया गया है)। नतीजतन, महामारी से संबंधित विस्तारवादी उपायों के बावजूद, कुल व्यय एच 1: 2021-22 के दौरान बीई के 46.7 प्रतिशत पर सीमित रहा, जबकि 2020-21 और 2019-20 की पहली छमाही के दौरान क्रमशः 48.6 प्रतिशत और 53.4 प्रतिशत था।

आगे बढ़ते हुए, 2021-22 की दूसरी छमाही में एक व्यय बढ़ोत्तरी की उम्मीद है, अनुदान के लिए पूरक मांग के दूसरे बैच के संबंध में, जिसने ₹ 2.99 लाख करोड़ के शुद्ध नकद व्यय का प्रस्ताव किया है - राजस्व व्यय पर ₹ 2.33 लाख करोड़ और ₹ 0.66 पूंजीगत व्यय पर लाख करोड़। अनुदान की पहली और दूसरी अनुपूरक मांग में बजट अनुमानों की तुलना में ₹3.23 लाख करोड़ की वृद्धि होती है, जो 2020-21 की दूसरी छमाही की तुलना में कुल व्यय में 2021-22 की दूसरी छमाही में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि और 2019-20 की दूसरी छमाही की तुलना में 82.0 प्रतिशत की वृद्धि में तब्दील हो जाती है (चार्ट 8)।

दूसरी तिमाही में उच्च राजस्व व्यय के कारण पहली छमाही में कुल मिलाकर 6.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में ति.1: 2021-22 में राजस्व व्यय में 2.4 प्रतिशत की कमी आई थी (हालांकि ति.1: 2019-20 की तुलना में 7.8 प्रतिशत अधिक), आंशिक रूप से ति.1: 2020-21 में उच्च आधार के



कारण जब व्यय करना पड़ा और महामारी की पहली लहर से निपटने के लिए उसे बढ़ाना भी पड़ा। व्यय का लक्ष्य रणनीतिक रूप से पूंजीगत व्यय की ओर झुका हुआ था, जो 2020-21 की पहली छमाही में 38.3 प्रतिशत की वर्ष -दर -वर्ष वृद्धि के साथ था (2019-20 की तुलना में 22.3 प्रतिशत की वृद्धि) (चार्ट 9 ए और बी)।



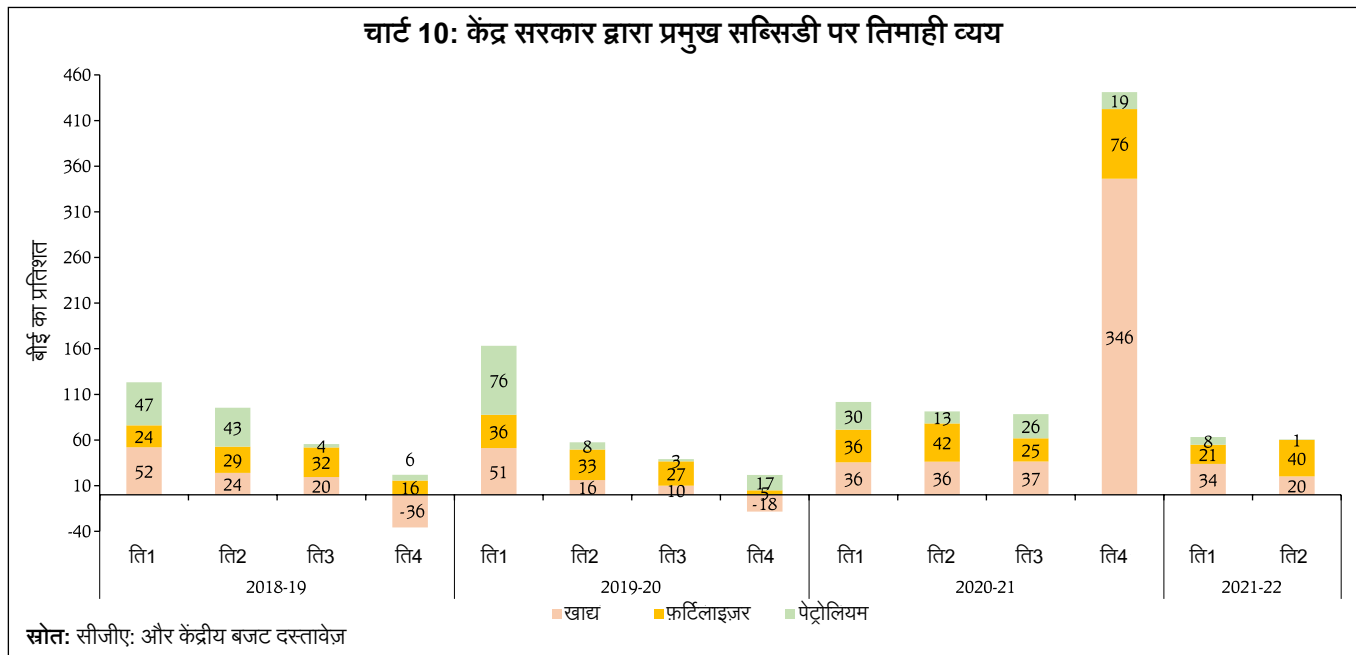
प्रधान मंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के आरंभ होने से भी देश में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) के आधार पर, गति शक्ति प्लेटफॉर्म सभी मौजूदा और प्रस्तावित आर्थिक क्षेत्रों को उनके मल्टी-मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर लिंकेज (रेल, सड़क आदि) के साथ मैप करेगा। विभिन्न मंत्रालयों की अलग-अलग परियोजनाओं के अनुमोदन को गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूपता के दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए, इस प्रकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक समग्र और समन्वित दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा। राज्यों द्वारा पूंजीगत संपत्ति निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र ने नई या जारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने की एक योजना शुरू की है।

केंद्र सरकार की प्रमुख सब्सिडी, जिसमें भोजन, ईंधन और उर्वरक शामिल हैं, पिछले वर्ष की इसी अवधि में बीई के 68.6 प्रतिशत की तुलना में 2021-22 की पहली छमाही में बीई का

53.8 प्रतिशत था। प्रमुख सब्सिडियों पर कुल व्यय का 72.5 प्रतिशत खाद्य सब्सिडी था (चार्ट 10)।

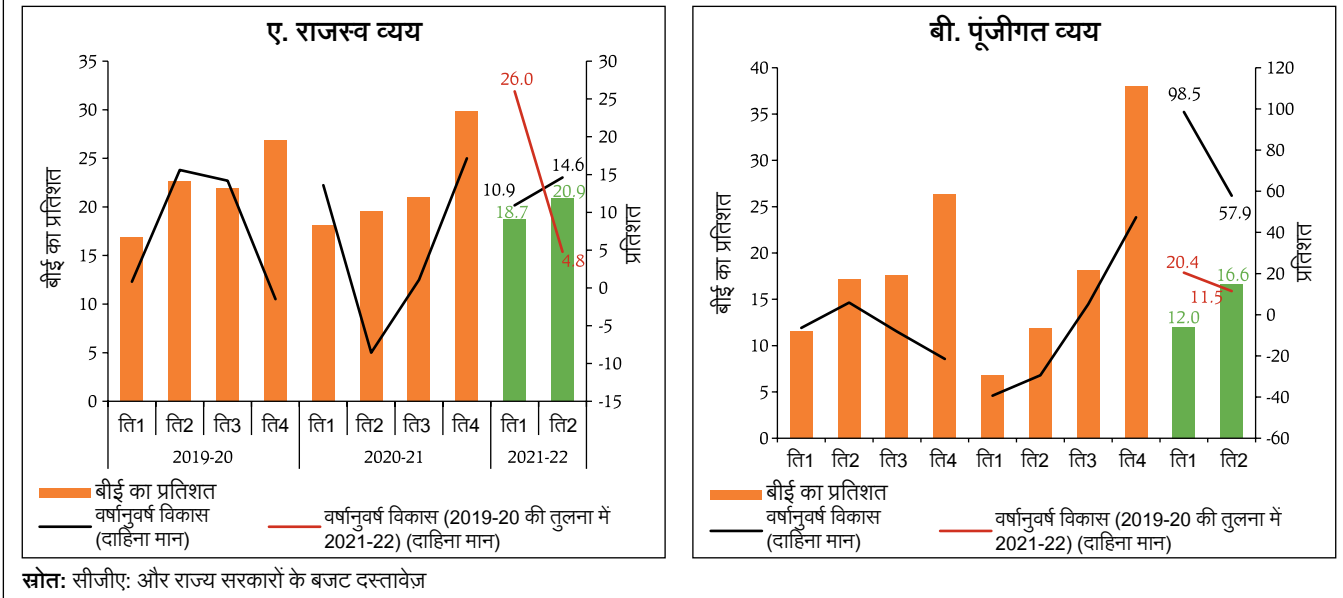
राज्यों के राजस्व व्यय में वर्ष 2021-22 की पहली और दूसरी तिमाही में क्रमशः 10.9 प्रतिशत और 14.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई (वर्ष 2019-20 की इन्हीं तिमाहियों की तुलना में क्रमशः 26.0 प्रतिशत और 4.8 प्रतिशत)। राज्यों के बजट अनुमानों के प्रतिशत के अनुसार, एच1:2021-22 में राजस्व व्यय मोटे तौर पर पिछले वर्ष के पैटर्न के अनुरूप है। पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर, केंद्र द्वारा 'पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से राज्यों को धक्का दिया जा रहा है।⁹ इसके अलावा, ति1:2021-22 के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित पूंजीगत व्यय लक्ष्य को पूरा करने पर, ग्यारह राज्यों को जीएसडीपी के 0.25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त खुले बाजार उधार लेने की अनुमति दी गई है। इस प्रकार, ति1 और ति2:2021-22 (चार्ट 11) के लिए राज्यों के पूंजीगत व्यय में सालाना आधार पर 98.5 प्रतिशत और 57.9 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि देखी गई है।

चार्ट 10: केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख सब्सिडी पर तिमाही व्यय



⁹ इस योजना के तहत राज्य सरकारों को 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 2020-21 के लिए ₹12,000 करोड़ तक की राशि रखी गई थी और 2020-21 में राज्यों को ₹11,830.3 करोड़ की राशि प्रदान की गई थी। 29 अप्रैल, 2021 को, केंद्र ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त 50-वर्षीय ऋण के रूप में ₹15,000 करोड़ तक की अतिरिक्त राशि प्रदान करने के निर्णय की घोषणा की। 25 सितंबर, 2021 तक, केंद्र ने '2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' नामक योजना के तहत 8 राज्यों में ₹2,903.8 करोड़ की पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मंत्रालय ने इन राज्यों, अर्थात् बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम और तेलंगाना को ₹1,393.8 करोड़ की राशि भी जारी की है।

चार्ट 11: राज्य सरकारों का तिमाही व्यय



III. राजकोषीय घाटा और उसका वित्तपोषण

ए. राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार

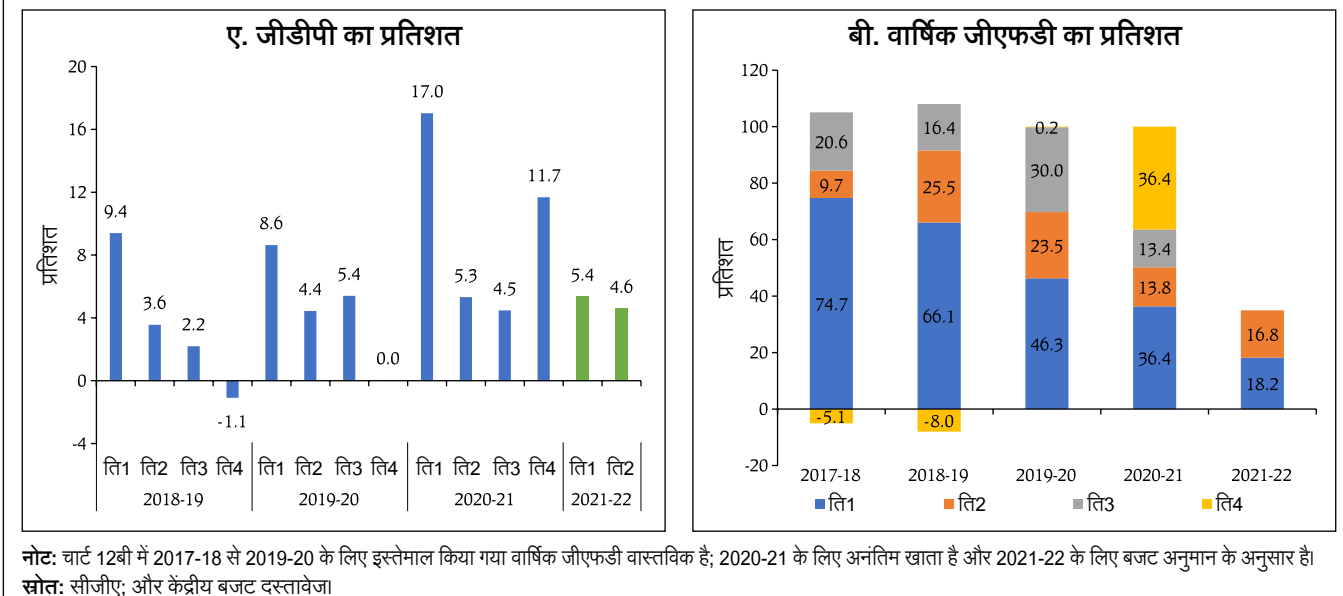
2020-21 (पीए) में सकल घरेलू उत्पाद का 9.2 प्रतिशत जीएफडी प्राप्त करने के बाद, संघ सरकार ने 2025-26 तक 4.5 प्रतिशत से नीचे की मध्यम अवधि के लक्ष्य के साथ 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद के 6.8 प्रतिशत के जीएफडी का बजट रखा

है। हालांकि, बेहतर राजस्व स्थिति और निहित व्यय के कारण, छमाही1: 2021-22 में केंद्र सरकार का जीएफडी, बजट अनुमान का 35.0 प्रतिशत है, जो पिछले वर्षों (चार्ट 12) की तुलना में बहुत कम है।

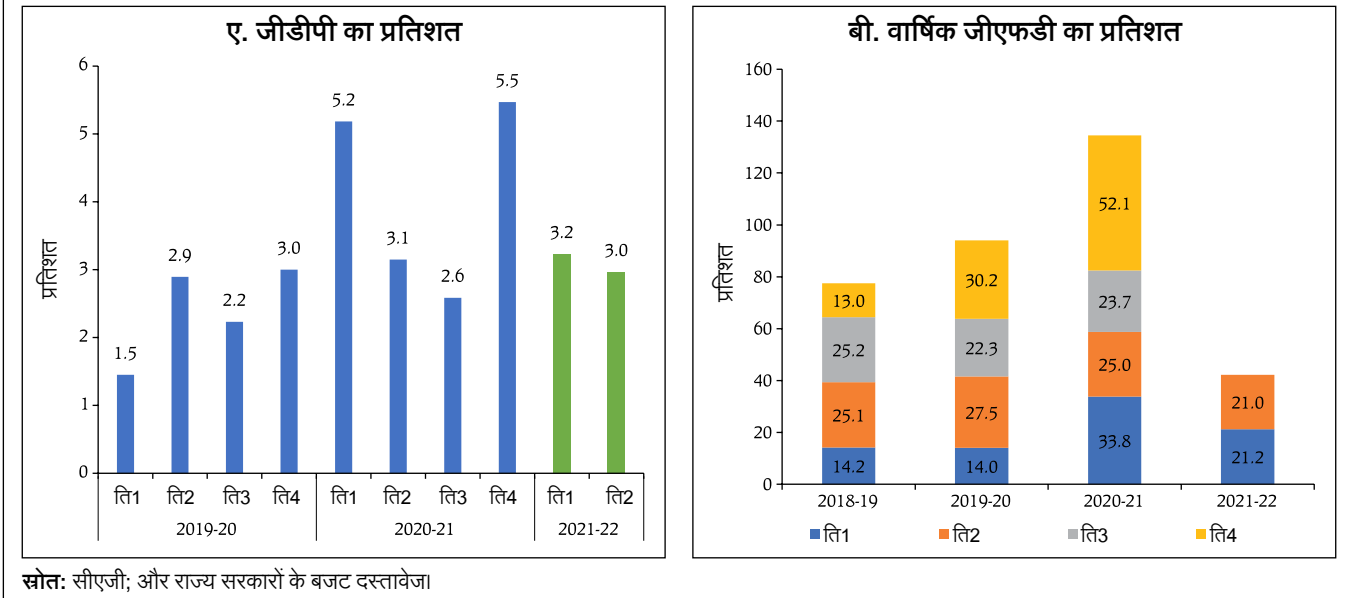
राज्य सरकारें

राज्यों ने 2021-22 के लिए जीडीपी के 3.7 प्रतिशत के जीएफडी का बजट रखा है, जबकि 2020-21 (आरई) में यह 4.7

चार्ट 12: केंद्र का सकल राजकोषीय घाटा



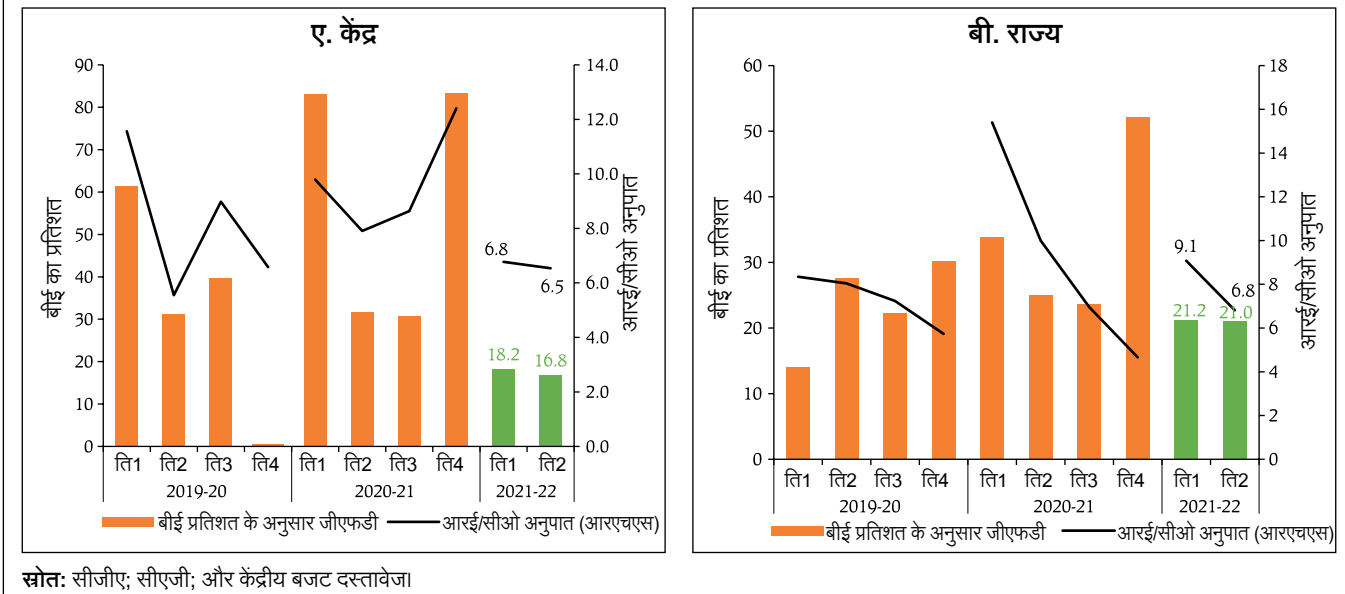
चार्ट 13: राज्य का सकल राजकोषीय घाटा



प्रतिशत था। तिमाही-1: 2021-22 में, उनका जीएफडी, त्रैमासिक सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत है, जो कि तिमाही-1: 2020-21 की तुलना में कम है, लेकिन महामारी पूर्व के वर्षों में देखी गई प्रवृत्ति की तुलना में काफी अधिक है। छमाही-1: 2021-22 में, राज्यों का जीएफडी, बजट अनुमानों का 42.2 प्रतिशत है (चार्ट 13)।

केंद्र और राज्यों दोनों के लिए व्यय की गुणवत्ता, जो राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) के अनुपात में मापा जाता है, छमाही-1: 2020-21 में -जब नई कैपेक्स परियोजनाएं शुरू करना महामारी के कारण गंभीर रूप से बाधित था - घटने के बाद अपने सामान्य स्तर पर वापस आ गया है। सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की विकास की संभावनाओं के लिए शुभ संकेत है (चार्ट 14)।

चार्ट 14: सकल राजकोषीय घाटा और केंद्र और राज्यों के लिए व्यय की गुणवत्ता



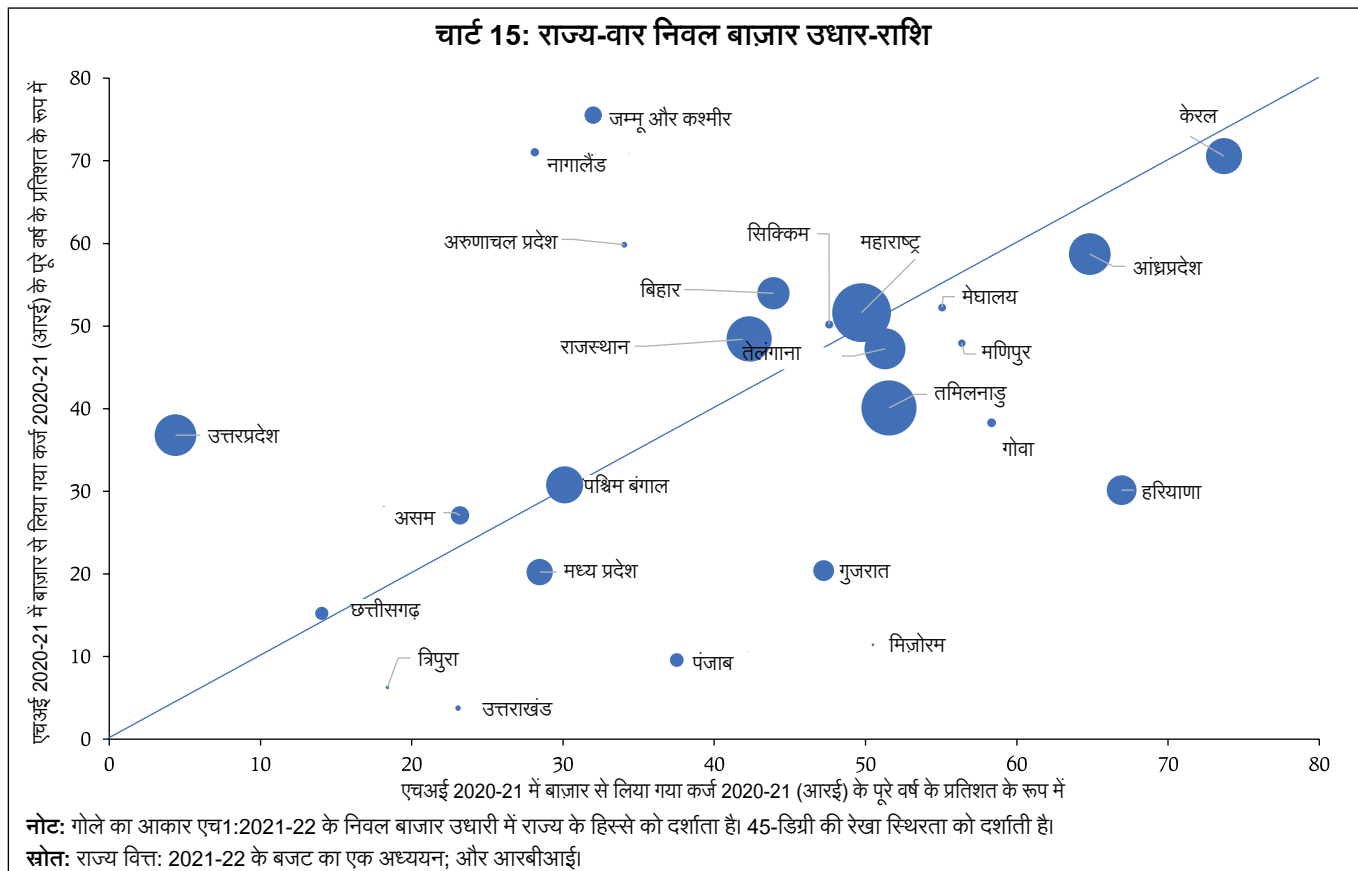
बी. जीएफडी का वित्तपोषण

छमाही1: 2021-22 में, केंद्र सरकार ने 2021-22 के लिए बजटीय निवल बाजार उधार का 57.5 प्रतिशत पूरा किया, जिसने वर्ष की पहली छमाही के दौरान अपने जीएफडी के 90 प्रतिशत से अधिक का वित्त पोषण किया। छमाही1:2021-22 के दौरान केंद्र सरकार के उधार कार्यक्रम को सुचारू रूप से अंजाम दिया गया, जिसमें 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति प्रतिफल 5.97 से 6.26 प्रतिशत के बीच था। यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अब तक अतिरिक्त उधारी का सहारा लिए बिना अपने स्वयं के उधार कार्यक्रम के अंतर्गत जीएसटी संग्रह में कमी के लिए राज्यों को पूरी तरह से मुआवजा दिया।

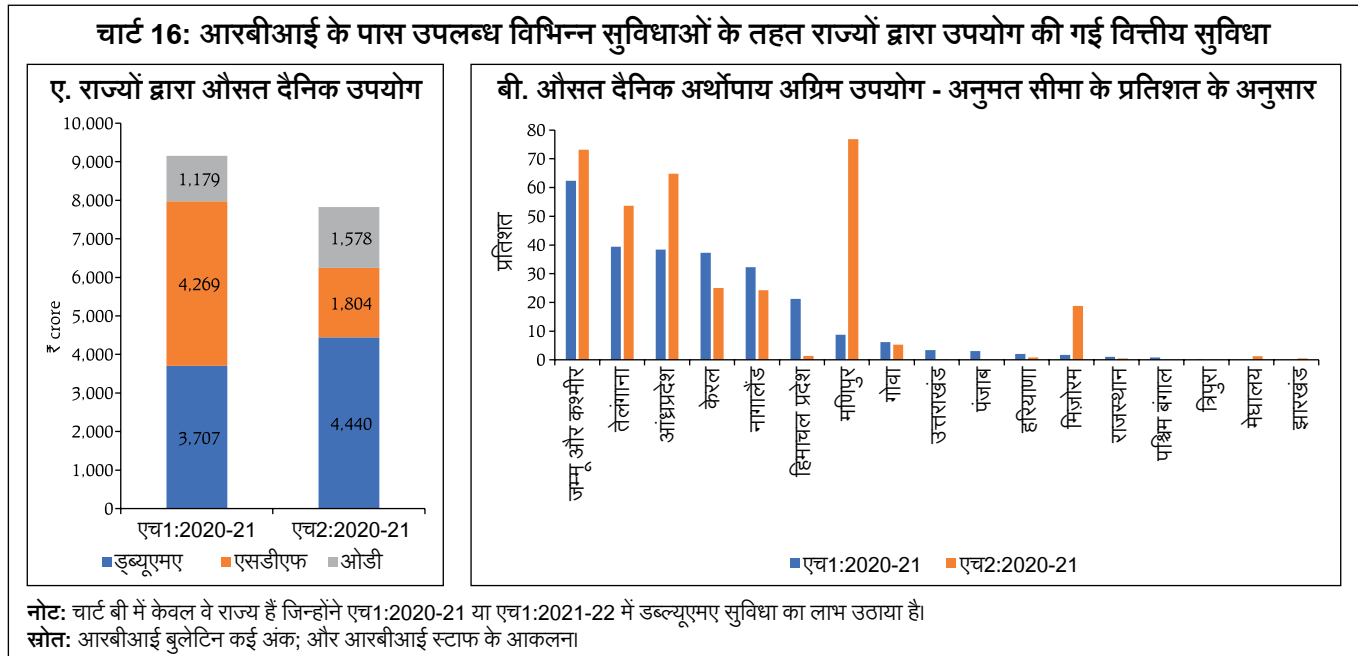
राज्य-स्तरीय विश्लेषण से पहली छमाही के बाजार उधार (बजट अनुमान के प्रतिशत के अनुसार) में एक सामान्यीकृत गिरावट का पता चलता है। बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश, बिहार और

राजस्थान में छमाही1 उधार में वृद्धि देखी गई है। छमाही1:2021-22 में समग्र निवल बाजार उधार जो बजट अनुमान का 34.4 प्रतिशत था और छमाही1:2020-21 (चार्ट 15) की तुलना में वह 20 प्रतिशत कम था।

आरबीआई से विभिन्न सुविधाओं के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त वित्तीय सुविधा पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, छमाही1:2021-22 में कम हो गया¹⁰। तीनों सुविधाओं के तहत समग्र दैनिक उपयोग में छमाही1:2021-22 में वर्ष-दर-वर्ष 14.6 प्रतिशत की कमी देखी गई। समग्र रूप से, जहाँ, अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) और ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधाओं में छमाही1:2021-22 में दैनिक उपयोग में वृद्धि देखी गई है, वहीं विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) के दैनिक उपयोग में 57.8 प्रतिशत की तीव्र गिरावट देखी गई है। प्रमुख राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जम्मू और कश्मीर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम ने छमाही1:2021-22 में, छमाही1:2020-21



¹⁰ आरबीआई द्वारा राज्यों को विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ), अर्थोपाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट (ओडी) के माध्यम से की वित्तीय सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

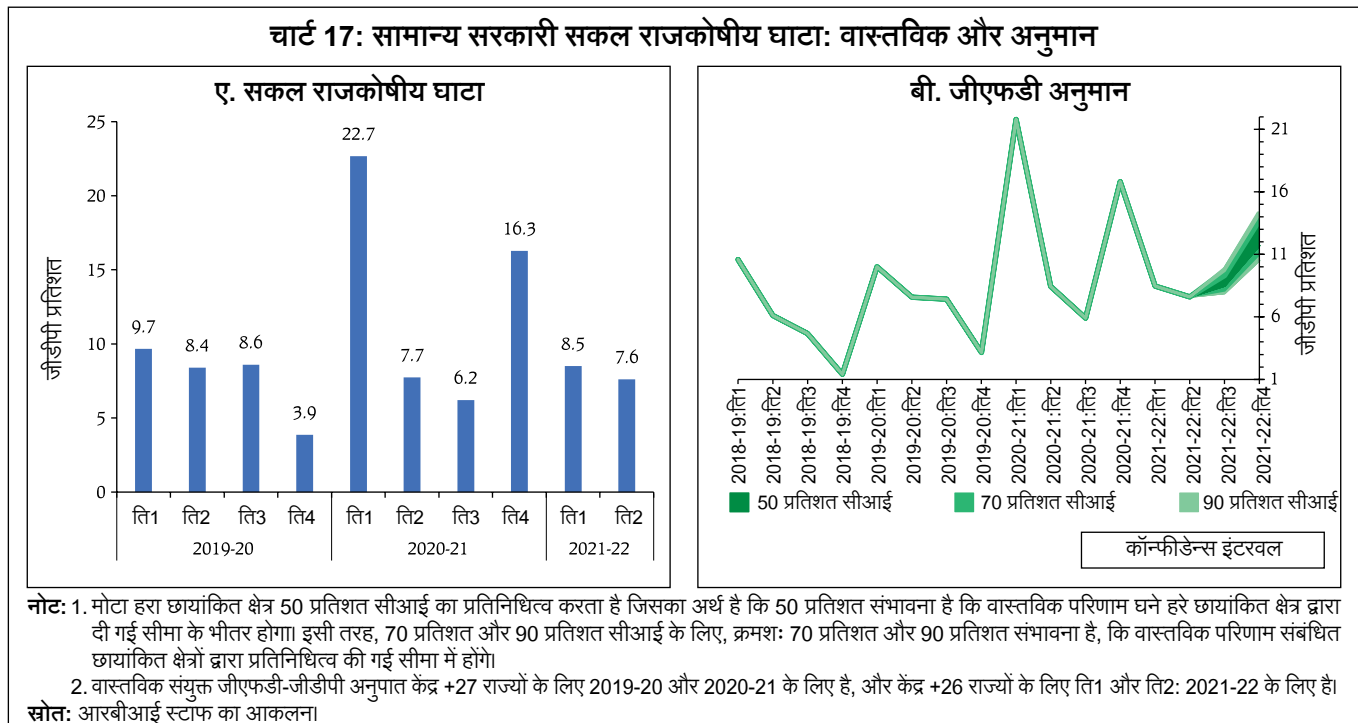


(चार्ट 16) की तुलना में डब्ल्यूएमए के दैनिक उपयोग में वृद्धि देखी है।

IV. सामान्य सरकार वित्त

2021-22 (बीई) के लिए सामान्य सरकार जीएफडी को, 2020-21 (आरई) में 13.3 प्रतिशत से सकल घरेलू उत्पाद के

10.2 प्रतिशत तक समेकित करने का बजट किया गया। सामान्य सरकार पर, राजकोषीय आंकड़े समय पर उपलब्ध कराने के प्रयास को जारी रखते हुए, सामान्य सरकार की तिमाही वित्तीय स्थिति को 2021-22 की दूसरी तिमाही तक संकलित किया गया है। लीक से हटकर, 2020-21 की चौथी तिमाही में सामान्य



सरकार जीएफडी, 2020-21 की दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही की तुलना में अधिक निकला, जिसका मुख्य कारण मार्च 2021 में भारतीय खाद्य निगम एफ़सीआई के पिछले बकाया को बजट प्रावधान में शामिल करना है। केंद्र और राज्यों दोनों द्वारा राजस्व जुटाने में सुधार के कारण, सामान्य सरकारी जीएफडी तिमाही-1 और तिमाही-2: 2021-22 में मंद रहा। आगे बढ़ते हुए, जबकि कर संग्रह में तिमाही-3 और तिमाही-4 में उछाल रहने की उम्मीद है, अपेक्षित व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप, सामान्य सरकार घाटा, तिमाही-3 और तिमाही-4 (अनुमानित) में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 12.9 प्रतिशत हो सकता है। तदनुसार, जीएफडी, छमाही1:2021-22 में जीडीपी के 8.0 प्रतिशत से बढ़कर छमाही 2: 2021-22 में 10.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है।

V. निष्कर्ष

2020-21 में महामारी के कारण सामान्य सरकार राजकोषीय घाटे के व्यापक विस्तार के बाद, केंद्र और राज्यों दोनों ने वृद्धि के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता को बनाए रखते हुए भी अपने 2021-22 के बजट में भरोसेमंद राजकोषीय दृढ़ता के प्रति

प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। छमाही1:2021-22 के दौरान, अनुमानित राजकोषीय दृढ़ता का अनुसरण करते हुए एक उत्साहजनक सुधार दिखा, जिसमें, तिमाही-2 :21-22 में जीडीपी महामारी-पूर्व के स्तर तक बढ़ा गया। कर राजस्व में तेज वृद्धि, बेहतर कर प्रशासन और पूंजीगत व्यय में वृद्धि, मध्यम अवधि में सतत वृद्धि पुनरुत्थान और राजकोषीय समेकन दोनों को प्राप्त करने हेतु अच्छे संकेत हैं। पूंजी परिव्यय के भीतर, हालांकि, केंद्र और राज्यों दोनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे उन क्षेत्रों के लिए व्यय को चैनलाइज़ करें जो निजी निवेश में परिणत हों और अंतर-सामयिक और अंतर-क्षेत्रीय संबंधों के आधार पर गुणक प्रभावों को इष्टतम बना सकें जो उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ावा दे। आगे बढ़ते हुए, वायरस के नए ओमाइक्रोन संस्करण से जुड़ी नई चिंताओं के बावजूद, जैसा कि आर्थिक पुनरुत्थान ने और अधिक गति प्राप्त की है, केंद्र और राज्यों को राजकोषीय नीति सामान्यीकरण की दिशा में विश्वसनीय मध्यम अवधि के दिशानिर्देश प्रदान करने चाहिए ताकि भविष्य के आर्थिक झटके, यदि कोई हों, से निपटने के लिए राजकोषीय बफर को फिर से भरा जा सके।

परिशिष्ट सारणी

सारणी 1: अप्रैल-सितंबर 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार की बजटीय स्थिति								
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बजट अनुमान का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष विकास दर	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1081.0	550.8	1788.4	2020.9	60.4	27.3	96.3	-32.5
1.1. निवल कर राजस्व	920.7	458.5	1545.4	1635.9	59.6	28.0	100.8	-24.5
1.2. गैर-कर राजस्व	160.4	92.3	243.0	385.0	66.0	24.0	73.8	-55.9
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	10.3	5.7	11.5	11.0	89.3	52.1	79.4	-11.3
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ	18.1	14.6	188.0	225.0	9.6	6.5	23.8	-28.9
2.1. ऋण की वसूली	9.0	8.9	13.0	15.0	69.3	59.2	1.7	7.5
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	9.1	5.8	175.0	210.0	5.2	2.8	57.7	-53.2
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	1099.2	565.4	1976.4	2245.9	55.6	25.2	94.4	-32.5
4. राजस्व व्यय	1396.7	1313.6	2929.0	2630.1	47.7	49.9	6.3	1.0
जिसमें से								
(i) ब्याज भुगतान	363.8	305.7	809.7	708.2	44.9	43.2	19.0	12.9
5. पूँजीगत व्यय	229.4	165.8	554.2	412.1	41.4	40.2	38.3	-11.6
जिसमें से								
(i) ऋण और अग्रिम	19.5	17.4	40.4	31.8	48.3	54.7	12.3	17.1
6. कुल व्यय (4+5)	1626.0	1479.4	3483.2	3042.2	46.7	48.6	9.9	-0.6
7. राजस्व घाटा (4-1)	315.6	762.8	1140.6	609.2	27.7	125.2	-58.6	57.4
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	526.9	914.0	1506.8	796.3	35.0	114.8	-42.4	40.3
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	163.1	608.3	697.1	88.1	23.4	690.2	-73.2	59.7

स्रोत: लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 2: केंद्र सरकार के वित्त की त्रैमासिक स्थिति										
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	ति1		ति2		बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष दर वर्ष विकास दर	
					ति1		ति2		2021-22	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	ति1	ति2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्तियाँ	540.0	150.0	541.1	400.8	30.2	7.4	30.3	19.8	260.0	35.0
1.1. निवल कर राजस्व	412.7	134.8	508.0	323.7	26.7	8.2	32.9	19.8	206.1	56.9
1.2. गैर कर राजस्व	127.3	15.2	33.0	77.1	52.4	3.9	13.6	20.0	738.4	-57.1
1.3. ब्याज प्राप्तियाँ	4.7	1.6	5.6	4.1	40.5	14.8	48.9	37.3	186.6	36.9
2. पूँजीगत प्राप्तियाँ	7.4	3.6	10.7	11.1	3.9	1.6	5.7	4.9	107.2	-3.1
2.1. ऋण की वसूली	3.4	3.6	5.6	5.3	26.2	23.9	43.1	35.3	-4.7	6.0
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	4.0	0.0	5.1	5.8	2.3	0.0	2.9	2.8		-11.5
3. कुल प्राप्तियाँ (1+2)	547.4	153.6	551.8	411.8	27.7	6.8	27.9	18.3	256.4	34.0
4. राजस्व व्यय	710.1	727.7	686.5	585.9	24.2	27.7	23.4	22.3	-2.4	17.2
जिसमें से										
(i) ब्याज भुगतान	184.3	160.5	179.5	145.2	22.8	22.7	22.2	20.5	14.8	23.6
5. पूँजीगत व्यय	111.5	88.3	117.9	77.6	20.1	21.4	21.3	18.8	26.3	51.9
जिसमें से										
(i) ऋण और अग्रिम	6.6	13.9	12.9	3.4	16.4	43.9	31.9	10.8	-52.5	276.6
6. कुल व्यय (4+5)	821.6	815.9	804.4	663.5	23.6	26.8	23.1	21.8	0.7	21.2
7. राजस्व घाटा (4-1)	170.2	577.7	145.5	185.1	14.9	94.8	12.8	30.4	-70.5	-21.4
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	274.2	662.4	252.6	251.6	18.2	83.2	16.8	31.6	-58.6	0.4
9. सकल प्राथमिक घाटा (8-4 (i))	90.0	501.9	73.1	106.5	12.9	569.4	10.5	120.8	-82.1	-31.3

स्रोत: लेखा महानियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

सारणी 3: अप्रैल-सितंबर 2021 के दौरान राज्य सरकारों की बजटीय स्थिति								
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)			
	वास्तविक		बजट अनुमान		बजट अनुमान का प्रतिशत		वर्ष दर वर्ष विकास दर	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. राजस्व प्राप्तियां	1,174.3	926.7	3,190.5	3,070.6	36.8	30.2	26.7	-14.6
1.1. कर राजस्व	853.5	652.0	2,172.5	2,181.7	39.3	29.9	30.9	-19.5
1.2. गैर कर राजस्व	83.3	56.7	254.4	250.5	32.7	22.6	46.9	-19.4
1.3. सहायता अनुदान और योगदान	237.6	218.0	763.6	638.4	31.1	34.2	9.0	6.0
2. पूंजीगत प्राप्तियाँ	4.7	2.3	21.0	18.1	22.2	12.7	102.2	-81.5
2.1. ऋण और अग्रिमों की वसूली	4.6	2.2	14.4	14.2	31.5	15.8	102.6	-81.8
2.2. अन्य प्राप्तियाँ	0.1	0.1	6.6	3.9	1.5	1.4	87.1	-11.3
3. कुल प्राप्तियाँ	1,179.0	929.0	3,211.5	3,088.7	36.7	30.1	26.9	-15.4
4. राजस्व व्यय	1,322.2	1,171.8	3,342.1	3,111.5	39.6	37.7	12.8	0.9
4.1. ब्याज भुगतान	154.7	145.3	417.8	370.5	37.0	39.2	6.4	11.5
5. पूंजीगत व्यय	185.7	107.5	648.5	573.5	28.6	18.8	72.7	-33.4
5.1. पूंजी परिव्यय	171.2	97.4	595.2	530.0	28.8	18.4	75.8	-31.5
6. कुल व्यय	1,508.0	1,279.4	3,990.5	3,685.0	37.8	34.7	17.9	-3.3
7. राजस्व घाटा (4-1)	147.9	245.2	151.5	40.9	97.6	599.5	-39.7	223.2
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	329.0	350.4	779.0	596.4	42.2	58.8	-6.1	55.9
9. सकल प्राथमिक घाटा {8-4 (i)}	174.33	205.07	361.23	225.88	48.3	90.8	-15.0	117.2

नोट: डेटा 26 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षका

सारणी 4: राज्य सरकार के वित्त की त्रैमासिक स्थिति										
मद	(₹ हजार करोड़)				(प्रतिशत)					
	वास्तविक				बजट अनुमान का प्रतिशत				वर्ष दर वर्ष विकास दर	
	ति1		ति2		ति1		ति2		2021-22	
	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	2021-22	2020-21	ति1	ति2
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. राजस्व प्राप्ति	535.5	400.6	638.8	526.1	16.8	13.0	20.0	17.1	33.7	21.4
1.1. कर राजस्व	378.4	262.4	475.1	389.6	17.4	12.0	21.9	17.9	44.2	21.9
1.2. गैर कर राजस्व	37.8	27.0	45.4	29.7	14.9	10.8	17.9	11.8	40.2	53.1
1.3. सहायता अनुदान और योगदान	119.3	111.2	118.3	106.9	15.6	17.4	15.5	16.7	7.3	10.7
2. पूंजीगत प्राप्ति	2.1	0.8	2.5	1.5	10.1	4.2	12.0	8.6	182.4	63.3
2.1. ऋण और अग्रिमों की वसूली	2.1	0.7	2.4	1.5	14.6	5.2	16.9	10.6	186.9	61.6
2.2. अन्य प्राप्ति	0.0	0.0	0.1	0.0	0.2	0.5	1.3	0.9	-6.6	133.3
3. कुल प्राप्ति	537.7	401.3	641.3	527.6	16.7	13.0	20.0	17.1	34.0	21.5
4. राजस्व व्यय	625.2	563.6	697.0	608.2	18.7	18.1	20.9	19.5	10.9	14.6
4.1. ब्याज भुगतान	66.5	65.0	88.2	80.3	15.9	17.6	21.1	21.7	2.2	9.8
5. पूंजीगत व्यय	78.0	39.3	107.7	68.3	12.0	6.9	16.6	11.9	98.5	57.9
5.1. पूंजी परिव्यय	68.9	36.6	102.3	60.8	11.6	6.9	17.2	11.5	88.3	68.3
6. कुल व्यय	703.2	602.9	804.8	676.5	17.6	16.4	20.2	18.4	16.6	19.0
7. राजस्व घाटा	89.7	163.0	58.3	82.1	59.2	398.7	38.5	200.8	-45.0	-29.0
8. राजकोषीय घाटा (6-3)	165.5	201.6	163.5	148.8	21.2	33.8	21.0	25.0	-17.9	9.8
9. सकल प्राथमिक घाटा (8 - 4.1)	99.1	136.6	75.3	68.5	27.4	60.5	20.8	30.3	-27.5	9.9

नोट: डेटा 26 राज्यों से संबंधित है।

स्रोत: भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक।

सारणी 5: कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित प्रमुख नीतिगत घोषणाओं का कालक्रम (मार्च 2021 के बाद)	
घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
30 मार्च, 2021	<ul style="list-style-type: none"> केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 30,000 करोड़ रुपये के साथ-साथ राज्यों /केंद्र शासित प्रदेशों को आईजीएसटी तदर्थ निपटान के रूप में 28,000 करोड़ रुपये जारी किए।
31 मार्च, 2021	<ul style="list-style-type: none"> आधार नंबर की सूचना देने और उसे स्थायी खाता संख्या (पैन) से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई थी। परिवाद निपटान पैनल (डीआरपी) द्वारा जारी निर्देश के लिए परिणामी आदेश पारित करने और समानीकरण लेवी विवरणों को प्रोसेस करने के लिए समय-सीमा को 30 अप्रैल, 2021 तक बढ़ा दिया गया था। ईसीएलजीएस 1.0 और 2.0 की वैधता को 30 जून, 2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि के लिए गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया था। ECLGS 3.0 को आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन, अवकाश और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए पेश किया गया था जो निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं। योजना के तहत वितरण की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है। एमओएफ ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को 2020-21 के संशोधित अनुमानों के अलावा अतिरिक्त न्यागमन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये जारी किए।
1 अप्रैल, 2021	<ul style="list-style-type: none"> केन्द्र ने आर्थिक सुधार को समय पर बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत राज्यों को 11,830 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्र ने वित्त वर्ष 2020-21 में राज्यों को अतिरिक्त न्यागमन के रूप में 45,000 करोड़ रुपये जारी किए, जो 2020-21 (आरई) की तुलना में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि है।
22 अप्रैल, 2021	कतिपय नकदी प्रबंधन दिशानिर्देशों से केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के लिए एक अस्थायी छूट प्रदान की गई है जो बड़े भुगतानों को जारी करने के समय को निर्धारित करती है ताकि महीने /तिमाही के दौरान कर राजस्व के अंतर्वाह के साथ उनका मिलान किया जा सके।
23 अप्रैल, 2021	मई और जून 2021 के दौरान प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत मुफ्त अनाज के वितरण की घोषणा की गई थी।
24 अप्रैल, 2021	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020 के तहत भुगतान की समय सीमा, एक अतिरिक्त राशि के बिना, 30 जून, 2021 तक बढ़ा दी गई। आयकर अधिनियम के तहत आदेश पारित करने के लिए विभिन्न समय सीमाओं को 30 जून, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन थेरेपी से संबंधित उपकरण जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक आदि और कोविड-19 टीकों को 31 जुलाई, 2021 तक मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई है।
30 अप्रैल, 2021	<ul style="list-style-type: none"> बिना सीमा शुल्क मंजूरी के पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टलों से खरीदे गए व्यक्तिगत उपयोग के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात में 31 जुलाई, 2021 तक छूट। आयातित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर देय जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है। COVID-19 टेस्टिंग प्रयासों को पूरा करने हेतु, इंप्लेमेंटरी डायमोनोस्टिक (मार्कर) किट और रेमडेसिविर इंजेक्शन के आयात पर 31 अक्टूबर तक मूल सीमा शुल्क से छूट। भारत सरकार ने पूंजीगत परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए ब्याज मुक्त 50 साल के ऋण के रूप में राज्यों को 15,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त राशि प्रदान करने की घोषणा की। इस समग्र सीमा का एक तिहाई उन राज्यों को प्रदान किया जाएगा जो मुद्रीकरण और / या अपनी परिसंपत्तियों का, उनके द्वारा प्राप्त राशि के 33 से 100 प्रतिशत की सीमा में विनिवेश करते हैं।

(जारी...)

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
1 मई, 2021	<ul style="list-style-type: none"> एक विशेष व्यवस्था के रूप में, केंद्र सरकार ने सामान्य समय से पहले, सभी राज्यों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के लिए केंद्रीय हिस्से की 2021-22 की पहली किस्त ₹8,874 करोड़ जारी की है। इस राशि का 50 प्रतिशत तक राज्यों द्वारा कोविड-19 रोकथाम उपायों के लिए उपयोग किया जा सकता है। आयकर अधिनियम के तहत विभिन्न अनुपालनों के लिए समय सीमा 31 मई, 2021 तक बढ़ा दी गई है।
2 मई, 2021	<p>जीएसटी भुगतानकर्ताओं के लिए राहत के उपाय</p> <ul style="list-style-type: none"> विलंबित कर भुगतान के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सामान्य ब्याज दर के बदले ब्याज की रियायती दें। कर अवधि मार्च 2021 और अप्रैल 2021 के लिए नियत तिथि से परे प्रस्तुत फॉर्म GSTR-3B में रिटर्न के संबंध में 15 दिनों के लिए विलंब शुल्क माफ कर दिया गया। जीएसटी अधिनियम के तहत किसी भी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति द्वारा विभिन्न कार्यों को पूरा करने की समय सीमा, जो 15 अप्रैल, 2021 से 30 मई, 2021 तक की अवधि के दौरान आती है, को 31 मई, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।
3 मई, 2021	कोविड-19 राहत सामग्री (पहले से ही सीमा शुल्क से छूट) के आयात पर आईजीएसटी से छूट जो 30 जून, 2021 तक मुफ्त वितरण के लिए भारत के बाहर से दान/प्राप्त किया गया।
9 मई, 2021	केंद्र ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को अनुदान प्रदान करने के लिए 25 राज्यों को ₹8,923.8 करोड़ की राशि जारी की। जारी की गई राशि वर्ष 2021-22 के लिए 'अनटाइड ग्रांट' की पहली किस्त थी, जिसका उपयोग आरएलबी द्वारा अन्य बातों के अलावा, COVID-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यक विभिन्न रोकथाम और शमन उपायों के लिए किया जाएगा।
19 मई, 2021	14,775 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की गई थी।
20 मई, 2021	आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कतिपय अनुपालनों के लिए समय-सीमा बढ़ा दी गई थी।
28 मई, 2021	<ul style="list-style-type: none"> 43वीं जीएसटी परिषद की बैठक ने आईजीएसटी से 31 अगस्त, 2021 तक कई निर्दिष्ट COVID-19 संबंधित सामानों जैसे कि चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और अन्य ऑक्सीजन भंडारण और परिवहन उपकरण, कुछ डायमोनोस्टिक मार्कर परीक्षण किट और COVID-19 टीके, आदि के लिए पूर्ण छूट की सिफारिश की। परिषद ने COVID-19 संबंधित राहत उपाय के रूप में GST करदाताओं को कुछ छूट देने की भी सिफारिश की।
30 मई, 2021	आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को ऑनसाइट ऑक्सीजन उत्पादन, ईसीएलजीएस 3.0 के व्यापक कवरेज और ईसीएलजीएस 1.0 के लिए अवधि में वृद्धि के लिए ईसीएलजीएस 4.0 के साथ विस्तारित किया गया था।
12 जून, 2021	44वीं जीएसटी परिषद ने 30 सितंबर, 2021 तक COVID-19 राहत और प्रबंधन में उपयोग की जा रही विशिष्ट वस्तुओं पर GST दरों को कम कर दिया।
25 जून, 2021	सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत निर्दिष्ट अनुपालन की समय-सीमा में और विस्तार दिया और COVID-19 उपचार पर खर्च के लिए कर छूट और COVID-19 के कारण मृत्यु पर प्राप्त अनुग्रह राशि की घोषणा की।
28 जून, 2021	<ul style="list-style-type: none"> स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई थी। ईसीएलजीएस का विस्तार स्वीकार्य गारंटी की समग्र सीमा के साथ किया गया था, जिसे 3 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया था। सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए ऋण गारंटी योजना की घोषणा की गई।

(जारी...)

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> 5 लाख पर्यटकों को एक महीने का मुफ्त पर्यटक वीजा या 31 मार्च, 2022 तक, जो भी पहले हो। आत्मा निर्भर भारत रोजगार योजना (ANBRY) के तहत पंजीकरण की तारीख 30 जून, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गई थी। पीएमजीकेएवाई के तहत मुफ्त अनाज के प्रावधान को नवंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया था। 23,220 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और मानव संसाधनों को मजबूत करने के लिए एक योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें अल्पकालिक आपातकालीन तैयारियों और बच्चों और बाल चिकित्सा देखभाल / बाल चिकित्सा बिस्तरों पर विशेष जोर दिया गया था। जलवायु प्रतिरोध विशेष फसल किस्मों की रिलीज की घोषणा की गई थी। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (एनईआरएएमएसी) के लिए 7745 करोड़ रुपये का पुनरुद्धार पैकेज प्रदान किया जाएगा। परियोजना निर्यात के लिए 33,000 करोड़ रुपये का बढ़ावा राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाते (एनईआईए) के माध्यम से प्रदान किया गया था। निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) में 5 वर्षों में इक्विटी निवेश की घोषणा निर्यात बीमा कवर को 88,000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के लिए की गई थी। भारत नेट पीपीपी मॉडल के माध्यम से प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड के लिए 19,041 करोड़ रुपये प्रदान किए गए थे। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। सुधार-आधारित परिणाम-लिंकड विद्युत वितरण योजना के लिए ₹3.03 लाख करोड़ की घोषणा की गई थी, जिसमें से केंद्र सरकार का हिस्सा ₹97,631 करोड़ होगा। पीपीपी परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन और मुख्य अवसंरचना परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए नई सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की जाएगी।
14 जुलाई, 2021	केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, परिधान / वस्त्र और मेड-अप के निर्यात पर, निर्यात उत्पादों पर कर और ड्यूटी की छूट (आरओडीटीईपी) योजना से अलग, राज्य और केंद्रीय करों और उगाही (आरओएससीटीएल) की छूट को उसी दरों के साथ, जैसा कि मार्च 2019 में कपड़ा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था, जारी रखने के लिए अपनी मंजूरी दे दी। यह योजना 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी।
27 जुलाई, 2021	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 13.07.2021 को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को "कोविड-19 के बफर स्टॉक प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश" जारी किए, जिसमें उनसे भविष्य में मामलों में किसी भी संभव उछाल के लिए दवाओं की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से आवश्यक खरीद प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर शुरू करने का अनुरोध किया गया था।
29 अगस्त, 2021	विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि और जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकरण रद्द करने के निरस्तीकरण के लिए आवेदन दायर करने की समय सीमा बढ़ा दी गई थी।
14 सितंबर, 2021	वित्तीय मंत्रालय द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित लक्ष्य को ग्यारह राज्यों ने 2021-22 की पहली तिमाही में हासिल किया। प्रोत्साहन के रूप में, इन राज्यों को व्यय विभाग द्वारा ₹15,721 करोड़ की अतिरिक्त राशि उधार लेने की अनुमति दी गई थी। दिया गया अतिरिक्त खुला बाजार उधार अनुमति उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.25 प्रतिशत के बराबर है।
17 सितंबर, 2021	<ul style="list-style-type: none"> सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा, आयकर अधिनियम के तहत दंड की कार्यवाही पूरी करने की नियत तिथि और बेनामी संपत्ति लेनदेन प्रतिषेध अधिनियम, 1988 के तहत निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समय सीमा बढ़ा दी है।

(जारी...)

घोषणा की तिथि	नीतिगत पहल
	<ul style="list-style-type: none"> 45वीं GST परिषद ने कुछ COVID-19 उपचार दवाओं पर मौजूदा रियायती GST दरों को 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ाने और कुछ और COVID-19 उपचार दवाओं पर GST दर को 31 दिसंबर, 2021 तक घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश की। केंद्र ने शहरी स्थानीय निकायों के लिए 11 राज्यों को 2,427 करोड़ रुपये की राशि जारी की। जारी की गई राशि वर्ष 2021-22 के लिए बंधे हुए अनुदान की पहली किस्त है।
25 सितंबर, 2021	केंद्र ने '2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता' नामक योजना के तहत 8 राज्यों में 2,903.80 करोड़ रुपये की पूंजीगत परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन राज्यों को 1,39383 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।
29 सितंबर, 2021	ईसीएलजीएस की समयसीमा को 31.03.2022 तक या योजना के तहत 4.5 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया गया था। इसके अलावा, इस योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि को 30.06.2022 तक बढ़ा दिया गया था और कोविड की दूसरी लहर से प्रभावित व्यवसायों को समर्थन देने के लिए योजना में कुछ संशोधन किए गए थे।
1 अक्टूबर, 2021	केंद्र ने 25.09.2021 को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत सहायता की वस्तुओं और मानदंडों को संशोधित किया गया, जिसमें कोविड -19 के कारण मृतक के परिजनों को अनुग्रह राशि देने का प्रावधान किया गया। राज्य सरकारों के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, एसडीआरएफ में उपलब्ध प्रारंभिक शेष राशि के अलावा, राज्य का हिस्सा सहित उनके एसडीआरएफ में ₹ 23,186.40 करोड़ की राशि होगी, जो उन्हें, COVID-19 के कारण मृतक के परिजन और अन्य अधिसूचित आपदाओं पर राहत प्रदान करने हेतु अनुग्रह राशि प्रदान करने के खर्च को पूरा करने के लिए होगा।
24 नवंबर, 2021	पीएमजीकेवाई, जिसके तहत लाभार्थियों को उनके सामान्य मासिक कोटे के अलावा 5 किलोग्राम गेहूं या चावल प्रदान किया जाता है, को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

भारत के परिधान निर्यात में क्या-क्या कठिनाइयां हैं*

भारत परंपरागत रूप से कपड़ा क्षेत्र, विशेष रूप से परिधान निर्माण में तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में रहा है। परिधान निर्यात भारत के निर्यात समूह का एक प्रमुख घटक है और घरेलू अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, हालिया वर्षों में परिधान निर्यात में ठहराव आया है, जिसका आंशिक कारण बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण है। यह आलेख भारत सहित प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं से परिधानों के निर्यात को निर्देशित करने में गंतव्य देश की प्रशुल्क व्यवस्था की भूमिका का विश्लेषण करता है। निष्कर्ष दर्शाते हैं कि बांग्लादेश और वियतनाम सहित विकासशील देशों से परिधान निर्यात में तेजी से वृद्धि के लिए अधिमानी प्रशुल्क सुविधा एक प्रमुख योगदान कारक रहा है। इन नीतियों ने कंबोडिया जैसे देशों को भी सक्षम बनाया है, जो हाल तक सीमांत आपूर्तिकर्ता थे, जो मूल मानदंडों के नियमों में छूट के साथ-साथ कम प्रशुल्क से लाभान्वित हुए थे। यह आलेख इस क्षेत्र की क्षमता का उपयोग करने के लिए नीतिगत सुझावों के साथ समाप्त होता है।

भूमिका

भारत के परिधान उद्योग को भारतीय उपमहाद्वीप, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक ऐतिहासिक अभिलेखों में भी इसके संकेत मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर भी परिधान दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े निर्यात उद्योगों में से एक है। परिधान उत्पादन राष्ट्रीय विकास के लिए एक गतिशक्ति है, और अक्सर इसकी निम्न निश्चित लागत और गहन-श्रम विनिर्माण पर जोर देने के कारण निर्यात-उन्मुख औद्योगीकरण में प्रवृत्त देशों के लिए आदर्श आरंभिक उद्योग है (अधिकारी और वीराटुंग, 2006; गेरेफी, 1999)।

परिधान निर्माण व्यापक वस्त्र उद्योग का एक अभिन्न अंग है, और कुल वस्त्र उद्योग के दो-तिहाई से अधिक भाग के लिए उत्तरदायी होने का अनुमान है। इसके अलावा, परिधान उद्योग के

* यह आलेख भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की श्रीमती रेखा मिश्र और श्री शोभित गोयल द्वारा तैयार किया गया है। इसमें व्यक्त विचार लेखकों के हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हों।

बाकी कपड़ा उद्योग के साथ सुदृढ़ उत्पादन-पूर्व संबंध हैं। तैयार परिधान तीन चरण मूल्य श्रृंखला का एक अंतिम उत्पाद है: पहला चरण कच्चे रेशों को सूत में परिवर्तित करने का; दूसरा चरण धागों को कपड़े में बदलने; और इसका अंतिम चरण एक परिधान में कपड़े की रंगाई/ मुद्रण, सिलाई और परिष्करण करने का होता है (हबीब, 2009)। परिधान उद्योग की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि विस्तृत वस्त्र उद्योग में परिचालित उत्पादन-पूर्व ये व्यवस्थाएं कितनी दक्ष और प्रतिस्पर्धी हैं। यदि एक परिधान निर्माता का अनिर्मित कपड़े और सहायक उत्पादों की आपूर्ति पर प्रभावी नियंत्रण है, तो उत्पादन प्रक्रिया के न केवल कुशल और विश्वसनीय होने की उम्मीद है, बल्कि यह अतिरिक्त कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता का स्रोत भी हो सकती है (सिद्धीकी, 2005)। इस प्रकार, परिधान उद्योग की संभावनाओं और कार्य-निष्पादन का समग्र कपड़ा क्षेत्र और इसके कार्य-निष्पादन पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है और इसके विलोमतः होता है।

विभिन्न कारकों के कारण पारंपरिक रूप से भारत ने कपड़ा क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ प्राप्त किया है। कपड़ा क्षेत्र का कुल सकल घरेलू उत्पाद में दो प्रतिशत से अधिक का योगदान है, इस प्रकार विनिर्माण क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद का 12-14 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, कपड़ा क्षेत्र अत्यधिक श्रम-प्रधान होने के कारण विशेष रूप से अकुशल और अर्ध-कुशल श्रम बल के लिए रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है।

कपड़ा क्षेत्र के बारे में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि यह भारत के निर्यात समूह का एक बड़ा भाग है। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में भारत के कुल निर्यात में वस्त्र निर्यात का हिस्सा घट रहा है। इसके अलावा, भारत के कपड़ा निर्यात को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि भारत का कपड़ा क्षेत्र एक काफी अधिक शोध का विषय है, हालांकि, हालिया दिनों में भारत के कपड़ा निर्यात, विशेष रूप से परिधान निर्यात में लगभग निष्क्रियता की स्थिति में पहुँचने में उत्तरदायी अंतर्निहित कारकों की जांच करने वाले बहुत कम अध्ययन हुए हैं। यह आलेख साहित्य में इस अंतर को पाटने का प्रयास करता है और विशेष रूप से गंतव्य बाजारों में प्रशुल्क व्यवस्था की नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण भी करता है। आलेख का प्राथमिक केंद्र बिंदु भारत से परिधान निर्यात में इस गिरावट के

लिए उत्तरदायी कारकों की जांच करना है। इसके अलावा, यह आलेख विश्व स्तर पर अन्य प्रमुख परिधान निर्यातकों के निर्यात कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करता है और भारत के परिधान निर्यात को बाधित करने वाले प्रमुख कारकों के बारे में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए इन निष्कर्षों की भारत के निर्यात कार्य-निष्पादन के साथ तुलना करता है।

शेष पेपर इस प्रकार से नियोजित किया गया है: खंड II भारत के कपड़ा और परिधान क्षेत्र से संबंधित शोधपरक तथ्यों की रूपरेखा तैयार करता है। वैश्विक स्तर पर किए गए प्रमुख नीतिगत परिवर्तन खंड III में दिए गए हैं। खंड IV वैश्विक परिधान बाजार का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है। इस विषय पर प्रासंगिक साहित्य की समीक्षा खंड V में सम्मिलित है। मॉडल विनिर्देशन और अनुभवजन्य परिणामों की चर्चा खंड VI में की गई है। खंड VII समापन टिप्पणियों और भविष्य के लिए संभावित मार्ग बताता है।

II. शोधपरक तथ्य

अर्थव्यवस्था के लिए 2012-17 की अवधि के दौरान कुल विनिर्माण में 11 प्रतिशत से अधिक और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2 प्रतिशत से अधिक का योगदान देने वाला कपड़ा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस अवधि के दौरान कुल विनिर्माण और समग्र सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्रों की हिस्सेदारी में मामूली वृद्धि दर्ज की गई (सारणी 1)।

कपड़ा क्षेत्र, विशेष रूप से परिधान विनिर्माण, एक प्रमुख रोजगार सृजन क्षेत्र है। 2016-17 में संगठित कपड़ा और परिधान क्षेत्र ने करीब 27 लाख लोगों को रोजगार दिया, इस प्रकार यह विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार का 18.1 प्रतिशत हिस्सा है (सारणी 2)। कुल मिलाकर विनिर्माण क्षेत्र में कपड़ा क्षेत्र के उत्पादन की

सारणी 1: भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा क्षेत्र की भूमिका

वर्ष	कपड़ा क्षेत्र के लिए मूल कीमतों पर जीवीए (₹ करोड़)	सकल देशी उत्पाद में कपड़ा क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत)	
		विनिर्माण	समग्र
2012-13	184.335	11.71	2.14
2013-14	197.617	11.92	2.16
2014-15	226.770	13.50	2.33
2015-16	232.718	12.43	2.22
2016-17	259.108	12.65	2.30

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

सारणी 2: रोजगार सृजन में संगठित कपड़ा क्षेत्र की भूमिका

वर्ष	कपड़ा और परिधान क्षेत्र में रोजगार (संख्या में)	विनिर्माण क्षेत्र में कुल रोजगार में कपड़ा क्षेत्र का हिस्सा (प्रतिशत)
2012-13	23,31,619	18.00
2013-14	24,74,903	18.28
2014-15	25,26,610	18.20
2015-16	26,48,238	18.52
2016-17	26,97,123	18.09

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

तुलना में रोजगार में अधिक हिस्सेदारी, (2016-17 में उत्पादन में 12.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी की तुलना में रोजगार में 18.1 प्रतिशत हिस्सा), कपड़ा और परिधान क्षेत्र के गहन श्रम की प्रकृति पर प्रकाश डालती है। कपड़ा क्षेत्र न केवल अत्यधिक श्रम प्रधान है, बल्कि यह अकुशल और अर्ध-कुशल श्रम बल को भी रोजगार देता है और महिलाओं के लिए औपचारिक क्षेत्र के रोजगार का एक स्रोत है (पनगरिया, 2018)।

इसके अलावा, वस्त्र भी निर्यात का एक प्रमुख घटक है जिसने 2018-19 में निर्यात उपार्जन में 40.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया, जिसमें से परिधान निर्यात से 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अर्जन हुआ था (सारणी 3)। हालांकि, हाल के वर्षों में भारत के निर्यात समूह में कुल मिलाकर परिधान और वस्त्र, दोनों की हिस्सेदारी में अत्यधिक कमी आयी है।

सारणी 3: निर्यात में कपड़ा और परिधान क्षेत्र की भूमिका (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2002-03	2006-07	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल कपड़ा निर्यात	12412	19147	39288	39011	39239	40431
जिनमें से: परिधान	5334	8282	16966	17368	16705	16176
समग्र निर्यात	52719	126263	262290	275852	303376	329536
निर्यात में वस्त्रों का हिस्सा (प्रतिशत)	23.5	15.2	15.0	14.1	12.9	12.3
निर्यात में परिधानों का हिस्सा (प्रतिशत)	10.1	6.6	6.5	6.3	5.5	4.9

स्रोत: वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।

वस्त्र और परिधान उद्योग के वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता है। भारतीय वस्त्र उद्योग में कुछ अंतर्निहित शक्तियां हैं। भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी तकनीकी और कुशल श्रमशक्ति है; इस प्रकार इसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है जिसमें 220 मिलियन से अधिक मध्यम आय वाले लोग हैं। भारत में कपास की खेती के अंतर्गत आने वाली भूमि विश्व में कपास की खेती के तहत आने वाली कुल भूमि का लगभग एक चौथाई हिस्सा है। इसलिए इसकी घरेलू कपास तक प्रचुर मात्रा में और आम कीमतों तक सुलभ पहुँच है, जो अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक हैं। भारत में अपशिष्ट उत्पत्ति उत्पादन की कुल लागत का सबसे कम 9 प्रतिशत है जबकि अन्य देशों में यह 11 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच है। भारत में श्रम लागत भी सबसे कम है, यानी कुल उत्पादन का 3 प्रतिशत जबकि अन्य देशों में श्रम लागत 5 प्रतिशत से 38 प्रतिशत के बीच है, सबसे अधिक इटली और जापान में क्रमशः 38 प्रतिशत और 29 प्रतिशत है (कट्टी और सेन, 1999)। इस प्रकार भारत में वस्त्र उद्योग के कार्य-निष्पादन को बेहतर बनाने के लिए सभी आधारभूत आवश्यकताएं उपलब्ध हैं।

हालांकि, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में इन कारकों की उपस्थिति से भारत का एकीकरण सुगम नहीं बन पाया है। परिधान श्रृंखलाएं खरीदार द्वारा संचालित श्रृंखलाएं हैं, जहां उत्पादन को विश्व स्तर पर फैले हुए उत्पादन नेटवर्क में किया जाता है, जो प्रमुख फर्मों द्वारा समन्वित होता है। उत्पाद में मूल्य वर्धन करने वाली गतिविधियां (जैसे डिज़ाइन और ब्रांडिंग) अक्सर प्रमुख फर्मों द्वारा समन्वित की जाती हैं। भारत के परिधान उद्योग के मंद एकीकरण की पृष्ठभूमि में उत्पादन सामग्री से जुड़ी लागतों और निर्यात/आयात में लगने वाले समय जैसे कारण उत्तरदायी हैं। इस मंद एकीकरण के अन्य संभावित कारण घरेलू बाजार का बड़ा आकार है। इसके अलावा, निर्यात के उच्च मानकों और सख्त डिलीवरी कार्यक्रम निर्धारण के कारण, कुछ कंपनियां घरेलू

बाजार पर निर्भर रहना पसंद करती हैं। हालांकि कपड़ा और परिधान निर्यात की मात्रा बढ़ी है, फिर भी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में मंद एकीकरण के कारण उनकी वृद्धि की गति समग्र निर्यात में वृद्धि से पिछड़ गई है, विशेष रूप से पिछले कुछ वर्षों में जिससे वस्त्र निर्यात में गिरावट आयी है।

III. नीतिगत व्यवस्था: कपड़ा क्षेत्र के लिए वैश्विक व्यापार समझौते

मल्टी फाइबर एग्रीमेंट (एमएफए), 1974 का विकासशील देशों द्वारा परिधान और कपड़ा निर्यात और परिधान निर्यात से संबंधित वैश्विक मूल्य श्रृंखला पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। चीन जैसे अत्यधिक प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्ताओं से आयात को सीमित करके संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) के घरेलू उद्योगों की रक्षा के लिए एमएफए का स्वरूप तैयार किया गया था। इसने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई यूरोपीय देशों जैसे विकसित देशों को विकासशील देशों से उनके द्वारा आयातित परिधान और कपड़ा वस्तुओं पर कोटा और अधिमाम्य प्रशुल्क स्थापित करने की अनुमति दी। इस प्रकार, एमएफए ने विकासशील देशों द्वारा प्रमुख उपभोक्ता बाजारों में निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया, जिसने बदले में परिधान आपूर्ति श्रृंखला के अंतरराष्ट्रीय विखंडन में योगदान दिया, जिससे निम्न मजदूरी वाले देशों ने आयातित वस्त्र घटकों का उपयोग किया और तैयार उत्पाद का पुनः निर्यात किया (थोबर्न (2009), गेरेफी (1999) और ऑडेट (2004))। यह पुनर्विन्यास तब शुरू हुआ जब कोटा प्रणाली के तहत हांगकांग, दक्षिण कोरिया, ताइवान और बाद में चीन से निर्यात अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। कपड़ों को व्यवस्थित करने की प्रक्रियाओं को तब पूरे एशियाई-प्रशांत क्षेत्र में निम्न मजदूरी वाले विकासशील देशों और अन्य जगहों जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम पर उप-अनुबंधित किया गया था, जिन्होंने निर्यात कोटा का प्रयोग नहीं किया था।

एमएफए को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा 1995 और 2005 के बीच वस्त्र और कपड़ों पर समझौते (एटीसी) के माध्यम से समाप्त कर दिया गया था। एटीसी चार चरणों के एकीकरण कार्यक्रम के साथ 10 साल का संक्रमणकालीन समझौता था। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, नए एटीसी में निम्नलिखित छह मुख्य विशेषताएं थीं:

1. उत्पाद कवरेज में मूल रूप से सूत, धागे, बने बनाए कपड़ों के उत्पाद और कपड़े शामिल हैं;
2. प्रशुल्क (टैरिफ) और व्यापार संबंधी सामान्य करार (जीएटीटी) 1994 नियमों पर सामान्य समझौते में इन उत्पादों के एकीकरण के लिए प्रगतिशील चार-चरणीय कार्यक्रम, यानी 1 जनवरी, 1995, 1998, 2002 और 2005 को हुए। किसी भी नई सुरक्षा का आधार जीएटीटी 1994 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए;
3. एक उदारीकरण प्रक्रिया जिसने एमएफए से प्राप्त मौजूदा कोटा स्तरों को स्वचालित रूप से बढ़ा दिया;
4. घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति के वास्तविक खतरे के मामलों से निपटने के लिए एक संक्रमणकालीन सुरक्षा तंत्र, जो संक्रमण अवधि के दौरान उत्पन्न हो सकता है;
5. अन्य प्रावधान, जिनमें अन्य बातों के अलावा एमएफए से इतर कोटा की परिधि, परिमाणात्मक प्रतिबंधों के प्रशासन पर उपधाराएं थीं और जीएटीटी 1994 के नियमों और विषयों का पालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई शामिल थी; तथा
6. टेक्सटाइल मॉनिटरिंग बॉडी (टीएमबी) - विश्व व्यापार संगठन की संरचना के भीतर एक अर्ध-न्यायिक स्थायी निकाय, जिसे एटीसी के कार्यान्वयन की निगरानी का कार्य सौंपा गया है।

एटीसी वस्त्र और कपड़ों (टी एंड सी) निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ, जिसमें वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के उद्भव और एमएफए की प्रक्रिया से बाहर होने के कारण पर्याप्त परिवर्तन हुए।

इस पृष्ठभूमि में, अगला खंड प्रमुख परिधान निर्यातकों के बीच भारत की स्थिति के साथ वैश्विक परिधान बाजार का एक संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है।

IV. वैश्विक परिधान बाजार

IV.1 वैश्विक आयात

यूरोपीय संघ परिधान निर्यात के लिए सबसे बड़ा बाजार है, जो 2018 में वैश्विक परिधान आयात का 38.4 प्रतिशत था (सारणी 4)। यूरोपीय संघ के देशों के व्यापार से इतर, यूरोपीय संघ परिधानों का सबसे बड़ा आयातक बना हुआ है, जो कुल परिधान आयात का 20.0 प्रतिशत है। इसके अलावा, यूरोपीय संघ द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को परिधानों के सबसे बड़े आयातक के रूप में विस्थापित करने के साथ विकासशील देशों के लिए परिधान निर्यात के बाजार के रूप में यूरोपीय संघ का महत्व बढ़ गया है, 2000 और 2018 के बीच इसकी हिस्सेदारी 19.6 प्रतिशत से बढ़कर 20.0 प्रतिशत हो गई है, जबकि इसी अवधि में अमेरिका की हिस्सेदारी 33.1 प्रतिशत से घट कर 17.4 प्रतिशत हो गई है।

IV.2 भारत का परिधान निर्यात

भारत के परिधान निर्यात के प्रमुख निर्यात स्थलों में यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात के बाद सऊदी अरब और कनाडा शामिल हैं। भारत के परिधान निर्यात में यूरोपीय संघ का महत्व पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गया है क्योंकि भारत के परिधान निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2000-01 में 32 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 38 प्रतिशत हो गई है, जो भारतीय परिधानों का सबसे बड़ा आयातक बन गया है (चार्ट 1 और 2)। यूरोपीय

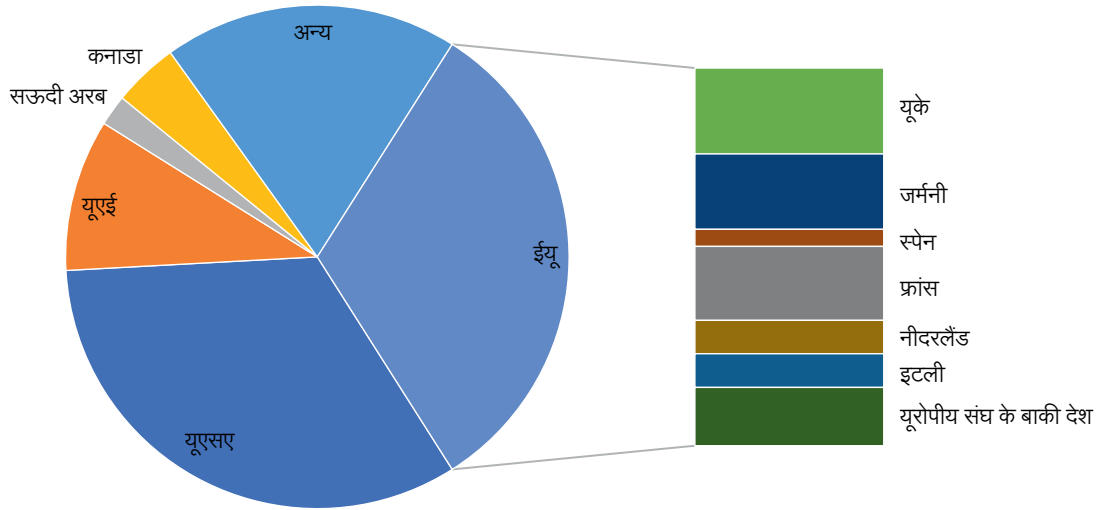
सारणी 4: विश्व वस्त्र आयात में हिस्सेदारी

(प्रतिशत)

देश/क्षेत्र	2000	2005	2010	2018
यूरोपीय संघ (28)	41.1	47.3	45.2	38.4
यूरोपीय संघ के अतिरिक्त देशों (28) का आयात	19.6	23.4	23.9	20.0
अमेरिका	33.1	28.7	22.1	17.4
जापान	9.7	8.1	7.2	5.7
दक्षिण कोरिया	0.6	1.0	1.2	2.0
कनाडा	1.8	2.1	2.2	2.0
चीन	0.6	0.6	0.7	1.6
रूस	0.1	0.3	2.0	1.5
स्विट्ज़रलैंड	1.6	1.6	1.4	1.4
ऑस्ट्रेलिया	0.9	1.1	1.3	1.3

स्रोत: विश्व व्यापार सांख्यिकीय समीक्षा (2019), विश्व व्यापार संगठन।

चार्ट 1: भारत के परिधान निर्यात की गंतव्य-वार संरचना: 2000-01



स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय और लेखकों के अनुमान।

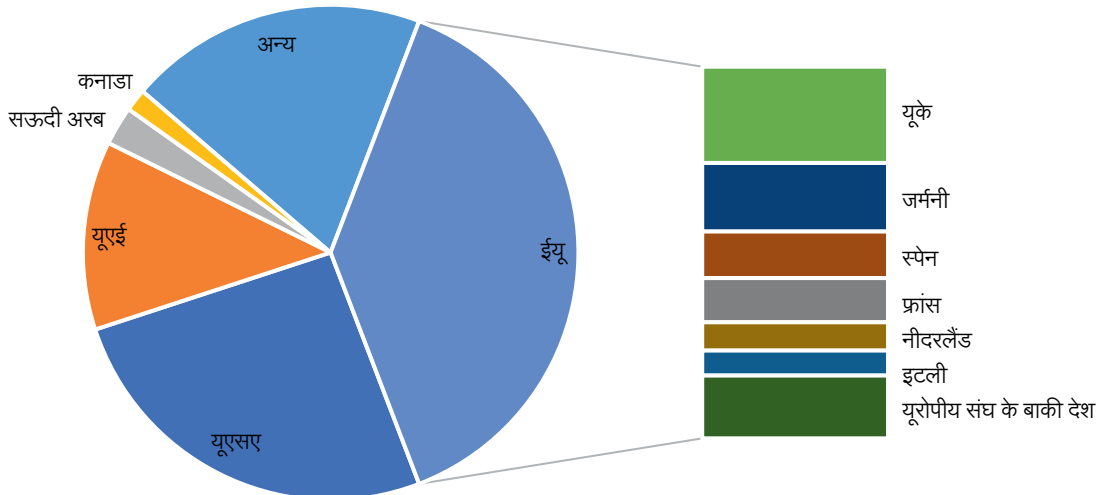
संघ के भीतर, 6 प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूके, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, नीदरलैंड और इटली भारतीय परिधानों के लिए सबसे बड़े बाजार हैं। इस प्रकार, यूरोपीय संघ को भारत के परिधान निर्यात के कार्य-निष्पादन का परिधान उद्योग की सफलता पर प्रभाव पड़ता है।

हालांकि, भारत के परिधान निर्यात में यूरोपीय संघ का हिस्सा 2000-01 से 2008-09 तक लगातार बढ़कर 49.5 के शिखर पर

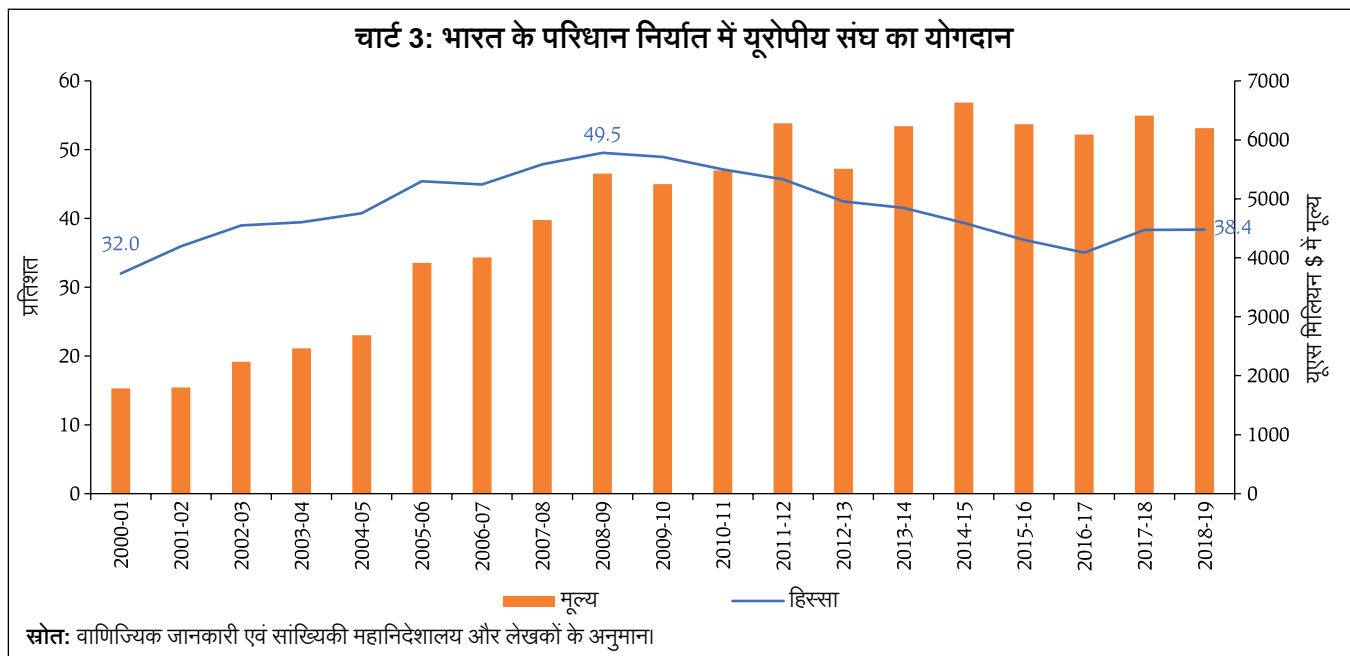
पहुंच गया, तब से यह ह्रासोन्मुख प्रवृत्ति पर है और 2018-19 में 38.4 प्रतिशत तक घट गया (चार्ट 3)। यह गिरावट पिछले कुछ वर्षों से यूरोपीय संघ को भारत के परिधान निर्यात में लगभग 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य के साथ ठहराव के साथ है।

चूंकि यूरोपीय संघ विशेष रूप से भारत के लिए परिधान निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, यूरोपीय संघ के लिए परिधान निर्यात में ठहराव चिंता का विषय है।

चार्ट 2: भारत के परिधान निर्यात की गंतव्य-वार संरचना: 2018-19



स्रोत: वाणिज्यिक जानकारी एवं सांख्यिकी महानिदेशालय और लेखकों के अनुमान।

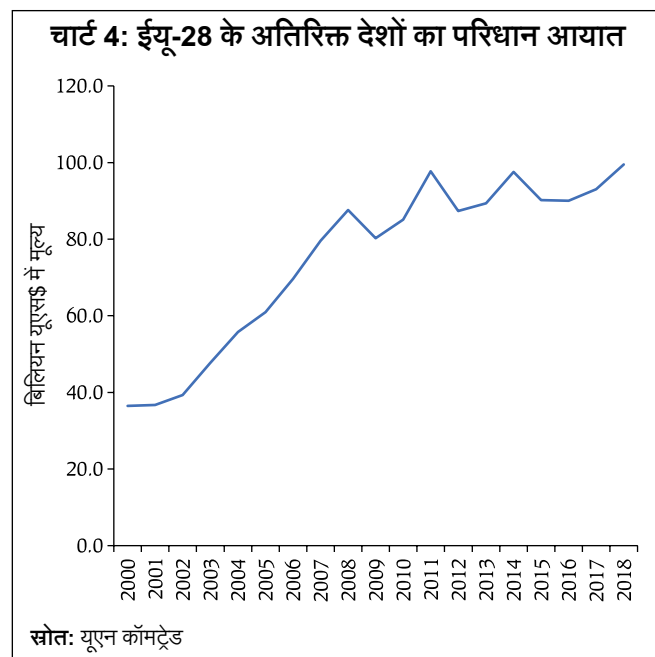


IV.3 यूरोपीय संघ के परिधान आयात का विकास

यूरोपीय संघ का परिधान आयात 2000 से 2008 तक लगातार बढ़ा, लेकिन उसके बाद से स्थिर है (चार्ट 4)। इसके अलावा, यूरोपीय संघ के परिधान आयात समूह की संरचना दर्शाती है कि शीर्ष 10 परिधान निर्यातकों में से दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों को कंबोडिया, वियतनाम और पाकिस्तान जैसे देशों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, जिसमें सस्ते श्रम और शिथिल श्रम मानदंडों, अनुकूल प्रशुल्क सुविधा और पहले के प्रमुख निर्यातकों के अधिक तकनीकी रूप से उन्नत उत्पादों के उपयोग के कारण इन देशों के लिए तुलनात्मक लाभ सहित कारकों के संयोजन शामिल हैं।

2000 में यूरोपीय संघ में चीन और तुर्की परिधानों के सबसे बड़े स्रोत थे, जिनका आयात क्रमशः 7.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बांग्लादेश चौथा और भारत सातवां सबसे बड़ा निर्यात भागीदार था। इसमें प्रमुख निर्यातकों में हांगकांग और दक्षिण कोरिया भी शामिल थे। 2005 तक 21.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परिधान निर्यात के लिए चीन ने शीघ्र ही शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था, जिसमें तुर्की 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक था।

बांग्लादेश और भारत ने क्रमशः 4.4 अमेरिकी डॉलर और 4.0 अरब अमेरिकी डॉलर के परिधान निर्यात के साथ शीर्ष 4 में अपना स्थान बनाया (सारणी 5)।



सारणी 5: यूरोपीय संघ हेतु शीर्ष 10 परिधान निर्यातक

(यूएस \$ बिलियन)

2000		2005		2010		2015	
चीन	7.0	चीन	21.2	चीन	38.6	चीन	33.4
तुर्की	5.0	तुर्की	10.1	तुर्की	10.7	बांग्लादेश	15.4
हांगकांग	2.9	बांग्लादेश	4.4	बांग्लादेश	8.2	तुर्की	10.5
बांग्लादेश	2.4	इंडिया	4.0	इंडिया	5.8	इंडिया	5.7
ट्यूनीशिया	2.4	ट्यूनीशिया	3.1	ट्यूनीशिया	3.1	कंबोडिया	3.3
मोरक्को	2.2	मोरक्को	2.8	मोरक्को	2.8	वियतनाम	3.1
इंडिया	1.9	हांगकांग	2.1	वियतनाम	1.8	मोरक्को	2.6
इंडोनेशिया	1.7	इंडोनेशिया	1.5	श्रीलंका	1.6	पाकिस्तान	2.6
थाईलैंड	0.9	श्रीलंका	1.0	इंडोनेशिया	1.5	ट्यूनीशिया	2.2
दक्षिण कोरिया	0.8	थाईलैंड	1.0	पाकिस्तान	1.4	श्रीलंका	1.8

स्रोत: संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड

चीन 2010 तक 38.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के परिधान निर्यात का सबसे बड़ा निर्यातक बना रहा। 8.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के साथ बांग्लादेश तीसरे स्थान पर तुर्की (10.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर) के करीब था। भारत 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बना रहा। वियतनाम, श्रीलंका और पाकिस्तान ने 2010 में शीर्ष 10 निर्यातक देशों में जगह बना ली।

2015 तक तुर्की को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 33.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था। 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ भारत के बाद कंबोडिया और वियतनाम क्रमशः 3.3 अमेरिकी डॉलर और 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर थे।

यूरोपीय संघ के परिधानों के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में संरचनागत परिवर्तन को मोटे तौर पर उनमें से प्रत्येक के ऊपर लगने वाले भिन्न-भिन्न प्रशुल्क की संरचना द्वारा समझाया जा सकता है।

IV.4 यूरोपीय संघ में प्रशुल्क संरचना

यूरोपीय संघ ने 2001 में एवरीथिंग बॉट आर्म्स (ईबीए) योजना पेश की, जो आयुध और शस्त्रों के अतिरिक्त सभी उत्पादों के लिए अल्पतम विकसित देशों के लिए यूरोपीय संघ के बाजारों में शुल्क और कोटा मुक्त अभिगम प्रदान करती है। वर्तमान में ईबीए लाभ 9 एशियाई देशों के लिए उपलब्ध हैं जिनमें बांग्लादेश और कंबोडिया शामिल हैं। इस प्रकार बांग्लादेश और कंबोडिया से परिधान निर्यात का प्रभावी प्रशुल्क शून्य है। यूरोपीय संघ ने

2011 में ईबीए योजना के तहत निर्यात के लिए मूल विनिर्देशों के नियमों में राहत दी। तुर्की और यूरोपीय संघ के बीच 1991 से एक मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है, जिसके तहत तुर्की के परिधान निर्यात की यूरोपीय संघ के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच है।

भारत और वियतनाम अधिमानों की सामान्यीकृत योजना (जीएसपी) कार्यक्रम के लाभार्थी हैं और इसलिए कम प्रशुल्क दर देना होता है (औसत प्रशुल्क 9.3 प्रतिशत है)। हालांकि, बांग्लादेश, कंबोडिया और तुर्की की तुलना में काफी अधिक प्रशुल्क लगाया जा रहा है। चीनी परिधान निर्यात जीएसपी तंत्र से बाहर हो गया है और 11.6 प्रतिशत के सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र (एमएफएन) प्रशुल्क का सामना कर रहा है। (परिशिष्ट 1 में प्रशुल्क संरचना में प्रशुल्क दरों की सूची का स्तर प्रदान किया गया है)।

V. साहित्यिक समीक्षा

वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र में भारत के निर्यात पर 2005 से पहले प्रकाशित अध्ययन ने मुख्य रूप से भारत के वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र के निर्यात कार्य-निष्पादन पर एमएफए को हटाने के प्रभाव की जांच की। एमएफए के अप्रयुक्त होने के बाद वैश्विक वस्त्र और कपड़ा बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा होने की उम्मीद थी, जिसका भारत के निर्यात पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा (हाशिम 2005)। शोध से पता चला कि एक प्रतिस्पर्धी बाजार में निर्यात कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए विनियमन और श्रम सुधारों की आवश्यकता थी (कथूरिया और भारद्वाज, 1998)। शोध के निष्कर्षों से यह भी पता चला है कि भारत और चीन जैसे निम्न श्रम लागत वाले विकासशील देशों को एमएफए के हटने से लाभ हुआ है (नोर्डस, 2004)। विभिन्न

अध्ययनों ने भारतीय कपड़ा निर्यात पर एमएफए के बाद संभावित प्रभावों का विश्लेषण किया। लेकिन भारतीय वस्त्र निर्यात पर कोटा हटाने के प्रभाव के बारे में शोधकर्ताओं के बीच कोई आम सहमति नहीं है। कुछ अध्ययनों ने एमएफए के बाद की अवधि में विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत के लिए एक उच्च संभावित लाभ की ओर इंगित किया (मेहता, 1997, चड्ढा और अन्य, 1999, एक्जिम बैंक, 2005 और चौधरी, 2011)। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि भले ही भारत के वस्त्र निर्यात ने एमएफए के बाद की अवधि में बेहतर स्थिति दिखाई, लेकिन बदले हुए परिदृश्य में वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतिगत उपायों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी (चौधरी, 2016)।

अनुसंधान अध्ययनों ने प्रचुर मात्रा में कच्चे माल, निम्न श्रम लागत और ऊर्ध्वाधर एकीकृत उत्पादन सुविधाओं के मामले में कपड़ा क्षेत्र में भारत की सुदृढ़ता पर भी ध्यान केंद्रित किया है। चूंकि वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र एक श्रम-प्रधान उद्योग है, प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में श्रम लागत एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत की श्रम लागत चीन और अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है, जो भारत के वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र को आकर्षक बनाती है (एंथनी और जोसेफ, 2014)।

शोधकर्ताओं द्वारा भारत के वस्त्र निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता का भी विस्तार से विश्लेषण किया गया है। अधिकांश अध्ययनों ने रिवील्ड कम्पैरटिव ऍडवांटेज (आरसीए) का उपयोग करके निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता का विश्लेषण किया, जिसे बलासा (1965) द्वारा विकसित किया गया था। इन अध्ययनों ने निष्कर्ष निकाला है कि भारत ने 1995 से 2003 तक कपड़ा उत्पादों में प्रतिस्पर्धा बनाए रखी। हालांकि, कन्नन (2018) ने पाया कि वस्त्र और कपड़ा क्षेत्र में भारत का तुलनात्मक लाभ 1995 से 2007 तक और कम हो गया। इसके अलावा, भारत को 2010 से 2014 तक आरसीए विश्लेषण पर आधारित अधिकांश कपड़ा उत्पादों में तुलनात्मक लाभ प्राप्त हुआ (कथूरिया 2013, 2018; धीमन और शर्मा 2017; कन्नन 2018)। विश्व वस्त्र व्यापार के बारह प्रमुख भागीदारों की तुलना में भारतीय वस्त्र उद्योग की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के विश्लेषण में पाया गया है कि एटीसी के उन्मूलन के बाद चीन के बाद भारत को सबसे अधिक लाभ हुआ है, यानी 1 जनवरी, 2005 के बाद विश्व निर्यात में प्रतिशत हिस्सेदारी के मामले में भारत को सबसे अधिक लाभ हुआ है (गुप्ता और खान, 2017)।

व्यापार समझौतों ने परिधान व्यापार प्रवाह को भी प्रभावित किया है। कई द्विपक्षीय और क्षेत्रीय व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर होने के कारण प्रमुख निर्यातकों और परिधानों के आयातकों ने एक दशक में परिधानों में व्यापार में वृद्धि देखी है (ब्रंटन और होप, 2017)। हालांकि, जबकि चीन का अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ कोई एफटीए नहीं है, कई वैश्विक ब्रांड प्रतिस्पर्धी दरों पर थोक उत्पादन करने की क्षमताओं के कारण चीन से बाह्यस्रोतीकरण कर रहे हैं (फोल और शेन, 2008)। निर्यात कारोबार में चीनी कंपनियां भारतीय फर्मों की तुलना में बहुत बड़ी हैं और वे बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संलग्न हैं (मिनियन, मार्टिनेज और इबनेज़, 2016)।

इस प्रकार, शोधकर्ताओं द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भिन्न हैं, कुछ के अनुसार भारत के वस्त्र निर्यात प्रतिस्पर्धी हैं जबकि कुछ अध्ययनों में विपरीत परिणाम प्राप्त हुए हैं।

अनुसंधान का एक अन्य क्षेत्र भारत के वस्त्र निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति के संचालन में प्रवृत्त कारक रहे हैं। कई अध्ययन दर्शाते हैं कि अनुसंधान एवं विकास में भारतीय फर्मों का निम्न स्तर का निवेश है और वे अपने वैश्विक प्रतिस्पर्धियों की तुलना में उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने में पिछड़ी हुई हैं (वरुकोलू, 2007)। चीन जैसे देशों में कंपनियां स्वचालन तथा अनुसंधान और विकास में भारी निवेश करती हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि और गुणवत्ता में सुधार होता है। इसके अलावा, लघु और मध्यम आकार की फर्मों के पहले से स्थापित प्रभुत्व के साथ परिधान क्षेत्र की खंडित प्रकृति इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है (लोपेज़-एकेवेडो और रॉबर्टसन, 2016)। इसके विपरीत, तुर्की में मूल्य-श्रृंखला के सभी स्तरों पर परिधान फर्मों का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

इस प्रकार भारत के परिधान निर्यात पर शोध अध्ययनों ने मुख्य रूप से तुलनात्मक लाभ के विश्लेषण और एमएफए के समाप्त होने के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि, हाल के दिनों में भारत के परिधान निर्यात में गतिहीनता को पूरी तरह से घरेलू कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी शक्ति के लोप के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। प्रतिस्पर्धी ताकत के इस लोप के लिए एक महत्वपूर्ण कारक प्रमुख परिधान निर्यातकों में से प्रत्येक के सामने भिन्न-भिन्न प्रशुल्क संरचना है और यह कैसे उनकी

सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करने में एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में उभरा है।

भारत के प्रमुख प्रतिस्पर्धी देशों के निर्यात कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करने वाले शोधकर्ताओं द्वारा इस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, चैन, और अन्य (2017) ने एशियाई देशों के पैनेल डेटा का उपयोग करके कपड़ा और परिधान बाजार पर व्यापार लागत के प्रभावों का विश्लेषण किया। ट्रेड कॉस्ट फंक्शन के साथ ग्रेविटी मॉडल का उपयोग करते हुए, उन्होंने पाया कि लागू प्रशुल्क और सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्रों के प्रशुल्क ने देशों के बीच व्यापार को काफी कम कर दिया।

भट्टाचार्य और रहमान (2000) ने बांग्लादेश के निर्यात कार्य-निष्पादन का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला कि बांग्लादेश में परिधान निर्यात की वृद्धि की एक महत्वपूर्ण गतिशक्ति यूरोपीय संघ (ईयू) में अधिमानों की सामान्यीकृत प्रणाली (जीएसपी) के तहत प्रशुल्क और आयात कोटा-मुक्त पहुंच है, जिसने यूरोपीय संघ के बाजार में परिधान निर्यात के विस्तार में योगदान दिया, बशर्ते कि बांग्लादेश मूल नियमों (आरओओ) की आवश्यकता की पूर्ति करता हो। जीएसपी योजना यूरोपीय संघ के आयातकों को बांग्लादेश से अपने आयात पर पूर्ण प्रशुल्क वापसी का दावा करने की अनुमति देती है। यूरोपीय संघ में परिधान उत्पादों की औसतन प्रशुल्क दर 12.5 प्रतिशत है, जो जीएसपी के तहत बांग्लादेश के लिए शून्य हो जाती है। इस तरह के अधिमानी व्यवहार ने यूरोपीय संघ में बांग्लादेश के लिए तुलनात्मक रूप से बाजार में अधिक पहुंच की पेशकश की है और यूरोपीय संघ को बांग्लादेश का सबसे बड़ा परिधान निर्यात बाजार बना दिया है।

इसी तरह, वियतनाम को भी परिधान निर्यात के मामले में अधिमानी प्रशुल्क सुविधा से लाभ हुआ है। मुक्त व्यापार समझौते वियतनाम को व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करते हैं जो उद्योग के लिए एक प्रमुख वृद्धि चालक साबित होता है। इसके द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एफटीए उद्योग की वृद्धि की शक्ति हैं (वलार्मथी, 2019)। वियतनाम और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता (बीटीए) वियतनाम द्वारा निर्यातित उत्पादों को लाभ देता है, जो

प्रशुल्क में लगभग 40 प्रतिशत से केवल 3 प्रतिशत की कमी करते हैं। इस निम्नतर प्रशुल्क का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है (सेट्योरिनी और बुडियोनो, 2020)।

इस प्रकार देश के निर्यात में लगने वाले प्रशुल्क देश के वस्त्र निर्यात के कार्य-निष्पादन में एक प्रमुख निर्धारण कारक के रूप में उभरे हैं। यह पेपर इस महत्वपूर्ण कारक की जांच करने का प्रयास करता है और अगला खंड वर्णनात्मक अर्थमितीय मूल्यांकन के साथ-साथ इसका सांख्यिकीय विश्लेषण प्रदान करता है।

VI. विश्लेषणात्मक अन्वेषण

इस खंड का उद्देश्य निर्यात का संचालन करने वाले अंतर्निहित कारकों की पहचान करने के लिए परिधान निर्यात का एक बहुराष्ट्रीय विश्लेषण प्रस्तुत करना है। इस खंड में पहले एक वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसके बाद निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए एक अर्थमितीय विश्लेषण शामिल है। इस अध्ययन में 1994 से 2018 तक यूरोपीय संघ के 6 प्रमुख देशों (फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम) द्वारा रिपोर्ट किए गए वार्षिक आयात आंकड़े का उपयोग किया गया है। उक्त आंकड़े संयुक्त राष्ट्र कॉमट्रेड डेटाबेस से प्राप्त किये गए हैं। विभिन्न निर्यातकों में डेटा की रिपोर्टिंग में निरंतरता बनाए रखने के लिए निर्यात के आंकड़ों की बजाय आयात के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा, आयात डेटा आमतौर पर अधिक सुदृढ़ और विश्वसनीय होता है, क्योंकि यह आयात करने वाले देश में सीमा शुल्क के संग्रह का आधार बनता है। परिधान निर्यात का विवरण मोटे तौर पर हारमोनाइज्ड कमोडिटी विवरण और कोडिंग प्रणाली के अध्याय 61 और 62 के अंतर्गत दिया गया है, अतः इस शोधपत्र

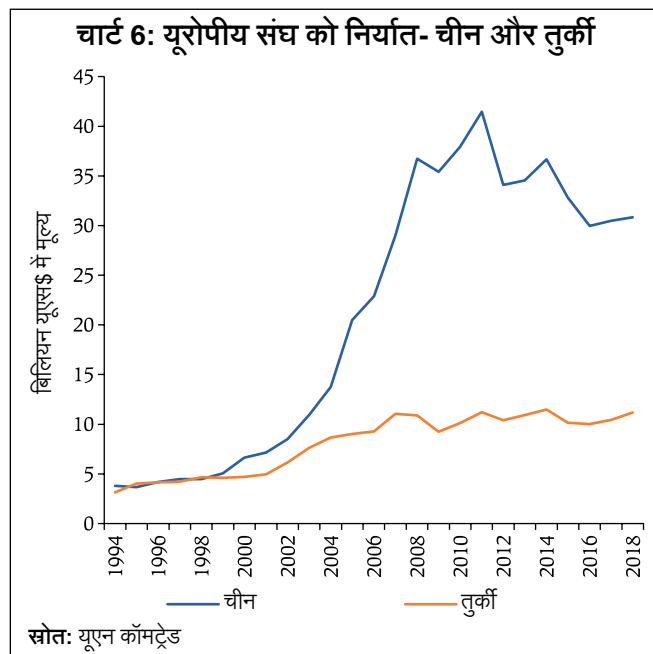
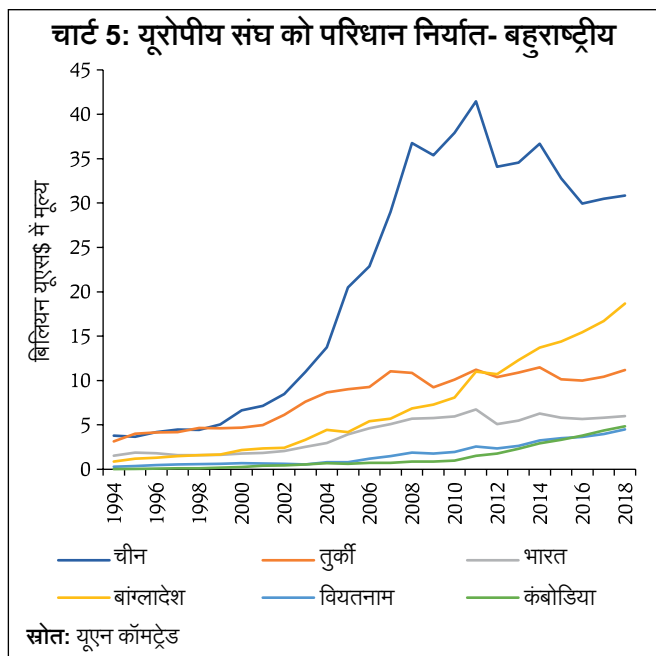
¹ यूरोपीय संघ के शेष देशों के लिए, परिधान आयात के लिए समय-श्रृंखला डेटा विचाराधीन पूरी अवधि के लिए उपलब्ध नहीं है। चूंकि इन देशों का भारत के परिधान निर्यात में केवल सीमित हिस्सा है जो मोटे तौर पर एक समय-सीमा में समान रहा है, वर्तमान विश्लेषण यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि नमूने के रूप में 6 प्रमुख यूरोपीय संघ के देशों के समग्र निर्यात को संकलित करता है। इसके अलावा, इन देशों के लिए उपलब्ध सीमित आंकड़ों के विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि इन भागीदार देशों से आयात ने उसी प्रवृत्ति का पालन किया, जैसा कि यूरोपीय संघ के प्रमुख 6 देशों के मामले में देखा गया था, इस प्रकार यह किसी भी नमूना चयन में पक्षपात से बचा रहा।

में आगे के विश्लेषण के लिए इन दो अध्यायों में वर्णित सकल आयात पर विचार किया जाता है।

VI.1 वर्णनात्मक विश्लेषण

चीन ने एमएफए से वापसी का लाभ उठाते हुए 2000-10 की अवधि के दौरान तीव्र विकास किया। तथापि, इसने संभवतः प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में गहन निर्यात पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसके बाद से इसे कम किया है। तुर्की जो 2000 से पहले के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक था, 2000-05 की अवधि में भी बढ़ा, लेकिन उसके बाद यह स्थिर हो गया (चार्ट 5 और 6)।

बांग्लादेश ने ईबीए कार्यक्रम के तहत यूरोपीय संघ के बाजार में शुल्क मुक्त अभिगम से लाभान्वित होने के बाद 2000 के बाद परिधान निर्यात में तेजी से वृद्धि देखी। ऐसा लगता है कि संभवतः चीन से रिक्त किये गए स्थान को भरते हुए, हाल के वर्षों में विकास में वृद्धि हुई है। सोर्सिंग मानदंडों को आसान बनाने से इसे सीएमटी (कट, मेक एंड ट्रिम) उत्पादन विधि पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिली है, जबकि अन्य देशों विशेष रूप से चीन, कोरिया, भारत, पाकिस्तान, इटली और तुर्की से कपड़े का बाह्यस्रोतीकरण किया जा रहा है। इस प्रकार, यह तुर्की और भारत से बहुत आगे बढ़कर दूसरा सबसे बड़ा परिधान निर्यातक बन गया है।

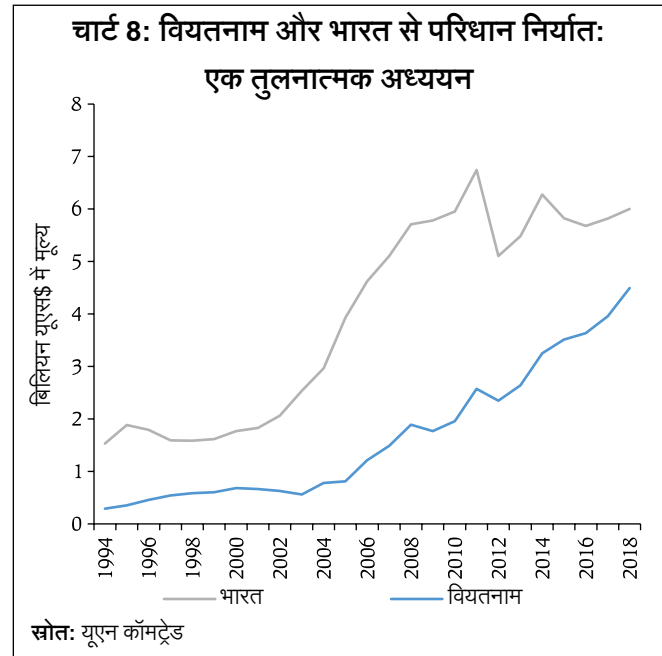
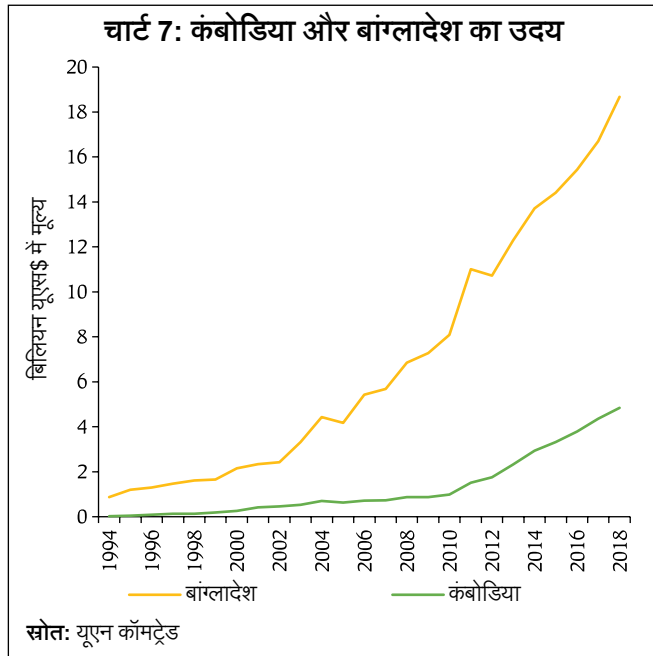


2010 तक एक सीमांत निर्यातक रहने वाला कंबोडिया उसके बाद से तेजी से विकास किया है। इसके लिए फिर से शुल्क मुक्त अभिगम का लाभ लेने के लिए चीन से परिधान उत्पादन के स्थानान्तरण को कारण बताया जा सकता है। 2011 के बाद से रियायती बाह्यस्रोतीकरण मानदंडों ने इसे अन्य देशों से अर्ध निर्मित माल आयात करते समय परिधान निर्यात को तेजी से बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया होगा (चार्ट 7)।

वियतनाम और भारत के निर्यात में 2000 और 2010 के बीच वृद्धि हुई है, लेकिन भारत तब से स्थिर हो गया है, जबकि वियतनाम का विकास जारी है और शीघ्र ही यह भारत को पीछे छोड़ सकता है। चूंकि दोनों देशों को यूरोपीय संघ में समान टैरिफ का सामना करना पड़ता है, भारत के विपरीत वियतनाम की निरंतर वृद्धि शायद वियतनाम द्वारा प्राप्त प्रतिस्पर्धी बढ़त और वैश्विक वस्त्र मूल्य श्रृंखलाओं में अपने घरेलू परिधान उद्योग के बेहतर एकीकरण को दर्शाती है (चार्ट 8)।

VI.2 अर्थमितीय विश्लेषण

इस खंड में, हम संरचनात्मक ब्रेक के लिए प्रत्येक देश के परिधान निर्यात डेटा का व्यक्तिगत रूप से परीक्षण करना चाहते हैं



और इन संरचनात्मक ब्रेक पॉइंट्स की व्याख्या करने के लिए आयात करने वाले देशों में नीतिगत बदलावों पर भी विस्तार से बताना चाहते हैं।

चाउ (1960) ने एफ-सांख्यिकीय का उपयोग करके एक अनुमानित ज्ञात तिथि पर एक एकल संरचनात्मक ब्रेक के परीक्षण के लिए योगदान दिया। क्वांडट (1960) ने एक अज्ञात ब्रेकपॉइंट के परीक्षण के लिए अनुमति देने के लिए चाउ के फ्रेमवर्क को संशोधित किया। एंड्रयूज (1993) ने क्वांडट-एंड्रयूज परीक्षण तैयार करने वाले क्वांडट परीक्षण आंकड़ों के सीमित वितरण को व्युत्पन्न किया।

उन्नत संरचनात्मक मॉडल एकाधिक ब्रेक पॉइंट्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा, उन्हें संरचनात्मक ब्रेक पॉइंट्स की संख्या संबंधी प्राथमिक जानकारी की भी आवश्यकता नहीं होती है और इसमें आंतरिक स्तर पर ही विभिन्न संरचनात्मक ब्रेक पॉइंट्स को निर्धारित कर सकते हैं।

बाई (1997) एक ब्रेकपॉइंट परीक्षण के बार-बार प्रयोग द्वारा, एक से अधिक ब्रेक का पता लगाने के लिए एक सरल दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार, अनुक्रमिक अनुमान मॉडल ऐसे

व्यवहार करता है, जैसे कि केवल एक ब्रेकपॉइंट है। यहां, पूर्ण नमूने से शुरू करते हुए, एक अज्ञात ब्रेक का अनुमान लगाया जाता है। अगले चरण में, अगले ब्रेक को निम्नलिखित में से किसी एक विधि द्वारा पहचाना जाता है:

- 1) उक्त खंडों में से प्रत्येक में एक अतिरिक्त ब्रेकपॉइंट्स के लिए परीक्षण (मॉडल 1)
- 2) एकल एडेड ब्रेकपॉइंट्स के लिए परीक्षण जो सम -ऑफ -स्क्वायर्स मोस्ट को कम कर देता है (मॉडल 2)

बाई और पेरॉन (1998) ने एक वैकल्पिक पद्धति प्रदान करते हैं। वे एम ब्रेक के साथ एक से अधिक रैखिक प्रतिगमन मॉडल पर विचार करते हैं

$$y_t = x_t' \beta + z_t' \delta_j + u_t$$

- $j = 1, \dots, m+1$ के लिए, जहाँ m ब्रेक की संख्या है,
- y_t निर्भर चर है, x_t और z_t सह-चर के वेक्टर हैं, β और δ_j गुणांक के समांतर वेक्टर हैं, और u_t डिस्टरबेन्स टर्म है।

ब्रेक का पता लगाने के लिए, दो दृष्टिकोण प्रस्तावित हैं:

- 1) वैश्विक दृष्टिकोण (मॉडल 3), जहां स्क्वायर्ड रेसिड्युयल्स (एसएसआर) के योग को कम करने के लिए ब्रेक पॉइंट्स $T_i, i=1, \dots, m$ निर्धारित किए जाते हैं:

$$\sum_{i=1}^{m+1} \sum_{t=T_{i-1}+1}^{T_i} [y_t - x_t' \beta - z_t' \delta_j]^2$$

यह तब वैश्विक एसएसआर-मिनिमाइजिंग ब्रेक को बेहतर ढंग से पता लगाने के लिए एक डायनामिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम का उपयोग करता है। परीक्षण के आंकड़े इस बात पर निर्भर करते हैं कि ब्रेक की संख्या पहले से अनुमानित है या नहीं:

- i) ब्रेक की संख्या ज्ञात है: H_0 (कोई ब्रेक नहीं) बनाम H_1 (k ब्रेक) एसएसई के बीच F -अनुपात का उपयोग करके परीक्षण किया गया: $\sup F(0, m)$

- ii) ब्रेक की अज्ञात संख्या: मानक एफ-आँकड़े अपर्याप्त हो जाते हैं: $\sup F(0, m)$ परीक्षण की भिन्नता का उपयोग किया जाता है (डबल मैक्सिमम परीक्षण)

$$D_{max} = \max_{n=1 \text{ to } m} (a_n \sup F(0, n))$$

- 2) अनुक्रमिक दृष्टिकोण (मॉडल 4) जहां एक एकल ब्रेक के साथ शुरू करके, जो एसएसआर को कम करता है, ब्रेक को क्रमिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ब्रेकपॉइंट वाले मॉडल के लिए, $l+1$ क्षेत्रों में से प्रत्येक को प्रत्येक विभाजन में $\sup F(0, 1)$ का उपयोग करके एक अतिरिक्त ब्रेकपॉइंट के लिए परीक्षण किया जाता है। यदि $l+1$ विभाजन में से कम से कम एक में 0 ब्रेक के शून्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो यह स्थापित करता है कि $l+1$ ब्रेक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक परीक्षण चरण में, शून्य (नल) के तहत एल ब्रेकपॉइंट्स को सम-ऑफ-स्क्वायर रेसिड्युयल्स के वैश्विक न्यूनतमकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है।

याओ (1988) ने दर्शाया कि श्वार्ज मानदंड को कम करने वाले ब्रेक की संख्या एक ब्रेकिंग मीन मॉडल में ब्रेक की सही संख्या का एक सुसंगत अनुमानक है। लियू, वू, और ज़िडेक (1997) एक

सारणी 6: परिणामों का सारांश

देश/मॉडल	मॉडल 1	मॉडल 2	मॉडल 3	मॉडल 4	मॉडल 5
बांग्लादेश	1 (2006)	1 (2006)	2 (2003, 2011)	1 (2006)	2 (2003, 2011)
कंबोडिया	1 (2011)	1 (2011)	1 (2011)	1 (2011)	1 (2011)
चीन	2 (2003, 2010)	2 (2003, 2010)	2 (2003, 2010)	2 (2003, 2010)	2 (2003, 2010)
भारत	2 (2002, 2012)	2 (2002, 2012)	2 (2002, 2012)	2 (2002, 2012)	2 (2002, 2012)
तुर्की	1 (2004)	1 (2004)	2 (2002, 2009)	1 (2004)	2 (2002, 2009)
वियतनाम	1 (2006)	1 (2006)	1 (2006)	1 (2006)	1 (2006)

प्रतिगमन फ्रेमवर्क (मॉडल 5) में ब्रेक की संख्या निर्धारित करने के लिए संशोधित श्वार्ज मानदंड (एलडब्ल्यूजेड) का उपयोग करने का प्रस्ताव देते हैं।

VI.3 परिणाम

उपर्युक्त सूचीबद्ध 5 मॉडलों के परिणामों को सारणी 6 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

चीन के लिए, सभी 5 मॉडल क्रमशः 2003 और 2011 में दो संरचनात्मक ब्रेक को इंगित करते हैं। चीन यद्यपि, 1994-2002 के बीच यूरोपीय संघ को अपने परिधान निर्यात में औसतन 580.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि कर रहा था, तथापि, इसने 2002-03 में एक संरचनात्मक बदलाव देखा, जिसके बाद इसके परिधान निर्यात में पिछली अवधि की तुलना में बहुत तेज गति से वृद्धि हुई। 2002-03 के बाद, चीन के परिधान निर्यात में सालाना 4566.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। हालांकि, इसने 2009-10 में एक और संरचनात्मक ब्रेक देखा, जिसके बाद इसके द्वारा यूरोपीय संघ को होने वाला परिधान निर्यात संकुचन की स्थिति में रहा है (सारणी 7)।

सारणी 7: चीन और तुर्की के परिधान निर्यात में वृद्धि दर

चीन		तुर्की	
अवधि	स्लोप	अवधि	स्लोप
1994-2002	580.4	1994-2001	215.6
2003-2009	4566.2	2002-2008	775.0
2010-2018	-1187.1	2009-2018	82.1

तुर्की के बारे में, जबकि मॉडल 1, 2 और 4; 2004 में एक ही ब्रेक दर्शाते हैं, मॉडल 3 और 5 क्रमशः 2002 और 2009 में दो ब्रेक दर्शाते हैं। बाई और पेरॉन (2003) सहित अन्य साहित्य, विभिन्न मॉडलों के बीच टकराव की स्थिति में ब्रेक की संख्या का अनुमान लगाने के लिए मॉडल 3 में उपयोग की जाने वाली डबल मैक्सिमम प्रोसीजर के उपयोग का सुझाव देते हैं। मॉडल 3 के ब्रेकपॉइंट अनुमान के बाद, हम पाते हैं कि तुर्की ने भी 2002 से यूरोपीय संघ को परिधान निर्यात की अपनी वृद्धि दर में वृद्धि देखी, लेकिन 2008 के बाद से उसका निर्यात स्थिर हो गया है।

बांग्लादेश के मामले में भी हमने मॉडलों के बीच अंतर पाया है। मॉडल 3 क्रमशः 2003 और 2011 में दो ब्रेकपॉइंट्स का सुझाव देता है। ज्ञात ब्रेकपॉइंट लोकेशन टेस्टिंग का उपयोग करके दो ब्रेकपॉइंट्स की उपस्थिति की पुष्टि की जाती है। संवेदनशीलता विश्लेषण से यह भी पता चलता है कि एकल ब्रेकपॉइंट मॉडल (मॉडल 1, 2 और 4), महत्व और ट्रिमिंग प्रतिशत में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं, इस प्रकार दो ब्रेकपॉइंट्स की उपस्थिति के लिए आगे का समर्थन करते हैं। बांग्लादेश ने 2003 के बाद निर्यात क्वांटम की अपनी दर को तीन गुना से अधिक कर दिया, जो 2011 के बाद फिर से दोगुना हो गया (सारणी 8)।

कंबोडिया के मामले में, 2010 में एकल संरचनात्मक ब्रेक के लिए सर्वसम्मति से समर्थन है। जबकि कंबोडिया 2010 से पहले एक सीमांत निर्यातक देश था, यह तेजी से विस्तारित हुआ और न केवल प्रतिशत के संदर्भ में बल्कि समग्रता के संदर्भ में भी यूरोपीय संघ के लिए परिधानों के सबसे तेजी से बढ़ते निर्यातकों में से एक बन गया।

भारत के मामले में, सभी मॉडल क्रमशः 2002 और 2012 में दो संरचनात्मक ब्रेक की ओर इशारा करते हैं। जबकि भारत ने 2002 के बाद बांग्लादेश और तुर्की के अनुरूप परिधान निर्यात की अपनी वार्षिक वृद्धि के अपने वस्त्र निर्यात का तेजी से विस्तार

सारणी 8: बांग्लादेश और कंबोडिया के परिधान निर्यात में वृद्धि दर

बांग्लादेश		कंबोडिया	
अवधि	स्लोप	अवधि	स्लोप
1994-2002	191.9667	1994-2010	63.09559
2003-2010	665.6905	2011-2018	489.1786
2011-2018	1115.833		

सारणी 9: भारत और वियतनाम के परिधान निर्यात में वृद्धि दर

भारत		वियतनाम	
अवधि	स्लोप	अवधि	स्लोप
1994-2001	11.86905	1994-2006	38.65734
2002-2011	520.9636	2006-2018	257.6099
2012-2018	98.96429		

किया। हालांकि, भारत में 2012 के बाद ठहराव देखा गया है, जबकि बांग्लादेश, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में वृद्धि जारी है (सारणी 9)।

वियतनाम के मामले में, 2006 में एक एकल संरचनात्मक ब्रेक पाया जाता है। एक दूसरा संरचनात्मक ब्रेक 2012 में मौजूद हो सकता है लेकिन संवेदनशीलता विश्लेषण से पता चलता है कि यह सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे संरचनात्मक ब्रेक को स्वीकार करने से पता चलता है कि वियतनाम ने वास्तव में 2012 के बाद यूरोपीय संघ को परिधान निर्यात की अपनी गति में वृद्धि की है। इसका तात्पर्य यह है कि वियतनाम ने बांग्लादेश और कंबोडिया से बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, संभवतः वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में बेहतर एकीकरण, उच्च प्रतिस्पर्धा और चीन द्वारा खाली किए गए स्थान पर बेहतर तरीके से काबिज हो कर स्वयं को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा है।

उपर्युक्त विश्लेषण से हम देख सकते हैं कि विभिन्न देशों के परिधान निर्यात में देखे गए संरचनात्मक विरामों को मोटे तौर पर नीतिगत परिवर्तनों द्वारा समझाया जा सकता है। भारत, बांग्लादेश, चीन और तुर्की सहित कई देशों ने वर्ष 2002 के आसपास एक संरचनात्मक ब्रेक का अनुभव किया, जिसके बाद उन्होंने परिधान निर्यात का तेजी से विस्तार देखा। यह इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि वस्त्र और कपड़ों के कई प्रमुख आयातकों ने 2002 तक इंतजार किया (एमएफए का तीसरा चरण) जब कोटा बाध्यकारी थे और तब कई वस्तुओं पर से कोटा को खत्म किया गया (भट्टाचार्य और इलियट (2005), हडसन एवं अन्य (2010))। इसके अलावा, यूरोप के ईबीए कार्यक्रम को इसी समय पेश किया

² सभी विकसित संरचनात्मक ब्रेक मॉडलों को संरचनात्मक ब्रेक की संख्या और ब्रेक के स्थान के संदर्भ में सबसे उपयुक्त माना जाता है। जैसा कि पूर्व में चर्चा की गई थी, यूरोपीय संघ ने 2001 में ईबीए कार्यक्रम को प्रारंभ किया।

गया था, जिससे किसी भी अर्थमितीय विश्लेषण से जुड़ी संभावना के द्वार खोलने के साथ-साथ वास्तविक आर्थिक निष्पादन में परिलक्षित होने के लिए नीति परिवर्तन के प्रभाव को शामिल किया गया था। यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि ईबीए कार्यक्रम की शुरुआत में जिन देशों के निर्यात निष्पादन पर प्रश्न उठाए जा रहे थे, उनपर प्रभाव पड़ा था। इसी तरह, 2006 में वियतनाम के संरचनात्मक ब्रेक और तेजी से विस्तार के बाद से 2005 में एमएफए से समाप्त करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

2011 में यूरोपीय संघ की ईबीए योजना के तहत मूल विनिर्देशों के नियमों में छूट, 2011 में कंबोडिया और बांग्लादेश के मामले में देखे गए ब्रेक पॉइंट की व्याख्या करती है। इन देशों को इस नीतिगत परिवर्तन के कारण लाभ हुआ क्योंकि वे निविष्टि आयात कर सकते थे और यूरोपीय संघ के बाजार में निर्यात के लिए परिधान उत्पादन का तेजी से विस्तार करने के लिए सीएमटी मॉडल पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। साथ ही इसने भारत को, जो ईबीए का लाभार्थी नहीं है, कम प्रतिस्पर्धी बना दिया है, जैसा कि 2012 में भारत के लिए ब्रेकपॉइंट द्वारा पुष्टि की गई थी, जिससे यूरोपीय संघ को परिधान निर्यात में ठहराव आया था।

इस प्रकार, अर्थमितीय विश्लेषण इस परिकल्पना को समर्थन प्रदान करता है कि भारत द्वारा अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में सामना की जाने वाली शुल्क संरचना के विकास ने परिधान निर्यात के निष्पादन को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

VII. निष्कर्ष और आगे का रास्ता

परिधान निर्यात भारत के वस्त्र निर्यात का एक बड़ा हिस्सा है और कपड़ा क्षेत्र के साथ मजबूत ऐतिहासिक संबंध हैं। तथापि, वस्त्र निर्यात, विशेष रूप से परिधान निर्यात में हाल के वर्षों में अल्प वृद्धि देखी गई है।

यह आलेख इस घटना का विश्लेषण करने की कोशिश करता है और हमारे प्रतियोगियों से बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा में कितना यथार्थ है। भारत के परिधान निर्यात का प्रमुख गंतव्य यूरो क्षेत्र ने बांग्लादेश और कंबोडिया सहित अन्य देशों के बढ़ते पदचिह्न को देखा है, जिन्होंने अपने ईबीए कार्यक्रम के तहत यूरोपीय संघ के बाजार में शुल्क मुक्त अभिगम से लाभ उठाया है। उन्होंने अन्य देशों से कपड़े मंगाते हुए परिधान उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उत्पादन के सीएमटी मॉडल को सफलतापूर्वक अपनाया है।

2011 में यूरोपीय संघ के मूल स्रोत के नियम में छूट और इन देशों से परिधान निर्यात में बाद में उछाल इस परिकल्पना का समर्थन करता है।

इसलिए, भारत को अपने प्रमुख निर्यात गंतव्यों - यूरोपीय संघ, अमेरिका के साथ सक्रिय रूप से मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वर्तमान में अपने प्रतिस्पर्धियों के लिए शुल्क मुक्त अभिगम के कारण हो रही प्रतिस्पर्धी हानि को रोका जा सके। वियतनाम ने 2019 में यूरोपीय संघ के साथ एक एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं (वियतनाम - यूरोपीय संघ व्यापक साझेदारी और सहयोग फ्रेमवर्क समझौता), जिससे भारत के लिए प्रतियोगिता के केवल बढ़ने की उम्मीद है।

इसके अलावा, वियतनाम जो यूरोपीय संघ में भारत के समान टैरिफ संरचना का सामना कर रहा है, ने अपने परिधान निर्यात का विस्तार करना जारी रखा है, जबकि भारत के परिधान निर्यात स्थिर हो गए हैं; जो भारत में परिधान निर्यातकों द्वारा सामना किए जा रहे कुछ अंतर्निहित समस्याओं को दर्शाते हैं। भारतीय परिधान उद्योग में कपास का प्रभुत्व है, जिसमें कपास के परिधानों का योगदान परिधान निर्यात में 70 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, वैश्विक परिधान की खपत भिन्न-भिन्न देशों में अच्छी तरह से विविध है। इसलिए, भारत को अन्य विभिन्न देशों में डिजाइन और उत्पादन क्षमताओं को विकसित करने की आवश्यकता है। यह भारत को धारण करने योग्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सन्निहित संस्तर परिधान जैसे बढ़ते संबंधित क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने की भी अवसर देगा। वस्त्रों के लिए हाल ही में शुरू की गई उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, विशेष रूप से मानव निर्मित देशों (एमएमएफ) कपड़े, एमएमएफ परिधान और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सही दिशा में एक कदम है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में उत्पादन क्षमता का एक बड़ा हिस्सा होने के कारण इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए वस्तु एवं सेवा कर फ्रेमवर्क के तहत ऋण उपलब्धता और निविष्टि कर जमा और कर वापसी से संबंधित समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा मार्च 2019 में वस्त्र और बने-बनाए वस्त्रों के निर्यात पर सन्निहित राज्य और केंद्रीय करों और परिधानों और बने-बनाए वस्त्रों पर प्रभार की छूट देने के लिए राज्य और केंद्रीय करों और प्रभार की छूट के लिए योजना की

शुरुआत करना एक स्वागत योग्य कदम है, जिससे भारतीय परिधान निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होने की उम्मीद है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू की गई समर्थ योजना भी वस्त्र उद्योग में कामगारों की श्रम उत्पादकता में सुधार करके प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने में मदद कर सकती है।

व्यापक भौगोलिक प्रसार, उच्च अंतर्देशीय परिवहन लागत और अंतर्देशीय स्थित प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के कारण उच्च परिवहन लागत भी प्रतिस्पर्धियों की तुलना में भारतीय परिधान निर्यात की उच्च लागत में योगदान करती है। इसलिए न केवल परिवहन इन्फ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की आवश्यकता है बल्कि व्यापक पावरलूम क्लस्टर विकास योजना के अंतर्गत लक्षित क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

यद्यपि, पूंजी निवेश सब्सिडी प्रदान करने के लिए 2016 से संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) शुरू की गई है, तथापि, इस क्षेत्र में एफडीआई को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। यह उपकरणों के उन्नयन और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करेगा और भारतीय वस्त्र क्षेत्र को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करने में भी मदद करेगा।

पीएम-मित्र (मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल) पार्क्स स्कीम, जिसके तहत देश में सात एकीकृत टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाने हैं, जिससे एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला विकसित करने में मदद मिलेगी। इससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने और इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है।

References :

Adhikari, R., & Weeratunge, C. (2006): "Textiles and Clothing Sector in South Asia: Coping with Post-Quota Challenges", South Asian Yearbook of Trade and Development 2006, Chapter 4, pp. 109-145. New Delhi, India: CENTAD.

Andrews, D. W. K. (1993): "Tests for Parameter Instability and Structural Change with Unknown Change Point", *Econometrica*, 61(4), 821.

Anthony, Anoo & Joseph, Mary. (2014). The Indian Textile Industry: Some Observations. 10.1057/9781137444578_4.

Audet, D. (2004): "A New World Map in Textiles and Clothing", Policy Brief. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Retrieved from <http://www.oecd.org/dataoecd/43/14/33824605.pdf>.

Bai, J. (1997): "Estimating Multiple Breaks One at a Time", *Econometric Theory*, 13(3), 315–352.

Bai, J., & Perron, P. (1998): "Estimating and Testing Linear Models with Multiple Structural Changes", *Econometrica*, Vol. 66, p. 47.

Bai, J., & Perron, P. (2003): "Computation and Analysis of Multiple Structural Change Models", *Journal of Applied Econometrics*, 18(1), 1–22.

Balassa, Bela (1965): "Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage". The Manchester School 33: pp. 99–123.

Bhattacharya, D., & Elliott, K. (2005): "Adjusting to the MFA Phase-Out: Policy Priorities", Retrieved from www.cgdev.org

Brenton, Paul; Hoppe, Mombert, (2007): "Clothing and Export Diversification : Still a Route to Growth for Low-Income Countries?" Policy Research Working Paper; No. 4343. World Bank, Washington, DC. © World Bank. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7334> License: CC BY 3.0 IGO."

Chaudhary, Asiya (2011): "Responsiveness of the Indian Textiles Exporters to the Phase Out of Multi Fiber Agreement (MFA)", *Far East Journal of Psychology and Business*, 2011, vol. 4, pp. 38-56, August.

Chaudhary, Asiya (2016): "Revealed Comparative Advantage Index: An Analysis of Export Potential of Indian Textiles Industry in the Post MFA Period", *American Journal of Economics* 2016, 6(6): pp. 344-351.

- Chadha, R., Pohit, S., Stern, R. M., & Deardorff, A. V. (1999): "Phasing out the Multi-Fibre Arrangement: Implications for India", Global Trade Analysis Project (GTAP) at Purdue University.
- Chen, W., Keung, C., Lau, M., Boansi, D., & Bilgin, M. H. (2017): "Effects of Trade Cost on the Textile and Apparel Market: Evidence from Asian Countries", *The Journal of The Textile Institute*, 108:6, 971-986, DOI: 10.1080/00405000.2016.1206459.
- Chow, G. C. (1960): "Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions", *Econometrica* (Vol. 28).
- Debapriya Bhattacharya and Mustafizer Rahman (2000): "Experience with Implementation of WTO-ATC and Implications for Bangladesh", CPD Working Paper 7, Centre for Policy Dialogue (CPD).
- Dhiman, Rahul, and Manoj Sharma (2017): "Productivity Trends and Determinants of Indian Textile Industry: A Disaggregated Analysis", *International Journal of Applied Business and Economic Research* 15, pp. 114-24.
- Exim Bank: Research Brief. (2005): "Textile Exports: Post MFA Scenario Opportunities and Challenges", No.11, February, www.eximbankindia.com. pp. 1-4.
- Gereffi, G. (1999): "International Trade and Industrial Upgrading in the Apparel Commodity Chain", *Journal of International Economics*, 48(1), pp. 37-70.
- Gupta GK and Khan MA (2017): "Exports Competitiveness of the Indian Textile Industry during and after ATC", *Journal of Textile Science and Engineering*.
- Habib, M. R. I. (2009). "Backward Linkages in Readymade Garment Industry of Bangladesh: Appraisal and Policy Implications". *Journal of Textile and Apparel, Technology and Management*, 6(2), 1-11.
- Hashim, Danish A. (2005): "Post-MFA: Making the Textile and Garment Industry Competitive", *Economic and Political Weekly* 40: pp. 117-27.
- Hudson, Darren & Ethridge, Don E. & Mutuc, Maria Erlinda M. (2011): "Lessons Learned from the Phase-out of the MFA: Moving from Managed Distortion to Managed Distortion", *Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy*, Estey Centre for Law and Economics in International Trade, vol. 12(1), pages 1-15, May.
- Kannan, Elumalai (2018): "India's Comparative Advantage in Export of Textiles and Apparel Products", In *A Study of India's Textile Exports and Environmental Regulations*. Edited by K. S. Kavi Kumar. Singapore: Springer, pp. 45-60.
- Kathuria, Lalit Mohan (2013): "Analysing Competitiveness of Clothing Export Sector of India and Bangladesh: Dynamic Revealed Comparative Advantage Approach", *Competitiveness Review: An International Business Journal* 23, pp.131-57.
- Kathuria, Lalit Mohan (2018): "Comparative Advantages in Clothing Exports: India Faces Threat From Competing Nations", *Competitiveness Review: An International Business Journal* 28, pp. 518-40.
- Kathuria, Sanjay, and Anjali Bhardwaj (1998): "Export Quotas and Policy Constraints in the Indian Textile and Garment Industries", *Policy Research Working Paper Series 2012*. Washington: The World Bank.
- Katti, V., Subir Sen (1999): "MFA Phasing out and Indian Textiles Industry, Select Issues for Negotiation", *Foreign Trade Review*. Vol.34(3-4) pp.102-120, October.
- Liu, J., Wu, S., & Zidek, J. V. (1997): "On Segmented Multivariate Regression", *Statistica Sinica*, Vol. 7, pp. 497-525. Institute of Statistical Science, Academia Sinica.
- Lopez-Acevedo, Gladys, and Raymond Robertson, (2016). "Stitches to Riches? Apparel Employment, Trade, and Economic Development in South Asia. Directions in Development". Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0813-5. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

Mehta, R. (1997): "Trade Policy Reforms, 1991-92 to 1995-96: Their Impact on External Trade", *Economic and Political Weekly*, pp. 779-784.

Minian, I., Martinez, A. & Ibanez, J. (2016). "Technological Change and the Relocation of the Apparel Industry." *Problemas del Desarrollo. Revista Latinoamericana de Economía*, 48(88), 139-164.

Nordas, Hildegunn Kyvik (2004): "The Global Textile and Clothing Industry Post the Agreement on Textiles and Clothing", Discussion Paper No. 5. Geneva: World Trade Organisation.

Panagariya, A. (2018): "Job: Apparel Industry Model holds the Key for India's Job Creation Requirements - The Economic Times", Retrieved November 6, 2020, from The Economics Times website: <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/apparel-industry-model-holds-the-key-for-indias-job-creation-requirements/articleshow/62514682.cms>

Pfohl, H.C. and Shen, X., (2008). "Apparel Supply Chain Between Europe and China. A Guide to Apparel Sourcing and Distribution in China." Darmstadt.

Quandt, R. E. (1960): "Tests of the Hypothesis That a Linear Regression System Obeys Two Separate Regimes", *Journal of the American Statistical Association*, 55, 324-330.

Setyorini, D. and Budiono (2017): "The Impact of Tariff and Imported Raw Materials on Textile and Clothing Export: Evidence from the United States Market", Working Paper in Economics and Development Studies Department of Economics, Padjadjaran University.

Siddiqi, H.G.A. (2005). "The Ready Made Garment Industry of Bangladesh". 2nd Edition, The University Press Limited, Dhaka.

S. Valarmathi and B. Rajasekaran (2019): "Evolution and Growth of Vietnam Textile Industry", *The International Journal of Analytical and Experimental Modal Analysis* Volume XI, Issue IX, September.

Thoburn, J. (2009): "The Impact of the World Garment Recession on the Textile and Garment Industries of Asia", Seoul (Korea) Workshop: November 13-15: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO).

Varukolu, Venu. (2007) "Technology Adoption of Indian Garment Manufacturing Firms" (2007). LSU Master's Theses. 3605. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_theses/3605.

Yao, Y. C. (1988): "Estimating the Number of Change-points via Schwarz' Criterion", *Statistics and Probability Letters*, 6, 181-189.

परिशिष्ट 1: यूरोपीय संघ में परिधान निर्यात पर लगाया जाने वाला शुल्क

चीन	
प्रशुल्क दर	प्रशुल्क लाइनों की संख्या
0.063	8
0.065	5
0.076	1
0.080	20
0.089	8
0.100	4
0.105	13
0.120	383
कुल योग	442

भारत और वियतनाम	
प्रशुल्क दर	प्रशुल्क लाइनों की संख्या
0.050	8
0.052	5
0.060	1
0.064	20
0.071	8
0.080	4
0.084	13
0.096	383
कुल योग	442

बांग्लादेश, कंबोडिया और तुर्की	
प्रशुल्क दर	प्रशुल्क लाइनों की संख्या
0	442

परिशिष्ट 2: विश्व स्तर पर निर्धारित ब्रेक के बाई-पेरॉन टेस्ट के परिणाम

बांग्लादेश				
ब्रेक की अनुमानित संख्या: 2				
विधि: 1 से एम तक के वैश्विक निर्धारित ब्रेक के बाई-पेरॉन टेस्ट				
ब्रेक: 2003, 2011				
अनुक्रमिक एफ-स्टैटिस्टिक निर्धारित ब्रेक;				2
महत्वपूर्ण एफ-स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा ब्रेक;				2
यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक				2
डब्ल्यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक				2
ब्रेक	एफ-स्टैटिस्टिक	मापित एफ-स्टैटिस्टिक	भारित एफ-स्टैटिस्टिक	महत्वपूर्ण मान
1 *	101.8267	203.6534	203.6534	15.37
2 *	112.6310	225.2621	284.9612	12.15
यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*		225.2621	यूडीएमएक्स महत्वपूर्ण मान**	15.41
डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*		284.9612	डब्ल्यूडीएमएक्स महत्वपूर्ण मान**	17.01
* 0.01 के स्तर पर महत्वपूर्ण है।				
** बाई-पेरॉन (अर्थमिति जर्नल, 2003) महत्वपूर्ण मान।				
अनुमानित ब्रेक तिथि:				
1: 2006				
2: 2003, 2011				
कंबोडिया				
ब्रेक की अनुमानित संख्या: 2				
विधि: 1 से एम तक के वैश्विक निर्धारित ब्रेक के बाई-पेरॉन टेस्ट				
ब्रेक: 2003, 2011				
अनुक्रमिक एफ-स्टैटिस्टिक निर्धारित ब्रेक;				2
महत्वपूर्ण एफ-स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा ब्रेक;				2
यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक				1
डब्ल्यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक				1
ब्रेक	एफ-स्टैटिस्टिक	मापित एफ-स्टैटिस्टिक	भारित एफ-स्टैटिस्टिक	महत्वपूर्ण मान
1 *	1328.380	2656.759	2656.759	15.37
2 *	810.8992	1621.798	2051.608	12.15
यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*		2656.759	यूडीएमएक्स महत्वपूर्ण मान**	15.41
डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*		2656.759	डब्ल्यूडीएमएक्स महत्वपूर्ण मान**	17.01
* 0.01 के स्तर पर महत्वपूर्ण है।				
** बाई-पेरॉन (अर्थमिति जर्नल, 2003) महत्वपूर्ण मान।				
अनुमानित ब्रेक तिथि:				
1: 2011				
2: 2001, 2011				

चीन

ब्रेक की अनुमानित संख्या: 2

विधि: 1 से एम तक के वैश्विक निर्धारित ब्रेक के बाई-पेरॉन टेस्ट

ब्रेक: 2003, 2010

अनुक्रमिक एफ-स्टैटिस्टिक निर्धारित ब्रेक;	2
महत्वपूर्ण एफ-स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा ब्रेक;	2
यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	2
डब्ल्यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	2

ब्रेक	एफ-स्टैटिस्टिक	मापित एफ-स्टैटिस्टिक	भारित एफ-स्टैटिस्टिक	महत्वपूर्ण मान
1 *	33.80038	67.60076	67.60076	15.37
2 *	74.26155	148.5231	187.8848	12.15

यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	148.5231	यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	15.41
डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	187.8848	डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	17.01

* 0.01 के स्तर पर महत्वपूर्ण है।

** बाई-पेरॉन (अर्थमिति जर्नल, 2003) महत्वपूर्ण मान।

अनुमानित ब्रेक तिथि:

1: 2008

2: 2003, 2010

भारत

ब्रेक की अनुमानित संख्या: 2

विधि: 1 से एम तक के वैश्विक निर्धारित ब्रेक के बाई-पेरॉन टेस्ट

ब्रेक: 2002, 2012

अनुक्रमिक एफ-स्टैटिस्टिक निर्धारित ब्रेक;	2
महत्वपूर्ण एफ-स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा ब्रेक;	2
यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	2
डब्ल्यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	2

ब्रेक	एफ-स्टैटिस्टिक	मापित एफ-स्टैटिस्टिक	भारित एफ-स्टैटिस्टिक	महत्वपूर्ण मान
1 *	19.11320	38.22639	38.22639	15.37
2 *	43.49999	86.99999	110.0568	12.15

यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	86.99999	यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	15.41
डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	110.0568	डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	17.01

* 0.01 के स्तर पर महत्वपूर्ण है।

** बाई-पेरॉन (अर्थमिति जर्नल, 2003) महत्वपूर्ण मान।

अनुमानित ब्रेक तिथि:

2: 2002, 2012

तुर्की

ब्रेक की अनुमानित संख्या: 2
विधि: 1 से एम तक के वैश्विक निर्धारित ब्रेक के बाई-पेरॉन टेस्ट
ब्रेक: 2002, 2009

अनुक्रमिक एफ-स्टैटिस्टिक निर्धारित ब्रेक;	2
महत्वपूर्ण एफ-स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा ब्रेक;	2
यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	2
डब्ल्यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	2

ब्रेक	एफ-स्टैटिस्टिक	मापित एफ-स्टैटिस्टिक	भारित एफ-स्टैटिस्टिक	महत्वपूर्ण मान
1 *	23.40770	46.81540	46.81540	15.37
2 *	25.22365	50.44730	63.81687	12.15

यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	50.44730	यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	15.41
डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	63.81687	डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	17.01

* 0.01 के स्तर पर महत्वपूर्ण है।
** बाई-पेरॉन (अर्थमिति जर्नल, 2003) महत्वपूर्ण मान।

अनुमानित ब्रेक तिथि:
1: 2004
2: 2002, 2009

वियतनाम

ब्रेक की अनुमानित संख्या: 2
विधि: 1 से एम तक के वैश्विक निर्धारित ब्रेक के बाई-पेरॉन टेस्ट
ब्रेक: 2006

अनुक्रमिक एफ-स्टैटिस्टिक निर्धारित ब्रेक;	2
महत्वपूर्ण एफ-स्टैटिस्टिक का सबसे बड़ा ब्रेक;	2
यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	1
डब्ल्यूडीएमएक्स निर्धारित ब्रेक	2

ब्रेक	एफ-स्टैटिस्टिक	मापित एफ-स्टैटिस्टिक	भारित एफ-स्टैटिस्टिक	महत्वपूर्ण मान
1 *	81.38151	162.7630	162.7630	15.37
2 *	68.62213	137.2443	173.6168	12.15

यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	162.7630	यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	15.41
डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक*	173.6168	डब्ल्यूडीएमएक्स स्टैटिस्टिक**	17.01

* 0.01 के स्तर पर महत्वपूर्ण है।
** बाई-पेरॉन (अर्थमिति जर्नल, 2003) महत्वपूर्ण मान।

अनुमानित ब्रेक तिथि:
1: 2006
2: 2006, 2012

कोयला आपूर्ति-मांग की स्थिति और प्रभाव*

भारत के कोयला क्षेत्र में हाल ही में घरेलू और वैश्विक कारकों के कारण मांग-आपूर्ति में असमानता देखी गई। कोयला, थर्मल विद्युत और कुछ अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है इसलिए इसकी समय पर और पर्याप्त आपूर्ति अनिवार्य है। सरकार के प्रयासों से हाल के हफ्तों में कोयले की कमी में सुधार हुआ है। मध्यम से लंबी अवधि में, ऊर्जा के हरित स्रोतों के लिए अवस्थांतरण बढ़ने से कोयले पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी और ग्लासगो में सीओपी 26 में की गई भारत की प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी।

हाल की अवधि में भारत में कोयला क्षेत्र विभिन्न कारणों से मांग-आपूर्ति असंतुलन से जूझ रहा है: बिजली की मांग में तेज वृद्धि, विस्तारित मानसून के कारण आपूर्ति में व्यवधान और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि के कारण आयात में कमी। प्रतिबंधों को हटाने और आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हुई, जबकि सितंबर में भारी मानसून और अक्टूबर के शुरुआती हिस्से ने कोयले के खनन को प्रभावित किया। पिछले कुछ महीनों के दौरान कोयले की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई है और वैश्विक ऊर्जा खपत में वृद्धि हुई है, जिससे कोयले की मांग इसकी आपूर्ति से आगे निकल गई है। चूंकि कोयले का उपयोग इस्पात जैसे कई उद्योगों में प्राथमिक इनपुट के रूप में भी किया जाता है, इसलिए इसकी कमी का इन उद्योगों के उत्पादन पर असर पड़ना तय है।

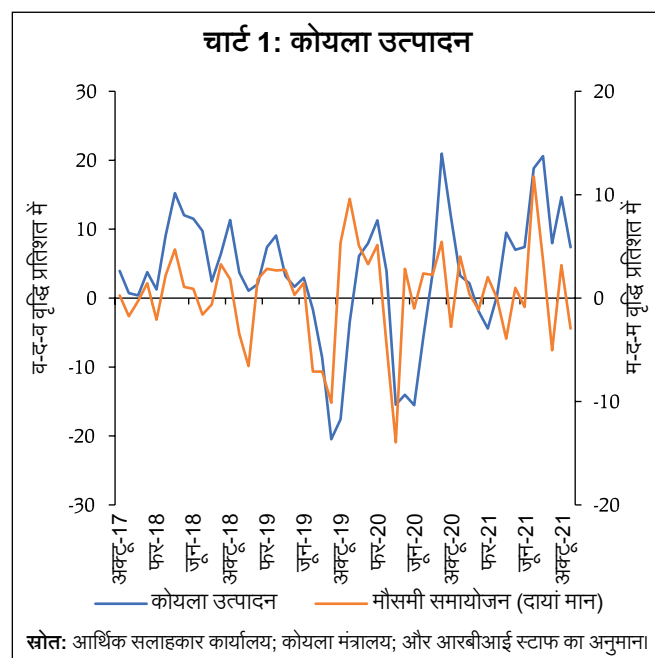
इस पृष्ठभूमि में, यह आलेख कोयले की आपूर्ति-मांग की स्थिति और उसके प्रभाव का आकलन करता है। घरेलू कोयला क्षेत्र में हाल के विकसित हो रहे रुझानों पर खंड II में चर्चा की गई है, जबकि खंड III में वैश्विक कोयला खपत और ऊर्जा की स्थिति का विश्लेषण किया गया है। खंड IV में विद्युत और इस्पात जैसे संबद्ध क्षेत्रों में प्रवृत्तियों और इन क्षेत्रों के लिए कोयले की कमी,

* यह आलेख कश्यप गुप्ता, विपुल कुमार घोष और मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) के सुनील कुमार द्वारा तैयार किया गया है। आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और वे जिस संगठन से संबंधित हैं, उसके विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सामान्य अस्वीकरण लागू है।

यदि कोई हो, के प्रभाव को दर्शाया गया है। खंड V में निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

II. घरेलू कोयला क्षेत्र - हाल के रुझान

कोयला उत्पादन, जिसका आठ प्रमुख उद्योगों (ईसीआई) के सूचकांक में 10.33 प्रतिशत का वेटेज है, ने सितंबर 2021 में 8.0 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की, जबकि पिछले साल के इसी महीने में 21.0 प्रतिशत और अगस्त 2021 में 20.6 प्रतिशत थी, आंशिक रूप से मानसून की वापसी ने कोयला उत्पादन के साथ-साथ खानों से आपूर्ति को प्रभावित किया था। नवंबर 2021 में 7.4 प्रतिशत तक कम होने से पहले अक्टूबर 2021 में कोयला उत्पादन वृद्धि 14.6 प्रतिशत हो गई, जैसा कि कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और कैप्टिव खानों जैसी दो प्रमुख कंपनियों के उत्पादन से साबित होता है। तदनुसार, ईसीआई के हिस्से के रूप में कोयला उत्पादन में वृद्धि, नवंबर 2021 में गिरावट गिरने की उम्मीद है। मौसमी रूप से समायोजित महीने-दर-महीने (एम-ओ-एम) आधार पर, कोयले के उत्पादन में सितंबर में 5.0 प्रतिशत की गिरावट आई, लेकिन नवंबर 2021 में फिर से 2.9 प्रतिशत की गिरावट से पहले अक्टूबर में 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट 1)।



सारणी 1: कोयला उत्पादन के मौसमी कारक

महीना	औसत (2012 से 2019)	2021
जून	88.4	84.5
जुलाई	82.0	80.4
अगस्त	80.2	76.9
सितंबर	81.3	77.6
अक्टूबर	95.8	93.5

टिप्पणी: मौसमी कारकों X13 एस्मि.स्रोत से लिए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

मानसून का आमतौर पर कोयला उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है लेकिन इस वर्ष प्रभाव अधिक गंभीर था जैसा कि ईसीआई कोयला सूचकांक के उपयोग से लिए गए मौसमी कारकों की तुलना से पता चला है (सारणी 1)।

घरेलू कोयले की खपत लगातार घरेलू उत्पादन से ऊपर बनी हुई है, जिसके लिए आयात के लिए पर्याप्त साधन की आवश्यकता है - 2018-21 के दौरान घरेलू खपत के लगभग 25 प्रतिशत थी (चार्ट 2 और सारणी 2)। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका कुल कोयले के आयात में लगभग 80 प्रतिशत का योगदान करते हैं। इन तीन बाजारों से कोयले की कीमतें हाल की अवधि में काफी बढ़ गई हैं; इसके साथ ही अगस्त 2021 में आयात में 13.7 प्रतिशत (व-द-व), सितंबर में 9.1 प्रतिशत और अक्टूबर में 3.4 प्रतिशत की गिरावट आई।

सारणी 2: कोयला उत्पादन, आयात और खपत

(मिलियन टन)

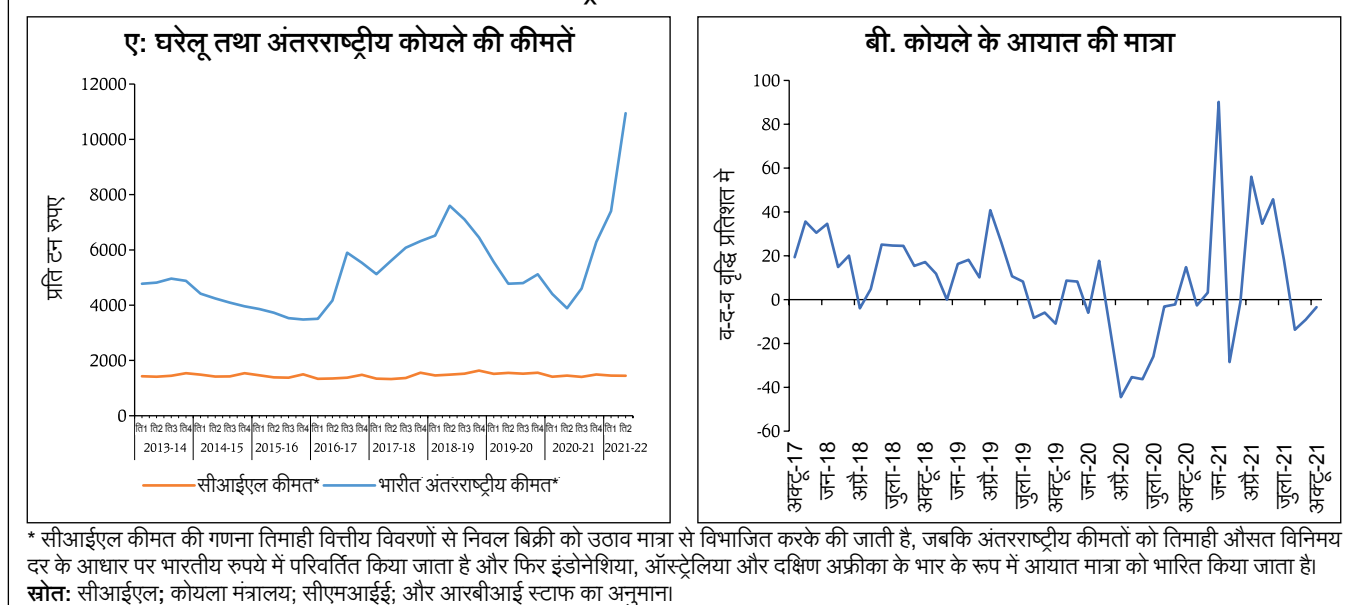
अवधि	उत्पादन	डिस्पैच	आयात	कुल खपत
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)
विव: 2016-17	657.9	646.0	191.0	836.9
विव: 2017-18	675.4	690.0	208.2	898.3
विव: 2018-19	728.7	732.8	235.3	968.1
विव: 2019-20	730.9	707.2	248.5	955.7
विव: 2020-21	716.1	690.9	230.3	921.2
2020-21 (अप्रै-अक्टू)	338.1	363.0	113.4	476.4
2021-22 (अप्रै-अक्टू)	379.6	448.8	130.6	579.4
अप्रैल 2021	51.6	65.5	21.4	86.9
मई 2021	53.3	67.3	20.7	88.0
जून 2021	51.0	62.5	19.8	82.3
जुलाई 2021	54.4	62.7	17.2	79.9
अग 2021	53.7	60.3	14.6	74.9
सितं 2021	51.7	59.8	15.6	75.4
अक्टू 2021*	63.8	70.4	21.5	91.9

*कोयला, लिग्नाइट और कोक की कुल मात्रा में कोयले की मात्रा के औसत हिस्से का उपयोग करके कोयले के आयात का अनुमान लगाया गया है।

स्रोत: कोयला मंत्रालय; सीएमआईई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

परिणामस्वरूप, आयातित कोयले पर अधिक निर्भर करने वाले विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान आयात नीति¹ के अनुसार, उपभोक्ता अपनी वाणिज्यिक समझदारी के आधार पर अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में

चार्ट 2: अंतरराष्ट्रीय कीमतें तथा कोयले की आयात



¹ <https://coal.gov.in/en/major-statistics/import-and-export>

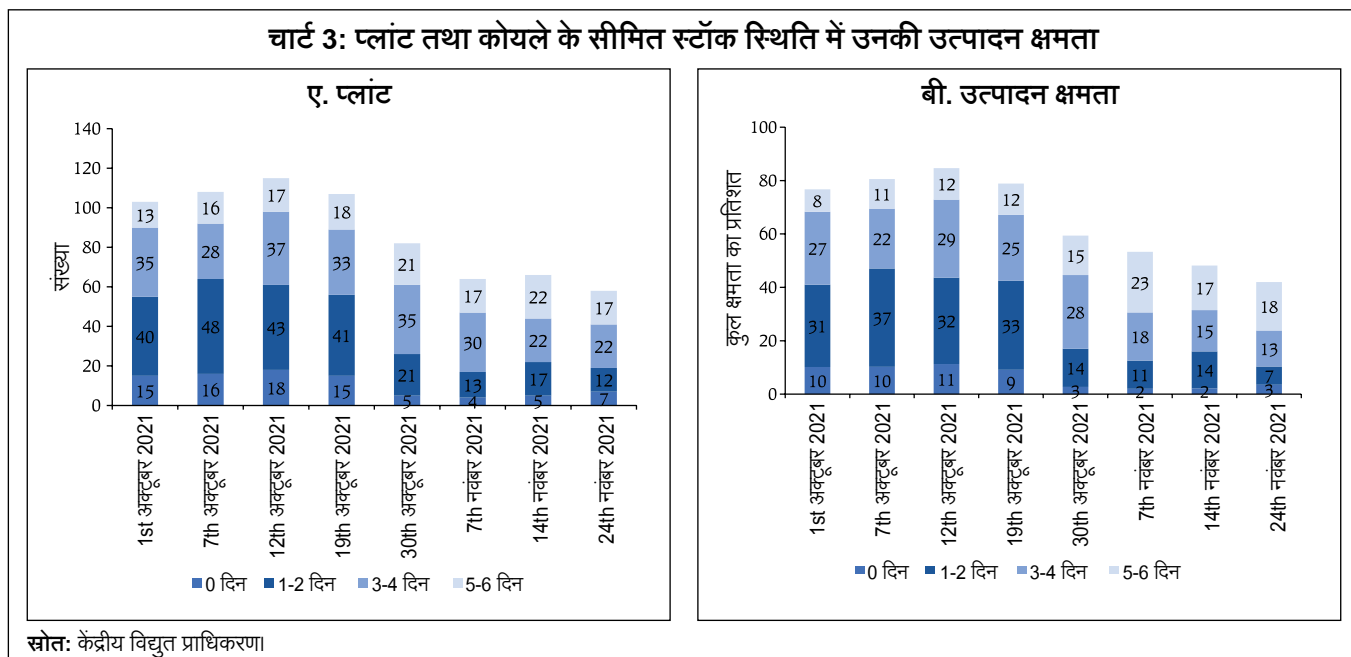
रखते हुए स्वतंत्र रूप से कोयले का आयात कर सकते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और अन्य इस्पात विनिर्माण इकाइयां मुख्य रूप से आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने और गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कोकिंग कोयले का आयात कर रही हैं, जबकि कोयला आधारित बिजली संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, कैप्टिव पावर प्लांट, स्पंज आयरन संयंत्र, औद्योगिक उपभोक्ता और कोयला व्यापारी गैर-कोकिंग कोयले का आयात कर रहे हैं।

12 अक्टूबर, 2021 तक, कुल थर्मल विद्युत क्षमता में लगभग 85 प्रतिशत का योगदान देने वाले 115 थर्मल संयंत्रों में 6 दिनों तक कोयले का स्टॉक था; इनमें से, कुल क्षमता के लगभग 11 प्रतिशत के साथ 18 संयंत्रों में कोयले का स्टॉक शून्य दिन था; कुल बिजली क्षमता के लगभग 32 प्रतिशत के साथ 43 संयंत्रों में 1-2 दिनों का कोयला स्टॉक था; और कुल क्षमता के लगभग 29 प्रतिशत के साथ 37 संयंत्रों में 3-4 दिनों का कोयला स्टॉक था (चार्ट 3)। इसके बाद, स्थिति में सुधार हुआ और 6 दिनों तक के कोयले के स्टॉक वाले संयंत्रों की संख्या 30 अक्टूबर को घटकर 82 (कुल थर्मल पावर क्षमता में लगभग 60 प्रतिशत का योगदान)

और 24 नवंबर को 58 हो गई (कुल थर्मल पावर क्षमता में लगभग 41 प्रतिशत का योगदान) (चार्ट 4)। राज्य-वार विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 24 नवंबर तक, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे कुछ राज्यों में कोयले के स्टॉक की स्थिति महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत सहज प्रतीत होती है। समाचार पत्रों की रिपोर्टों के अनुसार कोयला कंपनियों को अतिदेय भुगतानों ने भी कुछ राज्यों के मामले में कोयला भंडार में कमी को योगदान दिया है²।

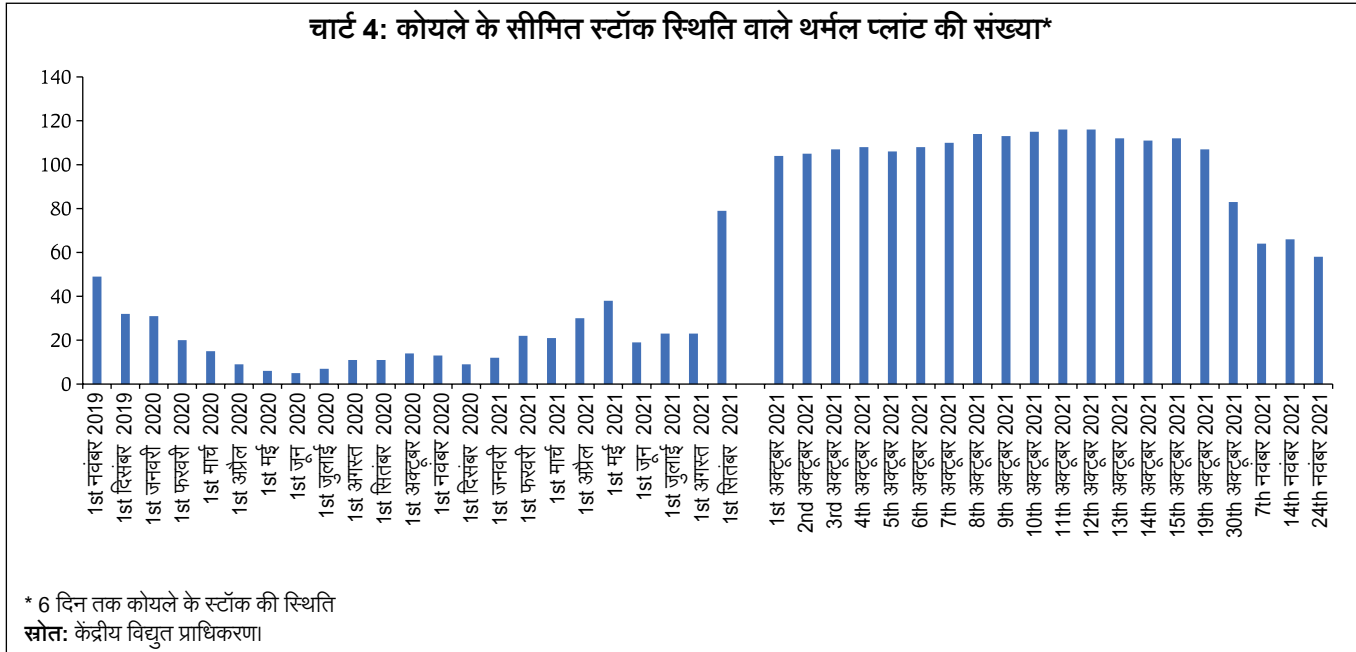
सरकार स्थिति को कम करने के लिए घरेलू स्रोतों से कोयले की आपूर्ति बढ़ा रही है। आपूर्ति में और सुधार करने के लिए, सरकार ने घरेलू कोयले का उपयोग करने वाले बिजली उत्पादकों को अपनी कोयला आवश्यकताओं के 10 प्रतिशत तक आयात करने की अनुमति दी है। सरकार घरेलू स्तर पर तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मध्यम से दीर्घावधि में कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी उपाय कर रही है। इस संबंध में, सरकार ने हाल ही में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू करके निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति दी है और 40 नई खानों को शामिल करते हुए कोयला खानों की नीलामी की अगली किस्त भी शुरू की है।

चार्ट 3: प्लांट तथा कोयले के सीमित स्टॉक स्थिति में उनकी उत्पादन क्षमता



² <https://indianexpress.com/article/business/clear-dues-to-coal-cos-govt-to-4-states-with-low-stock-high-thermal-capacities-7566897/>

चार्ट 4: कोयले के सीमित स्टॉक स्थिति वाले थर्मल प्लांट की संख्या*



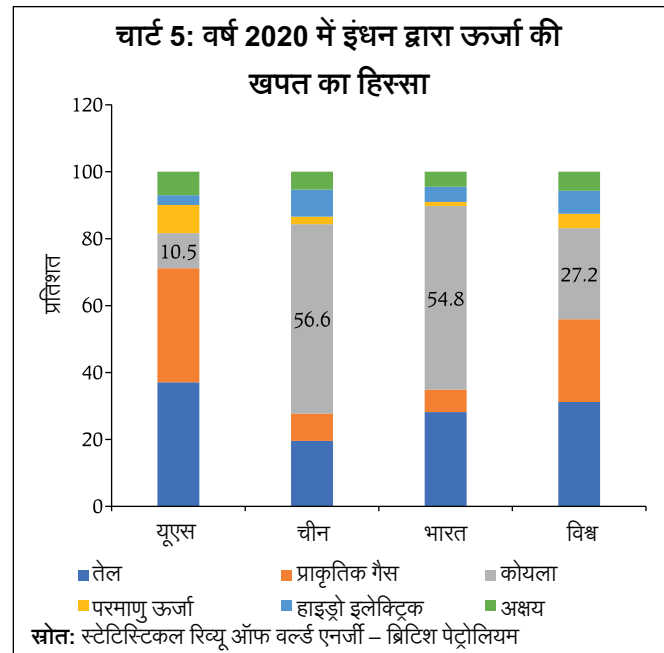
III. कोयले की वैश्विक खपत

वायरस कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर आर्थिक गतिविधियों में संकुचन के कारण 2020 में वैश्विक स्तर पर ऊर्जा की मांग में तेजी से गिरावट आई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार, 2020 में विश्व उत्पादन में 3.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) और उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) के उत्पादन में क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 2.1 प्रतिशत की गिरावट आई। वैश्विक आर्थिक गतिविधि में कोविड महामारी के हास के साथ उछाल आया, और 2021 में विश्व उत्पादन में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है - एई को 2021 में 5.2 प्रतिशत (यूएसए द्वारा 6.0 प्रतिशत) और ईएमडीई में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है (चीन 8.5 प्रतिशत तक)³। तदनुसार, विश्व ऊर्जा की मांग भी 2021 में विशेष रूप से दूसरी छमाही में बढ़ी, और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने 2021 में वैश्विक ऊर्जा की मांग को 4.0 प्रतिशत तक लाने की परियोजना की, जो 0.5 प्रतिशत (आईईए, ग्लोबल एनर्जी रिव्यू, 2021) से पूर्व-कोविड स्तरों से अधिक है। कोयला विश्व ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों में से एक बना हुआ है, हालांकि “जलवायु

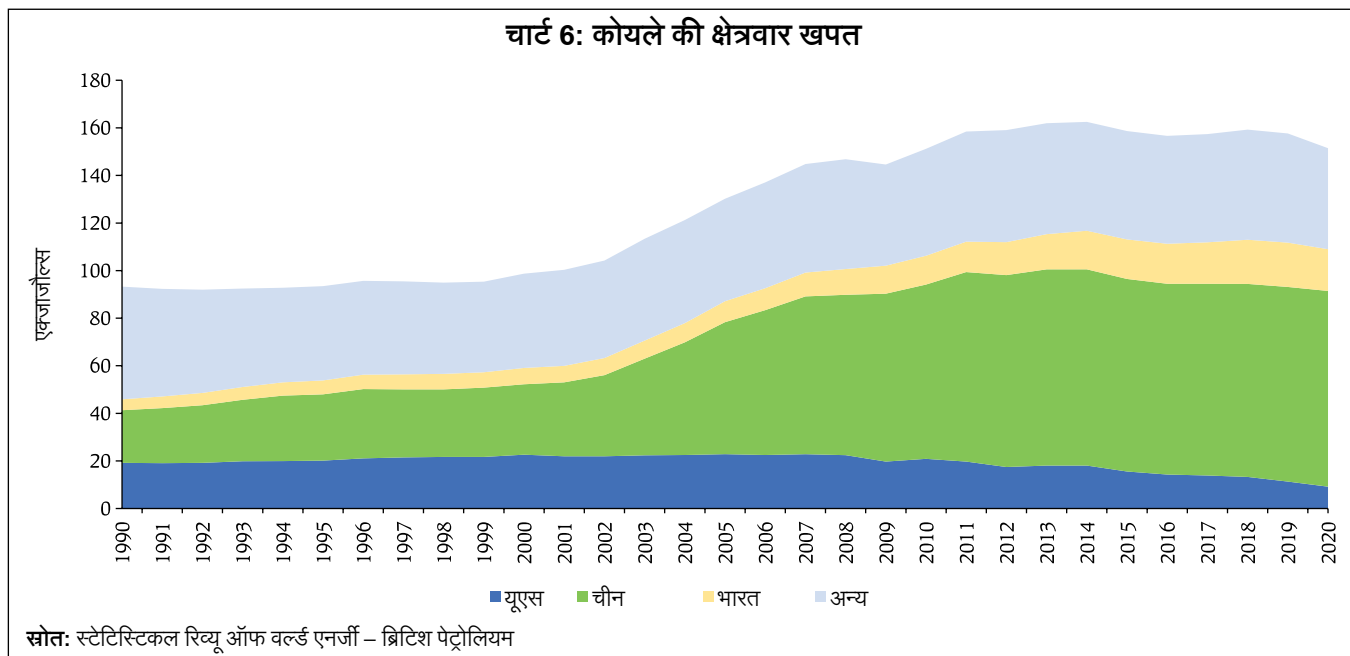
परिवर्तन” के तहत वैश्विक प्रयास हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं (चार्ट 5)।

आईईए के अनुसार, 2020 में वैश्विक कोयले की मांग में 4.0 प्रतिशत की गिरावट आई, जो कोविड -19 प्रतिबंधों से प्रभावित आर्थिक मंदी के कारण है तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ी गिरावट है। ऊर्जा की मांग में वृद्धि के साथ, वैश्विक कोयले की

चार्ट 5: वर्ष 2020 में इंधन द्वारा ऊर्जा की खपत का हिस्सा



³ आईएमएफ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अक्टूबर 2021 अपडेट।



मांग 2021 में बढ़ी क्योंकि यह कुल विश्व ऊर्जा खपत का एक बड़ा हिस्सा है। आईईए को उम्मीद है कि 2021 में वैश्विक कोयले की मांग में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि होगी, जो 2019 के स्तर से अधिक है। भारत के बाद चीन कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता रहा है और दोनों अर्थव्यवस्थाएं बहाल हुई हैं जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा के लिए कोयले की खपत में महत्वपूर्ण उछाल आया है (चार्ट 6)। वैश्विक कोयले की आपूर्ति भी 2021 में फिर से शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन भारी बारिश और घरेलू बाजार दायित्वों के सख्त प्रवर्तन के कारण बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले कोयले के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक इंडोनेशिया के सामने उत्पादन चुनौतियों का इस पर असर पड़ सकता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि मंदी के दौर के बाद चीन भी कोयले का उत्पादन बढ़ा रहा है। वहीं, चीनी अधिकारियों ने व्यापारियों और सटोरियों पर नियमन कड़ा कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू कोयले की कीमतों में भारी गिरावट आई है।

IV. घरेलू कोयले का उपयोग: बिजली और अन्य क्षेत्र

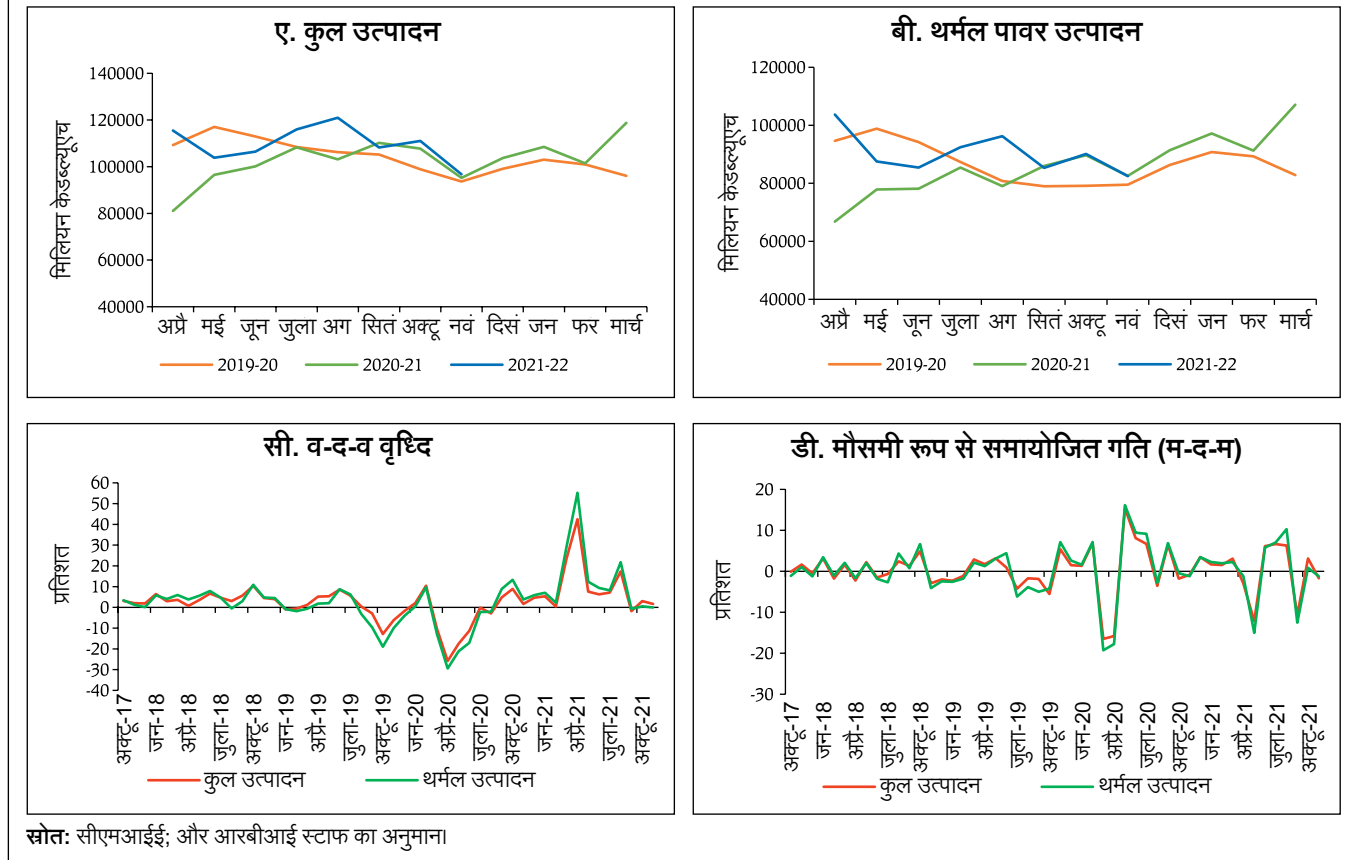
बिजली

हाल के महीनों में बिजली की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधि में तेजी से प्रेरित है। बिजली मंत्रालय के अनुसार, बिजली की खपत अगस्त-सितंबर 2019

(पूर्व-कोविड स्तर) के दौरान प्रति माह औसतन 107 बिलियन यूनिट (बीयू) से बढ़कर अगस्त-सितंबर 2021 में 124 बीयू प्रति माह हो गई (लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि)⁴। अगस्त में चरम पर पहुंचने के बाद सभी स्रोतों से बिजली उत्पादन सितंबर में 1.7 प्रतिशत व-द-व से कम हो गया, इससे पहले कि अक्टूबर में 3.1 प्रतिशत और नवंबर में 1.6 प्रतिशत का विस्तार हुआ (चार्ट 7)। योगदान के संदर्भ में, हाइड्रल ने नवंबर में कुल बिजली उत्पादन में पूरे वर्ष दर वर्ष वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया। मौसमी रूप से समायोजित म-द-म आधार पर, कुल उत्पादन और थर्मल उत्पादन में सितंबर में क्रमशः 10.7 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की कमी आई, इससे पहले कि अक्टूबर में 3.1 प्रतिशत और 0.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। नवंबर में, कुल उत्पादन और थर्मल उत्पादन में फिर से क्रमशः 1.7 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत की गिरावट आई। फिर भी, कुल बिजली उत्पादन में थर्मल पावर का प्रमुख योगदान बना हुआ है, हालांकि इसका हिस्सा 2015-16 में लगभग 81 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में लगभग 75 प्रतिशत हो गया। कुल उत्पादन में कोयला आधारित थर्मल उत्पादन का हिस्सा भी 2015-16 में 74 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 69 प्रतिशत हो गया - अक्टूबर 2021 में, कोयला आधारित थर्मल उत्पादन ने लगभग 75 प्रतिशत का योगदान दिया।

⁴ <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1762579>

चार्ट 7: बिजली उत्पादन



सितंबर के महीने और अक्टूबर की शुरुआत में भारी बारिश के कारण कोयला क्षेत्रों में जल जमाव ने कोयला खानों से आपूर्ति में बाधा डाली, जिसके परिणामस्वरूप अक्टूबर में थर्मल पावर प्लांटों द्वारा सामान्य स्टॉक संचय की तुलना में कम हो गया। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय कोयले की कीमतों में वृद्धि के कारण

कम कोयले के आयात ने भी मांग और आपूर्ति की असमानता में योगदान दिया। थर्मल पावर प्लांटों द्वारा कोयले के आयात में व-द-व सितंबर 2021 में लगभग 73 प्रतिशत और अक्टूबर 2021 में 61 प्रतिशत की गिरावट आई (सारणी 3)।

सारणी 3: थर्मल पावर प्लांट की कोयला सांख्यिकी

(मिलियन टन में)

महीना	घरेलू प्राप्ति		आयात		कुल प्राप्ति		कुल खपत	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
अप्रैल	39.1	54.6	3.4	4.3	42.5	58.9	38.0	63.6
मई	39.6	55.2	4.8	3.7	44.4	58.9	44.9	53.3
जून	38.5	50.7	2.7	3.3	41.2	53.9	45.1	54.0
जुलाई	40.6	49.8	3.9	2.1	44.5	51.9	51.3	57.3
अगस्त	41.8	47.3	3.3	1.9	45.1	49.2	48.0	59.6
सितंबर	43.6	50.4	4.0	1.1	47.7	51.5	51.9	55.8
अक्टूबर	48.4	57.9	4.6	1.8	53.0	59.8	53.6	57.7

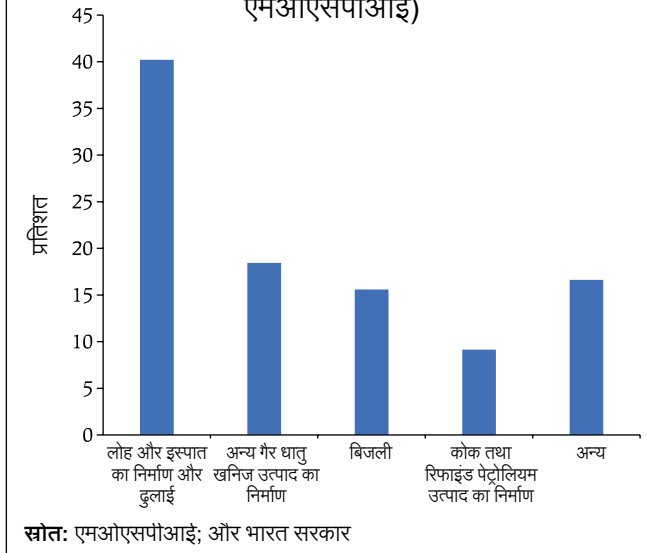
स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण।

अन्य क्षेत्र

बिजली क्षेत्र के अलावा, लोहा और इस्पात, गैर-धात्विक खनिज उत्पाद और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद उन प्रमुख उद्योगों में से हैं जो अपने उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में कोयला और लिग्नाइट का उपयोग करते हैं। आपूर्ति और उपयोग सारणी, 2015-16, एमओएसपीआई 5 के अनुसार, 'लोहा और इस्पात' इनपुट के रूप में कोयले के उच्चतम अनुपात की खपत करता है (चार्ट 8)।

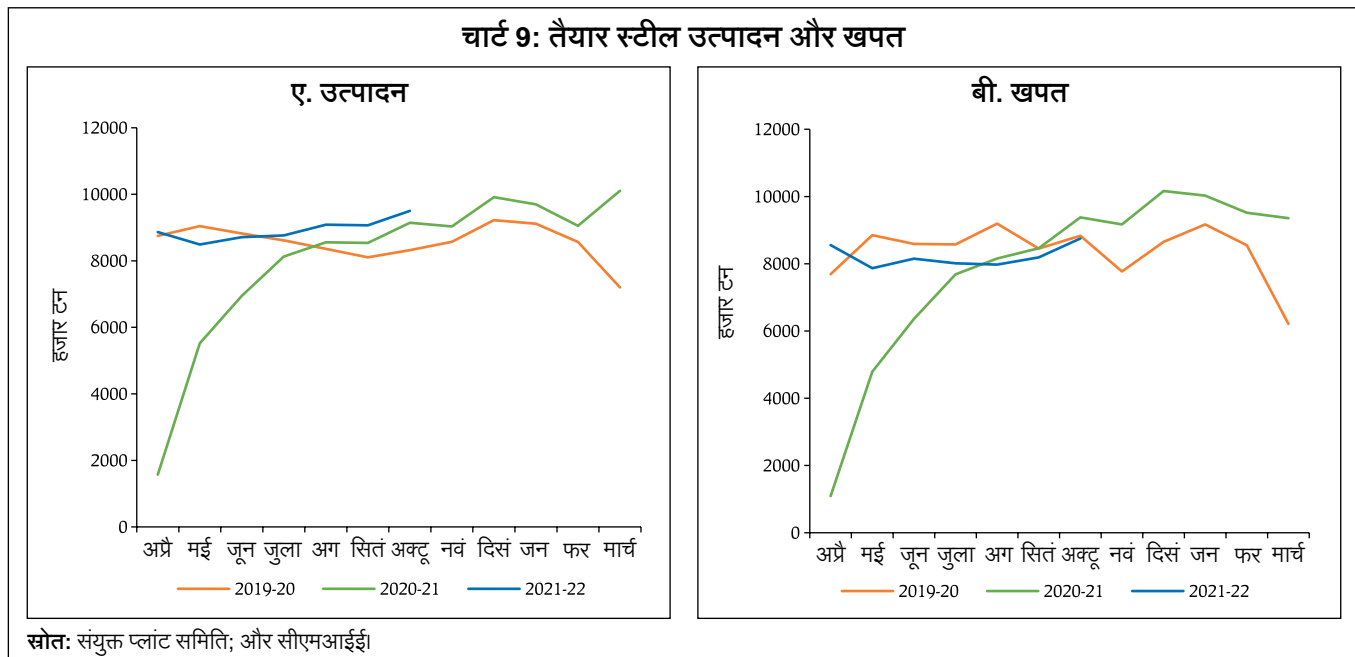
इनपुट के रूप में उपयोग की सीमा को देखते हुए, कोयले की कमी का कोयला-गहन उद्योगों पर कुछ नकारात्मक क्षणिक प्रभाव पड़ सकता है। तैयार इस्पात उत्पादन में वर्ष – दर – वर्ष गिरावट देखी गई जो जुलाई में 7.7 प्रतिशत से सितंबर में 6.2 प्रतिशत और अक्टूबर में 3.9 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई (चार्ट 9)। इस्पात की खपत में भी गिरावट आ रही है (सितंबर में -3.2 प्रतिशत और अक्टूबर में -6.7 प्रतिशत), आंशिक रूप से सेमी कंडक्टर और चिप्स की कमी के मद्देनजर ऑटो उत्पादन में मंदी

चार्ट 8: उद्योग-वार कोयला और लिग्नाइट का उपयोग (आपूर्ति और उपयोग सारणी 2015-16 के अनुसार, एमओएसपीआई)



के कारण, जबकि निर्माण गतिविधि में स्टील की मांग मजबूत बनी हुई है।

चार्ट 9: तैयार स्टील उत्पादन और खपत



⁵ <http://mospi.nic.in/publication/supply-use-tables>

V. निष्कर्ष

घरेलू आपूर्ति में मानसून संबंधी व्यवधानों और कम आयात के कारण पिछले कुछ महीनों में विशेष रूप से थर्मल विद्युत क्षेत्र में कोयले की मांग-आपूर्ति संतुलन बिगड़ गई है। वहीं, आर्थिक गतिविधियों में उछाल और मौसम के चलते बिजली की मांग बढ़ी है। सरकार थर्मल विद्युत संयंत्रों में पर्याप्त स्टॉक बनाने के लिए कोयले की आपूर्ति बढ़ा रही है और हाल के हफ्तों में स्थिति ठीक हो गई है। तथापि, उच्च आयात मूल्यों और उँची शिपमेंट माल दुलाई दरों के मद्देनजर घटते आयात के कारण निकट अवधि में मांग-आपूर्ति संतुलन तंग रह सकता है और आने वाले सर्दियों के महीनों में बिजली की मांग में कमी के कारण इसके कम होने की उम्मीद की जा सकती है। आयात पर बड़ी संरचनात्मक निर्भरता को देखते हुए, सरकार हाल ही में वाणिज्यिक कोयला खनन शुरू करके निजी क्षेत्र की भागीदारी की अनुमति देने सहित घरेलू मांग को पूरा करने के लिए मध्यम से लंबी अवधि में कोयले के उत्पादन

को बढ़ाने के साथ-साथ हरित संसाधनों (प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय, और परमाणु) के उत्पादन में तेजी लाने के उपाय कर रही है। मध्यम से दीर्घावधि में हरित संसाधनों को अपनाने से भारत को पेरिस समझौते और ग्लासगो में हाल ही में संपन्न सीओपी 26 वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन के तहत जलवायु परिवर्तन से संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

संदर्भ:

Statistical Review of World Energy (2021). British Petroleum. <https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html>

Global Energy Review (2021). International Energy Agency. <https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2021>

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी लेखा और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक शृंखला

विषय-वस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक	117
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	118
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	119
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय/विक्रय	120
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	121
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	121
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	122
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	123
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	124
9	कुल चलनिधि राशियां	124
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	125
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	125
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	126
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	126
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	127
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	128
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	129
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	130
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	131
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	131
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	131
21	थोक मूल्य सूचकांक	132
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	136
	सरकारी खाते और खजाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	136
24	खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	137
25	खजाना बिलों की नीलामी	137
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	138
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	139
28	वाणिज्यिक पत्र	139
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	139
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	140

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	141
32	विदेशी मुद्रा भंडार	141
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	141
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	142
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	142
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	143
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी)- पंजीकरण	144
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरीकी डॉलर)	145
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	146
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरीकी डॉलर)	147
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	148
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	149
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	150
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	152
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	153
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	154
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	155
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	156
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	157

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2020-21	2020-21		2021-22	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	-6.2	-22.4	-7.3	18.8	8.5
1.1.1 कृषि	3.6	3.5	3.0	4.5	4.5
1.1.2 उद्योग	-6.4	-31.0	-1.6	40.4	6.7
1.1.3 सेवाएं	-8.4	-24.9	-11.0	16.1	9.9
1.1क अंतिम खपत व्यय	-7.3	-19.9	-13.4	13.8	8.6
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-10.8	-46.6	-8.6	55.3	11.0
	2020-21	2020		2021	
	1	सित.	अक्टू.	सित.	अक्टू.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-8.4	1.0	4.5	3.1	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	11.4	10.5	11.1	9.4	10.0
2.1.2 ऋण	5.6	5.1	5.6	6.7	6.9
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	5.5	5.1	5.6	6.8	7.0
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	19.3	20.3	21.5	5.1	4.4
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	18.8	14.4	12.8	14.7	14.1
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	12.2	12.2	11.6	9.3	9.7
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.50	3.00	3.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.2	3.6	3.8	4.7	4.9
3.4 ऋण-जमा अनुपात	72.4	72.0	72.0	70.2	70.0
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	37.4	-14.3	2.0	1.5	20.7
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5	31.1	31.0	29.9	29.4
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	46.8	100.6	85.4	41.3	27.0
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
4.2 रिवर्स रिपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.4 बैंक दर	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
4.5 आधार दर	7.40/8.80	7.40/9.00	7.40/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	6.55/7.05	6.65/7.15	6.65/7.10	6.55/7.00	6.50/7.00
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
4.8 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	3.25	3.41	3.19	3.19	3.28
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.32	3.36	3.20	3.45	3.56
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.47	3.58	3.36	3.57	3.83
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	3.83	3.73	3.45	3.81	4.04
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.34	6.04	5.91	6.23	6.43
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरीकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.40	73.73	73.97	73.69	74.79
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	85.31	86.04	86.97	86.47	87.26
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरीकी डॉलर					
1-माह (%)	6.80	3.74	3.24	3.50	4.17
3-माह (%)	5.64	3.80	3.46	3.64	4.39
6-माह (%)	5.47	3.91	3.89	3.87	4.75
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	6.18	7.3	7.6	4.3	4.5
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.03	5.6	5.9	4.4	4.5
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.29	1.3	1.3	10.7	12.5
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	1.71	4.1	4.3	4.1	5.2
6.3.2 ईंधन और पावर	-7.99	-8.6	-11.1	24.8	37.2
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.75	1.9	2.2	11.4	12.0
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-16.91	-19.6	-10.3	84.2	62.5
7.2 निर्यात	-6.88	6.0	-4.9	22.7	43.0

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसारण शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2020-21	2020	2021				
		नव.	अक्टू. 29	नव. 5	नव. 12	नव. 19	नव. 26
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2831727	2744155	2917689	2961581	2965646	2961030	2955757
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	12	18	13	15	13	13
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2831738	2744167	2917707	2961595	2965661	2961044	2955770
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	106555	113222	114228	112760	116980	117180	113277
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2724437	2630160	2802933	2848313	2847974	2843171	2841822
1.2.3 रुपया सिक्का	746	785	545	521	707	692	671
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमा राशियां	1504697	1445616	2106098	2055529	2054708	2062381	2032713
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	100	100	100	101	100	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना							
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	43
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	542693	461900	663314	670135	633542	683604	656663
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6529	5547	7272	7106	6869	7150	6863
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3204	2414	3484	3652	3497	3728	3581
2.1.1.7 अन्य बैंक	31820	27333	36704	37301	37057	37080	37261
2.1.1.8 अन्य	895440	944501	1301553	1261063	1292879	1253617	1259369
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	24868	3778	93627	76129	80721	77060	68833
2.1.2 अन्य देयताएं	1343670	1462954	1377512	1341723	1333123	1332117	1346388
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2848367	2908571	3483609	3397251	3387831	3394498	3379102
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	12	18	14	15	13	14
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1204135	1349768	1556220	1479623	1463261	1460883	1489540
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1674	2112	1966	7635	10350	8631	460
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	90275	77097	93597	96986	93282	101928	93677
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	26422	23596	21902	21976	21976	21976	20231
2.2.3.7 एक्विजि बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	6678	9216	73	77	77	2577	77
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	24858	9703	77660	61063	61848	59217	43986
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1331671	1284031	1546119	1545487	1545973	1547903	1544832
2.2.6 अन्य आस्तियां	162643	153035	186055	184392	191050	191371	186286
2.2.6.1 सोना	146572	147429	177912	175986	182571	182885	177516

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घावधि रिपो परिचालन&	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	लघु वित्त बैंकों के लिए विशेष दीर्घावधि रिपो परिचालन	विशेष पुनः क्रय रिपो ₹	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12-2-4-7-8-13)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय					
अक्टू. 1, 2021	-	392929	-	-	150	-	-	15000	15000	-	-	-	-	-392779
अक्टू. 2, 2021	-	14729	-	-	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-14295
अक्टू. 3, 2021	-	3090	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-3086
अक्टू. 4, 2021	-	404319	-	-	80	-1900	-	-	-	-	350	-	-	-405789
अक्टू. 5, 2021	-	420811	-	200001	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-620577
अक्टू. 6, 2021	-	363682	-	-	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-363376
अक्टू. 7, 2021	-	339048	-	-	150	-	-	-	315	-	-	-	-	-338583
अक्टू. 8, 2021	-	253004	-	400002	1195	-	-	-	-	-	-	9296	-	-661107
अक्टू. 9, 2021	-	9307	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-9293
अक्टू. 10, 2021	-	5424	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-5410
अक्टू. 11, 2021	-	263634	-	-	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-263384
अक्टू. 12, 2021	-	272080	-	200013	562	-	-	-	-	-	-	-	-	-471531
अक्टू. 13, 2021	-	262968	-	-	540	-2300	-	-	-	-	-	-	-	-264728
अक्टू. 14, 2021	-	208245	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-207795
अक्टू. 15, 2021	-	1124	-	-	595	-	-	-	-	-	-	-	-	-529
अक्टू. 16, 2021	-	51112	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-51084
अक्टू. 17, 2021	-	5311	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-5303
अक्टू. 18, 2021	-	201304	-	-	806	-	-	-	-	-	-	-	-	-200498
अक्टू. 19, 2021	-	44534	-	-	3928	-	-	-	-	-	-	-	-	-40606
अक्टू. 20, 2021	-	207337	-	200008	1678	-	-	-	-	-	-	-	-	-405667
अक्टू. 21, 2021	-	169520	-	-	370	2500	-	225	315	-	-	-	-	-166560
अक्टू. 22, 2021	-	140873	-	418395	461	-2500	-	90	-	-	-	-	8365	-569762
अक्टू. 23, 2021	-	14916	-	-	476	-	-	-	-	-	-	-	-	-14440
अक्टू. 24, 2021	-	3560	-	-	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-3344
अक्टू. 25, 2021	-	139644	-	-	400	2500	-	-	-	-	-	-	-	-136744
अक्टू. 26, 2021	-	174518	-	200019	250	-2500	-	-	-	-	-	-	-	-376787
अक्टू. 27, 2021	-	179641	-	-	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-179317
अक्टू. 28, 2021	-	202492	-	-	230	2500	-	-	-	-	-	-	-	-199762
अक्टू. 29, 2021	-	184740	-	-	455	-2500	-	-	-	-	-	-	-	-186785
अक्टू. 30, 2021	-	61323	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-61323
अक्टू. 31, 2021	-	8289	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-8275

टिप्पणी: # लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ), लक्षित दीर्घावधि रिपोपरिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) और मांग के अनुसार लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन। ऋणात्मक(-) चिन्ह बैंकों द्वारा लिए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है। & ऋणात्मक (-) चिन्ह बैंकों द्वारा किए गए पुनर्भुगतान को दर्शाता है।
 ₹ 07 मई 2021 की प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/177 के अनुसार। 18 जून 2021 से, 4 जून 2021 के प्रेस विज्ञप्ति संख्या 2021-2022/323 के अनुसार डाटा में राशि शामिल है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरीकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	68315	15640	791	-100
1.1 क्रय (+)	162479	15640	9169	7755
1.2 विक्रय (-)	94164	0	8378	7855
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	510516	114896	7515	156
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	68315	58127	40430	40330
(करोड़ ₹)	510516	432863	304980	305136
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	72751	13556	49606	49106

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2020-21	2020	2021	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरीकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	12118	0	0	0
1.2 विक्रय (-)	12118	0	0	0
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरीकी डॉलर)	690	0	0	0

सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	31 अक्टूबर 2021 की स्थिति		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	8489	4610	3879
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	14023	550	13473
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	42424	10670	31754
4. 1 वर्ष से अधिक	0	0	0
कुल (1+2+3+4)	64936	15830	49106

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2020-21	2020	2021					
			नव. 20	जून 18	जुला. 30	अग. 27	सित. 24	अक्टू. 22
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	182	266	59	254	2	152	461	7201
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुनर्वित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900	4900
3.2 बकाया	-	0	0	0	0	0	0	0
4. अन्य								
4.1 सीमा	75000	75000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	32387	33234	5578	23296	23296	25396	21696	24196
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	32569	33500	5637	23550	23298	25548	22157	31397

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा अर्थात एफिजम बैंक को 22 मई 2020 से पुनः शुरू कर दिया।

2. अन्य के लिए पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात भारिबैंक अधिनियम 1934 के नाबार्ड/ सिडबी/एनएचबी यू/एस 17 (4 एच), 17 अप्रैल 2020 से।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा भंडार की मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2020-21	2020	2021		
		अक्टू. 23	सितं. 24	अक्टू. 8	अक्टू. 22
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2751828	2619578	2814948	2830528	2825630
1.1 संचलन में नोट	2826851	2688064	2897815	2914133	2917700
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	26170	25738	26550	26550	26550
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101935	94967	110159	110898	119363
2 जनता की जमाराशियां	2042471	1666403	2005135	1966964	2009808
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1995120	1625686	1958235	1919227	1962643
2.2 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	40717	46900	47738	47165
3 एम₁ (1 + 2)	4794299	4285981	4820083	4797492	4835438
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	170025	162613	170025	170025	170025
5 एम₂ (3 + 4)	4964324	4448594	4990108	4967517	5005463
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	14050278	13517758	14577217	14771380	14688688
7 एम₃ (3 + 6)	18844578	17803739	19397300	19568872	19524126
8 कुल डाकघर जमाराशियां	509544	476456	509544	509544	509544
9 एम₄ (7 + 8)	19354122	18280195	19906844	20078416	20033670

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
			अक्टू. 23	सितं. 24	अक्टू. 8
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5587218	6077160	6127887	5977920
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1099686	905454	1118511	1138634	1043103
1.1.1 सरकार पर दावे	1337300	1248802	1585465	1580145	1561612
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1333917	1242339	1577489	1570345	1556811
1.1.1.2 राज्य सरकारें	3383	6463	7976	9800	4802
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमा राशियां	237615	343348	466954	441511	518509
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	237572	343305	466912	441469	518467
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	43	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	4750689	4681764	4958649	4989253	4934817
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11668466	10999619	11666564	11722628	11750103
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	8709	14792	5796	4434	1980
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11659757	10984827	11660768	11718195	11748123
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10949509	10338868	10956817	11014967	11044619
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	694758	636209	686008	685555	685756
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	15490	9750	17943	17673	17747
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	4578846	4418671	4895023	4967794	4973808
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	4199400	4120941	4551673	4624443	4630458
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	4199637	4121184	4551917	4624684	4630698
3.1.2 विदेशी देयताएं	237	243	244	241	241
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	379446	297731	343350	343350	343350
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26481	27293	27293	27293
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	3280021	3228251	3268740	3276729	3204998
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1356660	1412121	1315185	1374052	1373122
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1923362	1816130	1953555	1902677	1831876
एम₃ (1+2+3+4-5)	18844578	17803739	19397300	19568872	19524126

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020		2021	
		अक्टू. 23	सितं. 24	अक्टू. 8	अक्टू. 22
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4794299	4285981	4820032	4797441	4835387
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	11048277	10294913	11314819	11378428	11379500
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	18936051	17894502	19498790	19675258	19634893
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2751828	2619578	2814964	2830544	2825645
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	15892848	14978869	16391028	16543575	16505050
1.2.1 मांग जमाराशियां	1995121	1625686	1958168	1919160	1962576
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13897727	13353183	14432860	14624416	14542473
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	6253977	6008932	6494787	6580987	6544113
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	180512	59966	59564	57773
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7643750	7344251	7938073	8043429	7998360
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	40717	46900	47738	47165
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	244025	255339	245898	253401	257033
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	18518950	17549225	18723508	18835366	18725052
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	5850374	5587218	6076808	6127535	5977569
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	1099686	905454	1118511	1138634	1043103
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	4750689	4681764	4958298	4988901	4934465
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	12668575	11962007	12646700	12707831	12747484
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	34134	38919	27626	26336	23882
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	12634441	11923088	12619074	12681495	12723602
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	951313	926628	949934	956210	968828
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26481	27293	27293	27293
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4438202	4222595	4798128	4857490	4858484
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4120941	4551673	4624443	4630458
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	238802	101655	246455	233047	228026
2.4 पूंजी खाता	2775245	2862261	2941756	3025969	3047506
2.5 अन्य मदें (निवल)	1272767	1041538	1108382	1018922	928429

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2020-21	2020	2021		
		अक्टू.	अग.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	18936051	17894502	19420610	19498790	19634893
2 डाकघर जमाराशियां	509544	476456	509544	509544	509544
3 एल₁ (1 + 2)	19445595	18370958	19930154	20008334	20144437
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	33179	35341	25923	27371	26662
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2645	3114	4244	4244	3627
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	25550	28700	16775	18175	18175
4.3 सावधि जमाराशियां	4984	3528	4905	4952	4860
5 एल₂ (3 + 4)	19478774	18406300	19956077	20035705	20171099
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	19510679	20067610	..

टिप्पणी : संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		अक्टू. 23	सितं. 24	अक्टू. 8	अक्टू. 22
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2714545	2925107	2941426	2944993
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	470552	687375	685590	685574
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	651748	437010	638826	637545	638589
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	40717	46900	47738	47165
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3599981	3225814	3659382	3674754	3677732
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	730328	490513	395602	397070	393104
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	1099686	905454	1118511	1138634	1043103
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1096345	899034	1110577	1128877	1038344
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1333174	1241461	1576829	1569722	1556230
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1333174	1241461	1576829	1569722	1556230
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	743	878	659	623	581
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	237572	343305	466912	441469	518467
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	3340	6420	7934	9758	4759
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-403492	-453860	-750535	-767901	-673881
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-378066	-429733	-728706	-745999	-651979
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	34134	38919	27626	26336	23882
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	25426	24127	21830	21902	21902
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26481	27293	27293	27293
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4120941	4551673	4624443	4630458
2.3.1 सोना	247723	271325	275988	285046	287854
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3951694	3849633	4275703	4339415	4342621
2.4 पूंजी खाता	1173033	1251601	1205606	1277469	1290235
2.5 अन्य मदें (निवल)	183626	160520	109579	96583	82887

सं. 11: रिज़र्व बैंक - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	मार्च 31 /माह के अंतिम शुक्रवारों/शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2020	2021					
		अक्टू. 30	सितं. 24	अक्टू. 1	अक्टू. 8	अक्टू. 15	अक्टू. 22	अक्टू. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3599981	3244482	3659382	3657522	3674754	3719171	3677732	3703451
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	2853763	2715266	2925107	2917557	2941426	2952540	2944993	2945130
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	698867	488063	687375	691926	685590	719164	685574	710775
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	47351	41154	46900	48038	47738	47467	47165	47546
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1099686	944911	1118511	1207762	1138634	1141864	1043103	1108510
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-378066	-467693	-728706	-829352	-745999	-702591	-651979	-696020
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	8709	14795	5796	6317	4434	2137	1980	2137
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	4199400	4150295	4551673	4568103	4624443	4653681	4630458	4635086
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26913	26541	27293	27293	27293	27293	27293	27441
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1356660	1424366	1315185	1322601	1374052	1403213	1373122	1373703

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवारों/ माह के रिपोर्टिंग शुक्रवारों की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2020-21	2020	2021		
		अक्टू. 23	सितं. 24	अक्टू. 8	अक्टू. 22
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	14960961	14126937	15455336	15609647	15567552
1.1.1 मांग जमाराशियां	1861193	1505254	1823739	1784686	1827341
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	13099768	12621683	13631597	13824961	13740211
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5894896	5679757	6134219	6221233	6183095
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	78702	180512	59966	59564	57773
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	7204873	6941925	7497378	7603729	7557116
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	244025	255339	245898	253401	257033
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16378019	15708663	16570318	16661873	16650633
2.1.1 सरकार को ऋण	4461632	4438623	4662056	4690646	4637469
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11916387	11270040	11908262	11971228	12013164
2.1.2.1 बैंक ऋण	10949509	10338868	10956817	11014967	11044619
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10888255	10272209	10894475	10952559	10980922
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	23633	11896	9212	7931	7491
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	894	1610	1262	1083	1189
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	942351	917666	940972	947247	959866
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	238802	101655	246455	233047	228026
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	454866	330844	453232	446365	442218
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	152552	164575	143611	146219	145469
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	63512	64614	63166	67099	68722
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	1010202	951675	1466234	1482978	1397969
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	542693	437010	638826	637545	638589
2.3.2 उपलब्ध नकदी	90748	84932	98703	99434	107401
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-376761	-429733	-728706	-745999	-651979
2.4 पूंजी खाता	1578041	1586490	1711980	1724330	1733101
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	843995	793227	869793	790520	718942
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	593095	499287	520219	508679	501782
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	80681	68612	36145	25762	25116

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	26 मार्च 2021 की स्थिति	2020	2021		
		अक्टू. 23	सितं. 24	अक्टू. 8	अक्टू. 22
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	4462526	4440234	4663319	4691729	4638658
2 वाणिज्यिक पत्र	82584	88751	74182	75085	74600
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	9840	11363	10724	10516	10137
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	64035	71675	70152	70067	69330
3.3 अन्य	5210	5430	5135	5165	5098
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	121008	126857	114811	116491	117204
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	308904	306444	320875	327595	327885
4.3 अन्य	149325	146949	146047	147897	147953
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	31142	31082	47849	44879	51553
5.2 वित्तीय संस्थाएं	167130	128920	151015	149553	156107

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति									
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
	2020-21	2020		2021		2020-21	2020		2021	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.
1	2	3	4	5	6	7	8			
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	209	209	210	211	133	133	134	135		
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	259530	277233	232513	233346	254589	272101	227943	228850		
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	200585	210335	171131	171880	195866	205405	166914	167700		
1.2 बैंकों से उधार राशि	40886	50821	42447	40957	40880	50821	42383	40957		
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	18059	16077	18934	20509	17843	15875	18645	20193		
2 अन्य के प्रति देयताएं	1645782	15733984	16864747	17168151	16014145	15303052	16428231	16727910		
2.1 कुल जमाराशियां	15540152	14835260	16019297	16291050	15113512	14420000	15598948	15865855		
2.1.1 मांग	1899343	1606832	1862818	1945841	1861193	1571374	1823739	1905459		
2.1.2 मीयादी	13640809	13228427	14156479	14345208	13252320	12848625	13775208	13960396		
2.2 उधार	248271	266583	251073	262440	244025	262285	245898	258114		
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	669359	632141	594377	614661	656607	620767	583385	603942		
3 रिजर्व बैंक से उधार	90275	115757	92417	93597	90275	115757	92382	93597		
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.2 अन्य	90275	115757	92417	93597	90275	115757	92382	93597		
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	650745	557017	756401	790076	633440	541682	737529	769740		
4.1 उपलब्ध नकदी	92793	89874	100793	109257	90748	87683	98703	106425		
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	557951	467143	655608	680819	542693	453999	638826	663314		
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	265729	276923	254797	268578	197541	216919	201009	214170		
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	179430	189036	180057	186501	143294	155579	144591	151000		
5.1.1 चालू खाते में	16796	21643	21816	19183	14226	19438	19142	16783		
5.1.2 अन्य खातों में	162634	167393	158241	167318	129068	136141	125448	134217		
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	36716	29193	22154	27610	10654	7747	7062	11960		
5.3 बैंकों को अग्रिम	19908	22005	24660	24344	16764	21494	24278	23963		
5.4 अन्य आस्तियां	29675	36689	27926	30123	26829	32099	25078	27247		
6 निवेश	4598924	4597987	4804642	4809006	4462526	4468088	4663319	4666403		
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	4591896	4590080	4797221	4801633	4461632	4466431	4662056	4664994		
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7029	7907	7421	7372	894	1656	1262	1409		
7 बैंक ऋण	11297014	10721829	11295015	11449352	10949509	10387948	10956817	11105586		
7क खाद्यान्न ऋण	91653	100684	98160	103290	61254	70281	62342	67472		
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	11081668	10548573	11091164	11231091	10736491	10217564	10754999	10889324		
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	30896	24977	31826	33167	30531	23826	31812	33151		
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	128831	102181	120033	131334	127883	101193	118694	130030		
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20762	17127	20016	19863	20394	16877	19844	19673		
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	34857	28971	31976	33898	34210	28488	31467	33408		

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 26, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			अक्टू. 23	सितं. 24		
	1	2	3	4	2021-22	2021
				%	%	
I. सकल बैंक ऋण (II+III)	10951561	10338853	10956792	11046293	0.9	6.8
II. खाद्यान्न ऋण	61254	66659	62342	63697	4.0	-4.4
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	10890307	10272194	10894450	10982596	0.8	6.9
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1271047	1220013	1321325	1344042	5.7	10.2
2. उद्योग	2895786	2741118	2829547	2854571	-1.4	4.1
2.1 सूक्ष्म और लघु ¹	383854	361389	395432	404316	5.3	11.9
2.2 मझौले	136054	121053	175081	179905	32.2	48.6
2.3 बड़े	2375878	2258675	2259034	2270350	-4.4	0.5
3. सेवाएं	2647362	2531104	2571563	2603938	-1.6	2.9
3.1 परिवहन परिचालक	133953	127794	131206	131133	-2.1	2.6
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	19183	17575	18621	19455	1.4	10.7
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	48019	48378	48854	48687	1.4	0.6
3.4 शिपिंग	7188	5334	7384	7203	0.2	35.0
3.5 नौवहन	25643	25228	27876	27095	5.7	7.4
3.6 पेशेवर सेवाएं	105253	109041	99459	100843	-4.2	-7.5
3.7 व्यापार	590377	555878	576621	595470	0.9	7.1
3.7.1 थोक व्यापार	309611	269719	291589	307176	-0.8	13.9
3.7.2 खुदरा व्यापार	280766	286159	285033	288293	2.7	0.7
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	264246	254943	255778	253582	-4.0	-0.5
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	937949	871122	876825	883614	-5.8	1.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	215189	185434	212148	211107	-1.9	13.8
3.9.2 सरकारी वित्तीय संस्थाएं (पीएफआई)	78442	52243	79674	84036	7.1	60.9
3.10 अन्य सेवाएं ³	515550	515812	528938	536856	4.1	4.1
4. व्यक्तिगत ऋण	2845527	2645896	2918538	2955599	3.9	11.7
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	8810	8055	10904	11628	32.0	44.4
4.2 आवास	1458358	1370010	1478451	1485234	1.8	8.4
4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	62975	55876	63690	63734	1.2	14.1
4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	4419	5967	4481	4608	4.3	-22.8
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	116537	110207	115641	123312	5.8	11.9
4.6 शिक्षा	63968	65609	63437	63601	-0.6	-3.1
4.7 वाहन ऋण	267352	251557	270378	272610	2.0	8.4
4.8 सोने के आभूषण पर ऋण	60724	43907	63770	65361	7.6	48.9
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	802385	734706	847788	865510	7.9	17.8
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)						
5.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां ⁴	1235082	1176274	1261764	1281929	3.8	9.0
5.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1113243	1126388	1100816	1120901	0.7	-0.5
5.3 मध्यम उद्यम ⁶	207615	179252	219344	223621	7.7	24.8
5.4 आवास	468659	462137	446129	445739	-4.9	-3.5
5.5 शिक्षा ऋण	48201	51789	47201	47260	-2.0	-8.7
5.6 नवीकरणीय ऊर्जा	1171	1194	1423	1372	17.2	14.9
5.7 सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर	2352	1057	2323	2336	-0.6	121.1
5.8 निर्यात ऋण ⁷	19028	15347	21444	18931	-0.5	23.4
5.9 अन्य	9169	10820	16595	17063	86.1	57.7
5.10 नेट पीएसएलसी- एसएफ/एमएफ सहित कमजोर वर्ग	813263	789819	844833	865136	6.4	9.5

टिप्पणी 1: डाटा अनंतिम हैं। सकल बैंक ऋण और गैर-खाद्य ऋण का डाटा धारा -42 रिटर्न पर आधारित है, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को (एससीबी) शामिल किया गया है, जब कि क्षेत्रवार गैर-खाद्य ऋण डाटा क्षेत्र-वार पर और उद्योग-वार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न, जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कुल गैर खाद्य ऋण के लगभग 90 प्रतिशत के चुनिंदा बैंकों को समाविष्ट किया गया है। टिप्पणी 2: जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

1. सूक्ष्म और लघु में विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी के अंतर्गत एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं (एमएफआई), स्वर्ण ऋण से जुड़ी एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. अन्य सेवाओं के अंतर्गत म्यूचुअल फंड, एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग व वित्त तथा अन्य सेवाएं जो सेवाओं के अंतर्गत अन्यत्र नहीं दर्शाए गए हैं।
4. कृषि और उससे सम्बद्ध कार्यकलापों के अंतर्गत प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल है।
5. सूक्ष्म और लघु उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण और पीएसएलसी भी शामिल हैं।
6. मध्यम उद्यमों में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के अंतर्गत मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।
7. प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्रों के अंतर्गत निर्यात ऋण विदेशी बैंकों से संबंधित हैं।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	26 मार्च, 2021	2020	2021		वित्तीय वर्ष में अब तक 2021-22	वर्ष-दर-वर्ष 2021
		अक्टू. 23	सितं. 24	अक्टू. 22		
	1	2	3	4	%	%
1 उद्योग (2.1 से 2.19)	2895786	2741118	2829547	2854571	-1.4	4.1
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	46052	42697	48829	49758	8.0	16.5
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	153286	135624	145334	144413	-5.8	6.5
1.2.1 चीनी	25519	19837	18461	17636	-30.9	-11.1
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	18972	16666	17891	17709	-6.7	6.3
1.2.3 चाय	4273	4455	4812	5061	18.4	13.6
1.2.4 अन्य	104523	94665	104171	104007	-0.5	9.9
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	15966	15062	14994	15136	-5.2	0.5
1.4 वस्त्र	200487	186300	198445	199359	-0.6	7.0
1.4.1 सूती वस्त्र	90546	83391	83868	83975	-7.3	0.7
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2724	2406	2650	2734	0.4	13.7
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	38861	34991	41943	42009	8.1	20.1
1.4.4 अन्य वस्त्र	68356	65512	69984	70641	3.3	7.8
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	10461	10895	10416	10537	0.7	-3.3
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	13186	12718	13470	13498	2.4	6.1
1.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	35466	33529	36349	36839	3.9	9.9
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक इंधन	66909	60069	68024	67918	1.5	13.1
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	192323	173116	182178	185374	-3.6	7.1
1.9.1 उर्वरक	32237	36261	27117	27348	-15.2	-24.6
1.9.2 औषधि और दवाइयाँ	51723	49501	50247	51487	-0.5	4.0
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	45621	34622	39324	40000	-12.3	15.5
1.9.4 अन्य	62742	52732	65490	66538	6.1	26.2
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	54308	49977	59773	61881	13.9	23.8
1.11 कांच और कांच के सामान	6319	6784	5918	5715	-9.6	-15.8
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	54194	59273	47393	46511	-14.2	-21.5
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	328867	334958	285726	280263	-14.8	-16.3
1.13.1 लोहा और स्टील	232934	243873	193685	187819	-19.4	-23.0
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	95933	91085	92041	92443	-3.6	1.5
1.14 सभी अभियांत्रिकी	147545	138511	147744	147637	0.1	6.6
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	33871	29572	34594	36495	7.7	23.4
1.14.2 अन्य	113674	108938	113150	111142	-2.2	2.0
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	83188	88224	85700	82822	-0.4	-6.1
1.16 रत्न और आभूषण	62983	64231	69598	70162	11.4	9.2
1.17 निर्माण	94565	101923	95699	95759	1.3	-6.0
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1092217	1018034	1086038	1108932	1.5	8.9
1.18.1 पावर	567584	548740	570403	582453	2.6	6.1
1.18.2 दूरसंचार	112120	106857	111333	111419	-0.6	4.3
1.18.3 सड़क	237061	197326	243541	243712	2.8	23.5
1.18.4 हवाई अड्डा	7327	5298	7541	7592	3.6	43.3
1.18.5 बंदरगाह	7363	8886	8930	7604	3.3	-14.4
1.18.6 रेलवे	11260	12945	12901	12677	12.6	-2.1
1.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	149502	137983	131388	143475	-4.0	4.0
1.19 अन्य उद्योग	237464	209193	227919	232056	-2.3	10.9

टिप्पणी : जनवरी 2021 से, क्षेत्रीय ऋण डेटा संशोधित प्रारूप पर आधारित हैं, जिसके कारण पहले प्रकाशित कुछ मौजूदा घटकों के मान और विकास दर में कुछ बदलाव हुए हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2020-21	2020	2021						
		सितं. 25	जुला. 02	जुला. 16	जुला. 30	अग. 13	अग. 27	सितं. 10	सितं. 24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	33	33	33	33	33	33	33
1 कुल जमा राशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	125859.6	126531.5	127404.4	127039.8	126626.5	125488.9	125501.3	125705.2	125238.2
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	23736.9	22560.3	27586.5	27279.7	27514.2	27669.6	27501.5	30915.2	26961.0
2.1.1 जमा राशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	4896.9	4189.6	5053.9	5397.3	5196.0	5399.0	5419.8	5686.7	5734.8
2.1.1.2 अन्य	13,899.4	13757.9	16367.1	16525.2	16070.2	15817.5	15695.3	15100.1	14619.8
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	229.9	819.8	849.8	1019.7	1069.6	1069.6	999.6	999.7
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	4940.6	4382.9	5345.6	4507.4	5228.2	5383.4	5316.8	9128.8	5606.6
2.2 मीयादी देयताएं	179957.5	172282.0	168077.2	169250.6	166914.3	165604.8	166716.0	167660.1	168977.8
2.2.1 जमा राशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	65333.7	56835.6	55274.4	56414.7	54660.1	54146.9	55115.2	55191.0	56505.0
2.2.1.2 अन्य	111960.2	112773.5	111037.3	110514.6	110556.3	109671.4	109806.0	110605.1	110618.4
2.2.2 बैंकों से उधार	630.0	673.0	908.0	908.0	908.0	908.0	908.0	911.0	911.0
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	2033.7	1999.9	857.6	1413.3	789.9	878.5	886.8	953.0	943.3
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	35.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	35.0	35.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	63559.8	58161.7	53897.7	55245.5	54718.0	56575.4	56497.3	55045.9	54926.2
4.1 मांग	15691.8	14065.7	10601.1	10615.3	10682.3	11558.3	11967.8	12202.9	12031.5
4.2 मीयादी	47868.0	44095.9	43296.6	44630.2	44035.8	45017.1	44529.5	42843.0	42894.6
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	8151.1	7010.2	8861.6	9149.7	9574.3	9175.0	8711.2	13259.6	8940.2
5.1 उपलब्ध नकदी	570.3	564.3	631.5	693.2	610.6	610.3	672.7	637.0	640.7
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	7580.8	6445.9	8230.0	8456.5	8963.6	8564.7	8038.4	12622.6	8299.5
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1148.1	1046.1	1383.6	1433.5	1321.3	1381.1	1310.9	1346.7	1223.7
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	64455.2	59312.3	68465.6	68048.9	67609.8	68266.4	69149.6	69633.6	70603.5
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	28835.7	26369.3	19278.0	21097.6	19409.0	19377.0	20512.8	18893.8	20170.1
9 बैंक ऋण (10.1+11)	114631.6	112190.0	108831.5	108426.4	109816.4	108302.6	107334.4	107521.7	106670.5
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	114612.1	112171.2	108827.4	108422.2	109812.3	108298.5	107314.7	107502.0	106650.9
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	89429.1	79397.4	86303.3	87316.9	85942.6	88700.2	88554.7	89065.7	88508.1
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	19.5	18.8	4.1	4.2	4.1	4.2	19.7	19.7	19.6

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2020-21			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अक्टू.'20	सितं.'21	अक्टू.'21(अ)	अक्टू.'20	सितं.'21	अक्टू.'21(अ)	अक्टू.'20	सितं.'21	अक्टू.'21(अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	156.7	161.1	158.3	163.4	162.1	165.5	167.0	167.3	171.5	164.7	164.0	167.7
1.1 अनाज और उत्पाद	145.4	149.9	146.8	145.4	145.4	146.1	149.7	149.3	150.1	146.8	146.6	147.4
1.2 मांस और मछली	185.2	192.4	187.7	188.6	202.1	202.6	195.5	207.4	208.4	191.0	204.0	204.6
1.3 अंडा	160.3	164.8	162.0	171.6	172.0	170.1	176.9	174.1	173.0	173.6	172.8	171.2
1.4 दूध और उत्पाद	154.1	154.4	154.2	153.8	158.0	158.4	153.9	159.1	159.2	153.8	158.4	158.7
1.5 तेल और चर्बी	148.2	139.9	145.2	145.4	195.5	198.7	138.0	175.0	176.5	142.7	188.0	190.5
1.6 फल	146.9	153.4	149.9	146.5	152.7	152.6	150.5	161.2	159.2	148.4	156.7	155.7
1.7 सब्जी	174.2	196.2	181.7	222.2	151.4	170.4	245.3	183.5	214.3	230.0	162.3	185.3
1.8 दाल और उत्पाद	154.4	156.0	154.9	155.9	163.9	165.3	158.7	164.5	165.3	156.8	164.1	165.3
1.9 चीनी और उत्पाद	114.4	117.0	115.3	114.9	119.3	121.6	117.2	120.4	122.5	115.7	119.7	121.9
1.10 मसाले	161.9	160.4	161.4	162.0	170.1	170.6	161.4	166.2	166.7	161.8	168.8	169.3
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	149.8	141.3	146.3	150.0	168.3	168.8	141.5	154.8	155.4	146.5	162.7	163.2
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	163.2	165.5	164.3	162.7	172.8	173.6	165.1	175.1	175.9	163.8	173.9	174.7
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	181.8	188.7	183.6	183.4	190.5	191.1	188.8	196.5	197.0	184.8	192.1	192.7
3 कपड़ा और जूते	155.6	149.7	153.3	155.5	167.1	168.3	148.8	157.4	158.3	152.8	163.3	164.3
3.1 कपड़ा	156.4	152.0	154.7	156.3	167.7	168.9	151.1	159.8	160.8	154.3	164.6	165.7
3.2 जूते	151.1	137.2	145.3	151.0	163.6	164.8	136.4	143.6	144.4	144.9	155.3	156.3
4 आवास	-	157.2	157.2	-	-	-	158.0	162.1	163.6	158.0	162.1	163.6
5 ईंधन और लाइट	149.1	140.9	146.0	147.5	163.7	165.5	137.3	160.8	162.1	143.6	162.6	164.2
6 विविध	153.9	146.1	150.2	154.5	163.8	164.7	146.6	156.0	157.0	150.7	160.0	161.0
6.1 घरेलू सामान और सेवा	152.9	145.2	149.3	152.8	161.3	162.0	145.1	153.3	154.4	149.2	157.5	158.4
6.2 स्वास्थ्य	160.3	151.3	156.9	160.4	171.9	172.5	152.0	162.8	163.5	157.2	168.4	169.1
6.3 परिवहन और संचार	144.9	135.0	139.7	146.1	157.8	159.5	135.2	150.5	152.2	140.4	154.0	155.7
6.4 मनोरंजन	154.0	144.3	148.5	153.6	162.7	163.2	144.4	153.9	155.1	148.4	157.7	158.6
6.5 शिक्षा	162.5	156.2	158.9	161.6	168.5	169.0	156.4	160.3	160.3	158.6	163.7	163.9
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	153.7	155.8	154.5	156.2	160.2	161.1	157.9	159.6	160.3	156.9	160.0	160.8
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	156.1	154.4	155.3	159.8	164.0	166.3	156.7	162.3	164.6	158.4	163.2	165.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अनंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2020-21	2021		
				अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	-	119.5	123.3	124.9
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1034	1052	1067	1081
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1040	1057	1076	1090

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2020-21	2020		2021	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.
	1	2	3	4	5
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	48723	50698	46584	47219	47219
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	59283	61320	61892	62890	62890

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				अक्टू.	अग.	सितं. (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	123.4	123.6	136.2	136.0	139.1
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	145.7	151.8	155.4	154.9	159.7
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	160.7	171.5	161.7	160.5	168.6
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.3	158.1	161.1	162.9	163.9
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	179.2	223.9	171.5	164.1	200.8
1.1.1.3 दूध	4.440	153.4	154.6	157.0	156.8	157.2
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	151.2	151.7	158.7	158.5	154.7
1.1.1.5 मसाले	0.529	149.5	152.9	151.5	155.3	155.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	162.0	167.5	163.4	163.9	164.8
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	130.5	129.8	161.5	161.1	153.7
1.1.2.1 फाइबर	0.839	119.8	114.5	147.1	147.1	156.0
1.1.2.2 तिलहन	1.115	161.7	158.0	239.6	235.0	199.7
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	109.0	109.8	118.2	119.8	119.8
1.1.2.4 फूल	0.204	210.0	231.7	210.5	211.2	217.9
1.1.3 खनिज	0.833	164.9	153.3	179.6	187.4	179.6
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	159.8	146.8	170.5	182.0	170.5
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.1	176.1	211.7	206.6	211.5
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	70.4	63.8	97.1	97.0	106.2
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	94.0	90.9	117.9	114.7	124.7
1.2.1 कोल	2.138	126.6	126.4	127.7	127.7	128.9
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	141.8	141.7	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.3	119.0	119.8	119.8	119.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	130.9	131.1	138.1	138.1	166.0
1.2.2 खनिज तेल	7.950	79.2	75.8	119.7	117.6	126.7
1.2.3 बिजली	3.064	109.6	105.3	106.4	98.2	116.7
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	121.5	120.4	133.2	133.8	134.9
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	141.4	140.5	157.6	158.5	158.4
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.2	137.2	142.4	142.3	142.4
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	139.0	135.1	140.2	139.3	144.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	120.2	120.4	124.3	122.3	122.1
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	143.5	140.6	188.7	187.9	186.4
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	146.9	144.7	148.3	148.6	149.0
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	143.5	142.8	144.0	145.8	145.8
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	115.9	107.8	129.1	128.9	130.2
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	138.1	138.1	143.6	144.1	145.3
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.4	118.6	120.9	126.3	127.4
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	128.0	127.8	128.4	128.7	129.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.3	131.3	132.2	138.4	139.0
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	166.5	183.2	168.1	168.6	168.5
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	147.0	145.8	154.8	156.2	155.4
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	132.2	130.0	134.9	135.6	135.4
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	142.9	140.6	154.3	155.1	154.6
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	170.5	169.9	209.0	208.6	207.4
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	124.5	123.7	127.2	126.9	127.3
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	120.2	120.1	123.8	123.4	123.7
1.3.2.2 माल्ट लिंकर और माल्ट	0.225	126.5	124.4	130.2	130.2	131.3
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	129.4	128.5	129.9	129.2	129.4
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	157.2	157.6	160.6	161.3	162.6
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	157.2	157.6	160.6	161.3	162.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				अक्टू.	अग.	सितं. (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.6	114.8	132.6	132.7	133.9
1.3.4.1 धागों की कलाई और वस्त्र तैयार करना	2.582	106.6	102.5	123.6	124.2	126.2
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	131.7	130.1	147.1	146.1	146.3
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	115.2	113.7	124.2	125.1	123.6
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	132.3	131.4	136.5	137.7	138.0
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	155.6	156.8	167.6	167.7	169.6
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.3	115.2	123.7	124.8	126.8
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.6	138.3	142.0	143.7	143.8
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	138.1	137.1	141.3	143.6	142.9
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	139.8	141.4	143.8	143.8	146.4
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	117.9	117.7	118.4	118.8	118.9
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	101.1	102.0	103.0	104.3	103.9
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	138.6	137.9	139.7	139.4	139.9
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.6	119.9	120.3	120.5	120.6
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	134.6	133.7	140.8	140.6	142.3
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	120.7	120.3	127.5	127.8	131.3
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.6	135.0	140.9	140.8	142.0
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगीरी	0.036	185.8	189.6	193.8	193.8	194.5
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	125.5	138.7	137.4	139.1
1.3.8 कागज और कागज के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.7	119.4	132.5	132.9	134.5
1.3.8.1 लुगदी, कागज और कागज बोर्ड	0.493	124.1	120.9	135.7	136.7	138.7
1.3.8.2 लहरदार कागज और पेपर बोर्ड और कागज के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	122.2	121.3	135.8	135.3	136.4
1.3.8.3 कागज की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	117.4	114.9	124.1	124.5	125.7
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	153.8	155.9	156.5	154.9	154.8
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	153.8	155.9	156.5	154.9	154.8
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	118.2	116.8	130.3	131.3	133.0
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	118.6	115.8	137.6	140.3	142.4
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.6	123.1	128.1	127.7	128.2
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	116.7	115.1	136.9	138.5	141.3
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	124.4	125.6	130.1	130.9	130.8
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.9	113.0	126.8	127.2	130.3
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	120.6	120.8	128.4	128.8	129.0
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	115.1	113.2	126.3	127.3	129.8
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	93.7	89.3	103.7	104.6	107.8
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	130.9	130.5	134.1	134.8	134.9
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	130.9	130.5	134.1	134.8	134.9
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	111.3	110.0	122.5	123.6	126.0
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.3	97.8	103.8	104.2	103.9
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.3	91.6	99.8	100.9	101.0
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	120.3	118.8	134.8	136.2	140.3
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	117.6	116.5	122.1	121.9	122.4
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	127.2	127.8	136.0	136.7	135.5
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	109.5	109.0	114.0	111.1	114.9
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	109.3	105.7	111.3	110.8	111.1
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	109.5	108.0	111.3	111.9	111.6
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	120.9	119.4	125.5	125.2	125.8

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				अक्टू.	अग.	सितं. (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेंट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	125.3	124.7	128.9	128.0	128.0
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	121.1	120.1	121.5	122.5	122.5
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	78.9	77.6	87.7	88.0	88.0
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	111.4	108.9	135.9	137.1	140.4
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	109.2	105.3	142.2	143.6	151.6
1.3.14.2 मेटेलिक आयर्न	0.653	113.3	111.2	142.9	145.2	151.2
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.8	96.0	116.9	116.8	118.9
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	112.0	108.0	132.9	133.6	137.8
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	117.2	115.6	156.4	156.1	159.2
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	108.3	102.7	128.7	129.6	134.8
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	108.7	106.1	135.9	138.2	139.2
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	127.9	123.4	151.6	153.5	155.5
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.3	111.5	134.6	137.4	140.0
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.1	108.9	118.8	118.9	119.2
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	145.7	143.4	155.8	157.8	157.2
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.9	114.6	130.6	130.6	130.9
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	114.1	112.3	124.1	123.6	123.6
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.8	125.4	157.2	157.3	157.6
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरस को छोड़कर	0.145	98.9	98.6	96.8	96.9	96.9
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.7	96.2	117.4	117.8	118.6
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	102.9	102.6	108.2	108.3	108.7
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	125.0	124.2	135.7	136.0	136.5
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	109.8	108.9	113.0	112.7	112.7
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	99.1	98.9	103.7	105.0	105.1
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	134.8	135.2	134.6	134.6	134.7
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	114.9	114.2	119.3	119.3	119.3
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.5	96.5	103.0	101.6	101.5
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	107.7	106.1	107.1	107.1	107.1
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	141.8	141.7	145.7	144.7	145.4
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	102.8	102.5	104.0	104.0	104.0
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	102.7	95.7	98.4	98.4	98.4
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	113.6	112.6	121.8	120.4	122.3
1.3.17.1 विद्युतमोर्टर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	113.2	111.6	119.5	116.4	119.8
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.1	119.3	120.7	121.5	122.3
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	98.1	97.2	101.0	99.4	100.4
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	115.9	114.5	138.8	139.4	140.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	110.7	113.8	113.7	114.1
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.7	118.6	127.7	128.4	129.1
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	109.5	109.0	114.5	112.9	113.0
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	114.0	114.2	119.6	120.3	120.5
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	106.3	105.7	119.7	119.4	120.6
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.4	120.4	121.0	120.8	120.8
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.6	111.0	114.9	114.8	114.9
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गैयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.8	113.3	117.3	118.0	117.5
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.2	81.4	75.1	75.3	75.0
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	113.4	114.0	119.5	120.4	123.3

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2020-21	2020	2021		
				अक्टू.	अग.	सितं. (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	128.7	130.6	134.7	134.6	131.6
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	121.6	121.2	127.0	128.6	129.3
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.4	108.1	115.3	115.3	116.0
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.7	75.3	78.4	78.1	78.1
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	128.0	128.4	129.0	132.7	133.0
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	121.9	121.6	122.9	124.5	124.8
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	128.7	129.5	134.1	135.2	134.7
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	65.2	65.4	66.2	66.5	66.6
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	117.8	117.6	121.8	122.5	122.4
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	119.4	119.6	121.5	122.7	122.4
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	116.1	115.4	122.1	122.3	122.5
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	126.2	126.7	131.0	131.4	131.7
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.9	158.9	158.9
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	105.0	104.7	104.9	104.9	104.5
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	124.7	125.6	130.1	130.7	131.1
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	130.3	128.6	136.4	137.3	137.3
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	128.5	127.7	132.6	134.2	136.0
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	133.2	132.5	149.0	148.5	150.7
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	133.2	132.5	149.0	148.5	150.7
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	132.4	135.9	133.3	135.1	137.9
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	130.5	134.3	131.2	133.0	136.0
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	173.7	166.4	183.4	189.2	190.5
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	132.0	131.9	138.7	138.8	141.1
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	142.4	140.7	151.5	151.0	149.9
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	167.4	168.1	171.3	172.9	172.9
2 खाद्य सूचकांक	24.378	153.4	159.9	160.1	159.8	164.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारंक	2019-20	2020-21	अप्रैल- सितंबर		सितंबर	
				2020-21	2021-22	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	129.0	118.1	101.9	125.8	124.1	127.9
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	109.6	101.0	85.2	104.2	87.6	95.1
1.2 विनिर्माण	77.63	129.6	117.2	99.6	124.8	126.5	129.9
1.3 बिजली	7.99	158.4	157.6	154.6	174.4	166.4	167.9
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	127.0	118.1	107.2	124.1	112.1	117.3
2.2 पूंजीगत माल	8.22	93.3	75.9	57.2	82.9	90.3	91.5
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	137.7	124.7	104.2	138.0	133.6	140.2
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	136.6	124.7	102.6	140.5	132.7	142.5
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	119.0	101.2	76.9	106.4	129.0	126.4
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.3	142.1	132.0	143.0	147.4	146.6

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(करोड़ ₹)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - अगस्त			
	2021-22 (बजट आकलन)	2021-22 (वास्तविक)	2020-21 (वास्तविक)	बजट आकलनों का प्रतिशत	
				2021-22	2020-21
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्ति	1788424	1259977	691903	70.5	34.2
1.1 कर राजस्व (निवल)	1545396	1053135	575697	68.1	35.2
1.2 करेतर राजस्व	243028	206842	116206	85.1	30.2
2 गैरेतर ऋण पूंजीगत प्राप्ति	188000	19722	16397	10.5	7.3
2.1 ऋण की वसूली	13000	10358	10218	79.7	68.3
2.2 अन्य प्राप्ति	175000	9364	6179	5.4	2.9
3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	1976424	1279699	708300	64.7	31.5
4 राजस्व व्यय	2929000	1573455	1464099	53.7	55.7
4.1 ब्याज भुगतान	809701	399737	333456	49.4	47.1
5 पूंजी व्यय	554236	253270	197355	45.7	47.9
6 कुल व्यय (4+5)	3483236	1826725	1661454	52.4	54.6
7 राजस्व घाटा (4-1)	1140576	313478	772196	27.5	126.8
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1506812	547026	953154	36.3	119.7
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	697111	147289	619698	21.1	703.1

स्रोत : भारत सरकार और केंद्रीय बजट 2021-22

सं. 24: खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2020-21		2021											
	2020		सितं. 24		अक्टू. 1		अक्टू. 8		अक्टू. 15		अक्टू. 22		अक्टू. 29	
	1	2	3	4	5	6	7	8						
1 91-दिवसीय														
1.1 बैंक	5676	2540	12894	16323	17737	12092	10507	11660						
1.2 प्राथमिक व्यापारी	16740	15647	13890	20166	21597	18516	27651	31896						
1.3 राज्य सरकारें	13347	70665	66717	68717	64717	69755	66865	68355						
1.4 अन्य	52802	128809	113596	99262	98724	108513	102057	98459						
2 182-दिवसीय														
2.1 बैंक	67473	152250	100171	95331	86076	80354	80391	81117						
2.2 प्राथमिक व्यापारी	30966	61725	62322	62046	60352	54863	52650	55234						
2.3 राज्य सरकारें	9436	4033	8377	8377	8377	7927	7717	7593						
2.4 अन्य	31800	101876	106158	107625	105633	106198	97684	83272						
3 364-दिवसीय														
3.1 बैंक	119024	135642	105842	107448	111024	110913	111412	114147						
3.2 प्राथमिक व्यापारी	154197	129471	101789	100599	100591	97078	96903	94931						
3.3 राज्य सरकारें	18510	15842	19416	19416	19176	19163	19263	19563						
3.4 अन्य	174501	119782	81683	85274	84266	90609	91150	93755						
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती														
4.1 बैंक														
4.2 प्राथमिक व्यापारी														
4.3 राज्य सरकारें	220351	116438	133145	100242	103954	98414	157140	178049						
4.4 अन्य	747	392	737	359	1140	871	785	1098						
कुल खजाना बिल														
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल को छोड़कर)#	694471	938281	792856	790583	778270	775981	764250	759982						

14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खजाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियाँ				स्वीकृत बोलियाँ				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या		कुल अंकित मूल्य		संख्या		कुल अंकित मूल्य				
		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी	प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खजाना बिल												
2021-22												
सितं. 29	9000	130	52506	4002	33	8998	4002	13000	99.15	3.4488		
अक्टू. 6	10000	123	41442	1005	49	9995	1005	11000	99.14	3.4777		
अक्टू. 13	10000	143	54277	7301	16	9999	7301	17300	99.16	3.3937		
अक्टू. 20	10000	91	36380	8200	25	10000	8200	18200	99.15	3.4496		
अक्टू. 27	10000	113	32893	8831	52	9999	8831	18831	99.12	3.5610		
182-दिवसीय खजाना बिल												
2021-22												
सितं. 29	4000	95	23665	0	13	4000	0	4000	98.25	3.5669		
अक्टू. 6	3000	64	11352	0	22	3000	0	3000	98.24	3.6033		
अक्टू. 13	3000	63	8889	0	22	3000	0	3000	98.22	3.6447		
अक्टू. 20	3000	40	7090	0	19	3000	0	3000	98.19	3.6996		
अक्टू. 27	3000	59	7159	0	37	3000	0	3000	98.13	3.8322		
364-दिवसीय खजाना बिल												
2021-22												
सितं. 29	4000	106	20290	0	43	4000	0	4000	96.34	3.8100		
अक्टू. 6	7000	150	30265	50	71	7000	50	7050	96.27	3.8872		
अक्टू. 13	7000	148	36808	0	39	7000	0	7000	96.26	3.8998		
अक्टू. 20	7000	130	26585	0	45	7000	0	7000	96.21	3.9490		
अक्टू. 27	7000	143	22795	300	49	7000	300	7300	96.13	4.0390		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1	2	2
अक्टूबर	1, 2021	1.95-3.45	3.22
अक्टूबर	4, 2021	1.95-3.40	3.20
अक्टूबर	5, 2021	1.95-3.40	3.19
अक्टूबर	6, 2021	1.95-3.40	3.19
अक्टूबर	7, 2021	1.95-3.40	3.17
अक्टूबर	8, 2021	1.95-3.45	3.28
अक्टूबर	11, 2021	1.95-3.40	3.27
अक्टूबर	12, 2021	1.95-3.45	3.18
अक्टूबर	13, 2021	1.95-3.45	3.25
अक्टूबर	14, 2021	1.95-3.50	3.29
अक्टूबर	16, 2021	2.25-3.45	2.82
अक्टूबर	18, 2021	1.95-3.60	3.28
अक्टूबर	20, 2021	2.00-3.45	3.32
अक्टूबर	21, 2021	2.00-3.45	3.32
अक्टूबर	22, 2021	2.00-3.60	3.33
अक्टूबर	25, 2021	2.00-3.50	3.31
अक्टूबर	26, 2021	2.00-3.65	3.33
अक्टूबर	27, 2021	2.00-3.50	3.28
अक्टूबर	28, 2021	2.00-3.50	3.24
अक्टूबर	29, 2021	2.00-3.55	3.22
अक्टूबर	30, 2021	2.70-3.45	3.27
नवंबर	1, 2021	2.00-3.55	3.30
नवंबर	2, 2021	2.00-3.50	3.33
नवंबर	3, 2021	2.00-3.65	3.41
नवंबर	6, 2021	2.60-4.00	3.37
नवंबर	8, 2021	2.00-3.45	3.30
नवंबर	9, 2021	2.00-3.50	3.24
नवंबर	10, 2021	2.00-3.50	3.19
नवंबर	11, 2021	2.00-3.50	3.20
नवंबर	12, 2021	2.00-3.50	3.21
नवंबर	15, 2021	2.00-3.40	3.19

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2020	2021			
	अक्टू. 23	सितं. 10	सितं. 24	अक्टू. 8	अक्टू. 22
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	74214.40	67144.54	60220.40	59201.66	57366.48
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	4634.88	6524.51	3229.92	1684.57	410.21
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.65-4.25	3.27-4.49	3.35-4.49	3.47-4.90	3.62-4.49

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2020	2021			
	अक्टू. 31	सितं. 15	सितं. 30	अक्टू. 15	अक्टू. 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	380112.20	401221.25	370982.10	399720.05	379278.30
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	40838.65	74402.55	59167.05	55664.10	56178.95
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	3.19-14.19	3.14-13.42	3.26-12.83	3.38-8.47	3.32-12.71

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(करोड़ ₹)

मद	2020-21	2020	2021					
		अक्टू. 30	सितं. 24	अक्टू. 1	अक्टू. 8	अक्टू. 15	अक्टू. 22	अक्टू. 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17461	10675	13382	17009	15018	11609	16775	14570
2 नोटिस मुद्रा	2604	4481	623	450	818	4533	940	2904
3 मीयादी मुद्रा	757	545	349	230	240	163	390	373
4 त्रिपक्षीय रिपो	421118	397522	510865	667063	700588	684968	571157	774300
5 बाजार रिपो	337341	350328	313962	369104	409709	414267	322638	388328
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	2990	5545	3968	1560	3660	2333	3654	5351
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	56477	77799	92814	74979	72191	76434	92929
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	62490	91127	99739	83826	63584	57532	61211	56616
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5080	4932	6267	6246	5896	3947	3862	5087
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	4970	5243	5224	6645	5228	2861	3901	3487
10.2 182-दिवसीय	4870	4644	2361	5217	2975	3350	1694	2329
10.3 364-दिवसीय	4010	2662	1897	2820	3702	6166	2653	1685
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	1490							
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	82910	108608	115488	104754	81385	73856	73320	69203
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	-	429	6353	6130	74	5	164	38

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2020-21		2020-21 (अप्रै-अक्टू.)		2021-22 (अप्रै-अक्टू.)*		अक्टू. 2020		अक्टू. 2021*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	74	102062	39	80668	76	54363	15	3837	18	3833
1ए प्रीमियम	73	97648	39	77315	72	53295	15	3747	17	3638
1.1 पब्लिक	53	38004	25	20131	61	52783	12	3284	13	3047
1.1.1 प्रीमियम	53	34848	25	17540	60	52013	12	3224	12	2996
1.2 राइट्स	21	64059	14	60536	15	1580	3	553	5	786
1.2.1 प्रीमियम	20	62800	14	59775	12	1281	3	524	5	643
2 अधिमान शेयर	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 बांड और डिबेंचर	16	5806	9	3729	17	8520	3	2697	3	1437
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	16	5806	9	3729	17	8520	3	2697	3	1437
3.1.1 पब्लिक	16	5806	9	3729	17	8520	3	2697	3	1437
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 कुल (1+2+3)	90	107868	48	84396	93	62883	18	6534	21	5270
4.1 पब्लिक	69	43809	34	23860	78	61303	15	5981	16	4484
4.2 राइट्स	21	64059	14	60536	15	1580	3	553	5	786

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।

2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कालम के आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2020-21	2020		2021			
			अक्टू.	जून	जुला.	अग.	सितं.	अक्टू.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2159043	183061	238999	264814	247965	248849	267056
	मिलियन अमरीकी डॉलर	291808	24920	32491	35533	33425	33828	35648
1.1 तेल	करोड ₹	190896	11513	29070	43658	34892	38356	399486
	मिलियन अमरीकी डॉलर	25804	1567	3952	5858	4703	5214	5333
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1968147	171547	209930	221156	213073	210493	-132430
	मिलियन अमरीकी डॉलर	266004	23353	28539	29675	28722	28614	30315
2 आयात	करोड ₹	2915958	250300	309387	343102	334464	410742	414832
	मिलियन अमरीकी डॉलर	394436	34074	42060	46037	45085	55835	55374
2.1 तेल	करोड ₹	611353	44077	78299	93640	71805	125069	108096
	मिलियन अमरीकी डॉलर	82684	6000	10644	12565	9679	17002	14429
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2304605	206223	231089	249462	262659	285673	306736
	मिलियन अमरीकी डॉलर	311752	28074	31416	33473	35406	38834	40944
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-756914	-67239	-70388	-78288	-86499	-161893	-147776
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-102627	-9153	-9569	-10505	-11660	-22007	-19726
3.1 तेल	करोड ₹	-420457	-32564	-49229	-49982	-36913	-86713	291390
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-56880	-4433	-6693	-6707	-4976	-11787	-9097
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-336458	-34676	-21159	-28306	-49587	-75180	-439166
	मिलियन अमरीकी डॉलर	-45748	-4720	-2876	-3798	-6684	-10220	-10629

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2020		2021				
		नव. 27	अक्टू. 22	अक्टू. 29	नव. 5	नव. 12	नव. 19	नव. 26
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	4257257	4793167	4807657	4772044	4765159	4757480	4776057
	मिलियन अमरीकी डॉलर	574821	640100	642019	640874	640112	640401	637687
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	3951006	4321443	4331763	4300702	4284065	4276977	4304119
	मिलियन अमरीकी डॉलर	533455	577098	578462	577581	575487	575712	574664
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	260651	287854	292141	288746	299551	300065	290793
	मिलियन अमरीकी डॉलर	35192	38441	39012	38778	40239	40391	38825
	मात्रा (मैट्रिक टन)	672.92	746.63	747.57	748.5	748.5	748.5	750.37
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1049	13657	13657	13657	13657	13657	13657
	करोड ₹	11069	144680	144553	143612	142812	141970	142576
	मिलियन अमरीकी डॉलर	1494	19321	19304	19287	19184	19110	19036
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	34532	39189	39201	38984	38732	38469	38569
	मिलियन अमरीकी डॉलर	4679	5240	5242	5228	5201	5188	5162

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से हैं।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2020-21	2020	2021		2020-21	2021-22
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	अप्रै.-अक्टू.	अप्रै.-अक्टू.
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	141895	137965	141555	141305	5995	3281
1.1 एफसीएनआर (बी)	20473	21958	18950	18802	-2286	-1671
1.2 एनआर (ई) आरए	102579	98992	102744	102485	7434	3167
1.3 एनआरओ	18842	17015	19861	20018	847	1785

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020-21	2021-22	2020	2021	
		अप्रै.-अक्टू.	अप्रै.-अक्टू.	अक्टू.	सित्त.	अक्टू.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	43,955	27,868	23,814	3,971	2,893	1,933
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	54,927	34,023	33,721	4,840	4,451	3,259
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	81,973	48,519	48,432	7,151	6,543	5,585
1.1.1.1.1 इक्विटी	61,088	36,148	35,686	5,456	4,623	3,845
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	948	217	1,437	45	46	1,105
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	51,597	31,244	23,708	4,357	4,062	2,076
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7,091	3,873	9,728	929	397	539
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1,452	814	814	126	118	126
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	16,935	9,489	9,836	1,464	1,372	1,464
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	3,950	2,882	2,910	230	548	276
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	27,046	14,496	14,711	2,311	2,092	2,326
1.1.1.2.1 इक्विटी	26,983	14,476	14,364	2,306	2,057	2,286
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	63	20	347	4	34	40
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	10,972	6,155	9,907	869	1,558	1,326
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	5,583	3,055	4,930	618	792	523
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3,013	1,758	1,764	251	251	251
1.1.2.3 अन्य पूंजी	6,688	2,955	5,169	494	911	803
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	4,313	1,612	1,956	493	396	251
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	36,137	9,376	1,787	1,737	2,393	-2,663
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	38,725	10,732	3,194	1,899	2,976	-2,128
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	2,589	1,356	1,407	162	583	535
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	80,092	37,244	25,601	5,708	5,286	-730

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	2020-21	2020	2021		
		अक्टू.	अग.	सित्त.	अक्टू.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	12684.40	938.37	1965.35	1970.01	1564.90
1.1 जमाराशियां	680.37	23.34	58.04	60.09	46.58
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	62.75	3.85	7.39	9.36	7.43
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	471.80	22.80	46.31	73.55	55.20
1.4 उपहार	1586.24	108.89	191.05	210.23	172.06
1.5 दान	12.59	1.29	0.75	0.85	0.83
1.6 यात्रा	3239.67	272.98	574.22	580.35	464.59
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2680.10	162.64	284.83	295.25	221.56
1.8 चिकित्सा उपचार	29.75	3.66	2.93	3.32	3.11
1.9 विदेश में शिक्षा	3836.12	333.45	780.26	718.32	579.84
1.10 अन्य	85.03	5.47	19.60	18.71	13.71

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

मद	2019-20	2020-21	2020	2021	
			नवंबर	अक्टूबर	नवंबर
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा बास्केट (आधार: 2015-16=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	98.00	93.92	93.01	93.60	94.04
1.2 रीर	103.20	103.46	104.84	105.27	106.24
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	97.38	93.59	92.98	93.15	93.99
2.2 रीर	102.88	102.96	104.63	104.37	105.74
6- मुद्रा बास्केट (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16=100					
1.1 नीर	94.92	88.47	87.42	86.59	87.60
1.2 रीर	103.62	101.88	103.35	102.79	104.61
2 आधार : 2018-19 =100					
2.1 नीर	100.78	93.93	92.81	91.93	93.00
2.2 रीर	103.32	101.59	103.06	102.49	104.31

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरीकी मिलियन डॉलर में)

मद	2020-21	2020	2021	2021
		अक्टू-20	सित्त.-21	अक्टू.-21
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1063	76	86	76
1.2 राशि	26799	1733	2595	1339
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	13	1	4	0
2.2 राशि	8456	300	1428	0
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1076	77	90	76
3.2 राशि	35255	2033	4023	1339
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.03	3.62	7.80	5.04
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.93	1.25	2.91	1.14
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-13.00	0.00-9.00	0.00-10.00	0.00-11.00
उधारकर्ता श्रेणियाँ				
I. कॉर्पोरेट विनिर्माण	12827	1372	1305	231
II. कॉर्पोरेट -बुनियादी संरचना	9985	144	1294	1065
ए) परिवहन	636	0	0	0
बी) ऊर्जा	2713	92	1291	166
सी) पानी और सफ़ाई व्यवस्था	151	0	2	0
डी) संचार	757	0	2	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	1761	0	0	0
एफ) अन्वेषण खनन और रिफाइनरी	1346	0	0	850
जी) अन्य उप-क्षेत्र	2622	52	0	48
III. कॉर्पोरेट सेवा क्षेत्र	1894	70	547	16
IV. अन्य संस्थाएं	1026	4	0	0
ए) एसई जेड में इकाई	26	4	0	0
बी) सिडबी	0			
सी) एक्विजिशन बैंक	1000	0	0	0
V. बैंक	0	0	100	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबी एफ सी के अलावा)	2110	0	0	0
VII. एनबीएफसी	6934	433	767	5
ए) एनबीएफसी -आई एफ सी/ए एफ सी	6024	300	75	0
बी) एनबी एफ सी -एमएफआई	84	0	6	0
सी) एनबीएफसी - अन्य	827	133	686	5
VIII. गैर-सरकारी संगठन	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था	8	0	0	0
X. अन्य	470	10	9	22

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अप्रै.-जून 2020			अप्रै.-जून 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	242565	222718	19846	335303	303432	31870
1 चालू खाता (1.1+1.2)	122413	103355	19058	180009	173512	6497
1.1 पण्य	52210	63200	-10990	97432	128148	-30716
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	70204	40156	30048	82578	45364	37213
1.2.1 सेवाएं	46953	26195	20758	56216	30404	25812
1.2.1.1 यात्रा	1868	2766	-897	1597	2885	-1289
1.2.1.2 परिवहन	4805	4216	588	6732	6616	116
1.2.1.3 बीमा	564	378	186	772	428	344
1.2.1.4 जीएनआईई	148	330	-182	203	236	-32
1.2.1.5 विविध	39567	18504	21063	46912	20239	26673
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	22623	1849	20774	27602	2466	25136
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	11282	11514	-232	12962	11635	1327
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1009	1062	-52	1201	1118	83
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	707	304	403	807	310	497
1.2.2 अंतरण	18223	1249	16974	20917	1980	18937
1.2.2.1 आधिकारिक	27	270	-243	23	308	-285
1.2.2.2 निजी	18196	979	17217	20894	1672	19222
1.2.3 आय	5027	12712	-7685	5445	12980	-7536
1.2.3.1 निवेश आय	3664	12043	-8379	3843	12269	-8426
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1364	669	695	1601	711	890
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	120151	118776	1376	155293	129528	25766
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	74498	74384	114	102664	90366	12298
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	11985	12513	-528	23628	11731	11896
2.1.1.1 भारत में	11840	9735	2105	23086	5910	17176
2.1.1.1.1 इक्विटी	6897	9725	-2828	17902	5818	12084
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3908		3908	4255		4255
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1035	10	1025	928	92	837
2.1.1.2 विदेश में	144	2778	-2633	542	5821	-5279
2.1.1.2.1 इक्विटी	144	1235	-1091	542	2381	-1839
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	753	-753	0	760	-760
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	789	-789	0	2681	-2681
2.1.2 संविभाग निवेश	62514	61872	642	79036	78634	402
2.1.2.1 भारत में	61869	60772	1098	77499	77121	378
2.1.2.1.1 एफआईआई	61869	60772	1098	77499	77121	378
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	52749	48334	4414	69769	68832	937
2.1.2.1.1.2 ऋण	9121	12437	-3317	7730	8289	-559
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	644	1100	-456	1537	1513	24
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	18847	16097	2750	16481	13328	3153
2.2.1 बाह्य सहायता	5743	1638	4105	1893	1619	274
2.2.1.1 भारत द्वारा	9	20	-11	14	30	-15
2.2.1.2 भारत को	5733	1618	4116	1879	1589	290
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	4087	5246	-1159	3286	2343	942
2.2.2.1 भारत द्वारा	442	1003	-562	736	293	443
2.2.2.2 भारत को	3646	4243	-597	2550	2050	500
2.2.3 भारत को अल्पावधि	9017	9213	-196	11303	9366	1937
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	9017	8412	605	9259	9366	-107
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	801	-801	2044	0	2044
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	17695	15460	2235	20595	16530	4065
2.3.1 वाणिज्य बैंक	17695	14693	3003	20595	16506	4089
2.3.1.1 आस्तियां	6871	4383	2487	7895	6289	1606
2.3.1.2 देयताएं	10825	10310	515	12700	10217	2483
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	10653	7653	3000	11212	8686	2525
2.3.2 अन्य	0	767	-767	0	25	-25
2.4 रुपया ऋण चुकोती	0	55	-55	0	57	-57
2.5 अन्य पूंजी	9111	12779	-3668	15553	9247	6306
3 भूल-चूक	0	587	-587	0	393	-393
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	19846	-19846	0	31870	-31870
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	19846	-19846	0	31870	-31870

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अप्रै.-जून 2020			अप्रै.-जून 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	1840444	1689862	150582	2473396	2238302	235094
1 चालू खाता (1.1+1.2)	928804	784203	144601	1327857	1279929	47929
1.1 पण्य	396138	479523	-83385	718715	945294	-226579
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	532666	304679	227986	609142	334634	274508
1.2.1 सेवाएं	356253	198750	157503	414684	224280	190404
1.2.1.1 यात्रा	14176	20984	-6808	11778	21283	-9505
1.2.1.2 परिवहन	36457	31992	4465	49660	48803	857
1.2.1.3 बीमा	4283	2872	1411	5696	3160	2536
1.2.1.4 जीएनआईई	1123	2504	-1381	1500	1739	-239
1.2.1.5 विविध	300215	140399	159816	346050	149294	196756
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	171650	14027	157623	203612	18192	185420
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	85604	87365	-1762	95612	85825	9787
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	7659	8056	-396	8856	8247	609
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5364	2309	3055	5951	2286	3664
1.2.2 अंतरण	138268	9477	128792	154296	14604	139692
1.2.2.1 आधिकारिक	205	2049	-1844	171	2272	-2101
1.2.2.2 निजी	138063	7428	130635	154125	12332	141793
1.2.3 आय	38144	96452	-58308	40163	95750	-55588
1.2.3.1 निवेश आय	27797	91375	-63578	28351	90506	-62156
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10347	5077	5270	11812	5244	6568
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	911640	901204	10437	1145539	955474	190065
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	565250	564387	863	757313	666592	90721
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	90933	94938	-4006	174292	86537	87755
2.1.1.1 भारत में	89839	73864	15975	170293	43594	126698
2.1.1.1.1 इक्विटी	52333	73787	-21454	132055	42917	89137
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	29652	0	29652	31390	0	31390
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	7853	77	7776	6848	677	6171
2.1.1.2 विदेश में	1094	21074	-19981	3999	42943	-38944
2.1.1.2.1 इक्विटी	1094	9372	-8278	3999	17565	-13566
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5715	-5715	0	5603	-5603
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	5987	-5987	0	19776	-19776
2.1.2 संविभाग निवेश	474318	469449	4869	583021	580055	2966
2.1.2.1 भारत में	469430	461102	8328	571680	568891	2789
2.1.2.1.1 एफआईआई	469430	461102	8328	571680	568891	2789
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	400227	366734	33493	514658	507747	6911
2.1.2.1.1.2 ऋण	69203	94368	-25165	57022	61143	-4121
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	4888	8347	-3459	11341	11164	177
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	143001	122135	20866	121576	98314	23262
2.2.1 बाह्य सहायता	43572	12426	31146	13964	11940	2024
2.2.1.1 भारत द्वारा	71	153	-82	106	220	-114
2.2.1.2 भारत को	43501	12273	31228	13858	11720	2138
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	31013	39806	-8792	24237	17286	6951
2.2.2.1 भारत द्वारा	3350	7612	-4262	5430	2164	3265
2.2.2.2 भारत को	27664	32194	-4530	18807	15122	3685
2.2.3 भारत को अल्पावधि	68416	69904	-1488	83375	69088	14287
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	68416	63825	4591	68300	69088	-788
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	0	6079	-6079	15076	0	15076
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	134263	117303	16960	151922	121938	29984
2.3.1 वाणिज्य बैंक	134263	111481	22782	151922	121756	30166
2.3.1.1 आस्तियां	52131	33257	18874	58236	46388	11847
2.3.1.2 देयताएं	82132	78223	3908	93687	75367	18319
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	80826	58063	22763	82703	64074	18629
2.3.2 अन्य	0	5823	-5823	0	182	-182
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	419	-419	0	419	-419
2.5 अन्य पूंजी	69126	96959	-27833	114727	68210	46518
3 भुल-चूक	0	4456	-4456	0	2900	-2900
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	150582	-150582	0	235094	-235094
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	150582	-150582	0	235094	-235094

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	अप्रै.-जून 2020			अप्रै.-जून 2021 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	122413	103330	19083	180008	173482	6526
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क. + 1.अ.ख.)	99163	89394	9768	153648	158552	-4904
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	52210	63200	-10990	97432	128148	-30716
1.अ.क.1 बौद्धिक स्वर्ण	52073	62512	-10439	97353	120259	-22906
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	137	0	137	79	0	79
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		688	-688		7888	-7888
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	46953	26195	20758	56216	30404	25812
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	77	6	71	83	9	73
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	32	128	-97	58	127	-70
1.अ.ख.3 परिवहन	4805	4216	588	6732	6616	116
1.अ.ख.4 यात्रा	1868	2766	-897	1597	2885	-1289
1.अ.ख.5 निर्माण	659	625	34	583	892	-309
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	564	378	186	772	428	344
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1009	1062	-52	1201	1118	83
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	399	1847	-1448	191	1972	-1781
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	23396	2269	21127	28489	3017	25473
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	11282	11514	-232	12962	11635	1327
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	500	347	153	647	804	-157
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	148	330	-182	203	236	-32
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	2212	705	1507	2698	665	2033
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5027	12712	-7685	5445	12980	-7536
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1364	669	695	1601	711	890
1.आ.2 निवेश आय	3054	11861	-8807	2877	12009	-9132
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1306	7361	-6055	1425	7195	-5770
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	24	1222	-1198	143	1852	-1709
1.आ.2.3 अन्य निवेश	66	3273	-3207	45	2961	-2916
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1657	4	1653	1264	1	1263
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	610	182	428	966	260	706
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	18223	1223	16999	20916	1950	18966
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	18196	979	17217	20894	1672	19222
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	17596	739	16857	20074	1183	18891
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	600	240	360	820	489	331
1.इ.2 सामान्य सरकार	26	244	-218	22	278	-256
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	91	872	-782	116	177	-62
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	5	790	-786	7	56	-49
2.2 पूंजी अंतरण	86	82	4	109	121	-13
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	120061	137775	-17714	155179	161250	-6072
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	11985	12513	-528	23628	11731	11896
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	11840	9735	2105	23086	5910	17176
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	10805	9725	1081	22157	5818	16339
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	6897	9725	-2828	17902	5818	12084
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3908		3908	4255		4255
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1035	10	1025	928	92	837
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1035	10	1025	928	92	837
3.1.आ भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	144	2778	-2633	542	5821	-5279
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	144	1988	-1844	542	3141	-2599
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	144	1235	-1091	542	2381	-1839
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		753	-753		760	-760
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	789	-789	0	2681	-2681
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		789	-789		2681	-2681
3.2 संविभाग निवेश	62514	61872	642	79036	78634	402
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	61869	60772	1098	77499	77121	378
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	52749	48334	4414	69769	68832	937
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	9121	12437	-3317	7730	8289	-559
3.2आ भारत द्वारा संविभाग निवेश	644	1100	-456	1537	1513	24
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	3421	3805	-385	3544	4841	-1297
3.4 अन्य निवेश	42142	39740	2403	48970	34174	14797
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमा शिथियां	10653	8420	2233	11212	8711	2501
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मवमेंट, एनआरजी)	0	767	-767	0	25	-25
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमा शिथियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमा शिथियां)	10653	7653	3000	11212	8686	2525
3.4.2.3 सामान्य सरकार			0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र			0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	16873	13924	2949	14562	11782	2781
3.4.3अ भारत को ऋण	16422	12901	3521	13812	11458	2353
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	451	1023	-573	750	323	427
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	40	47	-7	32	63	-30
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	9017	9213	-196	11303	9366	1937
3.4.6 अन्य खाते प्राय:देय-अन्य	5560	8135	-2575	11862	4253	7609
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार			0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	19846	-19846	0	31870	-31870
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण			0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.			0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.			0			0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	19846	-19846	0	31870	-31870
4. कुल आस्तियां / देयताएं	120061	137775	-17714	155179	161250	-6072
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	67803	65000	2803	97582	84208	13374
4.2 ऋण लिखत	46698	44794	1904	45735	40920	4815
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	5560	27981	-22422	11862	36123	-24261
5. निवल भूल-चूक		587	-587		393	-393

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	अप्रै.-जून 2020			अप्रै.-जून 2021 (प्र.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	928798	784007	144791	1327850	1279707	48143
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	752391	678274	74117	1133399	1169574	-36175
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	396138	479523	-83385	718715	945294	-226579
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	395100	474304	-79205	718135	887106	-168971
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	1038	0	1038	580	0	580
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	5219	-5219	0	58188	-58188
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	356253	198750	157503	414684	224280	190404
1.अ.ख.1 अन्य के स्वाभिमूर्ति वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	588	45	542	610	68	542
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	241	975	-733	424	938	-514
1.अ.ख.3 परिवहन	36457	31992	4465	49660	48803	857
1.अ.ख.4 यात्रा	14176	20984	-6808	11778	21283	-9505
1.अ.ख.5 निर्माण	5003	4743	260	4303	6581	-2278
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4283	2872	1411	5696	3160	2536
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	7659	8056	-396	8856	8247	609
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	3026	14016	-10990	1412	14547	-13135
1.अ.ख.9 दरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	177514	17215	160300	210155	22252	187903
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	85604	87365	-1762	95612	85825	9787
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3792	2632	1160	4776	5933	-1157
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1123	2504	-1381	1500	1739	-239
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	16787	5352	11435	19901	4903	14998
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	38144	96452	-58308	40163	95750	-55588
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	10347	5077	5270	11812	5244	6568
1.आ.2 निवेश आय	23171	89993	-66822	21224	88588	-67364
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	9912	55855	-45943	10515	53077	-42562
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	185	9273	-9088	1051	13662	-12610
1.आ.2.3 अन्य निवेश	500	24831	-24332	336	21843	-21508
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	12574	34	12540	9322	7	9315
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	4626	1382	3244	7127	1918	5209
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	138262	9280	128982	154289	14383	139906
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	138063	7428	130635	154125	12332	141793
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	133511	5606	127905	148076	8724	139352
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4553	1822	2731	6049	3608	2441
1.इ.2 सामान्य सरकार	199	1852	-1654	164	2051	-1887
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	690	6620	-5930	854	1309	-455
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नाम) / निस्तारण (जमा)	34	5996	-5961	51	413	-363
2.2 पूँजी अंतरण	656	624	32	803	895	-93
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	910956	1045362	-134406	1144692	1189480	-44788
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	90933	94938	-4006	174292	86537	87755
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	89839	73864	15975	170293	43594	126698
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	81986	73787	8199	163445	42917	120527
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	52333	73787	-21454	132055	42917	89137
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	29652	0	29652	31390	0	31390
3.1.अ.2 ऋण लिखत	7853	77	7776	6848	677	6171
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	7853	77	7776	6848	677	6171
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	1094	21074	-19981	3999	42943	-38944
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	1094	15087	-13993	3999	23167	-19168
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	1094	9372	-8278	3999	17565	-13566
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5715	-5715	0	5603	-5603
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	5987	-5987	0	19776	-19776
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	5987	-5987	0	19776	-19776
3.2 संविभाग निवेश	474318	469449	4869	583021	580055	2966
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	469430	461102	8328	571680	568891	2789
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	400227	366734	33493	514658	507747	6911
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	69203	94368	-25165	57022	61143	-4121
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	4888	8347	-3459	11341	11164	177
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	25953	28871	-2918	26144	35709	-9565
3.4 अन्य निवेश	319753	301522	18232	361235	252085	109150
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	80826	63886	16940	82703	64257	18447
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	5823	-5823	0	182	-182
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	80826	58063	22763	82703	64074	18629
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	128022	105649	22373	107420	86908	20512
3.4.3अ भारत को ऋण	124601	97884	26717	101884	84524	17361
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	3421	7765	-4344	5536	2384	3151
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	306	358	-53	238	462	-224
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	68416	69904	-1488	83375	69088	14287
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	42183	61725	-19541	87499	31370	56128
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	150582	-150582	0	235094	-235094
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	150582	-150582	0	235094	-235094
4. कुल आस्तियां / देयताएं	910956	1045362	-134406	1144692	1189480	-44788
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	514453	493185	21268	719825	621168	98657
4.2 ऋण लिखत	354320	339871	14449	337369	301848	35520
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	42183	212307	-170123	87499	266464	-178966
5. निवल भूल-चूक	0	4456	-4456	2900	-2900	0

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरीकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2020-21		2020		2021			
			जून		मार्च		जून	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	193929	482179	185590	419385	193929	482179	199208	493691
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	122726	456947	120286	395773	122726	456947	125324	467991
1.2 अन्य पूंजी	71203	25232	65304	23612	71203	25232	73884	25700
2 संविभाग निवेश	7936	281961	4303	241620	7936	281961	7912	281267
2.1 इक्विटी	2340	177278	830	138961	2340	177278	3146	176203
2.2 ऋण	5596	104682	3474	102659	5596	104682	4766	105064
3 अन्य निवेश	80606	446473	53558	432739	80606	446473	76911	447153
3.1 व्यापार ऋण	5644	100337	1145	103998	5644	100337	7861	102193
3.2 ऋण	13335	189993	7425	184813	13335	189993	13661	189520
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	42436	142069	27741	132942	42436	142069	35904	141873
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	19191	14074	17247	10987	19191	14074	19485	13567
4 रिज़र्व्स	576984		505702		576984		611075	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	859454	1210613	749153	1093744	859454	1210613	895106	1222111
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-351158		-344591		-351158		-327005

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)					
	वि. व 2020-21	2020		2021		विव 2020-21	2020		2021	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	सितं.		अक्टू.	सितं.	अक्टू.	
	1	2	3	4	5	6	7	8		
ए. निपटान प्रणाली										
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)										
1 सीसीआईएल प्रचलित प्रणाली (1.1 से 1.3)	27.97	2.44	3.21	2.85	161943141	12416671	16683094	16600978		
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	11.55	1.06	1.37	1.04	110634315	8849617	11404584	11415739		
1.1.1 आउटराइट	6.28	0.61	0.90	0.55	10032187	900488	1127485	745937		
1.1.2 रेपो	2.84	0.27	0.25	0.25	43751173	4108317	3885956	3822009		
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो	2.43	0.18	0.22	0.23	56850956	3840812	6391143	6847793		
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	16.04	1.36	1.77	1.73	48903961	3435633	4826170	4736040		
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	0.38	0.02	0.07	0.08	2404865	131420	452340	449200		
बी. भुगतान प्रणाली										
I वित्तीय बाजार आधार-संरचना (एफएमआई)										
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	1591.92	138.22	174.57	184.11	105599849	8496046	11069631	10134368		
1.1 ग्राहक लेनदेन	1573.47	136.54	173.33	182.90	91008367	7226105	9838858	8956918		
1.2 इंटरबैंक लेनदेन	18.45	1.68	1.24	1.22	14591482	1269941	1230773	1177450		
II खुदरा										
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	317867.74	28646.32	45720.72	52919.52	33504226	2993166	3495969	3748602		
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	11.31	1.02	0.98	0.86	623	57	57	49		
2.2 एपीबीएस \$	14372.99	961.85	781.62	1192.91	111001	5531	6199	7519		
2.3 आईएमपीएस	32783.47	3189.72	3848.84	4306.71	2941500	274645	324096	370712		
2.4 एनएसीएच जमा \$	16465.44	1015.89	1171.57	1660.26	1216535	91438	91281	122519		
2.5 एनईएफटी	30927.89	2761.65	3359.54	3574.46	25130910	2235389	2419688	2476397		
2.6 यूपीआई @	223306.64	20716.19	36558.17	42184.32	4103658	386107	654648	771407		
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	10.45	0.97	1.14	1.11	172	16	16	16		
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	10456.54	920.15	987.44	979.36	865520	79305	84660	85776		
3.1 भीम आधार पे @	160.84	10.55	19.39	21.49	2580	192	440	560		
3.2 एनएसीएच नामे \$	9645.75	848.34	878.31	865.69	862027	79022	84068	85103		
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	649.96	61.26	89.74	92.18	913	91	152	114		
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	57786.60	5650.70	5337.50	6008.76	1291799	133792	142817	177413		
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	17641.06	1718.03	1847.21	2155.81	630414	64652	80228	100943		
4.1.1 पीओएस आधारित \$	8688.81	818.33	961.53	1075.23	280769	26956	31743	38442		
4.1.2 अन्य \$	8952.25	899.70	885.68	1080.58	349645	37696	48485	62500		
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	40145.54	3932.66	3490.29	3852.95	661385	69141	62589	76471		
4.2.1 पीओएस आधारित \$	20773.50	1983.98	2053.00	2302.56	377630	37110	38591	47226		
4.2.2 अन्य \$	19372.04	1948.68	1437.29	1550.39	283755	32031	23998	29245		
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	49742.55	4623.12	4934.60	6131.06	197696	17802	30273	26372		
5.1 वॉलेट	39987.01	3639.89	3884.65	4888.97	152065	13718	25645	21702		
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	9755.54	983.23	1049.96	1242.09	45631	4084	4628	4670		
5.2.1 पीओएस आधारित \$	607.15	50.99	94.43	64.58	10591	947	825	998		
5.2.2 अन्य \$	9148.39	932.24	955.52	1177.51	35040	3136	3803	3672		
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6703.70	643.08	624.10	635.20	5627108	524090	566468	582604		
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6702.54	643.08	624.10	635.20	5625859	524090	566468	582604		
6.2 अन्य	1.17	-	-	-	1249	-	-	-		
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	442557.14	40483.36	57604.36	66673.91	41486348	3748156	4320187	4620768		
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	444149.06	40621.58	57778.93	66858.02	147086197	12244202	15389818	14755136		
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	437445.36	39978.50	57154.83	66222.82	141459089	11720112	14823351	14172532		

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि. व. 2020-21	2020	2021		वि. व. 2020-21	2020	2021	
		अक्टू.	सितं.	अक्टू.		अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	258033.70	22801.51	39989.49	44750.88	9201212	798327	1178882	1344959
1.1 इंटर-बैंक \$	25220.71	2103.09	3358.50	3761.37	1871390	158841	218049	243704
1.2 इंटर-बैंक \$	232812.99	20698.41	36630.99	40989.51	7329822	639486	960832	1101254
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	32493.63	2977.78	3187.18	3233.71	41581497	3407315	4003452	3960872
2.1 इंटर-बैंक @	6886.15	619.27	598.49	631.51	20601554	1646090	1795714	1723311
2.2 इंटर-बैंक @	25607.48	2358.51	2588.68	2602.20	20979943	1761225	2207737	2237561
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)	60905.81	5660.71	5545.36	6037.78	2889826	268881	257964	289913
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	51.41	4.85	4.98	5.64	2560	240	249	286
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	60602.23	5630.83	5512.90	6002.43	2878025	267747	256767	288605
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	252.17	25.04	27.48	29.71	9240	893	948	1022
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	394.77	34.11	5.37	4.79	1533	134	46	45
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	353.50	29.24	5.08	4.44	1484	129	40	39
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	41.27	4.87	0.29	0.35	49	5	6	6
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	9460.43	720.69	888.88	946.33	225420	18354	22793	24799
5.1 एईपीएस @	9460.43	720.69	888.88	946.33	225420	18354	22793	24799

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2021	2020	2021	
	तक	अक्टू.	सितं.	अक्टू.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	9602.51	9335.85	9853.28	10004.07
1.1 क्रेडिट कार्ड	620.49	594.20	650.25	663.61
1.2 डेबिट कार्ड	8982.02	8741.65	9203.03	9340.46
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	21952.60	20143.54	22461.77	25307.71
2.1 वॉलेट @	20052.10	18578.63	20203.10	22886.70
2.2 कार्ड @	1900.51	1564.92	2258.68	2421.01
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.39	2.34	2.41	2.41
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.14	2.10	2.13	2.13
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.25	0.24	0.28	0.28
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	4.04	3.49	5.13	5.34
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	47.20	45.81	49.77	51.55
6 भारत क्यूआर @	35.70	26.05	52.85	45.59
7 यूपीआई क्यूआर *	925.22	657.45	1196.08	1283.81

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।

* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिल दिया गया है।

3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।

4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2019-20	2020		2021	
			फर.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	159573	16911	16781	14261	14405
	बकाया	1078535	1046766	1196084	1210379	1224772
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	116389	11460	12407	9820	10143
	बकाया	734807	716363	827156	836976	847119
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	25893	2690	3307	2049	2252
	बकाया	166140	156258	190437	192486	194738
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	36	-20	-21	-26	-23
	बकाया	3143	2939	3086	3060	3037
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	-1	-3	-3	0	57
	बकाया	9	-23	-17	-17	40
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16510	1887	1053	1162	1135
	बकाया	209168	207059	217980	219142	220277
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	20334	2131	2014	1886	1950
	बकाया	76042	73728	90914	92800	94750
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	41795	4494	4330	3952	3798
	बकाया	166087	161115	195847	199799	203597
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	92618	90327	104601	105928	107099
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7097	6970	7324	7375	7418
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	7536	7464	7330	7285	7267
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	58836	56354	76592	79211	81813
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	11821	281	1727	797	974
	बकाया	114222	115291	128912	129709	130683
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	1	0	0	0	0
	बकाया	-25	-25	-24	-24	-24
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	30170	3937	3941	3909	3647
	बकाया	252190	248022	274905	278848	282483
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	19495	2619	1923	1903	1843
	बकाया	117987	115127	129270	131173	133016
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	-101	1	-1	-1	0
	बकाया	162	-288	158	157	157
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18168	-1120	-669	-603	-470
	बकाया	1135	3949	-5121	-5724	-6194
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	28972	2452	2677	2610	2274
	बकाया	122602	118507	140538	143148	145422
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	-4	0	8	0	0
	बकाया	-155	-180	-147	-147	-147
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-24	-15	3	0	0
	बकाया	-106	-99	-103	-103	-103
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	10565	11006	10310	10344	10332
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	13014	1514	433	532	615
	बकाया	91538	82381	94023	94555	95170

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियों हैं अर्थात् सकल प्राप्तियों माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

श्रेणी	केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां				
	2020		2021		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून	सित्त.
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	7137069	7357111	7635902	7882533	8235318
1. वाणिज्य बैंक	38.55	37.81	37.77	35.99	37.82
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.34	0.25	0.27	0.34	0.35
3. बीमाकृत कंपनियां	25.33	25.64	25.30	25.83	24.18
4. म्यूच्युअल फंड	2.42	2.62	2.94	2.82	2.91
5. सहकारी बैंक	1.86	1.83	1.82	1.82	1.50
6. वित्तीय संस्थाएं	1.42	1.00	1.00	1.43	1.17
7. कॉरपोरेट	0.94	1.05	1.06	1.39	0.72
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	2.05	2.10	1.87	1.79	1.81
9. भविष्य निधियां	4.77	4.61	4.44	4.04	3.77
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.00	15.71	16.20	17.11	16.98
11. अन्य	7.32	7.37	7.33	7.43	8.79
11.1 राज्य सरकार	1.86	1.76	1.69	1.67	1.67

श्रेणी	राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां				
	2020		2021		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून	सित्त.
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	3564979	3721573	3879982	4028849	4153508
1. वाणिज्य बैंक	34.60	34.19	33.69	33.75	35.94
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.54	0.36	0.48	0.39	0.44
3. बीमाकृत कंपनियां	30.26	30.25	30.04	29.67	27.50
4. म्यूच्युअल फंड	1.96	1.92	1.82	1.74	1.97
5. सहकारी बैंक	4.19	4.11	4.05	4.12	3.60
6. वित्तीय संस्थाएं	1.92	1.88	1.86	1.79	1.72
7. कॉरपोरेट	0.39	0.45	0.49	1.45	1.32
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
9. भविष्य निधियां	21.31	21.20	22.00	21.09	18.27
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.81	0.77	0.88	0.85
11. अन्य	4.80	4.82	4.77	5.10	8.38
11.1 राज्य सरकार	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18

श्रेणी	खजाना बिल				
	2020		2021		
	सित्त.	दिसं.	मार्च	जून	सित्त.
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	982286	839729	690646	901327	763582
1. वाणिज्य बैंक	53.50	54.75	55.54	52.25	50.22
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.16	1.65	2.82	1.82	1.33
3. बीमाकृत कंपनियां	4.06	4.50	5.61	4.75	4.12
4. म्यूच्युअल फंड	19.90	18.98	17.80	19.93	17.72
5. सहकारी बैंक	1.63	1.61	2.43	1.60	1.32
6. वित्तीय संस्थाएं	1.34	1.11	1.24	2.56	2.12
7. कॉरपोरेट	1.63	2.01	3.16	3.00	2.40
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
9. भविष्य निधियां	0.00	0.09	0.22	0.10	0.37
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	4.80	0.68	0.49	2.58	2.63
11. अन्य	10.99	14.63	10.70	11.42	17.62
11.1 राज्य सरकार	7.76	13.27	5.98	7.97	12.64

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (सं.अ.)	2021-22 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	4265969	4515946	5040747	5410887	6523916	7160694
1.1 गतिविधियां	2537905	2635110	2882758	3074492	3906147	4254004
1.1.1 राजस्व	1878417	2029044	2224367	2446605	3259401	3242247
1.1.2 पूंजी	501213	519356	596774	588233	636062	922982
1.1.3 ऋण	158275	86710	61617	39654	10684	88775
1.2 गैर गतिविधियां	1672646	1812455	2078276	2253027	2526514	2810847
1.2.1 राजस्व	1555239	1741432	1965907	2109629	2334608	2602289
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	724448	814757	894520	955801	1082302	1244457
1.2.2 पूंजी	115775	69370	111029	141457	189487	177328
1.2.3 ऋण	1632	1654	1340	1941	2419	31230
1.3 अन्य	55417	68381	79713	83368	91255	95843
2. कुल प्राप्तियां	4288432	4528422	5023352	5734166	6489736	7039032
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3132201	3376416	3797731	3851563	3834126	4682025
2.1.1 कर प्राप्तियां	2622145	2978134	3278947	3231582	3175594	3829889
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1652377	1853859	2030050	2012578	2100982	2514708
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	965622	1121189	1246083	1216203	1071552	1311449
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	4146	3086	2814	2800	3060	3732
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	510056	398282	518783	619981	658532	852135
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	33220	34224	36273	31137	39830	33198
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	69063	142433	140287	110094	54861	201138
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	20942	42213	44667	59515	21151	19581
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	48122	100219	95621	50578	33710	181557
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	1064704	997097	1102729	1449230	2634928	2277532
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	617123	144792	387091	571872	890012	-----
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	195816	-144847	325987	190241	107494	-----
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	429585	844375	710119	868676	1690394	-----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1046708	989167	1097210	1440548	2580406	2276017
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	689821	794856	795845	971378	1778062	1620936
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	35038	71222	88961	209232	455724	367863
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	45688	42351	51004	38280	47300	45504
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	-6436	18423	-18298	10411	-3450	5051
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	17792	25138	66289	-14227	29050	28868
3ख.1.6 नकद शेष	-22463	-12476	17395	-323279	34179	121663
3ख.1.7 अन्य	287268	49653	96014	548753	239540	86132
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	17997	7931	5519	8682	54522	1514
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	27.7	26.4	26.7	26.6	33.0	32.1
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	27.9	26.5	26.6	28.2	32.9	31.6
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	20.3	19.8	20.1	18.9	19.4	21.0
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	17.0	17.4	17.4	15.9	16.1	17.2
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.9	5.8	5.8	7.1	13.3	10.2

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2021 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	604	30	1757	28	1321	14
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	489	5	-	-	-	-
6	गोवा	8	1	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	179	2	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	1198	26	526	13
11	झारखंड	134	9	247	2	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	96	3	1004	2	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	-	-	307	31	161	26
17	मेघालय	60	2	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	94	29	-	-
19	नगालैंड	37	8	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	180	2	-	-	-	-
23	राजस्थान	2012	26	336	1	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	648	31	1280	29	460	12
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अक्टूबर 2021 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	9001	886	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1892	3	--	-
3	असम	4205	59	--	-
4	बिहार	6055	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	5082	--	1	4550
6	गोवा	665	336	--	-
7	गुजरात	5293	519	--	-
8	हरियाणा	838	1311	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	488	--	--	-
11	झारखंड	6273	--	--	23000
12	कर्नाटक	2327	--	--	-
13	केरल	--	996	--	-
14	मध्य प्रदेश	48121	685	--	24000
15	महाराष्ट्र	168	109	--	-
16	मणिपुर	785	45	9	-
17	मेघालय	381	49	--	-
18	मिज़ोरम	1789	36	--	-
19	नगालैंड	12154	1581	92	23863
20	उड़ीसा	333	--	--	975
21	पुदुचेरी	1700	--	8	-
22	पंजाब	--	--	129	4200
23	राजस्थान	7203	--	40	14023
24	तमिलनाडु	6147	1344	--	-
25	तेलंगाना	403	10	--	900
26	त्रिपुरा	1006	--	180	-
27	उत्तराखंड	3541	138	--	-
28	उत्तरप्रदेश	9654	632	214	-
29	पश्चिम बंगाल	--	--	--	-
	कुल	135505	8739	672	95511

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2019-20		2020-21		2021-22						2021-22 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	अगस्त		सितंबर		अक्टूबर		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	42415	33444	50896	41915	2000	840	6000	4840	5000	3840	30750	23899
2	अरुणाचल प्रदेश	1366	1287	767	767	-	-	-	-	-	-	400	400
3	असम	12906	10996	15030	14230	1700	1700	1700	1700	1600	1600	5500	5500
4	बिहार	25601	22601	27285	24685	2000	2000	2000	2000	4000	3000	16000	15000
5	छत्तीसगढ़	11680	10980	13000	10500	-	-	1000	1000	2000	1500	4000	3500
6	गोवा	2600	2000	3354	3054	200	200	400	200	100	100	1200	1000
7	गुजरात	38900	28600	44780	33280	1500	-500	3000	1000	5554	3554	17554	8554
8	हरियाणा	24677	20677	30000	25550	2500	2000	1000	1000	3000	2500	16500	12700
9	हिमाचल प्रदेश	6580	4460	6000	3755	-	-	1000	1000	-	-100	1000	900
10	जम्मू और कश्मीर	7869	6760	9328	6020	500	500	1100	1100	-	-	4200	3500
11	झारखंड	7500	5656	9400	8900	-	-500	500	500	1000	500	1500	500
12	कर्नाटक	48500	42500	69000	61900	-	-	-	-	6000	6000	6000	6000
13	केरल	18073	12617	28566	23066	2500	1500	5500	4500	2000	1000	19000	16000
14	मध्य प्रदेश	22371	16550	45573	38773	-	-	6000	6000	2000	-1000	10000	7000
15	महाराष्ट्र	48498	32998	69000	50022	8000	5000	8500	7000	2500	-1000	48750	38750
16	मणिपुर	1757	1254	1302	1044	-	-	147	47	140	90	887	737
17	मेघालय	1344	1070	1777	1587	-	-	400	400	200	140	1000	840
18	मिज़ोरम	900	745	944	677	-	-100	80	80	104	104	434	184
19	नगालैंड	1000	423	1721	1366	150	150	150	150	89	89	989	889
20	उड़ीसा	7500	6500	3000	500	-	-500	-	-	-	-1000	-	-3000
21	पुदुचेरी	970	470	1390	790	-	-	124	124	-	-	124	124
22	पंजाब	27355	18470	32995	23467	1250	-950	5170	3770	1162	862	12282	3032
23	राजस्थान	39092	24686	57359	44273	-	-	6000	5500	5000	3730	30600	25018
24	सिक्किम	809	481	1292	1292	-	-	251	251	-	-	751	751
25	तमिलनाडु	62425	49826	87977	76796	6000	6000	1000	1000	4000	2740	43000	37740
26	तेलंगाना	37109	30697	43784	37365	3500	2660	3500	2660	1500	660	25000	20051
27	त्रिपुरा	2928	2578	1916	1631	-	-	300	300	-	-	300	150
28	उत्तराखंड	69703	52744	75500	59185	7500	5988	7500	6500	7500	5524	35000	24278
29	उत्तरप्रदेश	5100	4500	6200	5208	-	-	-	-150	-	-	1200	350
30	पश्चिम बंगाल	56992	40882	59680	50180	5000	3000	8500	7000	5000	3500	34500	19327
	कुल	634521	487454	798816	651777	44300	28988	70822	59472	59449	37934	368421	273674

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

- 2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
 2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
 4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

- प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
 1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
 2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

- 1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान
 1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
 'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।
 हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2018-19 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

o बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल हैं।

o जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 29 मई 2020 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2020-21 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2020-21 से लिया गया है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

:- नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2021	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक 2020-21	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2020-21 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 2, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 1, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 41, सं. 2, 2020	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर्स; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं हैं।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 में किया जाएगा। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdepr@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001। एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैंक
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdepr@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।

